

भारतीय रिज़र्व बैंक
बुलेटिन



दिसंबर 2017
खंड 71 अंक 12

संपादन समिति

जनक राज

गौतम चैटर्जी

राजीव रंजन

संपादक

सुनील कुमार

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादन समिति के निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है। हस्ताक्षरित लेख में व्यक्त विचारों के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी है।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2017

सर्वाधिकार सुरक्षित।

सामग्री के पुनः प्रयोग की अनुमति है,

बशर्ते कि स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन के सदस्यता शुल्क के लिए कृपया “भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के महत्त्वपूर्ण प्रकाशन” खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को इंटरनेट के माध्यम से

<http://www.bulletin.rbi.org.in> पर भी देखा जा सकता है।

विषयवस्तु

मौद्रिक नीति वक्तव्य 2017-18

पांचवां द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 1

भाषण

भारत में मौद्रिक नीति का संचरण : यह महत्वपूर्ण क्यों है और इसने ठीक से काम क्यों नहीं किया?

विरल वी. आचार्य 7

भारत की मौद्रिक नीति समिति के कार्यकाल का एक वर्ष
माइकल देबब्रत पात्र

17

लेख

भारत के बाह्य ऋण का विवेचन : प्रमुख प्रवृत्तियों का निर्धारण

25

बैंकिंग सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सर्वेक्षण: 2016-17

45

वर्तमान सांख्यिकी

55

बुलेटिन लेख, 2018 के लिए सांकेतिक कैलेंडर

98

हाल के प्रकाशन

99

मौद्रिक नीति वक्तव्य 2017-18

पांचवां द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य

पांचवां द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प भारतीय रिज़र्व बैंक*

मौद्रिक नीति समिति ने आज की अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थितियों के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि -

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए।

परिणामस्वरूप, एलएएफ के तहत रिवर्स रिपो दर 5.75 प्रतिशत पर, और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर 6.25 प्रतिशत पर बरकरार रहती हैं।

एमपीसी का निर्णय मौद्रिक नीति के तटस्थ रुझान के अनुरूप है। इसका तारतम्य, वृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत के मध्यावधिक लक्ष्य को +2/-2 प्रतिशत के दायरे में रखने के उद्देश्य से भी है। इस निर्णय के समर्थन में प्रमुख विवेचनों का वर्णन नीचे दिए गए विवरण में किया गया है।

आकलन

2. अक्टूबर 2017 में एमपीसी की अंतिम बैठक से वैश्विक आर्थिक गतिविधि इस वर्ष की अंतिम तिमाही से मुख्य रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) के कारण गति पकड़ रही है। अमेरिकी वृद्धि भूचालों के प्रति मुख्य रूप से लचीली रही और इसमें वर्ष 2017 की तीसरी तिमाही में पिछले तीन वर्षों में उच्चतम गति से वृद्धि हुई जिसमें निजी उपभोग, निवेश गतिविधि और निवल निर्यात का सकारात्मक योगदान रहा। बेरोजगारी दर अक्टूबर में कम होकर 4.1 प्रतिशत हो गई जो पिछले 17 वर्षों में सबसे कम है। यूरो क्षेत्र में, आर्थिक वृद्धि में विस्तार हुआ जिसे उदार मौद्रिक नीति और मजबूत नौकरी

अभिलाषों से सहायता मिली। जापानी अर्थव्यवस्था भी तीसरी तिमाही में लगातार बढ़ती रही जिसमें मुख्य रूप से बाह्य मांग से सहायता मिली जिसने घरेलू उपभोग के धीमे होने की क्षतिपूर्ति में मदद की।

3. प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में सेवा क्षेत्र चीन में तीसरी तिमाही में वृद्धि का मुख्य संचालक रहा। तथापि, रियल एस्टेट और निर्माण गतिविधि में कमजोरी से वृद्धि में धीमापन रहा। ब्राजील में आवक आंकड़े बताते हैं कि तीसरी तिमाही में सुधार ने और गति पकड़ी जहां बेरोजगारी ने सितंबर में वर्ष के अंदर कम आंकड़े को छुआ। कारोबार और उपभोक्ता विश्वास अक्टूबर में बढ़ गया। रूस में, औद्योगिक उत्पादन में कमजोरी के चलते आर्थिक गतिविधि तीसरी तिमाही में नरम रही। दक्षिण अफ्रीका अर्थव्यवस्था कमजोर विनिर्माण गतिविधि, बेरोजगारी के बढ़े हुए स्तर और राजनीतिक अस्थिरता के कारण विपरीत परिस्थितियों का सामना करती रही।

4. चौथी तिमाही के लिए विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का नवीनतम आकलन कम होते निर्यात आदेशों के कारण वैश्विक व्यापार में गति का अभाव दर्शाता है। बाजार को पुनर्संतुलित करने के लिए पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) के प्रयासों के कारण नवंबर की शुरुआत में कच्चे तेल की कीमतें ढाई वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। बुलियन कीमतें बढ़ते अमेरिकी डॉलर के कारण कुछ बिजली दवाब में रही हैं। कमजोर गैर-तेल पण्य-वस्तुओं की कीमतें और नियंत्रित मजदूरी गतिकी ने कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखा है जबकि प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति परिदृश्य विविध रहा है।

5. वैश्विक वित्तीय बाजार में उछाल रहा जिसने उन्नत होता आर्थिक परिदृश्य और अमेरिकी फेडरल द्वारा मौद्रिक नीति का धीरे-धीरे सामान्यीकरण दर्शाया। इक्विटी बाजारों को उन्नत हुए कॉर्पोरेट अर्जन और अमेरिका में कर में बड़ी कटौतियों की प्रत्याशा से लाभ मिला है। हालांकि, इक्विटी बाजारों ने सामान्य रूप से उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में अभिलाभ प्राप्त किए हैं, कुछ देशों में इनको जोखिम से बचने की व्यवस्था करनी पड़ी। जबकि अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति दवाबों के अभाव में बॉन्ड प्रतिफल लगभग समान रहे हैं, किंतु

* 06 दिसंबर 2017 को जारी।

देश-विशिष्ट कारकों की वजह से अधिकांश उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में इनमें बढ़ोतरी हुई है। मुद्रा बाजारों में, अमेरिकी डॉलर में वृद्धि हुई जबकि यूरो में सकारात्मक आर्थिक आंकड़ों के कारण उछाल नवंबर में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण गायब हो गया। घरेलू कारकों की वजह से कई उभरती बाजार मुद्राएं कमजोर हो गईं। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में जोखिम-प्रतिफल ट्रेड-ऑफ पर निवेशक की अवधारणाओं के आधार पर पूंजी प्रवाह विभिन्न देशों में अलग-अलग रहा है।

6. घरेलू मोर्चे पर, लगातार पांच तिमाहियों की मंदी के बाद संवृद्धित वास्तविक सकल मूल्य (जीवीए) वृद्धि वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में क्रमवार तेज हुई। ऐसा औद्योगिक गतिविधि में तेज अभिवृद्धि के कारण हुआ। उद्योग के सभी तीनों उप-क्षेत्रों ने उच्चतर वृद्धि दर्ज की। उद्योग के मुख्य घटक विनिर्माण क्षेत्र में जीवीए वृद्धि बढ़ी हुई मांग तथा वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) के बात रि-स्टॉकिंग के कारण तेजी से बढ़ी। कोयला और प्राकृतिक गैस के उच्चतर उत्पादन के कारण दूसरी तिमाही में खनन क्षेत्र में वृद्धि हुई। उच्चतर मांग के कारण विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवा क्षेत्र में भी जीवीए वृद्धि मजबूत हुई। इसके विपरीत, कृषि और संबद्ध गतिविधियों में वृद्धि धीमी हुई जिसने प्रत्याशित से कम खरीफ फसल प्रतिलक्षित की। पहली तिमाही में सरकारी खर्च की बड़ी मात्रा में फ्रंट-लोडिंग के बाद मुख्य रूप से वित्तीय, बीमा, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाओं तथा लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं (पीएडीओ) में मंदी के कारण सेवा क्षेत्र की गतिविधि में कमी आई। थोड़े सुधार के बावजूद, निर्माण क्षेत्र की वृद्धि आरईआरए तथा जीएसटी के कार्यान्वयन के क्षणिक प्रभावों के कारण धीमी रही। पिछली तिमाही की तुलना में दूसरी तिमाही में वृद्धि में कुछ मंदी के बावजूद व्यापार, होटलों, परिवहन और संचार उप-समूहों में वृद्धि लचीली रही। व्यय पक्ष पर, सकल स्थायी पूंजी निर्माण की वृद्धि में लगातार दूसरी तिमाही में सुधार हुआ। तथापि, निजी अंतिम उपभोक्ता व्यय, जो समग्र मांग का आधार है, दूसरी तिमाही में आठ तिमाहियों के सबसे नीचले स्तर पर पहुंच गया।

7. दूसरी तिमाही से आगे देखते हुए, तीसरी तिमाही में रबी की बुआई अब तक पिछले वर्ष की तुलनात्मक अवधि के दौरान बुआई रकबे से थोड़ी सी कम रही है। अक्टूबर से बारिश

दीर्घावधि औसत (एलपीए) से लगभग 13 प्रतिशत कम रही है। प्रमुख जलाशय जो रबी की फसल के दौरान सिंचाई का मुख्य स्रोत हैं, पिछले वर्ष के 67 प्रतिशत की तुलना में पूरे जलाशय स्तर का 64 प्रतिशत रहे। सकारात्मक पक्ष पर, एक वर्ष पहले की तुलना में दलहन की बुआई काफी अधिक बढ़ी जो आंशिक रूप से दलहन की सभी किस्मों के लिए निर्यात प्रतिबंध हटाने के प्रभाव को दर्शाती है।

8. उपलब्ध उच्च-बारंबारता संकेतक तीसरी तिमाही के लिए औद्योगिक गतिविधि की मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। अक्टूबर में मुख्य उद्योगों की वृद्धि सपाट रही क्योंकि स्टील और उर्वरकों को छोड़कर सभी संघटकों में क्रमवार मंदी हुई। कोयला खनन जिसमें दूसरी तिमाही में मजबूती से पुनरुद्धार हुआ, में भी मंदी आई जबकि सीमेंट उत्पादन कम हो गया। इसके विपरीत, विनिर्माण के लिए परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) जिसमें अक्टूबर में गिरावट आई थी, उसमें आउटपुट और नए आदेशों के चलते नवंबर में सुधार हुआ। रिजर्व बैंक के औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण (आईओएस) के अनुसार तीसरी तिमाही में उत्पादन के बढ़ने की संभावना है क्योंकि आदेश बहियां बढ़ रही हैं।

9. सेवा क्षेत्र में गतिविधि अक्टूबर में मिश्रित रही है। परिवहन क्षेत्र में, वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री कम हुई, यात्री वाहन और दुपहिया वाहन संकुचन मोड में चले गए। इसके विपरीत, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री और मालभाड़े ट्रैफिक तथा रेलवे मालभाड़े में काफी वृद्धि हुई। रिजर्व बैंक का सर्वेक्षण संकेत करता है कि तीसरी तिमाही के लिए सेवा क्षेत्र की गतिविधि संबंधी भावनाएं सकारात्मक हैं और नवंबर में ऑटो बिक्री में सुधार हुआ है। दूसरी तरफ, सेवाओं के लिए पीएमआई नवंबर में संकुचन अंचल में चला गया।

10. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में वर्ष-दर-वर्ष बदलाव से आकलित खुदरा मुद्रास्फीति ने कुछ अनुकूल आधार प्रभावों द्वारा आंशिक रूप से सुदृढ़ गति में तेज वृद्धि के कारण अक्टूबर में सात महीने का उच्च स्तर दर्ज किया। खाद्य मुद्रास्फीति पिछले दो महीनों में अस्थिर रही जो सितंबर में कम हुई और अक्टूबर में मुख्य रूप से सब्जियों और फलों के कारणों वापस बढ़ गई। दूध और अंडों की मुद्रास्फीति ने वृद्धि दर्शाई जबकि दलहन की मुद्रास्फीति अक्टूबर में लगातार ग्यारहवें महीने के लिए नकारात्मक रही। खाद्य मुद्रास्फीति

स्थायी रही। ईंधन समूह की मुद्रास्फीति जो जुलाई से बढ़ोतरी पथ पर रही है, उसमें तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी), केरोसिन, कोक और विद्युत की मुद्रास्फीति में तेज वृद्धि के चलते और तेजी आई।

11. खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति जो जुलाई से सितंबर में बढ़ गई थी, वह अक्टूबर में स्थिर रही। यह केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों पर करों के वापस लेने के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में आई नरमी में दिखाई दी। तथापि, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग अवार्ड के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उच्चतर आवास किराया भत्तों के लागू होने के बाद आवास मुद्रास्फीति सख्त हो गई।

12. रिज़र्व बैंक के परिवार सर्वेक्षण ने आगामी तीन महीनों और एक वर्ष के नवीनतम दौर में मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को बढ़ना दर्शाया है। अक्टूबर में कृषि और औद्योगिक कच्चे माल की कीमतें बढ़ गईं। रिज़र्व बैंक के औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण पर प्रतिक्रिया देने वाली फर्म इनपुट कीमतों में वृद्धि को अपनी आउटपुट कीमतों में हस्तांतरित करने की आशा करती हैं। अन्य कीमतों की बात करते हुए, संगठित क्षेत्र में मजदूरी में वृद्धि हुई है जबकि ग्रामीण मजदूरी वृद्धि, विशेषकर कृषि में, कमजोर हुई है।

13. प्रणाली में अधिशेष चलनिधि अक्टूबर और नवंबर के दौरान कम होती रही। प्रचलित मुद्रा त्यौहारों पर मांग के कारण सितंबर के अंत से तीसरी तिमाही (1 दिसंबर 2017 तक) में ₹736 बिलियन तक बढ़ गई। रिज़र्व बैंक ने अधिशेष चलनिधि को ओवरनाइट से 28 दिवसीय नियमित परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो नीलामियों के माध्यम से व्यवस्थित किया। एलएएफ के अंतर्गत चलनिधि का निवल औसत दैनिक अवशोषण सितंबर में ₹2,229 बिलियन से घटकर अक्टूबर में ₹1,400 बिलियन और नवंबर में ₹718 बिलियन हो गया। रिज़र्व बैंक ने अक्टूबर-नवंबर में ₹300 बिलियन की खुली बाजार बिक्री आयोजित की जिससे वित्तीय वर्ष में अबतक टिकाऊ चलनिधि का कुल अवशोषण ₹1.9 ट्रिलियन तक हो गया जिसमें खुली बाजार बिक्री के रूप में ₹900 बिलियन और बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत दीर्घवधि खज़ाना बिलों का 1 ट्रिलियन शामिल है। भारत औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) सितंबर में रेपो दर के 13 आधार अंक कम

की तुलना में अक्टूबर और नवंबर के दौरान क्रमशः 12 आधार अंक और 15 अंक कम पर ट्रेड की गई।

14. लगातार 14 माह तक सकारात्मक संवृद्धि दर्शाने के बाद अक्टूबर 2017 में मर्चेन्डाइज़ निर्यातों में 1.1 प्रतिशत की गिरावट रही। माह के दौरान इंजीनियरिंग माल, पेट्रोलियम उत्पादों और रसायनों में सुस्थिर बढ़ोतरी भी रत्न और आभूषणों, रेडीमेड परिधानों और ड्रग्स तथा फार्मास्युटिकल के शिपमेंट में तीव्र गिरावट से धूमिल पड़ गई। आयातों में विस्तार बना रहा यद्यपि इसकी गति मामूली थी। यद्यपि अक्टूबर में सवर्ण के आयात में अनुक्रमिक बढ़ोतरी हुई तथापि, एक साल पहले के स्तर की तुलना में संयमित रही। परिणामस्वरूप, अक्टूबर में व्यापार घाटा फिर बढ़ गया। सितंबर में संयमित रहने का बावजूद 2017-18 की पहली छमाही में निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एक साल पहले के स्तर पर ही रहा। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए पुनः पूंजीकरण योजना की घोषणा के साथ ही इक्विटी में विदेशी पोर्टफोलियो का इन-फ्लो अक्टूबर में तेजी से बढ़ा, जबकि विगत माह में बहिर्वाह दर्ज हुआ था। भारत का विदेशी मुद्रा रिज़र्व 30 नवंबर 2017 को 401.94 बिलियन यूएस डालर था।

परिदृश्य

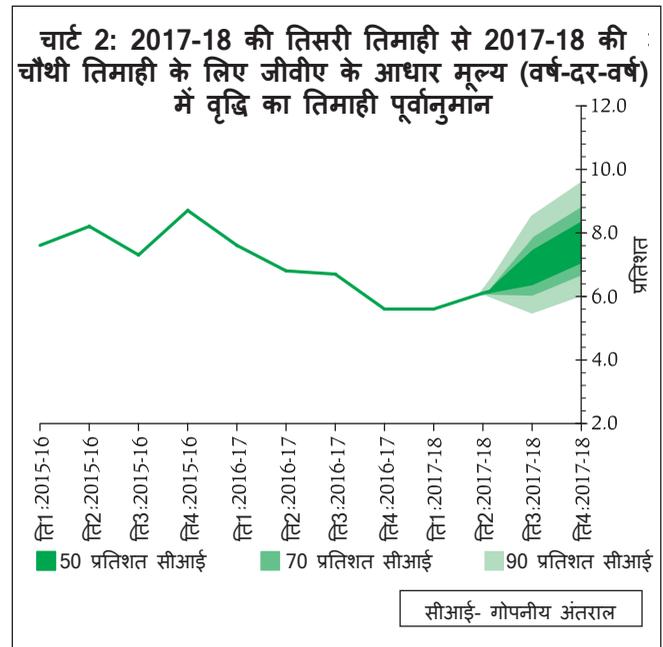
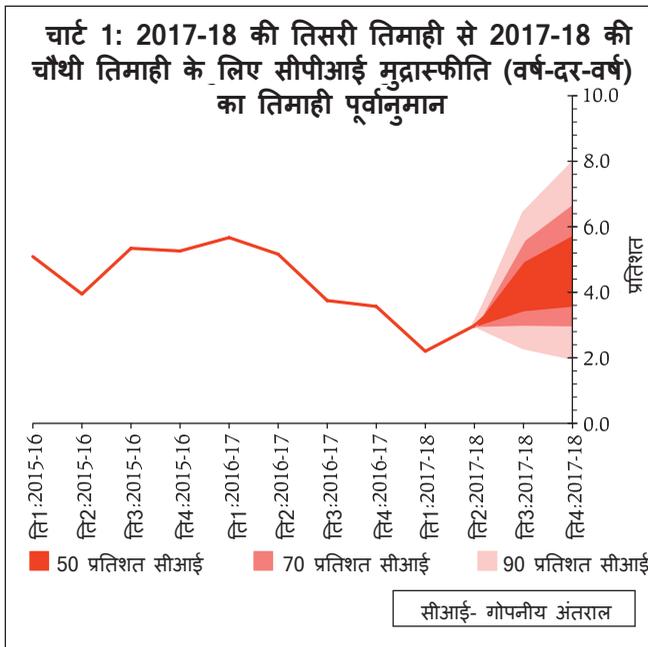
15. अक्टूबर के द्विमासिक विवरण में अनुमान थे कि इस साल की दूसरी छमाही में स्फीति बढ़कर 4.2-4.6 प्रतिशत के दायरे में रहेगी, जिसमें केन्द्र द्वारा मकान किराया भत्ते (एचआरए) में बढ़ोतरी के प्रभाव को भी शामिल किया गया था। हेडलाइन स्फीति परिणाम व्यापक तौर पर अनुमानों के अनुसार रहे। आगे चलकर स्फीति का पथ विभिन्न कारकों से प्रभावित होगा प्रथम यह कि खाद्य और ईंधन को शामिल नहीं करते हुए स्फीति में जो संयम 2017-18 की पहली तिमाही में दिखा था, वह कुल मिलाकर रिवर्स हो गया। ऐसा जोखिम है कि यह उर्ध्वगामी ट्रेजेक्टरी निकट काल में बनी रहेगी। द्वितीय यह कि केन्द्र सरकार द्वारा घोषित एचआरए का प्रभाव दिसंबर में अपने शीर्ष पर होने की संभावना है। तीसरे यह, कि कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हाल ही में हुई बढ़ोतरी बरकरार रह सकती है, खासकर ओपेक के इस निर्णय को देखते हुए कि अगले साल भी उत्पादन में कटौती की जाए। ऐसे परिदृश्य में भू-राजनैतिक गतिविधियों के कारण आपूर्ति पर कोई भी प्रतिकूल आघात हुआ तो कीमतें और

आगे जा सकती हैं। सब्जियों की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के बावजूद सर्दियों की फसल आते ही निकट में कुछ मौसमी संयमन संभावित है। दालों की कीमतों में अधोगामी रुझान जारी है। जीएसटी परिषद ने अपनी विगत बैठक में बहुत सी खुदरा वस्तुओं और सेवाओं को निम्नतर टैक्स-दायरे में कर दिया है, जो आगे चलकर कम खुदरा कीमतों में संपरिवर्तित होना चाहिए। कुल मिलाकर इस साल की तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही में स्फीति के 4.3 - 4.7 प्रतिशत के दायरे में रहने का अनुमान है, जिसमें जोखिमों को सम-संतुलित करते हुए एचआरए से पढ़ने वाला 35 आधार अंकों का प्रभाव भी शामिल है (चार्ट 1)।

16. जीवीए अनुमान की बात करें तो पता चलता है कि दूसरी तिमाही में वृद्धि, अक्टूबर संकल्प में अनुमानित वृद्धि की अपेक्षा कम थी। तेल की कीमतों में हाल में जो वृद्धि हुई उसका फर्म एवं जीवीए वृद्धि के मार्जिन में नकारात्मक प्रभाव पड़ा। खरीफ के उत्पादन एवं रबी की बुआई में कमी की वजह से कृषि की संभावना को लेकर प्रत्याशित से भी ज्यादा जोखिम का डर है। सकारात्मक पहलू को देखें तो पता चलता है कि हाल के महीनों में ऋण वृद्धि ने थोड़ा जोर पकड़ा। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूजीकरण से ऋण प्रवाह और बेहतर हो सकते हैं। स्थावर संपदा जैसे सेवा क्षेत्र के कतिपय घटकों में कमी होने के बावजूद, रिजर्व बैंक का सर्वेक्षण संकेत देता है कि चौथी

तिमाही में सेवा और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में, मांग, वित्तीय परिस्थिति एवं समग्र कारोबार स्थिति को लेकर सुधार की उम्मीद की जाती है। उपर्युक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2017-18 के लिए 6.7 प्रतिशत की वास्तविक जीवीए वृद्धि के अक्टूबर संकल्प को बरकरार रखा गया, जिसमें जोखिम को अच्छी तरह से संतुलित किया गया (चार्ट 2)।

17. एमपीसी यह उल्लेख करती है कि उभरते हुए प्रक्षेप-पथ की सावधानी पूर्वक निगरानी करनी आवश्यक है। पहला, जीवन-यापन स्थितियों की लागत और मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं का निर्धारण करने के दो प्रमुख कारकों अर्थात् खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति में नवंबर में मामूली बढ़ोतरी हुई है। रिजर्व बैंक द्वारा सर्वेक्षण किए गए हाउसहोल्ड की मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाएं पहले ही दृढ़ हो चुकी हैं और खाद्य तथा ईंधन के मूल्यों में होने वाली कोई भी वृद्धि इन प्रत्याशाओं को और मजबूत करेगी। दूसरा, बढ़ती हुई इनपुट लागतों का अल्पावधि में खुदरा मूल्यों में अंतरण होने का उच्चतर जोखिम है जैसा कि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा संकेत प्रदान किया गया है। तीसरा, चुनिंदा राज्यों द्वारा कृषि ऋण माफी के क्रियान्वयन, पेट्रोलियम उत्पादों के मामले में उत्पाद शुल्क और वैट को आंशिक रूप से वापस लेना और कई वस्तुओं और सेवाओं के लिए जीएसटी की दरों में कमी के कारण राजस्व में कमी होने से राजकोषीय चूक परिणत हो सकती है जिसका सहायक प्रभाव



मुद्रास्फीति पर पड़ सकता है। चौथा, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति के सामान्य स्थिति में लौटने के संबंध में अस्थिरता/उसकी धीमी गति के कारण वैश्विक वित्तीय अस्थिरता एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में राजकोषीय विस्तार से मुद्रास्फीतिक जोखिम हो सकता है। सब्जियों और फलों के मूल्यों में आशा के अनुरूप होने वाली मौसमी कमी, जीएसटी परिषद द्वारा हाल में की गई जीएसटी दरों में कटौतियों से वृद्धिशील दबावों में कमी आने की संभावना है। तदनुसार, एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर को बरकरार रखने का निर्णय लिया है। तथापि, उत्पादन अंतर प्रत्यावर्तनों (डॉयनेमिक्स) को ध्यान में रखते हुए एमपीसी ने तटस्थ रुख बनाए रखने और आगामी आंकड़ों पर सावधानीपूर्वक निगाह रखने का निर्णय लिया है। एमपीसी शीर्ष मुद्रास्फीति को टिकाऊ आधार पर 4 प्रतिशत के आस-पास बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है।

18. मौद्रिक नीति समिति के आकलन में, हाल की अवधि में बहुत सी महत्वपूर्ण गतिविधियां होती रही हैं जो आगे चल कर वृद्धि की दृष्टि से शुभ संकेत मानी जा सकती हैं। प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार रहीं - प्रथम, प्राथमिक पूंजी बाजार से उगाही गई पूंजी में कई वर्षों की मंद गतिविधि के बाद उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। चूंकि, उगाही गई पूंजी का अविनियोजन नई परियोजनाएं स्थापित करने में किया गया इसलिए इससे

अल्पावधि में मांग बढ़ेगी और मध्यावधि में इसके कारण अर्थव्यवस्था की वृद्धि की अंतर्निहित क्षमता में बढ़ोत्तरी होगी। द्वितीय, कारोबार करने की सहूलियत के श्रेणी क्रम में सुधार होने के कारण अर्थव्यवस्था में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बरकरार रखने में मदद मिलेगी। तृतीय, दबावपूर्ण बड़े उधारकर्ताओं को दिवाला और शोधन-अक्षमता संहिता (आईबीसी) के अंतर्गत लाया जा रहा है तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूजीकरण किया जा रहा है, जिससे वितरण दक्षता में सुधार होना चाहिए। तथापि, मौद्रिक नीति समिति ने यह नोट करती है कि बकाया ऋणों के संबंध में पिछले मौद्रिक नीतिगत परिवर्तनों को बैंकों द्वारा बेहतर ढंग से लागू करते हुए घरेलू उधारियों की लागत में कमी लाकर इन घटकों के प्रभाव को मजबूत बनाया जा सकता है।

19. डॉ. चेतन घाटे, डॉ. पामी दुआ, डॉ. माइकल देबब्रत पात्र, डॉ. विरल वी. आचार्य और डॉ. उर्जित आर. पटेल मौद्रिक नीति निर्णय के पक्ष में थे, जबकि डॉ. रविंद्र एच. ढोलकिया ने नीतिगत दर में 25 आधाभूत अंकों की कमी करने के पक्ष में मत दिया। मौद्रिक नीति समिति के कार्यवृत्त 20 दिसंबर 2017 तक प्रकाशित किए जाएंगे।

20. मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक 6 और 7 फरवरी 2018 को होना निर्धारित किया गया है।

भाषण

भारत में मौद्रिक नीति का संचरण : यह महत्वपूर्ण क्यों है और
इसने ठीक से काम क्यों नहीं किया?

विरल वी. आचार्य⁷

भारत की मौद्रिक नीति समिति के कार्यकाल का एक वर्ष
माइकल देब्रत पात्र

भारत में मौद्रिक नीति का संचरण : यह महत्वपूर्ण क्यों है और इसने ठीक से काम क्यों नहीं किया?*

विरल वी. आचार्य

मैं, जब विले पार्ले (पश्चिम) में अपने आवास से फोर्ट स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय की यात्रा करता हूँ, तब आने-जाने-दोनों में स्वर्गीय होमी जहांगीर भाभा के जन्म स्थल *केनिलवर्थ* के पास से गुजरता हूँ। भाभा साहब की विलक्षण बुद्धिमत्ता ही नहीं बल्कि भारत की सेवा की उनकी चेतना की संजीदगी के कारण भी दिन की शुरुआत और समापन के लिए यह अच्छा मार्ग है। इसलिए, आज होमी भाभा सभागृह में भाषण देने के लिए आमंत्रित किए जाने हेतु मैं प्रोफेसर दिपेन घोष, जो आईआईटी बांबे में मेरे अध्ययन काल के दौरान छात्राध्यक्ष थे, के प्रति और अपने प्रिय पुत्र अवीक गुहा की स्मृति में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआईएफआर) में इस व्याख्यान माला की शुरुआत करने के लिए डॉ. सुभेंदु गुहा के प्रति शुक्रगुजार हूँ। "अवीक" बंगाली भाषा का एक सुंदर नाम है, जिसका तात्पर्य "निडर" से है। सभी अनुसंधान ठीक इस अर्थ "निडर" की ही तरह होना चाहिए, जो अनंत चुनौतियों का सामना करते हुए, दृढ़तापूर्वक उनसे जूझते हुए अपने मार्ग पर खंडन-मंडन करते हुए खुरदरे आवरण में छुपे सत्य को छानते हुए पहचानने योग्य रूप में लाने तक कार्य करे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में भाषण करना किसी भी अनुसंधानकर्ता के लिए चुनौती पूर्ण प्रस्ताव होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भाषण के रूप में, इस फोरम में आज भारत में मौद्रिक नीति का संचरण - यह महत्वपूर्ण क्यों है और इसने ठीक से काम क्यों नहीं किया? - के विषय पर, जो हम सभी के लिए मुनासिब है और जिसे यथा समय नियंत्रित करने की जरूरत है, चर्चा के माध्यम से, अपनी प्रस्तुति से मैं इसके निर्धारित उच्चतम मानकों को प्राप्त करने में कुछ हद तक सफल रहूंगा।

मैं शुरुआत कुछ तकनीकी शब्दों से करना चाहूंगा और जिन पर यहां मैं ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, उनकी व्याख्या शुरुआती सिद्धांतों से करूंगा। 2016 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में संशोधन के साथ ही 'मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य वृद्धि के लक्ष्य के मद्देनजर मूल्य स्थिरता कायम रखना

हो गया है।' संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के तहत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) को नीतिगत रिपो दर के निर्धारण का अधिदेश है ताकि विनिर्दिष्ट मध्यावधि मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत के लक्ष्य, जो +/-2 प्रतिशत में दायराबद्ध हो, को प्राप्त किया जा सके। रिज़र्व बैंक के लिए अपने अधिदेश को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि 'मौद्रिक नीति का संचरण' के रूप में जानी जाने वाली आर्थिक प्रक्रिया निर्बाध रूप से कार्य करे। इसलिए, हम मौद्रिक नीति के संचरण का नियमित रूप से विश्लेषण करते हैं और संचरण बंद होने या इसके गंभीर रूप से अपूर्ण होना प्रतीत होने पर इसकी प्रभावोत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाते हैं।

मौद्रिक नीति का संचरण क्या है ? यह मूल रूप से वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से केंद्रीय बैंक की नीतिगत कार्रवाई का संचरण स्थिर मुद्रास्फीति और वृद्धि के खास उद्देश्य से किया जाता है। नीतिगत कार्रवाई के अंतर्गत विशिष्ट रूप से उस ब्याज दर को परिवर्तित किया जाता है जिसके अनुसार बैंक एक दिवसीय आधार पर वाणिज्यिक बैंकों से 'आरक्षित निधियां' (हमारे संदर्भ में, रुपया) उधार लेता या देता है। अन्य शब्दों में, मौद्रिक नीति के संचरण के अंतर्गत वह पूर्ण प्रक्रिया आती है जिसकी शुरुआत केंद्रीय बैंक द्वारा नीतिगत दर में परिवर्तन किए जाने से होती है, जिनका अंतिम प्रभाव मुद्रास्फीति और वृद्धि पर पड़ता है। इस नीतिगत दर का संबंध निम्नलिखित से होता है - अंतर-बैंक उधारी दरों, बैंक जमा दरों, हाउसहोल्ड एवं फर्मों को बैंक द्वारा दिए जाने वाले उधार की दरों, सरकार एवं कॉर्पोरेट बॉण्ड प्रतिफलों जैसी बाजार दरों और स्टॉक मूल्यों तथा आवास मूल्यों जैसी आस्तियों के मूल्य। अंतरण की कार्यविधि इस पर बहुत अधिक निर्भर होती है कि मौद्रिक नीति में हुए परिवर्तनों का हाउसहोल्ड एवं फर्मों के बर्ताव पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। यह परिवर्तन बहुत से माध्यमों से घटित हो सकता है। इन माध्यमों का अध्ययन करना वित्त एवं आर्थिक साहित्य के अंतर्गत एक विस्तृत विषय है। इसलिए, समय की बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का ही यहां जिक्र करूंगा। उसके बाद, मैं इस बात की व्याख्या करूंगा कि भारत में मौद्रिक नीति का संचरण कैसे और क्यों प्रभावी रहा और उससे भी महत्वपूर्ण बात कि यह अंतरण प्रभावी क्यों नहीं रहा है। मैं, संक्षेप में इसमें बेहतरी लाने के तरीकों का भी जिक्र करूंगा।

मौद्रिक नीति संचरण के माध्यम

केंद्रीय बैंक की नीतिगत दरों में परिवर्तन का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव विभिन्न माध्यमों से पड़ता है। प्राथमिक माध्यम

* डॉ. विरल वी. आचार्य, उप गवर्नर - 16 नवंबर 2017. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआईएफआर), मुंबई के होमी भाभा सभागृह में अवीक गुहा स्मृति व्याख्यान का उद्घाटन भाषण।

इस प्रकार हैं - (i) ब्याज दर माध्यम, (ii) ऋण माध्यम, (iii) विनिमय दर माध्यम, और (iv) आस्ति मूल्य माध्यम।

चलिए हम शुरुआत इस बात से करते हैं कि ब्याज दर माध्यम कैसे कार्य करते हैं। मौद्रिक नीतिगत दर में परिवर्तन का तत्काल प्रभाव अल्पावधिक मुद्रा बाजार दरों (यथा, मांग मुद्रा दर, जमा प्रमाण पत्रों, वाणिज्यिक पत्रों, खजाना बिलों), मुख्य वित्तीय बाजारों (विनिमय दर, इक्विटी मूल्यों), और मध्यावधिक तथा दीर्घावधिक लिखतों (सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों तथा कॉर्पोरेट बॉण्डों के प्रतिफल) पर भी पड़ता है। यह प्रभाव विशिष्ट रूप से तीव्र होता है और नीतिगत दरों और अल्पावधिक मुद्रा बाजार दरों, यथा मांग मुद्रा दर जो प्रत्याभूत नहीं होती या संपार्श्विक रहित अंतर-बैंक उधारी दर होती है; के बीच यह प्रभाव व्यापक रूप से प्रत्येक के लिए अलग-अलग होता है। कोई बैंक अपनी आरक्षित निधियों को किसी और बैंक को एक दिवसीय उधार के रूप में वह कम से कम उस दर पर देगा, जिस पर वह केंद्रीय बैंक के पास अपनी निधि रखकर लाभ कमा सकता है, और यदि इस तरह के उधार देने के लिए बैंकों के बीच पर्याप्त स्पर्धा हो तो यह दर केंद्रीय बैंक की नीतिगत दर के बहुत करीब होगी। नीतिगत दरों का अन्य बाजार दरों पर पड़ने वाला प्रभाव ऋण अवधि और लिखतों के अनुसार परिवर्तित होती है, जो चलनिधि परिस्थितियों और अन्य कारकों, यथा विभिन्न परिपक्वता अवधियों पर ब्याज दरें कैसे बदलती हैं; पर निर्भर होती हैं।

बदले में, केंद्रीय बैंक के लिए अपनी नीतिगत दरों में परिवर्तन करने के चुनौतीपूर्ण कार्य से बैंकों की निधि लागत पर प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। यह लागत बैंकों द्वारा जमाकर्ताओं को अदा की जाने वाली दरों और ऋण के बदले उनको मिलने वाली दर - दोनों के रूप में हो सकती है। उदाहरण के लिए, जब कोई केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में समग्र मांग को सहारा प्रदान करने के मंतव्य से नीतिगत रिपो दर में कमी करता है तब यह अपेक्षा की जाती है कि बैंकों की निधि लागत और उधारी दरों में तथा बाजार की ब्याज दरों (नीतिगत दर में वृद्धि होने पर इसका विपरीत) में कमी होगी। बैंकों की ऋण दरों के कम होने से समाज के विभिन्न तबकों में बैंक ऋण की मांग बढ़ने को बल मिलता है, उदाहरण के लिए व्यक्तियों और हाउसहोल्डों की ओर से टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं (यथा आटोमोबाइल्स) की तथा आवास ऋण की मांग बढ़ जाती है; और उद्यमियों की ओर से संयंत्र और मशीनों में निवेश बढ़ जाता है। आटोमोबाइल्स, आवास और मशीनों की बढ़ी हुई मांग से उद्योगों में श्रम सहित निविष्टियों की बढ़ी हुई मांग पैदा होती है, और इसलिए अर्थव्यवस्था में समग्र

मांग, आय तथा उत्पादन में वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया के जारी रहने से, यह श्रम की मजदूरी और निविष्टियों के मूल्यों में बढ़ोत्तरी का दबाव पड़ता है और इस प्रकार से मुद्रास्फीति बढ़ती है। इसलिए, वृद्धि का ध्यान रखते हुए स्थिर मूल्य बरकरार रखने के अधिदेश वाले केंद्रीय बैंक को अपनी नीतिगत दर को घटाने या बढ़ाने में सामंजस्य बैठाना पड़ता है।

यहां पर यह मान्यता स्पष्ट है कि बैंक के तुलन-पत्र मजबूत हैं और निधीयन की लागत कम होने तथा ऋण की मांग अधिक होने और मांग अपेक्षाकृत अधिक होने की प्रतिक्रिया स्वरूप वे (बैंक) तेजी से ऋण आपूर्ति करने के लिए सक्षम हैं - बैंकों के उधार देने या अंतरण के ऋण माध्यम। विभिन्न देशों के साक्ष्यों से पता चलता है कि बैंकों के तुलन-पत्र कमजोर होने और उनके ऋण की समस्या से सीधे निपटने में उनकी घाटा वहने करने की क्षमता कम होने से मौद्रिक नीति अंतरण में बहुत बाधा उत्पन्न होती है। साक्ष्यों से सचमुच यह संकेत मिलता है कि खराब ऋणों को चिरकाल तक लंबित रखा जा सकता है, और ऋण चूक के मामलों को जीवित रखने के लिए मजबूत फर्मों को दरों में छूट देकर ऋण प्रदान करने वाली 'जॉबी लेंडिंग' और अधिक बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा किए जाने की परिणति संसाधनों के त्रुटिपूर्ण आबंटन, उत्पादकता में हानि और कमजोर वृद्धि के रूप में होगी। इस तरीके से, जबकि बैंक के तुलन-पत्र में समस्याएं हों तब आक्रामक नीतिगत दर कटौती करते हुए वृद्धि बढ़ाने के प्रयास क्षीण हो सकते हैं और अनुचित निवेश, वृद्धि बढ़ने की झूठी आशाएं उत्पन्न करने और तुलन-पत्र की गहराई में मजबूती कारकों को मंद करने तथा बैंकिंग क्षेत्र' के संरचनागत सुधारों के रूप में विपरीत असर डाल सकते हैं। बैंक ऋण के इस माध्यम की प्रभावशीलता भारत के वर्तमान मोड़ में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसकी चर्चा में फिर कभी करूंगा।

ब्याज दरें अपेक्षाकृत कम रहने से आवास और इक्विटी जैसी आस्ति के मूल्य में मजबूती आती है क्योंकि अब उन्हें अपेक्षाकृत कम उधारी की लागत पर खरीदा जा सकता है। परिणामस्वरूप, हाउसहोल्ड/कॉर्पोरेट संपत्ति को मिलने वाले बढ़ावा और अपेक्षाकृत कम ब्याज दरों के कारण बेहतर नगदी प्रवाह भी मांग की लालसा बढ़ाते हैं। यह मौद्रिक नीति संचरण का आस्ति मूल्य माध्यम होता है। आस्तियों की अपेक्षाकृत अधिक कीमतों से संपार्श्विकों का मूल्य बढ़ सकता है या

¹ आचार्य वी.वी., टी. आईजेट, सी. यूफिंगर एवं सी.डब्ल्यू. हिश (2016), 'व्हाटएवर इट टेक्स : द रिअल इफेक्ट्स ऑफ अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी' वर्किंग पेपर, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्टेन स्कूल ऑफ बिजनेस।

भारत में मौद्रिक नीति का संचरण : यह महत्वपूर्ण क्यों है और इसने ठीक से काम क्यों नहीं किया?

भाषण

उधारकर्ताओं की निवल मालियत में वृद्धि हो सकती है। बैंक ऋण प्रदान करने या ऋण माध्यम के संयोग से प्रतिस्पर्धी दरों पर अधिक उधार लेने की क्षमता बढ़ती है, जिससे समग्र मांग की लालसा और अधिक मजबूत होती है।

अंततः, घरेलू ब्याज दरों के अपेक्षाकृत कम रहने के कारण घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन हो सकता है। इससे, जहां एक ओर वैश्विक बाजार में निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाएगा और घरेलू मांग तथा आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर आयातित सामग्री के घरेलू मुद्रा मूल्यों में सीधे वृद्धि हो सकती है, जिसके कारण आयात (उदाहरण, कच्चा तेल) महंगे हो सकते हैं। यह संचरण का विनिमय दर माध्यम होता है।

मैंने ऊपर जिन सभी माध्यमों - ब्याज दर माध्यम, बैंक द्वारा उधार देने/ऋण माध्यम, आस्ति मूल्य माध्यम, और विनिमय दर माध्यम - का उल्लेख किया है, वे एकल माध्यम नहीं हैं बल्कि; वे एक साथ प्रभावी होते हैं। ये एक दूसरे को मजबूत बना सकते हैं या उनमें टकराव भी हो सकता है। इसलिए उनके अपने प्रभाव को अलग-अलग करना कठिन कार्य है। यह स्वीकार करना भी आवश्यक है कि संचरण की कार्यपद्धति बहुत जटिल है। केंद्रीय बैंक की नीतिगत दरों में परिवर्तन का शेष अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की गति और मजबूती में एक देश से दूसरे देश में व्यापक परिवर्तन हो सकता है, जो अर्थव्यवस्था की संरचना और उसकी वित्तीय प्रणाली की अवस्था पर निर्भर होता है।

मौद्रिक नीति का पिछड़ना

भारत से संबंधित उपलब्ध अनुभव-जन्य साक्ष्यों से पता चलता है कि यहां पर मौद्रिक नीति संबंधी कार्रवाई का असर उत्पादन के मामले में 2-3 तिमाही के बाद, मुद्रास्फीति के मामले में 3-4 तिमाहियों के बाद महसूस किया जाता है, और यह प्रभाव 8-12 तिमाहियों तक बना रहता है। संचरण के माध्यमों के मध्य ब्याज दर माध्यम को सबसे अधिक प्रभावशील² पाया गया है। मौद्रिक नीति द्वारा उत्पादन और मुद्रास्फीति को लंबे (और बहुधा परिवर्तनशील) अंतराल के बाद प्रभावित करने को देखते हुए मौद्रिक नीति कार्रवाई का प्रगतिशील होना बहुत महत्वपूर्ण, अर्थात्, मौद्रिक नीति से

² मौद्रिक नीतिगत ढांचा को संशोधित एवं मजबूत बनाए जाने संबंधी विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष : उजित आर. पटेल), 2014, भारतीय रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट। मैंने अभी-अभी 2-4 तिमाहियों के जिन अंतरालों जिक्र किया वे विभिन्न अध्ययनों की अवधि के दौरान के औसत अंतराल रहे हैं, और किसी दिए गए समय में वास्तविक अंतराल इन औसत अंतरालों से काफी भिन्न हो सकते हैं, जिनका आधार घरेलू और वैश्विक कारोबारी चक्र की स्थिति, घरेलू चलनिधि-हालात और वित्तीय परिस्थितियां, राजकोषीय रुख, घरेलू बैंकिंग क्षेत्र और गैर-बैंकिंग क्षेत्र की अवस्था जैसे बहुत से कारक हो सकते हैं।

संभावित उत्पादन और मुद्रास्फीति की गतिविधियों पर प्रतिक्रिया देने की अपेक्षा की जाती है। निःसंदेह, उत्पादन और मुद्रास्फीति का उद्भव होना अनिश्चित होता है, और इसलिए संचरण का विश्लेषण करना और भी चुनौतीपूर्ण कार्य बन जाता है। इसके कारण केंद्रीय बैंक की निर्णय लेने संबंधी जटिलता (और इसके आलोचकों के लिए उत्तेजनापूर्ण अवसर भी पैदा हो जाते हैं!) और अधिक बढ़ जाती है। मुख्य बात यह है कि संचरण कार्यप्रणाली के पुर्ज बिखरे हुए हैं। ऐसी स्थिति में मौद्रिक नीति कम प्रभावी होगी।

भारत में नीतिगत दर से बैंक द्वारा उधार देने की दरों में संचरण : कार्य-निष्पादन

भारतीय वित्तीय प्रणाली बैंक-प्रभुत्व वाली प्रणाली बनी हुई है। यद्यपि, समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के वित्तपोषण में गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) एवं बाजारों (कॉर्पोरेट बांड, वाणिज्यिक पत्र, इक्विटी इत्यादि) का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। इसलिए, भारत में मौद्रिक नीतिगत संचरण की समग्र क्षमता, नीतिगत रिपो दर में परिवर्तन किए जाने से संकेत ग्रहण करते हुए - और उससे प्रेरित होकर - अर्थव्यवस्था की ऋण मांग को पर्याप्त रूप से पूरा करने के लिए बैंकों द्वारा अपनी जमा एवं उधार दरों को समायोजित करने के दायरे और गति पर निर्भर करती है। समग्ररूप से, आंकड़ों से पता चलता है कि नीतिगत दरों में परिवर्तनों के अनुरूप बैंक उधारी दरों में अंतर आने की प्रक्रिया बहुत मंद एवं थमी हुई रही है। मौद्रिक नीति के पर्याप्त संचरण की यह कमी रिज़र्व बैंक की प्रमुख नीतिगत चिंता का विषय रहा है, क्योंकि इसके कारण आर्थिक गतिविधियों तथा मुद्रास्फीति पर नीतिगत परिवर्तनों का प्रभाव मंथर पड़ जाता है।

1990 के दशक में ब्याज दरों के नियंत्रण मुक्त किए जाने के समय से, रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा ब्याज दरों को मौद्रिक नीतिगत दरों के अनुरूप बनाए जाने की गति और उसके दायरे में सुधार लाने के लिए बहुत से प्रयास किए हैं, साथ ही रिज़र्व बैंक ने उधारकर्ताओं के लिए ब्याज दर निर्धारण की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और उसे लचीला बनाने की भी कोशिश की है। हम, प्राइम लेंडिंग रेट (पीएलआर) प्रणाली (1994) को छोड़कर बैंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (बीपीएलआर) प्रणाली (2003), बेस रेट प्रणाली (2010), और वर्तमान निधि की सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) प्रणाली (2016) को अपना चुके हैं। मैं, बेस रेट एवं (वर्तमान) एमसीएलआर) प्रणाली के कार्यनिष्पादन (अतीत) के मूल्यांकन

पर बात करने के पहले ब्याज दर निर्धारण के दौर (समय) की संक्षेप में व्याख्या करना चाहूंगा।

भारत में भी अन्य बहुत से देशों की तरह ऋणों का बड़ा हिस्सा परिवर्तनशील दरों वाला होता है अर्थात्, उधारकर्ता द्वारा देय ब्याज दर पुनर्निर्धारित आवधि के आधार पर परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील दर किसी 'बैंचमार्क दर' (जो आदर्श रूप में समय के दौरान बदलने वाली समष्टिगत आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों और, विशेषरूप से केंद्रीय बैंक की नीतिगत दर के साथ परिवर्तित होती हैं) से संबद्ध होती है। अन्य कारकों के मध्य, बैंक बैंचमार्क के अलावा लाभांश और ऋण जोखिम का प्रभार भी लगाते हैं। बैंचमार्क आंतरिक या बाहरी हो सकते हैं; आंतरिक बैंचमार्क उन घटकों पर आधारित होंगे जो आंशिक रूप से बैंक के नियंत्रण में होते हैं, यथा निधियों की लागत, जबकि बाहरी बैंचमार्क बैंक के नियंत्रण के परे होते हैं (उदाहरण के लिए, यह जमा प्रमाण-पत्र दर या खजाना बिल दर या अंतर-बैंक प्रस्ताव की तरह बाजार से निर्धारित होने वाली हो सकती है या फिर यह केंद्रीय बैंक की नीतिगत दर हो सकती है)। बाहरी बैंचमार्क की विशेषता होती है कि यह पारदर्शी होता है, सभी बैंकों के बीच एक समान होता है, और उधारकर्ता ऋण के विभिन्न प्रस्तावों की तुलना महज़ बैंचमार्क के ऊपर स्प्रेड की तुलना करते हुए कर सकते हैं (ऋण की परिपक्वता जैसी अन्य सभी शर्तें समान रहें तो)। बाजार दरें सामान्यतः केंद्रीय बैंक की नीतिगत दर के अनुसार परिवर्तित होती हैं, इसलिए मौद्रिक नीतिगत संकेतों के संचार हेतु बाहरी बैंचमार्क को विश्व भर में आंतरिक बैंचमार्क की तुलना में अधिक उपयुक्त माना जाता है और उन्हें अपनाया जा रहा है। भारत में, रिज़र्व बैंक ने बैंकों को आंतरिक या बाहरी-दोनों बैंचमार्कों के प्रयोग की अनुमति दी हुई है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि बैंक बाहरी बैंचमार्क की तुलना में आंतरिक बैंचमार्क को वरीयता दिए हुए हैं। इसके दो मुख्य कारण हैं - पहला, आंतरिक बैंचमार्क उनकी निधियों की लागत को दर्शाते हैं, और दूसरा कारण यह कि हाल के समय तक यह माना जाता रहा है कि बाहरी बैंचमार्क बहुत सुदृढ़ और व्यवसायिक नहीं हैं।

1994 में, जब रिज़र्व बैंक ने ₹2 लाख से अधिक के ऋण की उधार देने की दर को नियंत्रण मुक्त किया था, बैंकों द्वारा प्राइम लेंडिंग दर (पीएलआर) अपेक्षित होता था - ऋण के सर्वाधिक सुपात्र उधारकर्ताओं के संबंध में लगाई जाने वाली ब्याज दर - जिसके अंतर्गत निधियों की लागत एवं लेनदेन की लागत जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाना होता था। इस प्रकार से, यह अपेक्षा की जाती थी कि पीएलआर से ₹2 लाख

से अधिक की उधारियों के संबंध में आधार दर के रूप में कार्य करे। हालांकि, इसके कार्य से संबंधित अनुभव संतोषजनक नहीं था, जिसके मुख्य दो कारण निम्नलिखित थे - (i) लगाई जाने वाली पीएलआर और उसके अतिरिक्त पीएलआर लगाए जाने वाले स्प्रेड में सभी बैंकों के बीच बिना कोई स्पष्ट कारण के, जो संभवतः अधिक महत्वपूर्ण कारण था, बहुत व्यापक अंतर होता था, और, (ii) बैंकों के पीएलआर, अर्थव्यवस्था में विद्यमान ब्याज दरों की समग्र दिशा की तुलना में कठोर और अनम्य थे।

इन चिंताओं के मद्देनजर, अप्रैल 2003 में रिज़र्व बैंक ने बैंकों से कहा कि निधियों की लागत, परिचालनगत लागत, विनियामकीय आवश्यकताओं को कवर करने के लिए न्यूनतम मार्जिन (प्रावधान एवं पूंजीगत प्रभार) एवं लाभ मार्जिन को ध्यान में रखते हुए बैंचमार्क पीएलआर (बीपीएलआर) की घोषणा करें। बीपीएलआर प्रणाली भी पारदर्शिता को बढ़ाने और ऋण उत्पादों के मूल्यन के संबंध में, संदर्भ दर के रूप में कार्य करने के अपेक्षित लक्ष्य को भी पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि उधार दिए जाने के कार्य का बड़ा हिस्सा घोषित बीपीएलआर से कम दर पर किया जा रहा है। बीपीएलआर से कम दर पर उधार दिए जाने का हिस्सा सितंबर 2008 में 77 प्रतिशत तक के उच्च स्तर पर था, जिसके कारण बैंकों की उधार दिए जाने की दरों पर रिज़र्व बैंक की नीतिगत दरों में किए जाने वाले परिवर्तनों के संचरण का मल्यांकन करना मुश्किल हो गया था। निवास के लिए आवास ऋणों और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं हेतु लिए जाने वाले ऋण बीपीएलआर के क्षेत्राधिकार से बाहर थे। इस प्रकार से, उधार कर्ताओं की सभी श्रेणियों में तिर्यक-छूट के संदर्भ में बीपीएलआर से कम दर में उधार दिया जाना एक बड़ी अड़चन बन गई।

इसके बाद, बीपीएलआर प्रणाली की कमजोरियों के कारण जुलाई 2010 में बेस रेट प्रणाली प्रारंभ की गई। बेस रेट, *अन्य बातों के साथ*, उधार ली गई निधियों की लागत पर भी आधारित था; बेस रेट निर्धारित करने का सांकेतिक सूत्र भी दिया गया था। बेस रेट सभी ऋणों (कुछ विशिष्ट श्रेणियों छोड़कर) के लिए न्यूनतम दर होनी थी, जिसके अंतर्गत उधारकर्ता से ली जाने वाली वास्तविक ऋण दर बेस दर में उधारकर्ता विशेष पर लगाए जाने वाले प्रभार या स्प्रेड के जोड़ से प्राप्त होने वाली दर होगी। व्यवहार में, निधियों की लागत निर्धारण के लिए बैंकों को प्रदान की गई छूट - औसत, सीमांत या मिले-जुले रूप में - के कारण बैंकों द्वारा ऋण दरों के निर्धारण में जटिलता उत्पन्न हुई और इसके कारण नीतिगत दरों के संचरण की गति और प्रभाव के सटीक आकलन में बाधा

उत्पन्न हुई। इसके अलावा, बैंकों ने नए उधारकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए स्प्रेड का निर्धारण अक्सर बेस दर से अधिक के स्तर पर किया, जबकि वर्तमान उधारकर्ताओं के संबंध में इसे बेस दर के स्तर पर रखा और संचरण को कमजोर बनाया।

बेस दर प्रणाली के अंतर्गत संचरण में कमजोरी एवं हठधर्मिता के कारण वर्तमान प्रणाली अर्थात एमसीएलआर प्रणाली 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी हुई। बैंकों द्वारा निधियों की सीमांत लागत [यह बेस दर प्रणाली से भिन्न है, जिसमें औसत दर और सीमांत लागत में से किसी को भी चुनने (या मिलीजुली लागत) का विवेक बैंकों के पास होता था] को ध्यान में रखते हुए बैंचमार्क उधार देने की दर निर्धारण की अपेक्षा की गई, जिससे उधार दर के एमसीएलआर प्रणाली के तहत इसकी पूर्ववर्ती प्रणाली (बेस दर प्रणाली) की तुलना में अधिक संवेदनशील होने की संभावना थी। वास्तविक उधार दर एमसीएलआर में स्प्रेड (कारोबारी रणनीति और ऋण जोखिम प्रीमियम) के योग पर आधारित है। पहले हुए ऋण करार जिनकी परिपक्वता शेष हो अथवा बैंक और उधारकर्ता के बीच आपसी समझौते की शर्तों के तहत एमसीएलआर प्रणाली में परिवर्तन के लिए बेस दर प्रणाली को सहगामी रूप से क्रियाशील रहने की अनुमति दी गई।

हालांकि, एमसीएलआर प्रणाली के संभावित लाभ - बेहतर पारदर्शिता, अधिक लचीलापन एवं अपेक्षाकृत अधिक तीव्र

संचरण - हाथ नहीं आ रहे हैं। यह बात कि रिज़र्व बैंक के ताजा अध्ययन 'निधि आधारित उधार दर प्रणाली की सीमांत लागत के कार्यप्रणाली की समीक्षा के आंतरिक अध्ययन समूह की रिपोर्ट' (अध्यक्ष : डॉ. जनक राज) के विश्लेषण में लिखित रूप में कही गई है। इस विश्लेषण में नीतिगत संचरण के संबंध में निम्नलिखित संकेत हैं :

- बेस दर और एमसीएलआर प्रणालियों -दोनों के अंतर्गत संचरण धीमा और अपूर्ण रहा है। हालांकि विमुद्रीकरण के बाद प्रणाली में बड़ी मात्रा में अधिशेष चलनिधि के दबाव में नवंबर 2016 के स्थिति में सुधार हुआ है (सारणी 1)।
- नए ऋणों के संबंध में संचरण उल्लेखनीय था, किंतु बकाया ऋणों (बेस दर एवं एमसीएलआर) के मामले में यह ठंडा रहा।
- सभी उधार श्रेणियों में संचरण असमान रहा।
- मौद्रिक नीति चक्रों के दौरान संचरण असममित रहा - नीति को कठोर बनाए जाने के चरण में अधिक संचरण हुआ और नीति को सहज बनाए जाने के दौर में इसमें कमी आई - ब्याज दर प्रणाली³ चाहे जो भी रही हो।

सारणी 1 : नीतिगत रिपो दर का बैंकों की जमा एवं उधारी दरों में संचरण

(प्रतिशतता बिंदुओं में परिवर्तन)

अवधि	रिपो दर	मीयादी जमा दरें		उधारी दरें			
		माध्यिका मीयादी जमा दर	डब्ल्यूएडीटीडीआर	माध्यिका बेस दर	माध्यिका एमसीएलआर (1-वर्षीय)	डब्ल्यूएलआर - बकाया रुपया ऋण	डब्ल्यूएलआर - नवीन रुपया ऋण
दिसंबर 2014 के अंत की तुलना में अक्टूबर 2017	-2.00	-1.66	-1.99	-0.75	*	-1.39	-1.92
1 अप्रैल 2014 की तुलना में अक्टूबर 2017	-0.75	-0.94	-1.08	-0.15	-1.15	-0.75	-0.94
मेमो :							
विमुद्रीकरण के पूर्व							
जनवरी 2015 से अक्टूबर 2017 तक	-1.75	-0.99	-1.26	-0.61	*	-0.75	-0.97
1 अप्रैल 2016 से अक्टूबर 2016 तक	-0.50	-0.27	-0.35	-0.01	-0.15	-0.11	0.01
विमुद्रीकरण के बाद							
नवंबर 2016 से अक्टूबर 2017 तक	-0.25	-0.67	-0.73	-0.14	-1.00	-0.64	-0.95

डब्ल्यूएडीटीडीआर : घरेलू मीयादी जमा दर का भारत औसत डब्ल्यूएलआर : भारत औसत उधारी दर
 एमसीएलआर : निधि आधारित उधारी दर की सीमांत लागत * एमसीएलआर प्रणाली को अप्रैल 2016 में स्थापित किया गया
 डब्ल्यूएलआर एवं डब्ल्यूएडीटीडीआर से संबंधित नवीनतम आंकड़ों का संबंध सितंबर 2017 से संबंधित है।
 स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

³ उदाहरण के लिए, कड़ाई किए जाने के चरण (जुलाई 2010 से मार्च 2012) के दौरान रिपो दर से बकाया ऋणों में अंतरण लगभग 60 प्रतिशत था, जबकि उसके बाद के सहूलियत के चरण (अप्रैल 2012 से जून 2013) के दौरान यह 40 प्रतिशत से कम था।

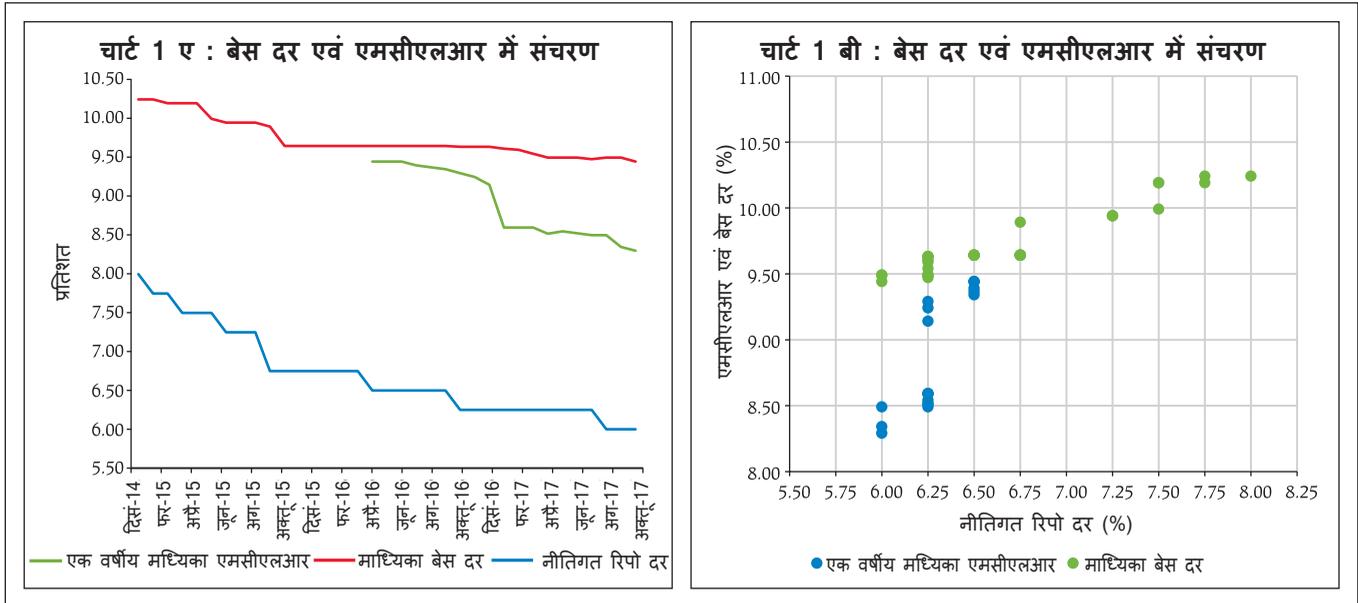
नीतिगत दर का बैंक उधार दरों में अंतरण : कुछ मुद्दे

नीतिगत दर में होने वाले परिवर्तनों का उधारी दरों में होने वाले अंतरण के धीमे और अपूर्ण होने की व्याख्या कैसे की जाए ? दो व्यापक कारकों ने उधारी दरों में अंतरण को कमजोर बनाया है।

पहला, बैंकों को विरासत में मिला काफी बड़ा ऋण पोर्टफोलियो (बकाया बैंक ऋणों का लगभग 30 प्रतिशत) अभी भी बेस दर से जुड़ा हुआ है। बेस दर प्रणाली के तहत उधारी दरें एमसीएलआर से संबद्ध ऋण दरों की तुलना में अधिक अपरिवर्तनशील हैं। मौद्रिक नीति को सहज बनाए जाने के वर्तमान चक्र के दौरान, रिपो दर में 200 बीपीएस की संचयी कटौती की तुलना में बेस दर में लगभग 80 बीपीएस की गिरावट आई है। अप्रैल 2016 में एमसीएलआर की शुरुआत किए जाने के समय से, रिपो दर में 50 पीपीएस की संचयी कटौती किए जाने की तुलना में बेस दर में सिर्फ 20 बीपीएस की गिरावट आई है (चार्ट 1ए एवं 1बी)। अध्ययन समूह के विश्लेषण से पता चलता है कि बैंक बेस दर और एमसीएलआर

की गणना से संबंधित विनिर्दिष्ट प्रणालियों से तदर्थ ढंग से भटक गए हैं, जिसका कारण या तो बेस दर और एमसीएलआर को बढ़ाना या फिर बेस दर और एमसीएलआर में निधियों⁴ की लागत के अनुरूप गिरावट को रोकना था।

दूसरा, बैंकों द्वारा एमसीएलआर में आए परिवर्तनों को समाप्त करने के लिए एमसीएलआर के ऊपर लगाए जाने वाले स्प्रेड प्रभार को समायोजित किया गया, जिसके कारण उधारी दरों में समग्र रूप से कमी आई। विशेष प्रवृत्तियों के कारण एमसीएलआर के ऊपर का स्प्रेड अलग-अलग बैंक में अलग-अलग हो सकता है। हालांकि, अध्ययन समूह के प्रेक्षकों के अनुसार, बैंक एमसीएलआर के ऊपर स्प्रेड का निर्धारण यादृच्छिक ढंग से बहुत प्रकार से करते हैं और बैंक-स्तरीय कारोबारी रणनीति और उधारकर्ता-स्तरीय ऋण जोखिम⁵ के आधार पर बैंकों के बीच स्प्रेड की विविधता की व्याख्या करना बहुत दुरूह कार्य मालूम पड़ता है। अध्ययन समूह का यह भी प्रेक्षण रहा है कि बैंकों द्वारा उधारी दर निर्धारण में जहां एमसीएलआर के ऊपर के स्प्रेड की बहुत मामूली भूमिका रहने



⁴ तदर्थ समायोजनों में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित शामिल हैं - (i) निधियों की लागत की अनुचित गणना, (ii) जमाराशियों की लागत में काफी कमी होने के बावजूद बेस दर में कोई परिवर्तन नहीं होना, (iii) निवल मालियन पर प्रतिलाभ में तेजी से वृद्धि होना जो उधारी दरों पर जमाराशियों की लागत में कमी के प्रभाव को समाप्त करने के अतीत की उपलब्धियों या भविष्य की संभावनाओं के अतरूप नहीं थीं, (iv) अपेक्षित स्तर के अनुरूप दर समायोजन के लिए बेस दर सूत्र में नए अवयवों का समावेश किया जाना। बेस दर ऋण पोर्टफोलियो के धीमे अंतरण पर दीर्घ (वार्षिक) समायोजन अवधि का और विपरीत असर पड़ा।

⁵ उदाहरण के लिए, अध्ययन दल ने पाया कि - (i) एमसीएलआर में बड़ी कमी किए जाने के असर को, कुछ बैंकों द्वारा कारोबारी रणनीति प्रीमियम में प्रकट रूप में उसी समय स्प्रेड में वृद्धि करके, आंशिक रूप से समाप्त किया गया ताकि उधारी दरों के अंतरण में कमी की जा सके, (ii) विभिन्न क्षेत्रों के लिए बारोबारी रणनीति प्रीमियम के निर्धारण से संबंधित तर्क को कहीं दस्तावेजी रूप नहीं दिया गया, (iii) बहुत से बैंकों के पास ग्राहकों पर लगाए जाने वाले स्प्रेड के अवयवों के निर्धारण के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति का अभाव था, (iv) कुछ बैंकों के पास स्प्रेड की गणना संबंधी कोई कार्यप्रणाली थी ही नहीं, जिसे एमसीएलआर से वास्तविक वर्तमान उधारी दर को घटाए जाने से शेष अंक के रूप में ही माना जाता रहा, और (v) ऋण जोखिम कारक की गणना संबंधित उधारकर्ता की क्रेडिट रेटिंग आधारित नहीं थी, बल्कि यह क्रेडिट पोर्टफोलियो/संबंधित क्षेत्र के ऐतिहासिक रूप से प्रेक्षित प्रायिकता चूक (पीडी) एवं चूक की स्थिति में हानि (एलजीडी) पर आधारित था।

सारणी 2 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मीयादी जमाओं की परिपक्वता की रूपरेखा

(कुल मीयादी जमाओं % में हिस्सा)

अंत-मार्च	90 दिनों तक	91-दिनों से 6 महीने	6-महीने से 1 वर्ष	1 वर्ष से 2 वर्ष	2 वर्ष से 3 वर्ष	3 वर्ष से 5 वर्ष	5 वर्ष एवं अधिक
2005	13.9	10.5	15.0	23.4	10.7	18.1	8.4
2010	6.9	8.4	13.7	37.9	12.3	12.4	8.3
2015	7.5	4.1	12.6	40.4	10.1	11.4	13.9
2016	7.2	4.0	9.2	43.3	10.6	11.8	14.0

स्रोत: भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित सांख्यिकी पुस्तिका, भा.रि.बैं.।

की संभावना थी, वहीं यह समग्ररूप से उधारी दरों के निर्धारण का मुख्य तत्व बन गया है।

कौन सा कारक नीतिगत दरों का बैंक उधारी दर में अंतरित होने की मंथर गति की व्याख्या करता है, या तो बैंकों द्वारा बेंचमार्क दर को परिवर्तित नहीं किया जाना या फिर स्प्रेड का समायोजन करना ?

बहुत से कारकों से उत्पन्न होने वाली बैंकों के देयता पक्ष की ओर से दर अनम्यता एक निहित स्वीकार्य कारण है। भारत में, बैंकों की कुल देयताओं का 90 प्रतिशत हिस्सा जमाराशियों के रूप में है। बैंक जमाराशियां प्रमुख रूप से नियत ब्याज दरों के आधार पर हैं, इस कारण से अंतरण प्रक्रिया अनम्य हो जाती है। इसके अलावा, बैंकों की जमाराशियों के 36 प्रतिशत से अधिक हिस्से की परिपक्वता तीन वर्ष या अधिक के बाद है (सारणी-2), जिसके कारण उन की दरें बार-बार पुनर्निर्धारित की जाती हैं और इनमें नीतिगत दर परिवर्तनों से काफी कम परिवर्तन होता है। नई जमाराशियों की ब्याज दरों में कमी किए जाने से बैंकों की निधियों की सीमांत लागत में तुरंत कमी आ सकती है, किंतु जमाराशियों की औसत लागत में कमी अपेक्षाकृत धीमी गति से आती है, जिसके कारण संचरण कमजोर होता है। बेस दर प्रणाली में ऐसा विशेषरूप से होता है।

जिसे अक्सर मान्यता नहीं मिल वह बात यह है कि हमारे बैंकों में कम लागत वाले चालू और बचत खाता (सीएसए) निधियों की विशाल उपलब्धता है। सीएसए के अंतर्गत आने वाली निधियां बैंकों की समग्र जमाराशियों के लगभग 40 प्रतिशत हिस्से को निर्मित करती हैं, जिसमें बचत जमाराशियों का हिस्सा लगभग 31 प्रतिशत है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्टूबर 2011 से बैंकों को बचत जमाराशियों की ब्याज दर निर्धारित करने की स्वतंत्रता है, किंतु हाल के समय तक अधिकांश बैंकों ने बचत जमाराशियों की ब्याज दर को अपरिवर्तित रखने का विकल्प चुना, जो मौद्रिक नीति के

संकेतों को पूर्णतः नजरअंदाज करने जैसा रहा है। उदाहरण के लिए, प्रमुख बैंकों ने अक्टूबर 2011 से जुलाई 2017 के बीच उनकी बचत जमाराशियों की ब्याज दर को अपरिवर्तित रखते हुए 4 प्रतिशत रखा, जबकि इस अवधि के दौरान रिजर्व बैंक की नीतिगत दर में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अक्टूबर 2011 में नीतिगत दर 8.5 प्रतिशत थी जो अगस्त 2013 में घटकर 7.25 प्रतिशत रह गई। अगस्त 2017 में घटकर 6.0 प्रतिशत रह जाने के पूर्व यह जनवरी 2014 में पुनः बढ़कर 8.0 प्रतिशत हो गई थी।

इसके अलावा, ऐसा मालूम पड़ता है कि पिछले 2-3 वर्षों के दौरान आस्ति गुणवत्ता में गिरावट आने से बैंकिंग क्षेत्र के हालात खराब होने और ऋण पोर्टफोलियो की संभावित ऋण हानियां भी आस्तियों के मूल्यन में बहुत अधिक परिवर्तनशीलता का कारण हो सकती हैं। अपने निवल ब्याज मार्जिन⁶ (एनआईएम) को संरक्षित करने का लक्ष्य वाले अल्प-पूंजीकृत बैंकों के साथ - कमजोर बैंकों के एनआईएम दबावपूर्ण विशाल आस्तियों के चलते सचमुच ही व्यापक रूप से अपरिवर्तित बने रहे हैं, ताकि वे अल्पावधि में लाभप्रदता को बनाए रखें, चाहे दीर्घावधि लाभों पर आंच आए। साथ ही, जमाराशियों और उधारी देने वाले शेरों, उधारी दरों के अंतरण में भी गंभीर प्रभाव पड़ा है। परिणामस्वरूप, कॉर्पोरेट ऋण हानियों को पूरा करने के लिए खुदरा जैसे अच्छे क्षेत्रों की उधारी दरों में वृद्धि की गई है।

अंततः, बैंक को वित्तीय बचतों के म्यूचुअल फंडों और लघु बचत योजनाओं जैसे वैकल्पिक लिखतों से जिस प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, उसने भी बैंकों को मीयादी जमाराशियों पर नीतिगत दर संकेतों के अनुसार परिवर्तन लाने

⁶ निवल ब्याज मार्जिन को बैंक की ब्याज से होने वाली आय (ऋण एवं आस्तियों से) में से ब्याज पर होने वाले व्यय (जमाओं तथा अन्य उधारियों पर) को घटाकर प्राप्त होने वाली संख्या के रूप में परिभाषित किया गया।

के प्रति दुविधा में डाला हुआ है। बैंक जमाराशियों में निश्चित प्रतिफल (म्यूचुअल फंड योजनाओं की तुलना में), चलनिधि (लघु बचत योजनाओं की तुलना में) के रूप में कुछ विशेष लाभ होते हैं, किंतु बैंक जमाराशियां कर-समायोजित प्रतिफलों की दृष्टि से इन योजनाओं की तुलना में हानि की स्थिति में होती हैं।

इन सभी कारकों ने बैंकों के तुलन-पत्र के देयता पक्ष को नीतिगत दर परिवर्तनों के संबंध में कठोरता प्रदान कर दी है, इसकी प्रतिक्रिया में बैंक के तुलन-पत्र के आस्ति पक्ष संबंधी व्यवहार को भी कठोर बना दिया है।

नीतिगत दर संचरण को बेहतर बनाना : आगे की राह

भारतीय रिज़र्व बैंक के अध्ययन समूह ने अपने समग्र विश्लेषण के आधार पर मौद्रिक नीतिगत संकेतों को वास्तविक उधारी दर में संचरण की पारदर्शिता तथा संचरण को मजबूत बनाने के लिए बहुत से सुझाव दिया है। उनकी अनुशंसाओं का संबंध वर्तमान उधारी दर प्रणाली के साथ ही साथ ब्याज दर निर्धारण प्रक्रिया में मूलभूत सुधार पर आधारित संचरण में सुधार लाने से संबंधित हैं। मैं, अध्ययन समूह की चार प्रमुख अनुशंसाओं की संक्षेप में चर्चा करना चाहूंगा।

आंतरिक बेंचमार्क आधारित उधारी दर प्रणालियों - पीएलआर, बीपीएलआर, बेस दर एवं एमसीएलआर - के अंतर्गत अब तक अपेक्षा से कम अंतरण और पारदर्शिता के मद्देनजर, अध्ययन समूह ने यह अनुशंसा की है कि बाहरी बेंचमार्क आधारित दर प्रणाली को अपनाए जाने की जरूरत है। आंतरिक बेंचमार्क-आधारित मूल्यन के दौर में बैंक ऋण मूल्यन की वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप नहीं हैं। एमसीएलआर प्रणाली के तहत निरंकुशता को देखते हुए, अध्ययन समूह ने यह अनुशंसा की है कि बाहरी बेंचमार्क में परिवर्तन के मामले का समयबद्ध ढंग से अनुसरण करने की जरूरत है। यह स्वीकार करते हुए कि भारत में कोई भी बाहरी लिखत किसी आदर्श बेंचमार्क की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता, और 13 संभावित उम्मीदवारों के नफा-नुकसान का विश्लेषण करने के बाद अध्ययन समूह ने यह अनुशंसा की है कि बाहरी बेंचमार्क की भूमिका के निर्वाह हेतु ट्रेजरी बिल दर, जमा प्रमाण-पत्र (सीडी) दर, और रिज़र्व बैंक की नीतिगत रिपो दर अन्य दरों की तुलना में अधिक मुनासिब हैं। अध्ययन समूह ने यह अनुशंसा की है कि 1 अप्रैल 2018 के बाद प्रदान किए गए सभी परिवर्तनशील दर वाले

ऋणों को हितधारकों से फीडबैक प्राप्त होने और उनका मूल्यांकन करने के बाद रिज़र्व बैंक द्वारा चयनित तीन में से एक बाहरी बेंचमार्क से जोड़ा जा सकता है।

दूसरा, अध्ययन समूह ने यह अनुशंसा की है कि बाहरी बेंचमार्क के ऊपर स्प्रेड के संबंध में निर्णय बैंकों के वाणिज्यिक विवेक पर छोड़ा जा सकता है, जिसके अंतर्गत ऋण चूक (क्रेडिट इवेंट) होने तक (मानकीकृत या प्रत्याशित स्वीकृति से "ऋण चूक") की तय परिभाषा के अनुसार) ऋण मीयादी ऋण की पूर्ण अवधि के दौरान स्प्रेड स्थिर रहना चाहिए।

तीसरा, बैंकों द्वारा परिवर्तनशील दर पर ऋणों, खुदरा के साथ ही कॉर्पोरेट भी, पर ब्याज दर पुनर्निधारित करने की आवश्यकता को वर्ष में एक बार से घटाकर तिमाही में एक कर दिया जाए, ताकि मौद्रिक नीतिगत संकेतों का वास्तविक उधारी दरों पर संचरण की प्रक्रिया को तेज किया जा सके।

चौथा, देयता पक्ष की कठोरता को कम करने के लिए बैंकों को सीधे तौर पर चुनिंदा बाहरी बेंचमार्क से संबंधित परिवर्तनशील दरों पर जमाराशियां, विशेषरूप से बड़ी जमाराशियां, स्वीकार करने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

नीतिगत दर में परिवर्तन होने पर इनका बैंकों की उधारी दर में वर्तमान और नए उधारकर्ताओं के लिए पारदर्शी ढंग से आपसी छूट और भेदभाव के बिना तीव्रता पूर्वक तथा पर्याप्त संचरण सुनिश्चित करना इन अनुशंसाओं की एक समान खास बात है। बात, बैंक के देयतापक्ष को अधिक लोचशील बनाए जाने की भी है, ताकि रिज़र्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीतिगत अंतरण को बेहतर बनाए जाने और बैंकों द्वारा निवल ब्याज दर के स्तर को मजबूत बनाए रखने के लक्ष्य में एकरूपता बनी रहे।

अध्ययन समूह की रिपोर्ट, जिसे 4 अक्टूबर 2017 को सार्वजनिक किया गया, में लोगों की काफी रुचि देखी गई है और रिज़र्व बैंक को सभी हितधारकों से व्यापक रूप से फीडबैक मिल रहे हैं। फीडबैक देने वालों में न सिर्फ बैंक बल्कि आम जनता और मीडिया भी शामिल है। अध्ययन समूह की अनुशंसाओं के बारे में हमें बहुत से उपयोगी सुझाव और टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। इनकी सावधानी पूर्वक जांच की जा रही है। हमें सुविचारित निर्णय लेने में इनसे मदद मिलेगी, जिसमें संचरण की लागत और अपेक्षित बेंचमार्क निर्धारित

भारत में मौद्रिक नीति का संचरण : यह महत्वपूर्ण क्यों है और इसने ठीक से काम क्यों नहीं किया?

करने की प्रणाली के लिए नपीतुली राह तैयार करने को ध्यान में रखा जाएगा।

मौद्रिक नीतिगत संचरण को बेहतर बनाना : बैंक के तुलन-पत्रों में तेजी

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, रिज़र्व बैंक ने भी अक्टूबर 2016 से अपनी नीतिगत रिपो दर में 50 बीपीएस की और दिसंबर 2014 से संचयी तौर पर 200 बीपीएस की कमी की है, किंतु बैंकिंग क्षेत्र की ऋण वृद्धि काफी स्थिर बनी रही है। ऋण वृद्धि में देखी गई गिरावट का एक कारण बैंक ऋण की मांग में कमी होना हो सकता है, किंतु मंदी का प्राथमिक कारण बड़ी अनर्जक आस्तियों के मद्देनजर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के तुलन-पत्रों का कमजोर होना रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस कमजोरी के कारण बैंक जोखिम विमुख हुए और उनके द्वारा ऋण आपूर्ति में कमी की गई : अल्प पूंजीकृत बैंकों के पास सिर्फ अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए ही पूंजी शेष है, वृद्धि⁷ करने के लिए कोई पूंजी ही नहीं। आपूर्ति पक्ष के कारक के आधिपत्य की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि निजी क्षेत्र के बैंकों (बेहतर आस्ति गुणवत्ता और औसतन बेहतर पूंजीकृत) की ऋण वृद्धि मजबूत बनी रही है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (विशेषरूप से वे बैंक जिनके पास अधिक दबावपूर्ण आस्तियां हैं) की ऋण वृद्धि में तीव्र गिरावट हुई है।

इस पृष्ठभूमि के साथ, दिसंबर 2016 में दिवालियापन एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) का अधिनियमित किया जाना, बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश 2017 (इसे कानूनी रूप दिया गया है) का लागू किया जाना, और उसके बाद इनके तहत की गई कार्रवाईयों के रूप में रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों से सबसे बड़े, महत्वपूर्ण और पुरानी अनर्जक आस्तियों को आईबीसी को भेजे जाने को कहे जाने से आईबीसी बैंकों की अनर्जक आस्तियों के समयबद्ध समाधान ढांचे के लिए धुरी की कील बन गया है।

इन कदमों को अब, ₹2.1 ट्रिलियन के आबंटन के साथ सरकारी क्षेत्र के बैंकों को प्रारंभ में ही पुनर्पूजीकृत करने के सरकार के निर्णय से सहायता मिलेगी, जिसके अंतर्गत बजटीय

प्रावधान (₹181 बिलियन), पुनर्पूजीकरण बांड (₹1.35 ट्रिलियन) और सरकारी इक्विटी शेयर (लगभग ₹580 बिलियन) में कमी लाते हुए बैंकों द्वारा पूंजी की उगाही शामिल हैं।

आस्ति समाधान और बैंक पुनर्पूजीकरण -दोनों कदमों के एक साथ उठाए जाने से बैंक तुलन-पत्रों में काफी मजबूती आने और नीतिगत दरों के अनुरूप दरों पर उधार देने की बैंकों की क्षमता और उनकी उत्सुकता में वृद्धि होने और परिणामस्वरूप बेहतर मौद्रिक नीतिगत संचरण की संभावना है।

समापक प्रेक्षण

सारांश रूप में, किसी भी केंद्रीय बैंक के लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीतिगत संचरण का प्रभावी होना अपरिहार्य होता है। पिछले दो दशकों के दौरान, रिज़र्व बैंक का प्रयास रहा है कि मौद्रिक नीतिगत संचरण प्रक्रिया को मजबूत बनाया जाए, किंतु इन प्रयासों से अपेक्षित परिणाम अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। नीतिगत रिपो दर का बैंक उधारी दरों में अंतरण, जो भारत में अंतरण का प्रमुख माध्यम है, चिंता का विषय रहा है। विधायिका द्वारा मूल्य स्थिरता के अधिदेश संबंधी स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए जाने से मौद्रिक नीतिगत संचरण के सुगम होने का महत्व और बढ़ गया है। इस पृष्ठभूमि के साथ, वर्तमान मौद्रिक नीतिगत संचरण प्रणाली की कमजोरियों के निवारण के लिए आंतरिक अध्ययन दल की रिपोर्ट हाल ही में तैयार की गई है। हमारे समक्ष एक प्रमुख विचार यह है कि ऋण मूल्यन प्रणाली को आंतरिक बेंचमार्क प्रणाली से बदल कर बाह्य मूल्यन प्रणाली को अपनाया जाए या नहीं। रिज़र्व बैंक, इस मामले में उचित समय पर सुविचारित रुख अख्तियार करेगा।

मेरे विचार से, बाहरी बेंचमार्क को अपनाए जाने के लिए अनुशंसा में गड़िन आर्थिक मामला अंतर्निहित है। मामला यह है कि : अर्थव्यवस्था में ब्याज दर जोखिम वहन कौन करे - उधारकर्ता, जमाकर्ता या बैंक ? ब्याज दर जोखिम को बेहतर ढंग से कौन संभाल सकता है ? खुदरा जमाकर्ता और उधारकर्ताओं के पास ब्याज दर जोखिम के कुशल प्रबंधन के उपाय होने की संभावना नहीं होती है। हालांकि, बैंकों के पास ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के साधन होने चाहिए। इसी प्रकार से, बड़े जमाकर्ताओं और बड़े कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं से ब्याज दर जोखिम प्रबंधन किए जाने की अपेक्षा की जा सकती है। बीमा और पेंशन निधि जैसे गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान, जिन

⁷ आचार्य, विरल वी. (2017), "अपूर्ण कार्यक्रम: भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के हालात बहाल करना", 8वां आर. के. तलवार स्मृति व्याख्यान।

पर ब्याज दर जोखिम कम होता है, भी इस जोखिम के अच्छे संग्राहक हो सकते हैं। विदेशी बैंक ब्याज दर जोखिम को वैश्विक स्तर पर संतुलित करने की स्थिति में हो सकते हैं। यदि बैंकों को ब्याज दर जोखिम को सुविधा की दृष्टि से उधारकर्ताओं पर अंतरित करने के स्थान पर सचमुच उसका प्रबंध करना हो, तो ब्याज-दर व्युत्पन्नियों (विशेषरूप से

अदला-बदली) जैसे ब्याज-दर जोखिम अंतरण व्यवस्थाओं और संपार्श्विकृत ऋण प्रतिबद्धताओं (सीएलओ) जैसे प्रतिभूतिकृत उत्पादों के संयोजन से काम बन पाएगा।

उम्मीद है कि मैं शीघ्र ही फिर कभी 'भारत में मौद्रिक नीतिगत संचरण : इसे कैसे बेहतर बनाया जाए ?' के अगले हिस्से के रूप में इन मुद्दों पर चर्चा करूंगा।

भारत की मौद्रिक नीति समिति के कार्यकाल का एक वर्ष*

माइकल देबब्रत पात्र

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की वेबसाइट पर 4 अक्टूबर 2017 को अपराह्न 2.30 बजे प्रकाशित किया गया और इस प्रकार छोटे पैमाने पर एक इतिहास रचा गया। ठीक एक वर्ष पहले, परंपरा के उस पन्ने को पलटा गया जिसका संबंध स्वतंत्रता-पूर्व के भारत में आरबीआई के उद्भव से था। मौद्रिक नीति संबंधी निर्णय छह-सदस्यों वाली एक समिति को सौंपा गया, जो अब तक अकेले भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर द्वारा लिया जाता था। समिति के अध्यक्ष रिज़र्व बैंक के गवर्नर हैं। इस समिति में मौद्रिक नीति के उप गवर्नर, आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड द्वारा नियुक्त एक अधिकारी, एवं केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तीन बाह्य सदस्य हैं। विचार-विमर्श और वाद-विवाद, चुनौती एवं जवाबी-चुनौती, पूर्णतः समर्थित व्यक्तिपरक आकलन, तथा वोटिंग युक्त भारत की मौद्रिक नीति की व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा था। बिना किसी श्रेष्ठता या इस प्रकार की कोई महत्ता के शनैः-शनैः यह भारत में मौद्रिक नीति के बर्ताव को आधुनिक रूप देने की दिशा में एक सबसे बड़ा कदम था।

वैधानिक अधिदेश के साथ आरबीआई अधिनियम में संशोधन करने के जरिए वृद्धि को लक्ष्य बनाते हुए मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के ध्येय के साथ भारत की गिनती उन चुनिंदा किंतु प्रगतिशील देशों में होने लगी जहां 1990 की शुरुआत से मौद्रिक नीति को लेकर ऐसी रूपरेखा बनाई गई है जिसके तहत लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्य (एफआईटी) अपनाया गया है। एफआईटी के अंतर्गत, मौद्रिक नीति के लक्ष्य के रूप में मूल्य स्थिरता को प्रमुखता दी गई है और साथ ही अर्थव्यवस्था की स्थिति पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। तदनुसार, मुद्रास्फीति के लक्ष्य को मध्यावधि सीमा में प्राप्त किया जाना है, बजाय किसी निश्चित समय पर, जिससे अवस्फीति से

* माइकल देबब्रत पात्र, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 27 अक्टूबर 2017 को भारतीय रिज़र्व बैंक के जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय में दिया गया भाषण।

इस भाषण की विषय-वस्तु 09 अक्टूबर 2017 को गवर्नर, डॉ. ऊर्जित आर पटेल का मिंट के साथ हुए साक्षात्कार से प्रेरित है, जो <http://www.livemint.com/Industry/Gr9H0MnqAL5Ko4PdGa7fdL/RBI-governor-Urjit-Patel-Weve-started-seeing-the-upturn-in.html> पर उपलब्ध है।

मैं डॉ. विरल वी. आचार्य के बहुमूल्य टिप्पणियों के लिए उनका आभारी हूँ। श्री सितिकान्ता पट्टनायक, डॉ. प्रजा दास, डॉ. राजीव रंजन, डॉ. राजीव जैन एवं डॉ. जय चन्द्र द्वारा दी गई जानकारी के लिए उन सभी का आभार। सामान्य अस्वीकरण लागू होते हैं।

पैदावार पर पड़ने वाले प्रभाव को कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त, आपूर्ति को लेकर कमी की संभावना को महसूस करते हुए लक्ष्य को इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि उसे एक ऐसे बैंड या दायरे के अंतर्गत रखा गया है जो मौद्रिक नीति के अधिकार क्षेत्र के बहुत बाहर है। मुद्रास्फीति बैंड सुनिश्चित न कर पाने की जवाबदेही आम तौर पर निश्चित की जाती है, लेकिन मौद्रिक नीति के परिचालन को लेकर विभिन्न कमियाँ पर विचार करने के बाद।

भारत में, संशोधित आरबीआई अधिनियम में, मुद्रास्फीति लक्ष्य के संबंध में मेट्रिक्स को मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया गया है। सरकार ने मुद्रास्फीति को लेकर 4 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें गुंजाइश का स्तर अधिकतम 6 प्रतिशत एवं न्यूनतम 2 प्रतिशत तय किया गया है। संशोधित आरबीआई अधिनियम में, मौद्रिक नीति के बर्ताव में स्वाभाविक रूप से जो कमियाँ आती हैं उसे महसूस करते हुए मुद्रास्फीति का लक्ष्य हासिल करने में नाकामयाबी को लेकर जवाबदेही संबंधी मानदंड भी विनिर्दिष्ट किए गए हैं। इसमें नाकामयाबी को, तत्काल न होकर, लगातार तीन तिमाहियों के लिए औसत मुद्रास्फीति गुंजाइश के दायरे को तोड़ने के रूप में परिभाषित किया गया है। यद्यपि, सामाजिक असहिष्णुता की सीमा के विपरीत पिछले दशकों के दौरान मुद्रास्फीति को लेकर व्यक्त की गई चिंता मौद्रिक नीति पर हावी रही, लेकिन मौद्रिक नीति के केंद्र-बिंदु के रूप में मुद्रास्फीति लक्ष्य की संख्या को लेकर ऐसी सुनिश्चित प्रतिबद्धता कभी नहीं की गई।

यह एमपीसी के लिए वास्तव में एक नई शुरुआत थी, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के संदर्भ में यह शब्द नया है। आरबीआई अधिनियम में संशोधन, मुद्रास्फीति लक्ष्य एवं इसकी गुंजाइश सीमा, और लक्ष्य पूरा न कर पाने की जवाबदेही को भारत के गजट में मई-अगस्त 2016 में अधिसूचित किया गया था। यह समाचार दूर-दूर तक फैला और इसने मीडिया के खबरों में जगह बनाया। फिर भी, इस बात का पता तब चला जब भारत सरकार ने 29 सितंबर 2016 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के जरिए एमपीसी की नियुक्ति के बारे में विश्व को बताया। महज एक कार्य दिवस बाद एमपीसी अपने कार्य में जुट गई और 04 अक्टूबर को इसने अपना पहला संकल्प सर्वसम्मति से जारी किया। इस शुरुआत के साथ कई पहल जुड़ी हुई हैं। जैसा अक्टूबर 2016 की सांविधिक अर्ध-वार्षिक मौद्रिक नीति रिपोर्ट (एमपीआर) में उल्लेख किया गया है: 'आरबीआई के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि उसको देश की मौद्रिक नीति रूपरेखा संचालित करने के लिए स्पष्ट वैधानिक अधिदेश

प्रदान किया गया। मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य को भी पहली बार परिभाषित किया गया। संशोधन में मौद्रिक नीति समिति के गठन की भी व्यवस्था की गई है, जो मुद्रास्फीति का लक्ष्य प्राप्त करने में आवश्यक नीतिगत दर निर्धारित करेगी, यह भारत के मौद्रिक इतिहास में एक और क्रांतिकारी परिवर्तन है। इन प्रत्येक मील के पत्थरों की अधिक गहराई से व्याख्या करने की जरूरत है ताकि जो नए मोड़ हैं उसके रूपांतरण को समझा जा सके। वास्तव में, प्रत्येक को इसकी वजह मिलेगी और मेरे संस्मरणों में ख्याति-प्राप्त व्यक्तियों के समूह में स्थान पाएंगे। तथापि, संक्षिप्तता और समय को ध्यान में रखते हुए, मैं अपने बाकी के व्याख्यान में निम्नांकित पर अपने विचार प्रकट करूंगा, (I) वह प्रारंभिक स्थितियां जिसकी वजह से आलोचक समूह को व्यवस्था में बदलाव करने की जरूरत महसूस हुई; (II) एफआईटी के पूर्व एवं उसके लिए बुनियाद तैयार करने हेतु संस्थागत संरचना के निर्माण में आरबीआई के प्रयास; (III) एमपीसी द्वारा उसके प्रारंभिक वर्ष में लिए गए छह निर्णयों को आंदोलित कर देन वाले अत्यंत सख्त कदम; एवं (IV) परस्पर विरोधी दबाव एवं दुविधा जिसने 04 अक्टूबर 2017 के निर्णय के लिए मार्ग प्रशस्त किया, विवादास्पद रूप से अत्यधिक कठिन परीक्षा की घड़ी थी।

II. आरंभिक स्थितियां

आज भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक मौद्रिक स्थायित्व की बात की जाती है और आंकड़े ऐसे दिए जाते हैं जिनसे दूसरे समकक्ष देशों को ईर्ष्या हो जाए; राजकोषीय घाटे की स्थिति ऐसी जो लगातार मास्ट्रिक्ट संधि के मानकों की ओर बढ़ रही है और जो अधिकांश लोगों के मत में उच्च गुणवत्ता वाली है; मुद्रास्फीति जो कि लक्ष्य से नीचे बनी हुई है जिसकी निगरानी एक मौद्रिक नीति समिति कर रही है जो यह सुनिश्चित करती है कि यह सरकार द्वारा सूचित बैंड के भीतर बनी रहे; चालू खाता घाटा जो सकल घरेलू उत्पाद के 1 प्रतिशत के नीचे है और बाह्य क्षेत्र संकेतकों के डैशबोर्ड की दृष्टि से वहनीय है - कुल मिलाकर एक सुखद स्थिति, चाहे किसी भी रूप में देखें ! फिर भी, अभी चार ही वर्ष पहले की बात है जब इसी अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियों का पहाड़ खड़ा था। 'टेपर टैंट्रम' के समय में स्थितियाँ कुछ इस प्रकार बन गयीं कि अर्थव्यवस्था में विद्यमान 6.6 प्रतिशत की वृद्धि-दर और लगभग 300 बिलियन यूएस डालर का विदेशी मुद्रा भण्डार भी 2013 की गर्मियों में 'फ्रेज़ाइल फाइव' के शर्मनाक टैग से भारत को बचा न सका। मूल रूप से यही वे कठिन परिस्थितियां थीं जो मौद्रिक नीति प्रशासन में परिवर्तन की प्रेरणास्रोत बनीं।

भारत वैश्विक आर्थिक संकट से सबसे पहले उबरने वाले देशों में से एक था और इसे अनुकूल हवा मिली राजकोषीय प्रोत्साहन से, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नीतिगत दरों में कुल मिलाकर 425 आधार अंकों की कटौती किए जाने से और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पर्याप्त मात्रा में चलनिधि की उपलब्धता को बढ़ाते हुए इसे जीडीपी के 10 प्रतिशत तक किया जाने से ताकि वित्तीय संस्थानों को क्रियाशील बनाए रखा जा सके क्योंकि वित्तीय बाजार निष्क्रिय हो चुके थे। वर्ष 2009 में ऐसा लग रहा था कि आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य के मुताबिक द्वि-अंकीय होने की दिशा में तेजी से अग्रसर थी। भौतिक आधारीक संरचना की दयनीय दशा के कारण लम्बे समय से विद्यमान अपमानजनक स्थितियों को दूर करने की दिशा में कदम उठाते हुए हमने विश्वस्तरीय सड़कें, एयरपोर्ट, विद्युत आपूर्ति और बदरगाह बनाने का कार्य प्रारंभ किया। इस बड़े कार्य के लिए उपयुक्त स्थितियों का निर्माण करने की दिशा में भी मुख्य भूमिका के निर्वहन की आशा वित्तीय क्षेत्र से ही की गयी थी यद्यपि, जैसा कि इस संबंध में हमारा दुःखद अनुभव बताता है, यह प्रशासन और जोखिम नियंत्रण की दृष्टि से बहुत हानिकार था।

हालांकि, इसमें एक प्रच्छन्न खतरा था। खाद्य-वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोत्तरी के पीछे खराब मानसून का हवाला देते हुए मुद्रास्फीति ने बड़ी ही मासूमियत के साथ अपना सिर उठाना शुरू किया और उसका यह विद्रूप चेहरा आर्थिक संवृद्धि में आई अकस्मात् तेजी, जो उस समय इतनी सकारात्मक लग रही थी कि इसमें हस्तक्षेप नहीं किया गया, की आड़ में छुपा रहा। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई), जो उस समय मुद्रास्फीति को मापने का आधिकारिक पैमाना था, शुरुआत में इसका पता लगाने में असफल रहा - यद्यपि, वर्ष 2009 में डब्ल्यूपीआई खाद्य सूचकांक में लगभग 15% की बढ़ोत्तरी हुई, तथापि हेडलाइन मुद्रास्फीति, जो डब्ल्यूपीआई में वर्ष-दर-वर्ष होने वाले परिवर्तन का माप होती है, 4% के नीचे बनी रही। उन दिनों के मूलभूत मापदंड की वजह से इसमें अत्यधिक गिरावट आई - डब्ल्यूपीआई गैर-खाद्य विनिर्मित उत्पाद मुद्रास्फीति करीब-करीब शून्य थी। लेकिन इसके विपरीत, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में मुद्रास्फीति (सीपीआई-आईडब्ल्यू) लगभग 12 प्रतिशत से अधिक थी। प्रारंभिक तौर पर बढ़ते हुए, खाद्य मुद्रास्फीति 2010-11 तक सामान्य हो गई। तब तक डब्ल्यूपीआई की वजह से यह बढ़ गई, और गैर-खाद्य विनिर्मित उत्पादों की कीमतों पर उसका प्रभाव दिखना शुरू हो गया। जब तक मार्च 2010 में नीतिगत प्रतिक्रिया हुई, बहुत देर हो चुकी थी। वर्ष 2009-12 के दौरान मुद्रास्फीति, सीपीआई-आईडब्ल्यू के आकलन के मुताबिक औसतन 10.4 प्रतिशत और डब्ल्यूपीआई के अनुसार 7.4 प्रतिशत रही। नीतिगत दरें 13 बार बढ़ने के

बावजूद उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब व्यवस्था में शामिल हो जाने के बाद, यह मल्टी-हेड्ड हाईड्रा के रूप में रूपांतरित होने लगा।

मुद्रास्फीति महज मूल्य स्तर की वृद्धि दर नहीं होती है। इसे राज्य द्वारा अभिशासन और व्यापक आर्थिक प्रबंधन की गुणवत्ता का सूचकांक भी माना जाता है। अपने लोगों की भलाई सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व होता है। राज्य के लोग बेहतर सामूहिक हितों की आस में अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ नियंत्रण राज्य पर छोड़ देते हैं। यह सर्वविदित है कि भारतीय समाज द्विअंकीय मुद्रास्फीति को कतई स्वीकार नहीं करता। बीते वर्षों में यह कई बार मुख्य चुनावी मुद्दा भी बन चुकी है और प्याज जैसी वस्तुओं की कीमतों में भारी गिरावट के चलते सरकारें बदल गयीं हैं। 2009 वर्ष के दौरान ही हाउसहोल्ड्स की आगामी वर्ष के लिए मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाओं में 400 आधार अंकों की वृद्धि हुई। वर्ष समाप्त होते-होते वे 12 प्रतिशत का आंकड़ा पार कर गयीं और यह वृद्धि जारी रही और उन्हीं उच्चतम बिंदुओं के इर्द-गिर्द बनी रही। मुद्रास्फीति के इस जिन्न को फिर से बोटल में कैद कर पाने की कोई संभावना लोगों को दिखाई नहीं दे रही थी। हालांकि, इस बार उन्होंने मतपत्रों का सहारा नहीं लिया। उन्होंने कुछ ऐसा किया जो कहीं अधिक खतरनाक था - उन्होंने सोना खरीदा।

जैसे-जैसे स्फीति के परिणाम और स्फीति प्रत्याशाएं बढ़ीं, बैंक जमा पर वास्तविक प्रतिलाभ की दर घटने लगी, यहां तक कि नकारात्मक हो गयी। वित्तीय आस्तियों में बचत करना नुकसानदेह लगने लगा। इसलिए लोग बैंक जमा और अन्य वित्तीय आस्तियों से अपना पैसा निकाल कर उसका निवेश सोने की खरीद में करने लगे। भारत में सोना खरीदना पूंजीपति बनने का सबसे कारगर मार्ग माना जाता है; भारत की कुल स्वर्ण मांग के केवल 2 प्रतिशत का खनन घरेलू रूप से किया जाता है। वर्ष 2012 तक भारत सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता बन चुका था। संकटकालीन वर्षों (2009-12) में सोने का वार्षिक औसत आयात 700-800 टन से बढ़कर 1000 टन के ऊपर पहुंच गया। सोने का आयात देश के कुल आयात का 11 प्रतिशत हो जाने के कारण चालू खाता घाटा बढ़ने लगा और 2012-13 की तीसरी तिमाही तक यह जीडीपी का 6.8 प्रतिशत हो गया। यह एक टाइम बम की तरह था जो कभी भी फट सकता था। वास्तव में आरबीआई ने वर्ष 2011-12 और 2012-13 के अपने मौद्रिक नीति वक्तव्य में इस उभरते चालू खाता घाटे से उत्पन्न खतरे के प्रति आगाह किया था परंतु उस समय पूंजी-अंतर्वाह में विद्यमान भारी वृद्धि के चलते इन चेतावनियों को अनसुना कर दिया गया।

थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो पायेंगे कि इस संकट की पृष्ठभूमि पहले ही बन चुकी थी। जरूरत थी तो बस एक

चिंगारी की। वह चिंगारी 2013 में मिल गयी जब फेडरल रिज़र्व (फेड) ने वर्ष के आखिरी महीनों में मौद्रिक नीति को सामान्य बनाने की संभावना की ओर इशारा किया। वर्ष 2009 से फेड द्वारा शुरू की गयी क्वांटिटेटिव ईज़िंग (क्यूई) के परिणामस्वरूप शिथिल पड़ चुके वित्तीय बाजारों को इससे एक जोरदार झटका लगा। निवेश के लिए सुरक्षित स्थल की तलाश में उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) से विदेशी पूंजी बाहर निकालने के लिए छटपटाहट होने लगी। मुद्राओं के मूल्यों में, प्रतिलाभों में और ईक्विटी में भारी गिरावट आयी क्योंकि ईएमई - जिसमें पूंजी निवेश को जोखिमपूर्ण की श्रेणी में माना जाने लगा - से निवेशक भाग खड़े हुए और उसका संक्रामक प्रभाव एक से दूसरी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ने लगा। निवेशकों का विश्वास विशेष रूप से पांच उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं - ब्राजील, इण्डोनेशिया, टर्की, दक्षिण अफ्रीका और भारत - पर से उठ गया। वित्तीय बाजारों में एक नया मुहावरा - 'फ्रेजाइल फाइव'- चल पड़ा।

मुद्रास्फीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई तरह से असर डाला था। प्रारंभ में जो स्फीति केवल खाद्य वस्तुओं तक सीमित थी, उसने कालांतर में भुगतान संतुलन संकट का रूप ले लिया। मौद्रिक नीति के समक्ष अब तक का सबसे गंभीर संकट उत्पन्न हो गया - विश्वसनीयता खोने का संकट। अकस्मात् स्थितियां ऐसी बनीं कि सुधार अवश्यभावी हो गए और इस पर तत्काल ध्यान देना बेहद जरूरी हो गया।

III. संस्थागत फ्रेमवर्क तैयार करना

इस स्थिति की प्रतिक्रिया स्वरूप रिज़र्व बैंक और सरकार दोनों ने सबसे पहले विदेशी खातों का गुणात्मक क्षरण को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया। आरक्षित निधि का बफर तैयार करना, सोने के आयात पर प्रतिबंध लगाना, घरेलू चलनिधि में कमी लाना ताकि बाजार में ब्याज दरें बढ़ सकें - इस प्रकार के बहुत से उपायों के बारे में लिखा-पढ़ा गया है और आज भी उस उथल-पुथल की कुछ यादें बाकी हैं। परंतु यह आत्ममंथन का समय था - कुछ बहुत ही बुनियादी चीज ऐसी थी जो टूट गयी थी और उसे जोड़ा जाना जरूरी था। आम जनता के लिए सुशासन और व्यापक आर्थिक प्रबंधन की जो शपथ ली गयी थी उसे चोट पहुंची थी और इस नुकसान की भरपायी शीघ्र की जानी आवश्यक थी। बहुत जल्द यह मसहूस किया गया कि एक मूलभूत परिवर्तन जरूरी है, कुछ ऐसा जो पूरी प्रणाली को हिला कर रख दे और परंपरागत तौर-तरीकों के वर्चस्व को समाप्त कर सके, कुछ ऐसा जिससे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता उत्पन्न हो जाए। इसी दिशा में आरबीआई ने मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क को संस्थागत आधार प्रदान करने हेतु 2014 में चरणबद्ध प्रयास प्रारंभ किए - हालांकि ये प्रयास पूरी तरह से क्रमबद्ध नहीं थे।

सितंबर 2013 में मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क को संशोधित और सुदृढ़ करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना हुई। इस विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों ने एक बौद्धिक आधार प्रदान किया जिस पर नया फ्रेमवर्क आधारित होगा। यह आंतरिक रूप से समनुरूप मॉडल था, अपने आप में परिपूर्ण, इसका दायरा मौद्रिक नीति के लक्ष्य(यों); इस लक्ष्य को हासिल करने में नीति निर्माता का पथ-प्रदर्शन करने वाले साधक-नियम; परिचालन पद्धति; परेक्षण; और मौद्रिक नीति के अंतरराष्ट्रीय आयामों तक व्याप्त था। इसका मुख्य आधार पहले से संकलित कार्य था और इसने नए आधार भी निर्धारित किए।

समिति की पैमाइश हेतु आधिकारिक मैट्रिक्स-उपभोक्ता कीमत सूचकांक में खुदरा स्तर पर कीमत परिवर्तन को लेते हुए हाउसहोल्ड और उपभोक्ताओं के साथ मिलकर एक तार को इंकृत किया, थोक मूल्य सूचकांक तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक के निकट रहता है, या कम-से-कम यह थोक कीमतों में बदलावों को प्रकट करता है और परिवारों को वह महंगाई बताता है, जो उन तक पहुंचने से पहले ही आकलित की गई। इसके अलावा जनवरी 2012 तक डब्ल्यूपीआई साप्ताहिक सूचकांक हुआ करता था जिसमें 676 वस्तुएं शामिल थीं। कीमत सापेक्षताएं हमेशा उपलब्ध था संगृहीत नहीं रहती और बहुधा इनकी बस पुनरावृत्ति कर दी जाती थी¹। यह सब कहना आसान था लेकिन करना कठिन था। जनता को काफी समय से रिज़र्व बैंक द्वारा निरूपित महंगाई संबंधी चिंताओं को जानने की आदत थी, यह निरूपण बहुआयामी संकेतक आधारित मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क के तहत डब्ल्यूपीआई के रूप में किया जाता था। जनवरी 2015 में नया अखिल भारतीय उपभोक्ता कीमत सूचकांक तैयार किया गया जिसमें सन 2012 को आधार वर्ष लिया गया। रिज़र्व बैंक के लिए समस्या यह थी कि इसने पहले कभी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर प्रतिक्रिया नहीं दी थी। परिणामस्वरूप नीतिगत प्रवर्तनों में सीपीआई स्फीति की प्रतिसादात्मकता अज्ञात थी। नीतिगत संक्रियाओं को अंशांकित करने का कोई तरीका नहीं था। महंगाई के आधिकारिक पैमाने के रूप में हेडलाइन सीपीआई स्फीति का प्रयोग एक अन्य उल्लेखनीय दृष्टि से भी बहादुरी भरा कदम था - क्योंकि सीपीआई की लगभग आधी बॉस्केट खाद्य

वस्तुओं से भरी थी। भारतीय अर्थव्यवस्था का काफी लंबा इतिहास था कि यह खाद्य जन्य आघातों से प्रभावित हो जाती थी, जिसमें अटलता और सहवर्ती कुप्रभाव भी दिखाई देते थे। आपूर्ति संबंधी आघातों को मौद्रिक नीति के नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता है। रिज़र्व बैंक ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि यद्यपि खाद्यजन्य आघात की प्रथम व्याप्ति मौद्रिक नीति के दायरे से बाहर है, लेकिन क्या द्वितीय चक्र के प्रभाव यथा स्फीति अनुमानों पर और खासकर शेष स्फीति को प्रभावित करने वाले सहवर्ती कुप्रभाव भी बाहर हैं। इसने यह भी निर्णय लिया कि अपने सर्वाधिक मूक घटकों से वंचित व्यतिरेकी उपाय की तुलना में हेडलाइन सीपीआई स्फीति अधिक सहज रूप में संप्रेषित होती है।

महंगाई को नवंबर 2013 के सर्वोच्च 11.5 प्रतिशत से नीचे लाने के लिए रिज़र्व बैंक ने एक ढलवा पथ निर्धारित किया, ताकि यह अधिक स्वीकार्य स्तर पर आए और अवस्फीति की आउटपुट हानियों को न्यूनतम करने के लिए बिग-बैंग को त्याग सके। इस परिपथ के भीतर इसने स्वतः निर्धारित लक्ष्य रखे - सन 2014 के अंत तक 8 प्रतिशत की कमी; सन 2015 के अंत तक 6 प्रतिशत की कमी; और 2016 के अंत तक 5 प्रतिशत की कमी। इन लक्ष्यों को सौभाग्य (सन 2014 में अंतरराष्ट्रीय पण्य कीमतों में गिरावट; नए सीपीआई में गुणोत्तर - औसत रखना) के व्यापक प्रभाव के कारण प्राप्त कर लिया गया, शायद वीरभोग्या वसुंधरा। इस पृष्ठभूमि में एमपीसी ने अपना कार्य आरंभ किया। आगामी साल के लिए अत्यधिक अनिश्चय के बीच इसे तलवार की धार पर संवृद्धि-स्फीति संतुलन का सामना करना तो तय हो गया था।

IV. बीता हुआ साल

एमपीसी के कार्यकाल का पहला साल एक नहीं कई प्रकार से उथल-पुथल से भरा रहा। कई बार कृत्रिम शुरुआतों के बाद वैश्विक मांग और व्यापार ने सन 2016 की दूसरी छमाही में अपना पैर थोड़ा सा जमाया और सन 2017 की पहली छमाही में इसे कुछ कर्षण हासिल हुआ। वित्तीय बाजारों में राजनैतिक मंथन चल रहा था। नवंबर 2016 में अमरीका में राष्ट्रपति चुनाव ने ईएमई से पूंजी प्रवाह को बेदखल कर दिया और यूएस डालर में आए उछाल ने समस्त संसार की मुद्राओं में उल्लेखनीय हास पैदा कर दिया। पुनः जनवरी 2017 में 'ब्रेक्सिट' रोडमैप और नए यूएस प्रशासन द्वारा राजकोषीय विस्तारवाद की प्रत्याशाओं ने यूएस डालर को बहुवर्षीय उच्चता

¹ डब्ल्यूपीआई में खाद्य वस्तुओं के लिए न्यून भारांक रहता है, जो परिवारों के उपभोग-व्यवहार से संबद्ध नहीं होता। इसमें सेवाएं शामिल नहीं होती। कीमत-सापेक्षताओं को मिश्रित बाजारों से हासिल किया जाता है, लेकिन प्रथमतया थोक बिक्री बाजारों से जहां सामान्य उपभोक्ता खरीदारी नहीं करता है।

पर जा चढ़ाया। जैसे-जैसे सन 2017 बीतता गया पुनस्फीति ट्रेड ने इक्विटी बाजारों को उठाया, बॉन्ड से कम प्रतिलाभ मिलने लगे और उदीयमान बाजारों की तरफ पूंजी का प्रवाह फिर से होने लगा। मार्च मध्य तक यूएस डालर के तेजड़िया धावे की सांसे उखड़ चुकी थीं, और सितंबर के आरंभ तक यह काफी कमजोर पड़ चुका था, जबकि ईएमई मुद्राओं का ट्रेड ऊपर उठ रहा था। हालांकि सितंबर के अंत तक स्थिति पूरी तरह उलट गई। फेड बैलेन्स शीट में सामान्य स्थिति आने की घोषणा के साथ अमरीकी डॉलर ने अपना खोया हुआ आधार फिर से हासिल कर लिया और उत्तरी कोरिया के आसपास तनाव की स्थिति बन गई। ईएमई इक्विटी बाजारों से पूंजी का बहिर्प्रवाह बढ़ गया। भारत के लिए इन वैश्विक गतिविधियों के बावजूद बाह्य क्षेत्र की व्यवहारिता में सुधार हुआ। सामान्यतया अति तीव्र पूंजी अन्तर्वाह ने विदेशी मुद्रा रिज़र्व को बढ़ा दिया।

सारे साल एमपीसी को जो चुनौती मिलती रही वह थी स्वदेशी दुविधा स्फीति और संवृद्धि के बीच जो ट्रेड-ऑफ काफी तीक्ष्ण बनने को था और दोनों के बीच का तनाव इतना प्रखर हो गया कि अंततः इसने एमपीसी के वोटिंग तरीके को प्रभावित किया। जल्द ही मैं इस बात पर आता हूँ कि यह संतुलन साधने में एमपीसी किन आरोपों और विचारों का सामना कर रही है, हालांकि फिलहाल मैं आरबीआई की तरफ से विश्लेषण करूंगा।

एक साल पहले एमपीसी की पहली बैठक के समय रिज़र्व बैंक भी नेतृत्व परिवर्तन की वेदना झेल रहा था - चौबीसवें गवर्नर ने अपना पदभार संभाला ही था। मौद्रिक नीति का दायित्व संभालने वाले उप गवर्नर की नियुक्ति नहीं हुई थी; और वरिष्ठतम उप गवर्नर को छह सदस्यों वाली एमपीसी को पूरा करने के लिए आगे आना पड़ा। यह भी कि आरबीआई सन 2005 से ही तकनीकी सलाहकार समिति के मित्रवत मार्गदर्शन में कार्य कर रही थी। एमपीसी के साथ जुड़ी हुई अधिक औपचारिक प्रक्रिया को देश विशेष में अपनाने के लिए शब्दशः देश के अनुभव के अनुरूप ढालना होता है। जो सामने आया वह संस्थागत पद्धतियों की अद्वितीय श्रृंखला के रूप में था, जिसपर आंतरिक प्रबंधन सूचना प्रणाली का बोझा लदा हुआ था।

जब एमपीसी अपनी पहली बैठक की प्रक्रिया में थी तो भारत जनवरी 2015 में शुरू हुआ समायोजनकारी मौद्रिक नीति का चक्र परिपक्व होने वाला था, जिसके पहले ही नीतिगत दरों को संचयी रूप में 150 आधार अंकों तक कम

किया जा चुका था। तो भी आधार खिसक रहा था। समष्टि आर्थिक और चलनिधि की स्थितियों में भूचाल जैसी स्थिति बन रही थी। सब्जियों की कीमतों में सामान्य उछाल, दालों की अत्यधिक बढ़ी हुई कीमतों और हाल ही में गिरावट के बाद मजबूती हासिल कर रही कच्चे तेल की कीमतों के संयोग ने अप्रैल-जुलाई 2016 के दौरान स्फीति को अनुमोदित पथ से दूर धकेल दिया और संवृद्धि भी धीमी रही। एमपीसी को जो पहला सीपीआई प्रिन्ट उपलब्ध कराया गया उसमें यह निर्मित हो रहा वोरटेक्स प्रकट हो रहा था। अप्रैल-जुलाई में हुई बढ़ोतरी में अचानक ही बदलाव आया और सब्जियों तथा दालों की कीमतों में अवस्फीति के कारण स्फीति अपने शिखर से लुड़कने लगी।

इस प्रकार की चुनौतीपूर्ण स्थितियों में, एमपीसी ने स्फीति की गतिविधियों को '.... खाद्य सामग्री की स्फीति की गति में अधोगामी विस्थापन - जो स्फीति के भावी परिणामों की कुंजी है...' पूर्वसंकेतित माना गया। यह आकलन भविष्यवाणी जैसा हो सकेगा। इस आशा में कि संतोषजनक मानसून और सावधानी भरी कारोबारी आशावादिता अवसर के गवाक्ष में से संवृद्धि को तेज करेगी और स्फीति में ठहराव आरंभ होगा, इसलिए एमपीसी द्वारा नीतिगत दर में 25 आधार अंकों की कमी सर्वसम्मति से की गई। सहज करने की इस अवस्था में, इस गिरावट से दरों में कुल कटौती 175 आधार अंक हो गई। इस बैठक में एमपीसी ने समायोजनकारी नीति की अवस्थिति को कायम रखा।

सिर्फ एक ही माह के बाद, विमुद्रीकरण हुआ - जिसमें लगभग 87 प्रतिशत मुद्रा परिचालन के स्टॉक में से बाहर हो गई - इसने प्रणाली में अचानक ही चलनिधि की कमी पैदा कर दी - तथा मौद्रिक स्थितियों में भारी परिवर्तन हुए। अगले कुछ माह राष्ट्र मुद्रा विनिमय के कार्य में व्यस्त रहा, लेकिन जब कभी भी उस समय का सही इतिहास लिखा जाएगा तो आशा है कि वित्तीय स्थायित्व की रक्षा में आरबीआई के पराक्रम का आद्योपांत उल्लेख अवश्य होगा। जनता द्वारा जब चलन से बाहर हो चुके नोटों को लौटाया जा रहा था तो बैंकों में जमाराशियों की बाढ़ आ गई और उनके पास निष्क्रिय मुद्रा भंडार जमा हो गया। वित्तीय बाजारों में चलनिधि की एक दीवार खींचनी शुरू हो गई और भय व्याप्त हो गया कि इसके मार्ग में - ब्याज दरें; प्रतिलाभ; विनिमय दरें; आस्ति कीमतें - जो भी आया, दब जाएगा। इस चलनिधि के महासागर और वित्तीय उथल-पुथल के बीच अकेले आरबीआई ने ही अद्वितीय चलनिधि अवशोषण रणनीति का अवलंबन लिया। इसने गैर-

पारम्परिक लिखतों को सामान्य परिचालनों के साथ उस समय सम्मिश्रित कर लिया नहीं तो चलनिधि की यह सुनामी इतनी विकराल थी कि इससे रिवर्स रेपो नीलामियों में संपार्श्विक के तौर पर प्रयोग किए जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों के रिज़र्व बैंक के स्टॉक को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जाता। सरकार से बाजार में स्थायित्व लाने वाली स्कीम की प्रतिभूतियों को प्राप्त करने में देरी से निपटने के लिए वृद्धिशील नकदी निधि अनुपात (आईसीआरआर) का प्रयोग किया गया और रिज़र्व बैंक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि बैंकों की संगत मांग और सामयिक देयताओं का 100 प्रतिशत हिस्सा आईसीआरआर में रहा।

इन कठिन परिस्थितियों ने एमपीसी की दिसंबर 2016, फरवरी और अप्रैल 2017 में हुई बैठकों पर बहुत ही कष्टदायी बोझ डाल दिया। आरंभ से ही एमपीसी ने यह मान लिया था कि अंतर्निहित स्थितियों के बारे में इसके आकलनों पर नोटबंदी के प्रभावों की छाया रहेगी, जो कि अर्थव्यवस्था के नकदी-प्रधान हिस्सों में संक्रमणकालीन व्यवधान, मांग में अचानक ही संकुचन, प्रतिबंधित विवेकपूर्ण व्यय और जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को औने-पौने बेचने के रूप में सामने आ रहे थे, जिनसे अस्थायी तौर पर स्फीति कम हुई। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया - पुनः सर्वसम्मति से - कि परिदृश्य को असंगत रूप से प्रभावित कर रहे 'संक्रमणकालीन लेकिन अस्पष्ट प्रभावों' पर ध्यान दिया जाए। इन बैठकों में इसने नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखा लेकिन यह ध्यान देते हुए कि खाद्य और ईंधन को छोड़ें तो स्फीति द्वारा अधोगामी लोचहीनता दिखाते हुए हेडलाइन स्फीति का आधार बन रहा था। एमपीसी ने यह चिंता भी जाहिर की कि वैश्विक वित्तीय बाजारों के कुप्रभाव उदीयमान बाजारों में बृहद आर्थिक स्थितियों को प्रभावित कर सकते हैं। तदनुसार, इसने अपनी फरवरी बैठक में नीतिगत रुख को समायोजनकारी से बदलकर तटस्थ कर दिया। महत्वपूर्ण यह रहा कि एमपीसी ने स्फीति के लिए अपनी वचनबद्धता के लक्ष्य को नवीकृत करके 4 प्रतिशत कर लिया। इस रुख को बनाए रखने के लिए रिज़र्व बैंक ने अपने चलनिधि प्रबंधन फ्रेमवर्क को अप्रैल की बैठक में संशोधित किया और अन्य बातों के साथ-साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) कॉरिडर को संकीर्ण करके +/- 25 आधार अंक (पूर्ववर्ती +/- 50 आधार अंक) कर दिया ताकि भारत औसत मांग मुद्रा का नीतिगत दरों के साथ बारीक अनुरूपण सुनिश्चित किया जा सके, जो कि मौद्रिक नीति का परिचालनगत लक्ष्य होता है।

एमपीसी की इन बैठकों को तीन बातें अलग बनाती हैं। पहली तो यह कि जून तक स्फीति प्रिन्ट तक भारी एकांगी स्फीति अनुमान गुटियों की आलोचना का सामना कर रही थी, बाद में यह ऐतिहासिक न्यून स्तर साबित हुआ। नोटबंदी का दोषारोपण तो तरोताजा ही था। हालांकि स्फीति की गिरावट अगस्त 2016 से ही हो गई थी, जिसने इसे नवंबर 2016 - जनवरी 2017 के दौरान अगस्त 2016 और 2017 के बीच परिवर्ती तौर पर बढ़ा दिया। वास्तविक स्फीति और अनुमानों के बीच 80 धार अंकों का संघर्ष विचलन पूरी तरह से सब्जियों और दालों की कीमतों की दोहरी अवस्फीति के कारण रहा जिसने प्रवृत्तिगत अंतरण पैदा किया, जो कि खाद्य प्रबंधन में गंभीर त्रुटियों को आईना दिखाता है, बाद में इसी वजह से व्यापक तौर पर किसानों में अशान्ति की ज्वाला फैली। इसी सन्दर्भ में अक्टूबर 2017 की एमपीआर में कहा गया : 'इन गतिविधियों के चलते खाद्य प्रबंधन रणनीतियों के दायरे और गुणवत्ता का फिर से मूल्यांकन करना होगा, दूसरी दिशा से मिलने वाले आघातों को देखते हुए इनकी विफलता अवश्यंभावी है। अतीत में भी ऐसा हुआ आपूर्ति के आघातों के अनुमानों ने स्फीति का एकांगी स्फीति विचलन दर्शाया जो कि अवस्फीति प्रकरणों की तरफ ले जाने वाले एक लक्षण मात्र थे। बलि के बकरे को अधिक शिकंजे में जकड़ने की जल्दी में ध्यान को वास्तविक मुद्दों से भटकाया गया और परिणामस्वरूप सही समाधानों से भी दूर रहे। दूसरे यह कि नोटबंदी के संक्रमणकालीन प्रभावों के निष्क्रिय होने को अपरिहार्य प्राथमिकता दी गई। यद्यपि, आज यह तर्क सम्मत निर्णय प्रतीत होता है, लेकिन इस तटस्थ रुख से बाजार चकित हो जाए और मंदड़िया संवेदना चल पड़ी। लहजे में कुछ तलखी की कीमत पर एमपीसी अनुमानों को ऐसी स्थिति में आधार देने के लिए संघर्षरत थी जब तत्काल सामने भी अंधेरे में कदम बढ़ाना था। तीसरे यह कि इन बैठकों में एमपीसी ने सर्व सम्मति से निर्णय लिए, यद्यपि इनके लिए व्यक्तिगत दृष्टिकोण की पद्धति अपनाई गई। अप्रैल 2017 की एमपीआर में हाल ही में देश के अनुभव का सर्वेक्षण किया और पाया कि बहुत से निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए। जहां मतभेद भी प्रकट हुए तो पाया गया कि ये मतभेद ओवरआर्किंग नीतिगत रुख का प्रतिरोध करने के स्थान पर नीतिगत दर में परिवर्तन की मात्रा तक ही खासतौर पर परिसीमित हैं।

एमपीसी की जून और अगस्त की बैठकें, पहले की तीनों बैठकों से अलग थी, वस्तुतः ये संवृद्धि स्फीति की दुविधा की नोक पर हुई। यद्यपि फरवरी और मार्च में कुछ मजबूत हुआ

लेकिन अप्रैल में अचानक और अहम बदलाव की वजह से एमपीसी ने 2017-18 के लिए स्फीति के अनुमान पथ को छ1 के 4.5 प्रतिशत और छ2 के 5 प्रतिशत से घटाकर जून की अपनी बैठक में छ1 के लिए 2 से 3.5 प्रतिशत और छ2 के लिए 3.5 से 4.5 प्रतिशत कर दिया। इसने बिना किसी लाग-लपेट के कहा था, 'रिकार्ड उपज और आयातों के कारण आपूर्ति आधिक्य के प्रभाव से दालों की कीमत साफ तौर पर नीचे गिर रही है। कीमतों में इस गिरावट को रोकने के लिए मुक्त व्यापार सहित नीतिगत हस्तक्षेप की जरूरत है।' प्रचुर आपूर्ति के साथ निर्धारित एजेन्सियों द्वारा सरकारी खरीद से इनकार करने के कारण सरकार द्वारा निर्धारित दालों की बाजार कीमतें दालों की समर्थन कीमतों से भी नीचे चली गईं। इसके बावजूद एमपीसी ने स्फीति के असामान्य रूप से न्यून आवेग के बारे में संदेह प्रकट किए थे, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना बताई और यह संभावना भी बताई कि खाद्य और ईंधन के अलावा स्फीति की अचलता स्वयं को फिर से मजबूत बनाएगी। इसने यह भी संकेत किया कि नोटबंदी के संक्रमणकालीन प्रभावों ने 'कीमत निरूपण को विलंबित किया है' और यह चेतावनी दी कि 'इस स्तर पर अपरिपक्व कार्रवाई करने से नीतियों में हानिकारक बदलाव का जोखिम पैदा होगा और विश्वसनीयता घटेगी।' अहम बात यह है कि आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में एमपीसी के पूर्वानुमानों में आवेगों के आरंभिक अनुमानित हानि की तुलना में कहीं अधिक हानि के बारे में चिंता जाहिर की गई थी। इसने निजी निवेश को फिर से बढ़ाने की तात्कालिकता, बैंकिंग क्षेत्र के स्वास्थ्य और संरचनागत बाधाओं को हटाने पर जोर दिया, ये सभी तथ्य मौद्रिक नीति के दायरे से बाहर के थे लेकिन प्रभावोत्पादकता को काफी बढ़ाते हैं। पहली बार एमपीसी ने सर्वसम्मति से नहीं बल्कि पांच सदस्यों के बहुमत से नीतिगत दर को अपरिवर्तित रखने के लिए वोट किया, क्योंकि गिरती हुई संवृद्धि और स्फीति के संघर्षी खिंचावों को सामने ला दिया था।

अगस्त की बैठक में एमपीसी ने पहली बार आवास किराया भत्ते (एचआरए) के कार्यान्वयन का प्रभाव देखा, यह भत्ता केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को दिया गया था, खासकर 'सांख्यिकीय' और दूसरे चक्र के प्रभावों के लिए खास तौर पर जिसके लिए जनता को काफी समय से आग्रह किया जा रहा था। इसमें पहले तो केवल सूचकांक ऊपर सरकता है और वास्तव में कोई स्फीति नहीं होती, लेकिन दूसरे में साधारणीकरण के साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक निगरानी अपेक्षित

होती है। एमपीसी ने पाया कि स्फीति के ऊपर जाने के जोखिमों को कुछ कम किया है। एचआरए प्रभाव को अलग करते हुए जो स्फीति होगी वह ति4 तक 4 प्रतिशत से थोड़ा सा अधिक रहेगी; विगत तीन माह के दौरान खाद्य और ईंधन को अलग रखें तो स्फीति में उल्लेखनीय गिरावट रही है - लेकिन कॉरपोरेट डीलिवरेजिंग और निवेश की मांग में संकुचन को देखते हुए उद्योग और सेवाओं में आंतरिक संवृद्धि की प्रवृत्ति कमजोर हो गई। वस्तुतः, 2016-17 और 2017-18 के लिए संवृद्धि अनुमानों को संचयी तौर पर क्रमशः 70 आधार अंक और 10 आधार अंक कम कर दिया गया है (अक्टूबर 2017 की बैठक में एमपीसी इसे और भी कम करेगी, इस बारे में, मैं आगे जिक्र करूंगा, और इस प्रकार प्रत्येक वर्ष के कटौती संबंधी सकल समायोजन 70 आधार अंक हो जाएंगे)। समायोजन के लिए प्राप्त अवसर का उपयोग करते हुए एमपीसी ने निर्णय किया कि नीतिगत रेपो दर को 25 आधार अंक कर दिया जाए, लेकिन रुख तटस्थ ही रखा जाए। दरों में कटौती का अधिकतम प्रभाव हासिल करने के प्रयोजन से समिति ने निजी निवेश को नवजीवन देने की संरचनागत बाधाओं को दूर करने; कॉर्पोरेट के तुलनपत्रों के समाधान और क्रेडिट प्रवाह को फिर से आरंभ करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पुनः पूंजी प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता पर फिर से जोर दिया। इस बार मतदान में चार सदस्यों का बहुमत रहा और मतदान प्राथमिकताओं का विभेद द्विपक्षीय रहा - एक सदस्य ने यथास्थिति के पक्ष में वोट दिया और दूसरे ने 50 आधार अंकों की दर कटौती के पक्ष में वोट दिया।

V. चतुर्थ द्विमासिक मौद्रिक नीति 2017-18

अक्टूबर 2017 के मौद्रिक नीति वक्तव्य की रचना काफी नाटकीय अंदाज में हुई। यहां तक कि वैश्विक संवृद्धि में व्यापकता आने के बावजूद अप्रैल-जून में लगातार दूसरी तिमाही के दौरान भी भारत में गिरावट रही। इस दर पर भी भारत विश्व की तेजी से विकास कर रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, लेकिन संवृद्धि की तरफ से होने वाले आघात इतने तो थे ही कि कई तरफ से अलार्म बज उठे।

यह मंदी अनिवार्यतया विनिर्माण क्रियाकलापों में रही जो कि 20 तिमाहियों के निचले स्तर पर जा पहुंची। हाल ही के कुछ वर्षों के दौरान औद्योगिक आउटपुट ने समूचे भौगोलिक इलाके में समक्रमिकता दिखाई है, और व्यापार को सह-गतिविधियों के तौर पर अभिनिर्धारित किया जा रहा है। हालांकि 2017-18 के आरंभ में भारतीय उद्योग लीक से हटकर रहा, इसमें

गिरावट रही जबकि सारे विश्व में औद्योगिक उत्पाद में सुधार हो रहा था। जीएसटी लागू करने के संक्रमणकालीन व्यवधान इसके कारणों में रहे। इसके बावजूद राष्ट्र ने इसे उद्योग के दुश्मन के तौर पर लिए, खासकर तब जब कि पूंजी निरूपण ने संयमित बहाली दिखाई थी।

एमपीसी के लिए दुविधा और भी प्रखर हो गई जब यह पाया गया कि विगत बैठक के बाद से स्फीति में लगभग 200 आधार अंकों की बढ़ोतरी हुई। यह ऊर्ध्वगति काफी व्यापक आधार वाली थी, इससे हाउसहोल्ड यह सोचने को बाध्य हुए कि आने वाले महीनों में कीमतों के सामान्य स्तर वर्तमान दर से अधिक दर पर बढ़ेंगे। फर्मों और खेती दोनों ही की इनपुट लागतें बढ़ीं लेकिन नियंत्रित मांग की स्थितियों में कमजोर कीमत निर्धारण शक्ति ने पूर्ण गति वाले पास-थ्रू को खुदरा स्फीति में व्याप्त होने से रोक लिया।

एमपीसी के आकलन में शेष वर्ष के दौरान कृषि ऋण माफी और केन्द्र की शैली में राज्यों द्वारा वेतन और भत्तों में संशोधन लागू करने के कारण स्फीति अपने वर्तमान स्तर से ऊपर जाने की संभावना है, जिससे अपसाइड जोखिम पैदा होगा। एमपीसी ने सारे परिदृश्य पर मंडराने वाली भूराजनैतिक तनावों की काली छाया और केन्द्रीय बैंकों के सर्वांगी तुलन-पत्रों में सन्निकट साधारणीकरण की चिंताओं को विचारपूर्वक व्यक्त किया। खाद्य-स्फीति के बारे में एमपीसी का पूर्वानुमान अधिक आशावादी था, यद्यपि पर्याप्त खाद्य भंडारों और आपूर्ति प्रबंधन प्रयासों को शमनकारी कारक माना गया।

संवृद्धि के बारे में एमपीसी ने खरीफ उपज के प्रथम आकलनों पर ध्यान दिया - यह उपज इस साल के लक्ष्य और विगत साल के स्तर से कम रही - और जीएसटी लागू होना संक्रमणकालीन आघात के तौर पर रहा। इसका विश्वास था कि अब कृषि के क्रियाकलापों में सुधार होगा। इसके अलावा, इसने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही की संभावनाओं के लिए फर्मों द्वारा व्यक्त कारोबारी प्रत्याशा को समर्थनकारी पाया। अगस्त संवृद्धि अनुमान को एमपीसी ने 60 आधार अंक कम किया, जो कि मोटे तौर पर समझो तो नोटबंदी और जीएसटी जैसे आघातों का शुद्ध प्रभाव कहा जा सकता है।

एमपीसी ने यह विचार व्यक्त किया कि हाल ही में हुए संरचनागत सुधार मध्यम अवधि में संवृद्धि में सहायता करेंगे। तदनुसार, जीएसटी संबद्ध बाधाओं के समाधान और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधनों को देखते हुए इसने संवृद्धि अनुमानों की दिशा को ऊर्ध्वगामी रखा,

जबकि इनपुट लागतों में बढ़ोतरी और उपभोक्ता कॉन्फिडेंस में हुई कमी से जोखिम संतुलित हो जाता है।

एमपीसी यह निम्नतम रेखा खींचने में स्पष्टवादी था - '..... निवेश क्रियाकलापों का पुनरुत्थान अनिवार्य है।' इसके लिए निवेश हेतु सहायक परिवेश का सृजन, दबावग्रस्त बैंकों का पर्याप्त पुनर्पूजीकरण, अवसंरचना अन्तराल को पाटना, जीएसटी को सरल बनाना, अनापत्तियां शीघ्रता से देना और निवेश प्रस्तावों से संबंधित पद्धतियों को राज्यों द्वारा औचित्यपूर्ण बनाया जाना अनिवार्य है।

इस पृष्ठभूमि में समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थितियों के मूल्यांकन में एमपीसी ने अपने निरूपण में यह निर्णय लिया कि नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखा जाए और तटस्थ नीतिगत रुख को बरकरार रखा जाए। इसके बाद जो प्रतिक्रियाएं मिलीं, उसका केन्द्रीय भाव यही रहा कि एमपीसी ने सही फैसला लिया।

V. समापन

मुझे आशा है कि हाल ही के मौद्रिक नीति निर्धारण में एमपीसी के सामने चुनौतियों और उसके निर्णयों में अंतर्निहित औचित्यों के बारे में मेरे विचारों ने कुछ स्पष्टता प्रदान की होगी। अन्ततोगत्वा मौद्रिक नीति संभाव्यता की कला है या विज्ञान। बेन बेरनान्के जब फेडरेल रिज़र्व बोर्ड के चेयरमैन थे तब उनसे 'लार्ड्स ऑफ फिनान्स' के लेखक लियाकत अहमद ने पूछा था कि 'मात्रात्मक सहजता या क्यूई का यह सिद्धान्त काम करेगा इस बारे में आप कितने विश्वस्त हैं।' लेखक को जवाब मिला - 'क्यूई के साथ यही समस्या है कि यह व्यवहार में तो काम करती है लेकिन सिद्धान्त में काम नहीं करती है।' वहां ठाहके गूँज उठे थे लेकिन आमतौर पर मौद्रिक नीति के बारे में यह सत्य है। मौद्रिक नीति का निर्णय लेना हमेशा ही जटिल और कठिन परीक्षा होता है। इसे किसी विस्फोट के बारे में विभिन्न दृष्टिकोणों के जैसा समझा जा सकता है, कि तीव्रता और प्रचंडता को सब अलग-अलग बताते हैं। हमारी एमपीसी का यही प्रयास रहा है कि अपने संकल्पों और अलग-अलग कार्यवृत्तों के माध्यम से जनता तक संतुलित आकलनों का सेट पहुंचाया ताकि भारत में मौद्रिक नीति पारदर्शी और अनुमान योग्य बन सके। आगे देखें तो एमपीसी का कार्य एक कट-आउट है और इस बारे में गवर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल के शब्दों से बेहतर शब्द मुझे नहीं मिल रहे, 'आर्थिक संवृद्धि के लिए समर्थन को नजरअंदाज किए बिना ही स्फीति लक्ष्यों को प्राप्त करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए।

लेख

भारत के बाह्य ऋण का विवेचन : प्रमुख प्रवृत्तियों का निर्धारण
बैंकिंग सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सर्वेक्षण: 2016-17

भारत के बाह्य ऋण का विवेचन : प्रमुख प्रवृत्तियों का निर्धारण*

इस आलेख में वर्ष 2016-17 में भारत के बाह्य ऋण से संबंधित गतिविधियों का खाका प्रस्तुत किया गया है और यह 1990 के दशक के प्रारंभ से लेकर अब तक इसके परिवर्तनशील प्रोफाइल का आकलन करता है। जहाँ एक ओर सरकारी से लेकर गैर सरकारी क्षेत्र तक की उधारियों में क्रमिक संगठनात्मक बदलाव देखने को मिले हैं, वहीं 2000 के दशक के मध्य से अल्पकालिक (मूल परिपक्वता अवधि की दृष्टि से) ऋण में तीव्र वृद्धि देखी गयी है जहां व्यापार क्रेडिट से जुड़ा हुआ ऋण एक ऐसा घटक रहा है जिसमें सर्वाधिक गति से वृद्धि हुई है।

भूमिका

बाह्य ऋण उभरते बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में बाहरी वित्तपोषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो कि घरेलू पूंजी की कमी से उत्पन्न अंतराल को भरने तथा चालू खाता घाटे (सीएडी) के निधियन की जरूरत को पूरा करने के साथ-साथ उपभोग को सुचारु रूप से बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैश्विक स्तर पर संसाधनों की प्रचुरता से उपलब्धता होने के कारण कम पूंजी वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह संभव हो गया है कि वे कम लागत पर बाहरी उधार प्राप्त कर सकें (मंजोकी, 1997)। परंतु बाह्य ऋण जहां एक ओर घरेलू निवेश के पूरक के रूप में कार्य करते हुए घरेलू अर्थव्यवस्था की संवृद्धि में सहायक बनता है, वहीं दूसरी ओर बाहरी उधारियों पर अतिशय निर्भरता किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अवहनीय बोझ बन सकती है और समष्टि प्रबंधन पर भी समग्र रूप से इसका असर पड़ सकता है।

आजादी के समय भारत का बाह्य ऋण लगभग न के बराबर था। आजादी के बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जैसे-जैसे विकास की नीतियां बनीं, भारत का बाह्य उधार (मध्यावधि एवं दीर्घावधि) मार्च 1955 के अंत के 1.8 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 1970 के अंत में 17 प्रतिशत हो गया। विदेशी उधारियों और अनुदान के रूप में विदेशों से अंतरित राशियों का उपयोग राष्ट्रीय बचत के पूरक के रूप में करते हुए मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के निवेश की गति को बढ़ाने पर

ध्यान केंद्रित किया गया। 1980 के दशक में बढ़े हुए सीएडी के लिए वित्तपोषण मुख्य रूप से वाणिज्यिक उधारियों और आईएमएफ से मिले ऋणों के माध्यम से किया गया। परिणाम यह हुआ कि मार्च 1991 के अंत तक कुल बाह्य ऋण तेजी से बढ़ता हुआ जीडीपी के 28.7% तक पहुंच गया।

1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत के साथ ही भारत के बाह्य ऋण के आकार और उसके संघटन में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले जिससे ऐसे नीतिगत परिवर्तन हुए जिन्होंने पूरी की पूरी बाह्य ऋण नीति को प्रभावित किया। आर्थिक सुधार प्रक्रिया के प्रमुख तत्वों में शामिल थे- सीएडी को वहनीय सीमा में बनाए रखते हुए चालू खाता लेन-देन को उदार बनाना जिससे चालू खाता परिवर्तनीयता की ओर बढ़ा जा सके; पूंजी खाते को धीरे-धीरे खोलना; पूंजी प्रवाह में संघटनात्मक बदलाव लाते हुए इसे ऋण से गैर-ऋण उत्पादक पूंजी प्रवाह की ओर ले जाना तथा बाह्य आघातों के मददेनजर बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी), विशेष रूप से अल्पावधि ऋण के प्रति एक नपा-तुला दृष्टिकोण अपनाना जिससे पूंजी प्रवाह में अस्थिरता लाने वाले तत्वों को हतोत्साहित किया जा सके।

इसी पृष्ठभूमि में यह आलेख 2016-17 के दौरान भारत के बाह्य ऋण से जुड़ी गतिविधियों और 1990 के दशक से लेकर अब तक इसके परिवर्तनशील प्रोफाइल को सारांश रूप में समझने का प्रयास करता है। शेष आलेख पांच खण्डों में विभाजित है। खण्ड II वर्ष 2016-17 के दौरान भारत के बाह्य ऋण से जुड़ी गतिविधियों का सार-संक्षेप प्रस्तुत करता है। खण्ड III में उन प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया गया है जो बाह्य ऋण के क्रमिक विकास की नियामक रही हैं। खण्ड IV के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बाह्य ऋण आधारित संकेतकों का इस्तेमाल करते हुए बाह्य जोखिमों का मूल्यांकन किया गया है और इसमें बाह्य ऋण एवं ऋण चुकौती भुगतान के बीच के संबंध की अनुभव के आधार पर जांच-पड़ताल भी की गयी है। खण्ड V विश्व के अन्य देशों, अर्थात् उभरते बाजार वाली अन्य अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) की तुलना में भारत के बाह्य उधार की स्थिति का निर्धारण करता है। खण्ड VI में निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

II. वर्ष 2016-17 के दौरान भारत के बाह्य ऋण से जुड़ी प्रमुख गतिविधियाँ : एक नज़र में

भारत के बाह्य ऋण की स्थिति मार्च 2017 के अंत में 471.9 बिलियन थी और वर्ष 2001-02 के बाद पहली बार इसमें वार्षिक आधार पर गिरावट दर्ज की गयी। चूंकि भारतीय रुपये की तुलना में यू एस डालर में गिरावट आयी, अतः 1.5

* यह आलेख आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्त प्रभाग में कार्यरत डॉ. राजीव जैन (निदेशक) और श्री जॉन वी. गुरिया (सहायक परामर्शदाता) द्वारा तैयार किया गया है। श्री राजन गोयल (परामर्शदाता) से प्राप्त बहुमूल्य सुझावों को शामिल करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया गया है। आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के निजी विचार हैं और ये भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते।

टेबल 1 : बाह्य ऋण - बकाया और अंतर

(बिलियन यूएस डालर)

घटक	मार्च के अंत में बकाया			प्रतिशत अंतर	
	2015	2016	2017 पीआर	मार्च 15 की तुलना में मार्च 16	मार्च 16 की तुलना में मार्च 17
1. बहुपक्षीय	52.4	54.0	54.5	3.0	1.1
2. द्विपक्षीय	21.7	22.5	23.2	3.4	3.4
3. आईएमएफ	5.5	5.6	5.4	2.1	-3.5
4. व्यापार क्रेडिट	12.6	10.6	9.8	-15.6	-8.3
5. वाणिज्यिक उधार	180.3	180.7	172.8	0.2	-4.4
6. एनआरआई जमा	115.2	126.9	116.9	10.2	-7.9
7. रुपये में ऋण	1.5	1.3	1.2	-15.1	-3.9
8. अल्पकालिक ऋण	85.5	83.4	88.0	-2.5	5.5
इसमें से अल्पकालिक व्यापार क्रेडिट	81.6	80.0	86.5	-2.0	8.1
कुल बाह्य ऋण	474.7	485.0	471.9	2.2	-2.7
<i>मेमो मदें</i>					
अ. दीर्घावधि ऋण	389.2	401.6	383.9	3.2	-4.4
ब. अल्पकालिक ऋण	85.5	83.4	88.0	-2.5	5.5
क. बाह्य ऋण-जीडीपी अनुपात (प्रतिशत)	23.9	23.5	20.2		

पीआर : अंशतः संशोधित

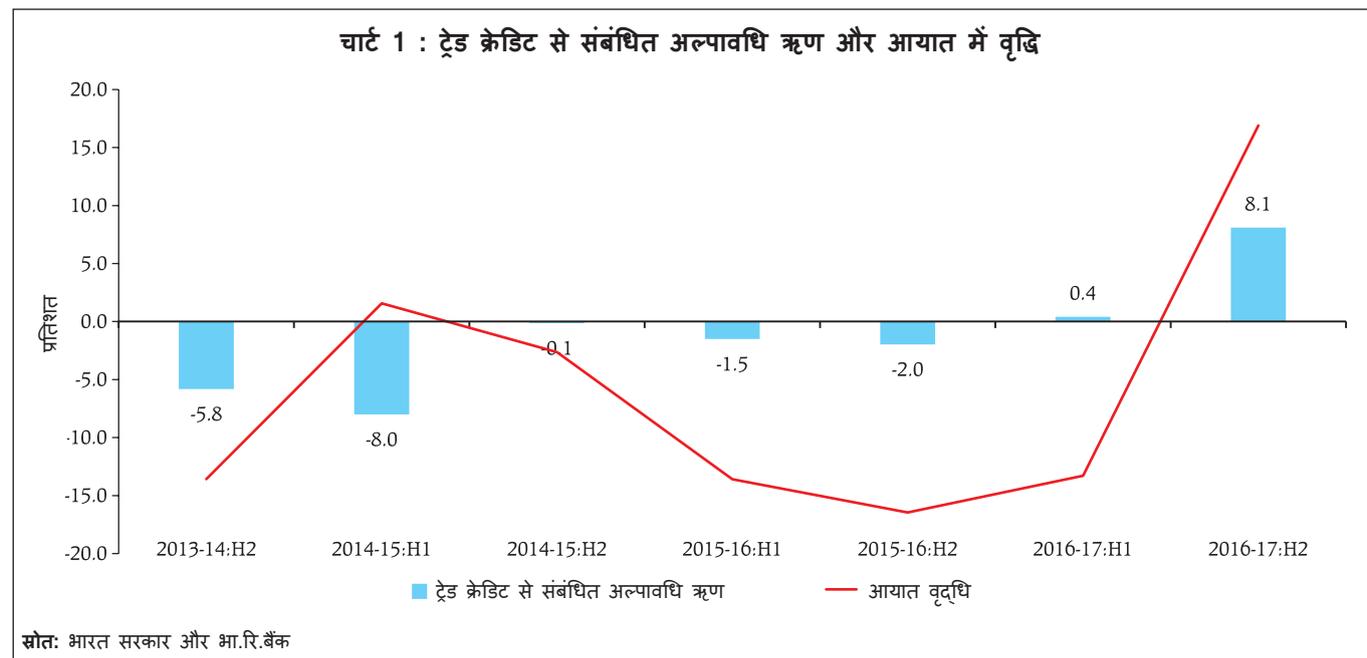
स्रोत: भारत सरकार और भा.रि.बैंक

बिलियन यूएस डालर की मूल्यन हानि हुई जिसके परिणामस्वरूप बाह्य ऋण कम होकर 13.1 बिलियन यूएस डालर रह गया जबकि अगर मूल्यन में यह परिवर्तन न हुआ होता तो 2016-17 में बाह्य ऋण में कमी 14.6 बिलियन यूएस डालर हुई होती। बैंकों द्वारा सितंबर से नवंबर 2013 के दौरान एक विशेष स्वैप योजना के तहत उगाहे गए एफसीएनआर जमा का

बड़ी-बड़ी किस्तों में मोचन अनिवासी जमा के स्टॉक में कमी आने का प्रमुख कारण रहा। इसके अलावा, चूंकि वर्ष के दौरान नये संवितरणों की तुलना में चुकौतियां ज्यादा रहीं, अतः वाणिज्यिक उधार के स्टॉक में भी कमी आयी। मार्च 2017 के अंत में जब जीडीपी 20.2% थी तब बाह्य ऋण मार्च 2016 के अंत के अपने स्तर से 3.3 प्रतिशतता अंक कम था (टेबल 1)।

घटकवार देखें तो वाणिज्यिक उधार 36.7 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ लगातार सबसे बड़ा घटक बना रहा और इसके बाद क्रमशः अनिवासी जमा (24.8%) और अल्पावधि व्यापार क्रेडिट (18.3%) का स्थान रहा। जहाँ परिपक्वता प्रोफाइल के अंतर्गत दीर्घावधि ऋण देयताएं सर्वाधिक रहीं, वहीं अल्पावधि ऋण (मूल परिपक्वता) की हिस्सेदारी बढ़ी क्योंकि 2016-17 की दूसरी छमाही में वस्तुओं के व्यापार में आयी तेजी के प्रभाव के कारण अल्पावधि व्यापार क्रेडिट में तीन वर्षों की अवधि के बाद निवल आवक देखने को मिली (चार्ट 1)। हालांकि, अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर मार्च 2017 के अंत में अल्पावधि ऋण कुल बाह्य ऋण का 41.5% था (मार्च 2016 के अंत में 42.7%) और कुल विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि का 52.9% था (मार्च 2016 के अंत में 57.4%) (टेबल 2)। इस प्रकार, अवशिष्ट परिपक्वता की दृष्टि से देखें तो एफसीएनआर (बी) जमाराशियों की बड़े पैमाने पर चुकौती के चलते अल्पावधि ऋण 206.9 बिलियन यूएस डॉलर से घटकर 195.9 यूएस डॉलर हो गयी।

मुद्रावार पैटर्न यह दर्शाता है कि कुल बाह्य ऋण का



टेबल 2 : बाह्य ऋण की अवशिष्ट परिपक्वता मार्च 2017 के अंत में बकाया

(बिलियन यूएस डालर)

घटक	अल्पकालिक एक वर्ष तक	दीर्घकालिक	कुल
1. सरकारी ऋण (दीर्घावधि)\$	4.6	91.1	95.7
2. वाणिज्यिक उधारियां#	24.0	147.3	171.3
3. एनआरआई जमा	79.3	37.6	116.9
(i) एफसीएनआर (बी)	11.4	9.6	21.0
(ii) एनआर(ई)आरए	57.4	25.8	83.2
(iii) एनआरओ	10.5	2.2	12.7
4. अल्पकालिक ऋण* (मूल परिपक्वता)	88.0	-	88.0
कुल (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार)	195.9	276.0	471.9

मेमो मदें

अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार अल्पकालिक ऋण निम्नलिखित के प्रतिशत के रूप में : -

कुल बाह्य ऋण	41.5	
कुल आरक्षित निधियां	52.9	

*इसमें विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए निवेश को भी शामिल किया गया है।

#वाणिज्यिक उधारियों के अंतर्गत व्यापार क्रेडिट, कॉर्पोरेट ऋण लिखतों में एफपीआई निवेश और गैर सरकारी बहुपक्षीय और द्विपक्षीय उधारियों का एक हिस्सा शामिल है और इसीलिए अन्य तालिकाओं में मूल परिपक्वता के तहत दिए गए आंकड़ों से ये आंकड़े भिन्न भी हो सकते हैं।

* इसके अंतर्गत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी जमा रसीदों में विद्यमान कॉर्पोरेट ऋण सीमाओं के तहत किए गए एफपीआई निवेश भी शामिल हैं।

स्रोत: भा.रि.बैंक

52.1% यूएस डॉलर में था, उसके बाद भारतीय रुपये (33.6%), एसडीआर (5.8%), जापानी येन (4.6%) और यूरो (2.9%) का

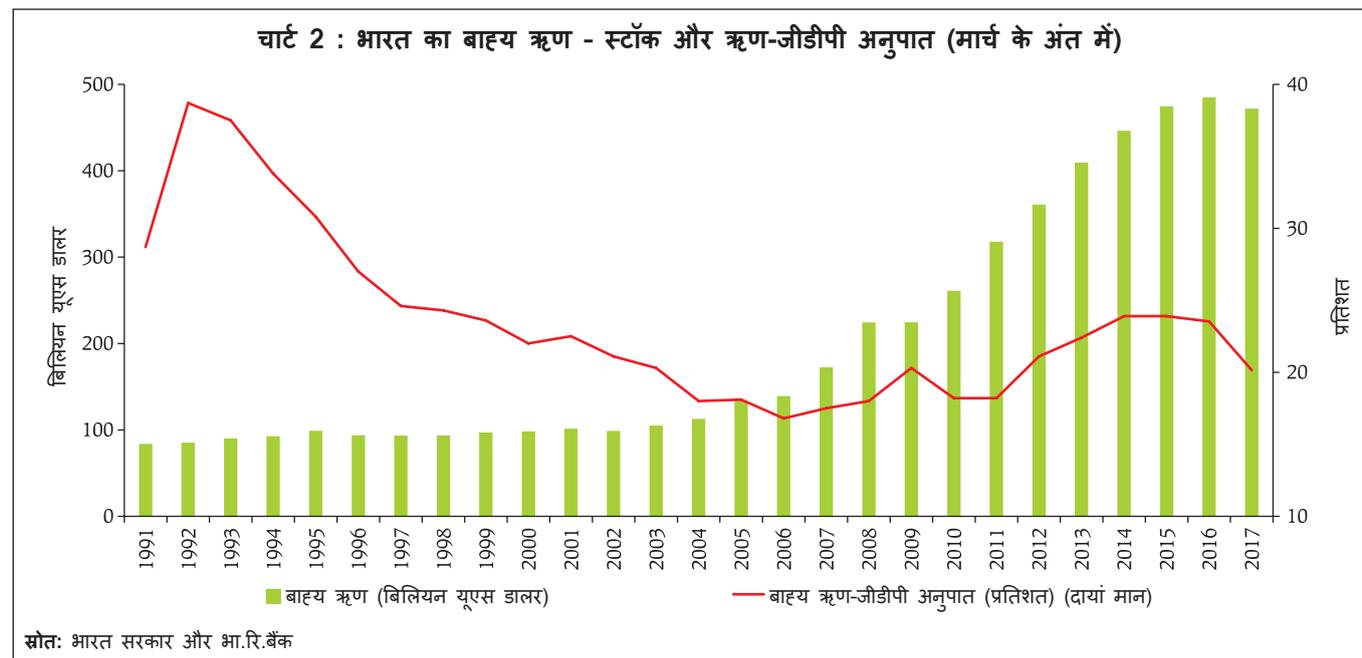
स्थान था। उधारकर्ताओं के विश्लेषण से पता चलता है कि वर्ष के दौरान प्राप्त हुई बाहरी सहायता के कारण सरकार का बकाया ऋण थोड़ा अधिक रहा, यद्यपि मार्च 2017 की समाप्ति पर गैर सरकारी ऋण में गिरावट दर्ज की गयी।

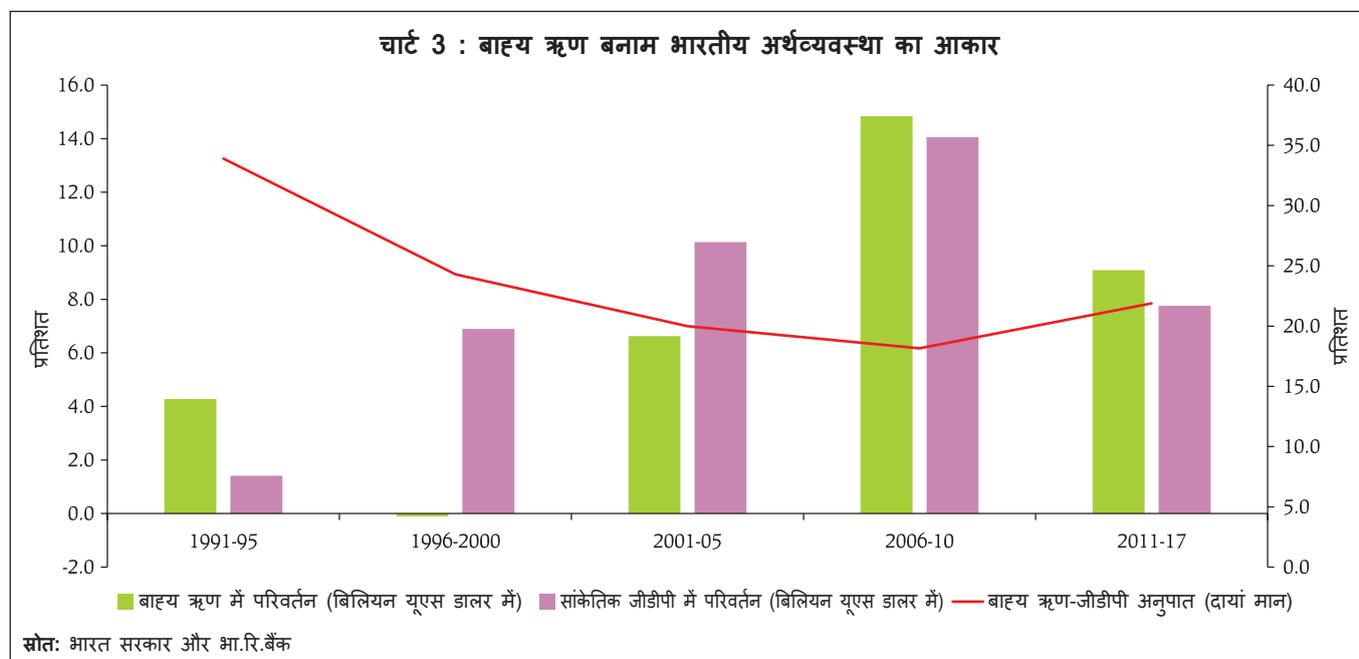
III. भारत के बाह्य ऋण को आकार देने वाले महत्वपूर्ण दीर्घावधि रुझान

1990 के दशक के शुरुआती वर्षों से ही भारत के बाह्य ऋण के स्तर और उसके संघटन में उल्लेखनीय परिवर्तन देखे गए हैं। 1991 के बाह्य भुगतान संकट और भुगतान शेष पर गठित उच्च स्तरीय समिति, 1993 (अध्यक्ष : डॉ. सी. रंगराजन) की सिफारिशों से सीख लेते हुए इस उद्देश्य से बने नीतिगत दृष्टिकोण की मार्गदर्शक बातें रहीं हैं- i) ईसीबी के आकार, परिपक्वता और उसके अंतिम उपयोग पर प्रतिबंध; ii) अनिवासी जमा पर लिबोर-आधारित ब्याज सीमा आरोपित करना ताकि इन जमाराशियों में अस्थिरता का घटक कम किया जा सके; iii) उच्च लागत वाले बाह्य ऋण का समय-पूर्व भुगतान और पुनर्वितीयन; और iv) ऋण न उत्पन्न करने वाले वित्तीय प्रवाहों- यथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) और विदेशी संविभाग निवेश (एफपीआई) को प्रोत्साहित करने के उपाय।

जैसे-जैसे पूंजी खाते की परिवर्तनीयता बढ़ी, भारत के बाह्य ऋण का आकार मार्च 1991 के अंत के 83.8 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर मार्च 2017 के आखिर में 471.9 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। यद्यपि बाह्य ऋण और

चार्ट 2 : भारत का बाह्य ऋण - स्टॉक और ऋण-जीडीपी अनुपात (मार्च के अंत में)





जीडीपी के अनुपात - जो किसी भी देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं के निर्यात द्वारा बाह्य ऋण की चुकौती की उसकी क्षमता को मोटे तौर पर दर्शाता है - में तेजी से गिरावट हुई और यह मार्च 1992 के अंत के 37.3 प्रतिशत से घटकर मार्च 2006 के आखिर में 16.8 प्रतिशत हो गया (चार्ट 2)। यद्यपि सन् 2000 के दशक से बाह्य ऋण में हुई वृद्धि की दर - औसतन - घरेलू अर्थव्यवस्था में हुई वृद्धि की दर से अधिक रही है, तथापि 1990 के दशक की तुलना में देखें तो इसका स्तर का आनुपातिक रूप से कम ही रहा और मार्च 2017 के अंत में यह 20.2 प्रतिशत रहा (चार्ट 3)।

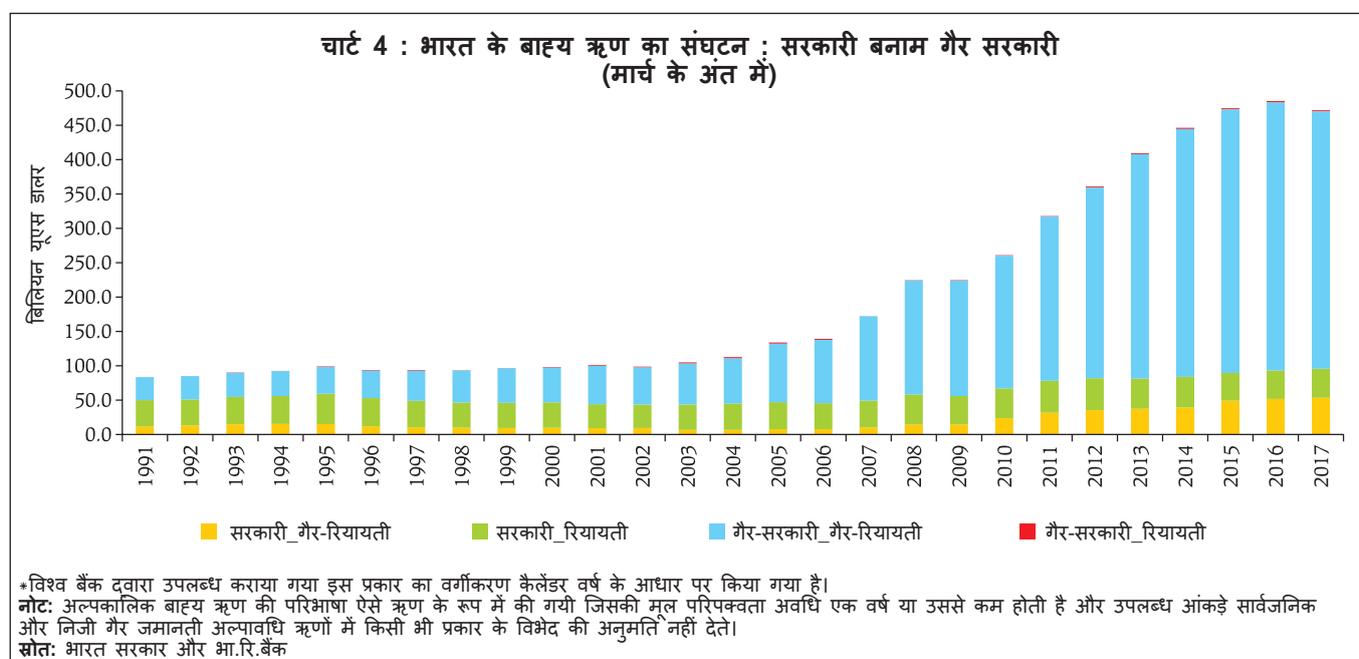
III.1 बाह्य उधारियों में संघटनात्मक बदलाव

सन् 2000 के दशक के पूर्वार्ध में सरकार ने अपने ऊपर ब्याज का भार कम करने के उद्देश्य से उच्च लागत वाले बहुपक्षीय और द्विपक्षीय ऋणों का परिपक्वतापूर्व भुगतान कर दिया। परिणामस्वरूप सरकारी ऋण की हिस्सेदारी - जिसमें सरकारी ऋणदाताओं से रियायती दरों पर प्राप्त ऋण भी शामिल हैं - मार्च 2000 के अंत के 48 प्रतिशत की तुलना में घटकर मार्च 2017 के अंत में 20 प्रतिशत हो गयी। रियायती ऋण की हिस्सेदारी भी मार्च 2011 के अंत के 15 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2017 के अंत में 9 प्रतिशत हो गयी (चार्ट 4)।

सन् 1990 के दशक में हुए उदारीकरण के बाद विनिर्माण क्षेत्र को आधुनिक बनाने तथा इसमें विदेशी प्रौद्योगिकी तथा

विदेशी पूंजी की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रयासों के मददेनजर निजी कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए संभावनाएं खुलीं। इसका परिणाम यह हुआ कि वर्ष 2000 के बाद पहली बार कुल बाह्य उधार में गैर सरकारी उधार की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

1991 के पहले, अल्पकालिक ऋण बहुतायत में पब्लिक सेक्टर कैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और उर्वरकों के आयात के वित्तपोषण के लिए लिया गया उधार था। सन् 1980 के दशक के दौरान इस प्रकार का अल्पकालिक ऋण कुल बाह्य ऋण का 10 प्रतिशत था। सन् 1991 में उपजे भुगतान संतुलन संकट से मिले अनुभवों के मददेनजर बाह्य ऋण प्रबंध नीति को अधिक विवेकपूर्ण बनाते हुए अल्पकालिक विदेशी पूंजी पर निर्भरता को कम किया गया। परिणामस्वरूप 1990 के दशक में कुल ऋण में अल्पकालिक ऋण की हिस्सेदारी घटी; हालांकि मूल परिपक्वता अवधि की दृष्टि से अल्पकालिक ऋण - निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों द्वारा लिए गए - की हिस्सेदारी सन् 2000 के दशक के प्रारंभिक वर्षों से फिर से बढ़ने लगी जो कि आयात में तीव्र वृद्धि का आधार बनी जो कि वर्ष 1990-91 से 2001-02 की अवधि के 8 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2002-03 से 2011-12 की अवधि में बढ़कर औसतन 26 प्रतिशत हो गया। वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल (वीईसीएम) के तहत वर्ष 2000 की दूसरी तिमाही से वर्ष 2017 की चौथी तिमाही तक की अवधि के लगाए गए पूर्वानुमान इस बात का संकेत करते हैं कि वाणिज्यिक वस्तुओं के आयातों से संबंधित व्यापार क्रेडिट की



प्रत्यास्थता और रुपये की विनिमय दर धनात्मक और सांख्यिकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं (टेबल 3)।

एक अन्य उल्लेखनीय घटना थी एक वर्ष तक की परिपक्वता अवधि वाले अनिवासी जमा को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना - एफसीएनआर(बी) जमा के परिपक्वता ढाँचे के अनुसरण में अप्रैल 2003 से नये एनआर(ई)आरए जमा की न्यूनतम परिपक्वता अवधि बढ़ाकर एक वर्ष कर दिए जाने के बाद - जिसके कारण कुल अल्पावधि ऋण में अनिवासी जमा

की हिस्सेदारी मार्च 2005 के अंत तक घटकर लगभग शून्य हो गयी (चार्ट 5)।

अवशिष्ट परिपक्वता अवधि के आधार पर परिगणित अल्पावधि ऋण से यह पता चलता है कि अगले एक वर्ष में ऋण की चुकोती स्वरूप किए जाने वाले भुगतान में कुल कितनी विदेशी मुद्रा बाहर जाएगी और इस प्रकार यह परिचालनात्मक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। मूल परिपक्वता अवधि वाले अल्पावधि ऋण के अलावा इसके अंतर्गत अगले एक वर्ष में चुकोती योग्य मूल परिपक्वता अवधि की दृष्टि से मंझोले और दीर्घावधि ऋण को भी शामिल किया जाता है। इस दृष्टि से देखें तो कुल बाह्य ऋण में अल्पावधि ऋण की हिस्सेदारी (अवशिष्ट परिपक्वता) मार्च 2008 के अंत के 37.6% की तुलना में बढ़कर मार्च 2013 के अंत में 42.1% हो गयी³। अप्रैल 2014 से ट्रेजरी बिलों के नये निर्गमों में एफपीआई द्वारा निवेश किए जाने की मनाही से 2013 और 2014 के दौरान अवशिष्ट परिपक्वता वाले ऋण की हिस्सेदारी कम हो गयी⁴। विशेष स्वाप विंडो के तहत संग्रहीत एफसीएनआर (बी) जमा के चलते, जो कि सितंबर से नवंबर 2016 की अवधि के दौरान मोचन योग्य था, अवशिष्ट परिपक्वता अवधि की दृष्टि से अल्पावधि ऋण की हिस्सेदारी बढ़कर मार्च 2016 के अंत तक 42.7% हो गयी।

टेबल 3 : वीडसीएम मॉडल : व्यापार क्रेडिट से संबंधित बाह्य ऋण (2000:ति.2 से 2017:ति.1)

	ईसीटी	सी	एलआईएमपी	एलईआर	समा.आर ²
गुणांक	-0.15	-2.70	1.40	0.55	0.80
टी-सांख्यिकी	-3.94*		3.87*	2.28**	

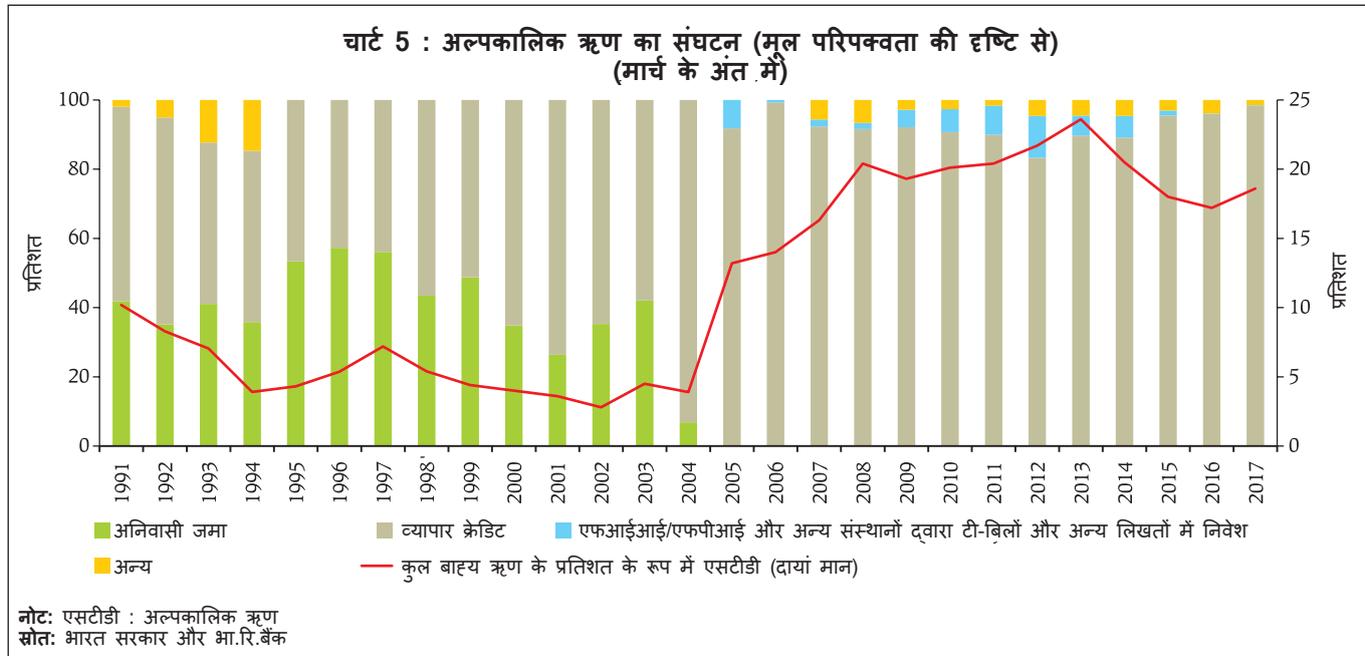
नोट: एलआईएमपी और एलईआर जो क्रमशः वस्तुओं की आपूर्ति और आईएनआर विनिमय दर का प्रतिनिधित्व करते हैं, को लॉग के रूप में परिभाषित किया गया है। ईसीटी एरर करेक्शन टर्म है।
 * और ** क्रमशः 1 प्रतिशत और 5 प्रतिशत पर सांख्यिकीय महत्व को दर्शाते हैं।

¹ रुपये की विनिमय दर में परिवर्तनों के प्रति बाह्य ऋण की संवेदनशीलता संकेत करती है- (क) कॉनफीडेंस चैनल - ऋण पात्रता और इसके परिणामस्वरूप ऋण की आपूर्ति में सुधार करते हुए मूल्यवृद्धि को दर्शाया जाता है; और (ख) लागत चैनल जिसके तहत मूल्यवृद्धि से बचाव लागत में कमी आती है।

² जोहानसन को-इंटीग्रेशन परीक्षण का उपयोग करते हुए सभी तीन चरों (1) (परिशिष्ट II देखें) और सीरीज को सहसंबद्ध पाया गया है। इस प्रकार वेक्टर त्रुटि सुधार मॉडल (वीडसीएम) को विनिर्दिष्ट किया गया है जो अंतर्जात चरों के दीर्घकालिक व्यवहार को नियंत्रित करते हुए अल्पकालिक समायोजन गतिकी की अनुमति देने के साथ-साथ उनके सह-एकीकरण को ओर ले जाता है।

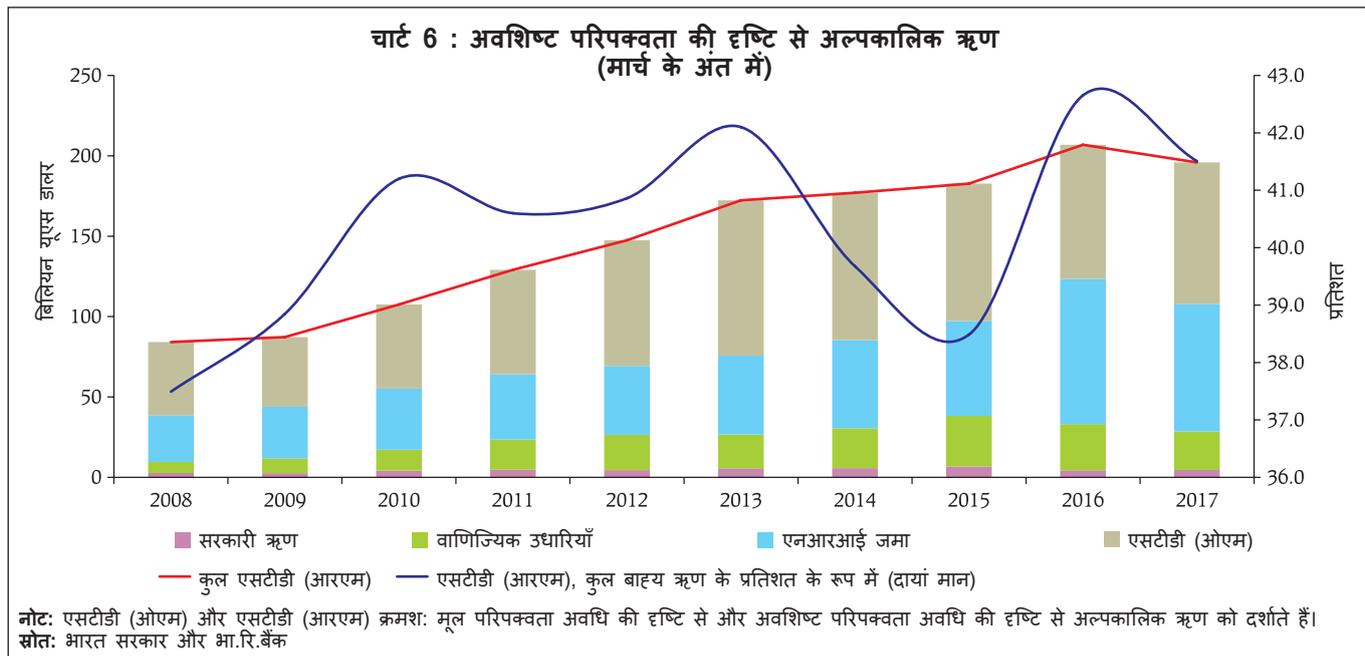
³ अवशिष्ट परिपक्वता अवधि की दृष्टि से अल्पावधि बाह्य ऋण संबंधी संगत टाइम सीरीज डाटा केवल मार्च 2008 के अंत से ही उपलब्ध है।

⁴ 07 अप्रैल 2014 की स्थिति के अनुसार सभी टी-बिलों में बकाया सभी एफपीआई धारिताओं को परिपक्वता/बिक्री पर टेपरिंग की अनुमति दी गयी थी।



बैंकों द्वारा इन जमा राशियों के एक बड़े भाग का मोचन करा लिए जाने के बाद कुल बाह्य ऋण में अवशिष्ट परिपक्वता की दृष्टि से अल्पकालिक ऋण की हिस्सेदारी मार्च 2017 के अंत

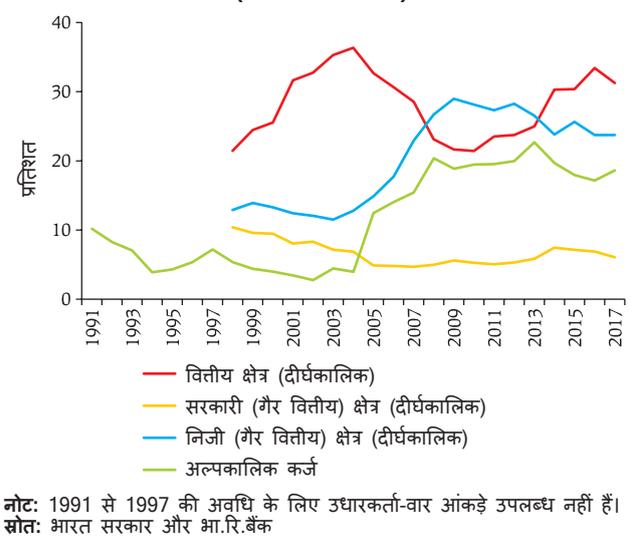
तक घटकर 41.5% हो गयी बावजूद इसके कि एनआरआई/एनआरओ और व्यापार क्रेडिट जैसे अन्य घटक नये सिरे से इसमें जुड़े (चार्ट 6)।



सन् 2000 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में निजी क्षेत्र द्वारा उगाहे गए बाह्य ऋण में हुई भारी वृद्धि ने बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) से संबंधित नीतियों में आयी उदारता को दर्शाया⁵। रिज़र्व बैंक ने भी अक्टूबर 2004 से कुछ शर्तों के अधीन ईसीबी को इक्विटी में बदलने के लिए सामान्यतया मंजूरी दे दी थी। इसी प्रकार, आयात के लिए वित्त की उपलब्धता को अधिक सुलभ बनाने के लिए प्राधिकृत डीलरों (एडी) की सीमा में विस्तार करने की दिशा में भी कई कदम उठाए गए थे।

वित्तीय क्षेत्र जिसकी हिस्सेदारी 1998 के अंत में कुल बाह्य ऋण का 22 प्रतिशत थी, वह बढ़कर मार्च 2017 के आखिर में 32 प्रतिशत हो गयी। इसी तर्ज पर कुल बाह्य ऋण में निजी (गैर वित्तीय) क्षेत्र की हिस्सेदारी जो 1998 के अंत में 13 प्रतिशत थी, वह बढ़कर मार्च 2017 के आखिर में 23 प्रतिशत हो गयी। चूंकि पिछले दशक में घरेलू गैर वित्तीय कॉर्पोरेट सेक्टर द्वारा किया गया लगभग पूरा का पूरा निवेश ऋणपोषित (लीवरेज्ड) था (लिंडर एण्ड जंग, 2014), अतः वैश्विक आर्थिक संकट के बाद की अवधि में बाह्य ऋण बढ़ने की गति तेज हो गयी। वहीं दूसरी ओर कुल बाह्य ऋण में सार्वजनिक (गैर वित्तीय) क्षेत्र की हिस्सेदारी जो 1998 के अंत

चार्ट 7 : कुल बाह्य ऋण में उधारकर्ता-वार और परिपक्वता-वार गैर-सरकारी ऋण (मार्च के अंत में)



नोट: 1991 से 1997 की अवधि के लिए उधारकर्ता-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
स्रोत: भारत सरकार और भार.रि.बैंक

में 10 प्रतिशत थी, उसमें गिरावट दर्ज की गयी और यह मार्च 2017 के आखिर में 6 प्रतिशत हो गयी (चार्ट 7, टेबल 4)।

III.2 रुपये में मूल्यवर्गित ऋण

जब घरेलू मुद्रा में मूल्यहास होता है, तब मुख्यतया घरेलू मुद्रा में बाह्य ऋण - विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित ऋण के विपरीत - में वास्तविक रूप में कमी आती है। विदेशी मुद्रा में लिए गए बाह्य ऋण पर विदेशों में आने वाले वित्तीय संकटों का कुप्रभाव पड़ने का जोखिम अपेक्षाकृत अधिक रहता है, जैसा कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर आए वित्तीय संकटों के निरीक्षण से यह देखने को मिला है, स्थानीय मुद्रा के मूल्य में सहसा आए परिवर्तन से उधारकर्ता अर्थव्यवस्था के तुलन-पत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार उत्पन्न मौद्रिक जोखिम के क्रेडिट जोखिम में बदल जाने की संभावना रहती है। भारत

टेबल 4: उधारकर्ता-वार बाह्य ऋण: चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर

घटक	प्रतिशत	
	1998-2008	2009-17
गैर-सरकारी वित्तीय क्षेत्र (दीर्घावधि)	9.8	14.9
गैर-सरकारी गैर-वित्तीय निजी क्षेत्र (दीर्घावधि)	1.2	10.8
गैर-सरकारी गैर-वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र (दीर्घावधि)	17.2	7.0
गैर-सरकारी (अल्पावधि)	24.5	9.5
सरकारी ऋण (दीर्घावधि + अल्पावधि)	2.2	7.0
कुल बाह्य ऋण	9.0	9.7

स्रोत : भारत सरकार और भार.रि.बैंक

⁵ ईसीबी अनुमोदनों को और अधिक उदार बनाने के उद्देश्य से सितंबर 2000 में सरकार ने अपनी 01 सितंबर 2000 की प्रेस विज्ञप्ति एफ.नं.4(32)-2000 ईसीबी जारी करते हुए 50 मिलियन यूएस डालर तक के नये ईसीबी अनुमोदनों तथा मौजूदा सभी ईसीबी के पुनर्वित्तपोषण हेतु स्वचालित मार्ग प्रारंभ करने का निर्णय लिया [ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.10(5 सितंबर 2000)].

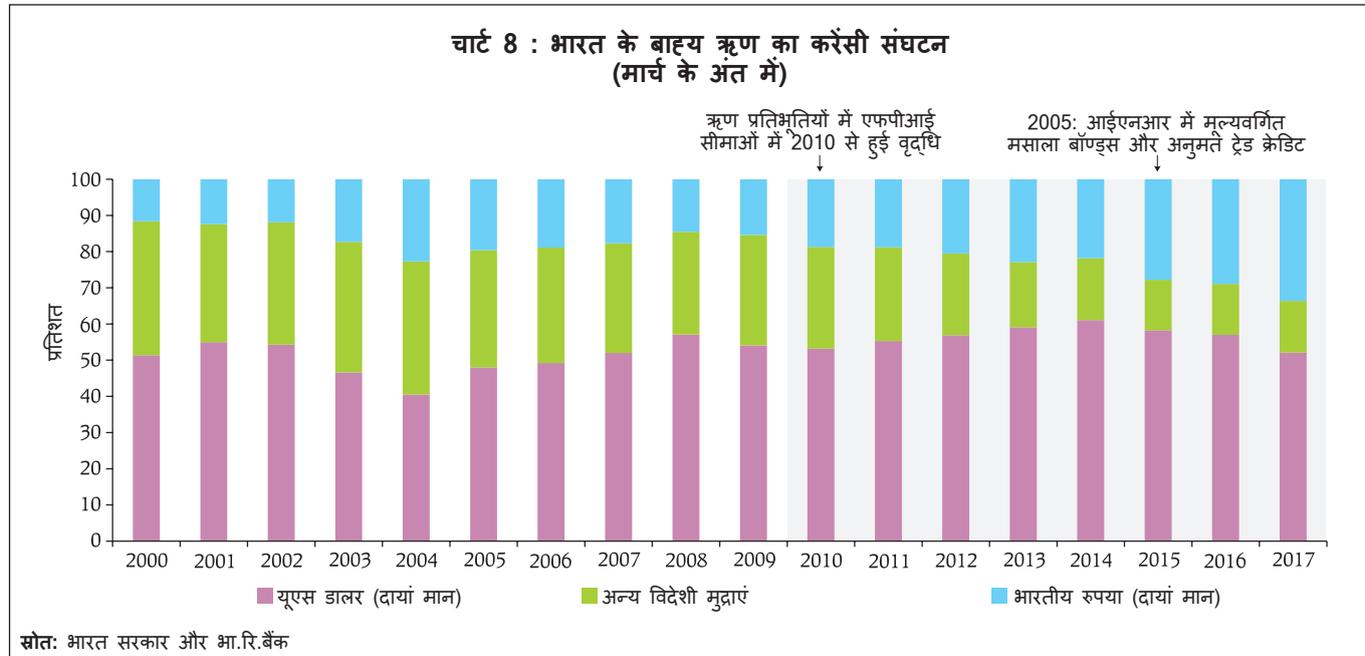
सितंबर 2002 में अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दरों में होने वाली कमी से होने वाले लाभ को प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए समय-पूर्व चुकोती के रूप में कॉर्पोरेटों को छूट प्रदान की गयी। [ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.22(17 सितंबर 2002)].

जनवरी 2003 में ईसीबी की उगाही करने वाले कॉर्पोरेटों को कुछ शर्तों के अधीन विदेशों में स्थित बैंक खातों में निधियां जमा रखने की अनुमति दी गयी ताकि विदेशी मुद्रा संबंधी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वे इनका उपयोग कर सकें। [ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.70(13 जनवरी 2003)].

फरवरी 2004 में, भारतीय कॉर्पोरेटों को ओवरसीज़ प्रत्यक्ष निवेश की सुविधा देते हुए उन्हें वैश्विक स्तर पर व्यापार करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से ईसीबी के अनुमति प्राप्त अंतिम उपभोग की परिधि में विस्तार करते हुए इसके अंतर्गत संयुक्त उद्यमों (जीवी)/पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक संस्थाओं(डब्ल्यूओएस) में किए गए ओवरसीज़ प्रत्यक्ष निवेश को भी शामिल कर लिया गया। [ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.75].

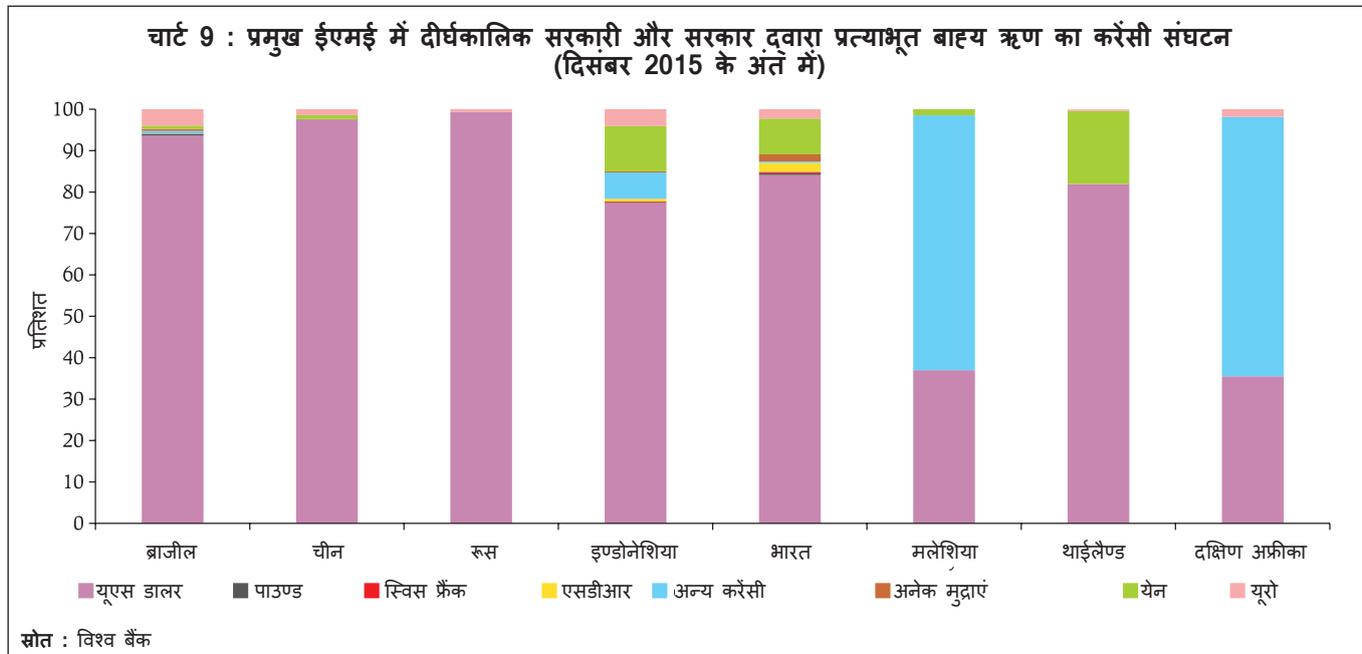
आधारिक संरचना से जुड़ी परियोजनाओं को पट्टे पर उपलब्ध कराने के लिए आधारिक संरचना उपकरणों के आयात के वित्तपोषण हेतु गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बहुआयामी वित्तीय संस्थानों, प्रतिष्ठित क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों आदि से लिए गए न्यूनतम 5 वर्ष की परिपक्वता वाले ईसीबी को 01 अगस्त 2005 से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत माना जाए [आरबीआई/2005-06/87/ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.5].

नवंबर 2005 में, मल्टी-फाइबर करार को हटाये जाने के बाद भारतीय वस्त्र उद्योग में प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता विस्तार को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बैंकों को यह अनुमति दी गयी कि वे गारंटियां, आपाती साख पत्र, वचन-पत्र अथवा टेक्सटाइल कंपनियों द्वारा उनकी टेक्सटाइल इकाइयों के आधुनिकीकरण और विस्तार के उद्देश्य से लिए गए ईसीबी के मामलों में चुकोती आश्वासन-पत्र जारी कर सकें [आरबीआई/2005-06/197/ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.15].



के संदर्भ में देखें तो बाह्य ऋण अभी भी मुख्यतया विदेशी मुद्रा आधारित ही है, हालांकि हाल के वर्षों में रुपये में मूल्यवर्गित ऋण की हिस्सेदारी धीरे-धीरे बढ़ी है (चार्ट 8)। जहां तक भारत में सरकारी और सरकार द्वारा प्रत्याभूत दीर्घावधि बाह्य ऋण का प्रश्न है, यह मुख्यतया यूएस डालर में होता है (चार्ट 9)।

आईएनआर में मूल्यवर्गित ऋण में हुई वृद्धि बहुतायत में जीएफसी-संकट के बाद की अवधि में दिखायी पड़ती है क्योंकि ऋण संविभाग - जी-सेक और कॉर्पोरेट बाण्ड - में एफपीआई के लिए निवेश सीमा धीरे-धीरे बढ़ा दी गयी (परिशिष्ट 1)। इसके अलावा, अपेक्षाकृत कम मुद्रास्फीति, आईएनआर के मूल्य में स्थिरता और प्रतिलाभ में हुए



⁶ हाल के दिनों में किए गए अन्य नीतिगत उपायों में दूसरी बातों के साथ-साथ एफपीआई को फरवरी 2017 के दौरान गैर-सूचीबद्ध कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों एवं प्रतिभूतकृत ऋण लिखतों में निवेश की अनुमति भी शामिल है।

सकारात्मक परिवर्तनों के चलते विदेशी निवेशक भारतीय रुपये में ऋण की ओर आकर्षित हुए। हाल के वर्षों में कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार में आया उछाल भी बढ़ी हुई पारदर्शिता और मूल्य निर्धारण में आयी सुगमता के चलते था (सेबी, 2017)। सितंबर 2015 में निवासी आयातकों को यह अनुमति दी गयी कि वे निर्धारित फ्रेमवर्क के अंतर्गत ओवरसीज उधारदाताओं के साथ एक ऋण करार करते हुए आईएनआर में ट्रेड क्रेडिट

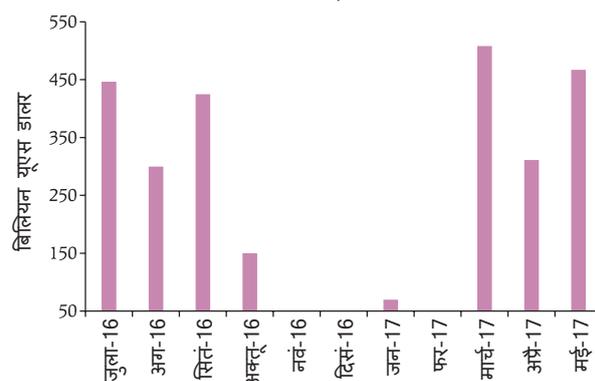
ले सकते हैं। इसी प्रकार पात्र घरेलू इकाइयों को भी आईएनआर में मूल्यवर्गित ईसीबी/बॉण्ड, जहाँ कि करेंसी जोखिम उधारदाताओं द्वारा वहन किया जाता हो, के जरिए उगाही की अनुमति दी गयी है (बॉक्स I)। इन उपायों का प्रभाव यह हुआ कि रुपये में मूल्यवर्गित ऋण की हिस्सेदारी मार्च 2000 के अंत के 11.6% से बढ़कर मार्च 2017 के आखिर में 33.6% हो गयी।

बॉक्स I : मसाला बॉण्ड

मसाला बॉण्ड हाल के वर्षों में भारतीय निवासी इकाइयों के लिए ओवरसीज उधारी के लोकप्रिय लिखतों में से एक बन गया है। रिज़र्व बैंक द्वारा सितंबर 2015 में ईसीबी नीति के संशोधन के पूर्व देश की आधारीक संरचना के विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराने हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और एशियाई विकास बैंक को अनुमति दी गयी थी कि वे ओवरसीज बाजार में रुपये में मूल्यवर्गित बॉण्ड जारी कर सकें। संशोधित नीति के तहत भारतीय कॉर्पोरेटों, स्थावर संपदा निवेश न्यासों (रिट्स) और आधारीक संरचना निवेश न्यासों (इनवित्स) को ओवरसीज मसाला बॉण्ड जारी करने की अनुमति दे दी गयी है। नवंबर 2016 में रिज़र्व बैंक ने भारतीय बैंकों को भी मसाला बॉण्डों के ज़रिए पूंजी/दीर्घावधि निधि की उगाही करने की अनुमति दी। फरवरी 2017 में बहुपक्षीय और क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों को रुपये में मूल्यवर्गित बॉण्डों (आरडीबी) में निवेश करने की अनुमति दी गयी और ओवरसीज निवेशकों द्वारा रुपये में ऋण की मांग बढ़ने का यह भी एक कारण रहा होगा। समष्टिगत दृष्टिकोण से देखें तो कॉर्पोरेट ऋण में विदेशी निवेश के प्रयोजन से अभी तक आरडीबी का निर्गम आईएनआर 2443.23 बिलियन की कुल सीमा के भीतर ही माना जाता रहा है। तथापि, 3 अक्टूबर 2017 से एफपीआई द्वारा कॉर्पोरेट बॉण्डों में निवेश के लिए आरडीबी के निर्गमों को इस सीमा से छूट दी गयी है।

चूंकि मसाला बॉण्ड आईएनआर में मूल्यवर्गित होते हैं, अतः जारी करने वाले के लिए इसमें निहित करेंसी जोखिम का निराकरण हो जाता है। भारतीय मसाला बॉण्ड जारीकर्ताओं के लिए लंदन स्टॉक एक्सचेंज (एलएसई) सबसे लोकप्रिय बाजार बन गया है और इसके बाद क्रमशः सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज (एसजीएक्स) और स्टॉक एक्सचेंज ऑफ मॉरिशस (एसईएम) का स्थान आता है। मसाला बॉण्ड का प्रथम भारतीय जारीकर्ता हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनांस कॉर्पोरेशन (एचडीएफसी) लिमि. था और यह जुलाई 2016 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर जारी किया गया। उसके बाद जुलाई 2016 से जुलाई 2017 के बीच भारतीय निवासी इकाइयों ने लगभग 2.7 बिलियन यूएस डालर मूल्य के मसाला बॉण्ड ओवरसीज पूंजी बाजारों में जारी/सूचीबद्ध किए हैं जिनकी कूपन दर 6.88 प्रतिशत से 9.05 प्रतिशत तक थी (चार्ट ए)। वर्ष 2016-17 में आरडीबी - दोनों, निजी

चार्ट ए : ओवरसीज पूंजी बाजार में भारतीय निवासी इकाइयों द्वारा जारी/ सूचीबद्ध मसाला बॉण्ड (राशि मिलियन यूएस डालर में)



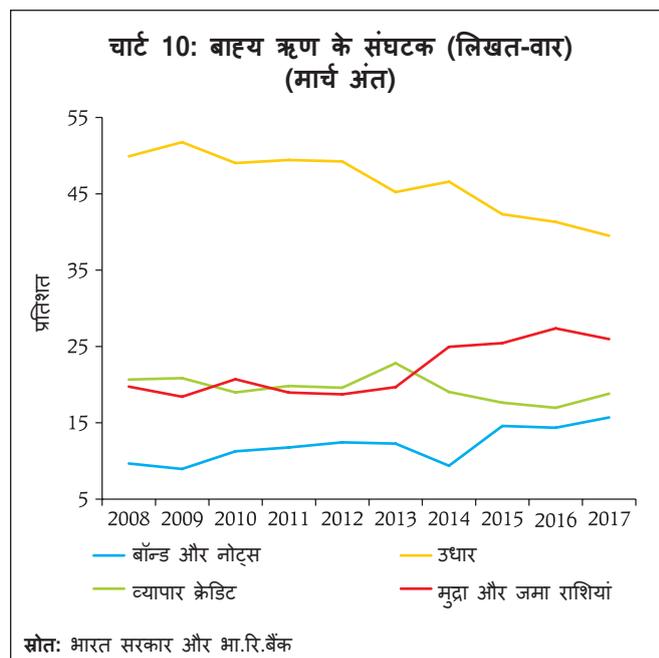
नोट: नवंबर और दिसंबर 2016 में एवं फरवरी, जून तथा जुलाई 2017 में ओवरसीज पूंजी बाजार में भारतीय निवासी इकाइयों द्वारा जारी मसाला बॉण्ड्स की संख्या 'शून्य' थी।
स्रोत: एलएसई, एसजीएक्स तथा एसईएम

तौर पर जारी किए गए और ओवरसीज स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किए गए - का मूल्य 3.5 बिलियन यूएस डालर था।

ओवरसीज बाजार में आईएनआर में मूल्यवर्गित बॉण्ड (मसाला बॉण्ड) जारी करने के फ्रेमवर्क की समीक्षा की दृष्टि से और ईसीबी फ्रेमवर्क के विभिन्न तत्वों को सुसंगत बनाने के उद्देश्य से जून 2017 में रिज़र्व बैंक द्वारा निर्णय लिया गया कि (i) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आईएनआर 50 मिलियन यूएस डालर के समतुल्य में राशि जुटाने वाले मसाला बॉण्डों के लिए न्यूनतम मूल परिपक्वता अवधि 3 वर्ष होगी और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आईएनआर 50 मिलियन यूएस डालर से अधिक राशि के समतुल्य राशि जुटाने वाले मसाला बॉण्डों के लिए यह 5 वर्ष होगी; (ii) इस प्रकार के बॉण्डों के लिए समग्र लागत (ऑल-इन-कॉस्ट) सीमा भारत सरकार की समतुल्य परिपक्वता अवधि वाली प्रतिभूतियों के तत्कालीन प्रतिलाभ से 300 आधार अंक अधिक होगी; और (iii) निवेशक के रूप में अनुमति प्राप्त इकाइयां इंडिया-एएस-24 में उल्लिखित आशय के तहत संबंधित पार्टि नहीं होनी चाहिए।

III.3 भारत के बाह्य ऋण का लिखत-वार वर्गीकरण

हाल के वर्षों में बाह्य ऋण की लिखत-वार आकृति में भी परिवर्तन हुआ है। संकट-के बाद की अवधि में जहां बॉण्डों और नोट्स जैसी बाजार आधारित लिखतों के जरिए जुटाई जाने वाली पूंजी में सतत वृद्धि हुई है जबकि, 'कर्ज' की हिस्सेदारी मार्च 2008 के अंत के 50 प्रतिशत से कम होकर मार्च 2017 के अंत में 40 प्रतिशत हो गई। फिर भी, अधिकतर बाह्य ऋण कर्ज के रूप में उठाया जाता रहा है। भारत के बाह्य ऋण में दूसरी सबसे बड़ी लिखत 'मुद्रा और जमा राशियां' है जिनमें सितंबर 2013 में रिज़र्व बैंक द्वारा एफसीएनआर(बी) डॉलर के लिए स्वैप सुविधा लागू करने के बाद सितंबर-नवंबर 2013 के दौरान काफी उल्लेखनीय तेजी देखने को मिली थी, जिसके परिणामस्वरूप इसकी भागीदारी मार्च 2013 के अंत के 20 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2014 के अंत में 25 प्रतिशत हो गई। 2016-17 में एफसीएनआर(बी) जमा राशियों का स्थूल मोचन होने के बावजूद यह बाह्य ऋण का एक चौथाई से अधिक बना हुआ है। मार्च 2013 के अंत से व्यापारिक उधार की कम होती हिस्सेदारी आयात गतिविधियों में धीमापन प्रदर्शित करती है (चार्ट 10)।



IV. बाह्य ऋण व्यवहार्यता और संवेदनशीलता संकेतक

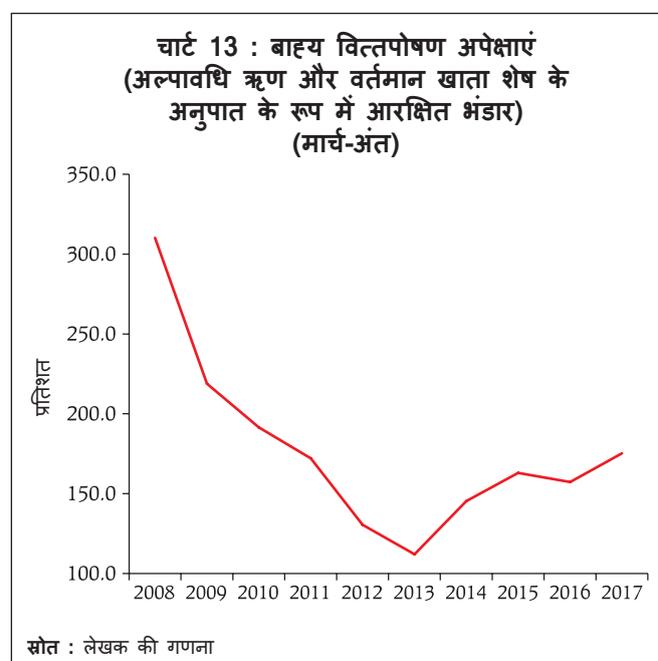
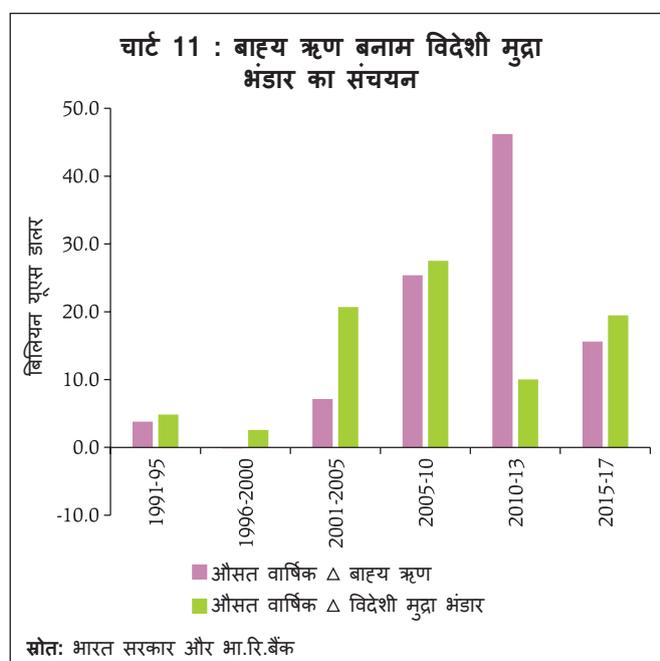
बाह्य ऋण आधारित संकेतक अर्थव्यवस्था की बाह्य संवेदनशीलता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होते हैं। परंपरागत रूप से बाह्य ऋण का मूल्यांकन इसके परिपक्वता ढांचे, आरक्षित निधि पर्याप्तता और इस उद्देश्य के लिए ऋण चुकौती के संदर्भ में किया जाता है।

IV.1 बाह्य ऋण का परिपक्वता ढांचा

वैश्विक वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल की अवधि के दौरान जिन देशों का उच्च एकसपोज़र अल्पावधि बाह्य ऋण में होता है उन्हें रोल-ओवर जोखिम का खतरा होता है, विशेष रूप से यदि उनका घरेलू आधार कमजोर हो तो। इस प्रकार के जोखिमों को नापने के लिए परंपरागत संकेतक इस प्रकार हैं, (i) कुल बाह्य ऋण में अल्पावधि ऋण की हिस्सेदारी; और (ii) अल्पावधि ऋण के प्रति आरक्षित निधियां। 1990 के दौरान जैसे-जैसे बाह्य ऋण की संचयन दर में कमी आई, वैसे-वैसे वास्तविक परिपक्वता अवधि के संदर्भ में अल्पावधि बाह्य ऋण की हिस्सेदारी में भी कमी आई जो 2003-04 तक लगभग 4 प्रतिशत के करीब आ गई जो कि मार्च 1991 के अंत के स्तर की तुलना में लगभग आधी थी। बाद के वर्षों में यद्यपि इसमें इजाफा हुआ परंतु इसका मुख्य कारण आयातों में हुई तीव्र वृद्धि के कारण व्यापारिक उधार स्तर ऊंचा होना था। अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर अल्पावधि ऋण की गणना वास्तव में कहीं अधिक प्रचलित संकेतक है क्योंकि यह वास्तविक ऋण चुकौती भुगतानों पर आधारित होता है और इस प्रकार, यह आगामी बारह महीनों में विदेशी मुद्रा के संभावित बहिर्वाह पर निगरानी रखने में मदद प्रदान करता है।

IV.2 आरक्षित कोष

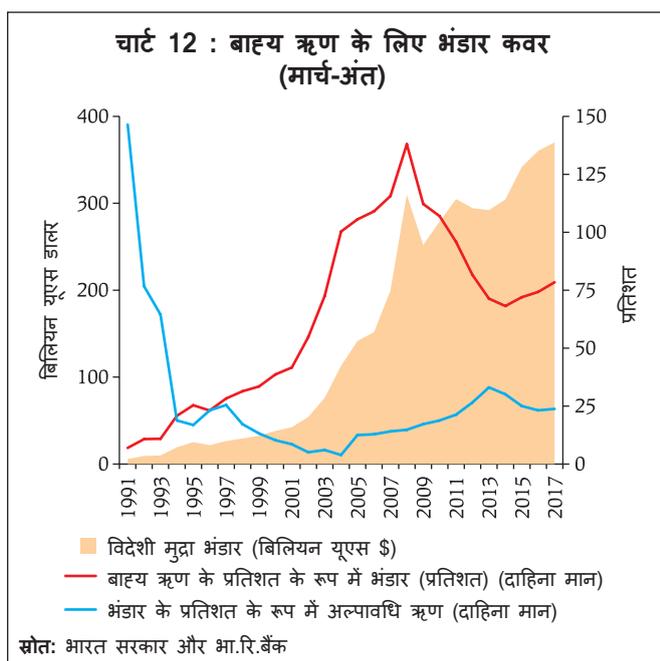
बाह्य ऋण के लिए आरक्षित कोष मार्च 1991 के अंत के 7 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2008 के अंत में 138 प्रतिशत हो गया (चार्ट 11)। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की अवधि में बाह्य ऋण में तीव्र वृद्धि हुई और आरक्षित कोष गिरकर मार्च 2014 के अंत में 68 प्रतिशत रह गया। तथापि, अगले तीन वर्षों में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि के निवल एकत्रण में सुधार हुआ और यह मार्च 2017 के अंत में 78.4 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया जो ऋण चुकौती क्षमता की दिशा में वृद्धिशील है। एक अन्य संकेतक- जिसे अनुभवजन्य साहित्य



में एक महत्वपूर्ण चर के व्यापक मान्यता प्राप्त है, आरक्षित निधि की तुलना में अल्पावधि ऋण का अनुपात है - इसे अक्सर उभरते बाजारों में विनिमय बाजार दबावों की पूर्व चेतावनी के रूप में संदर्भित किया जाता है (उदा., आईएमएफ, 2000; और आईजेनमैन और हचिन्सन, 2010) (चार्ट 12)। वस्तुतः मार्च 2017 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार अवशिष्ट परिपक्वता आधार पर परिकल्पित अल्पावधि ऋण दायित्वों की तुलना में लगभग दोगुने के स्तर पर था। इसका अर्थ यह है कि आरक्षित निधि आईएमएफ (2000) द्वारा परंपरागत रूप

से संस्तुत युनिटी अनुपात की तुलना में कहीं अधिक थी, जिसे पूंजी बाजारों तक उल्लेखनीय परंतु अनिश्चित पहुंच रखने वाले देशों हेतु आरक्षित निधि पर्याप्तता विश्लेषण के लिए एक प्रारंभिक बिंदु माना जाता है।

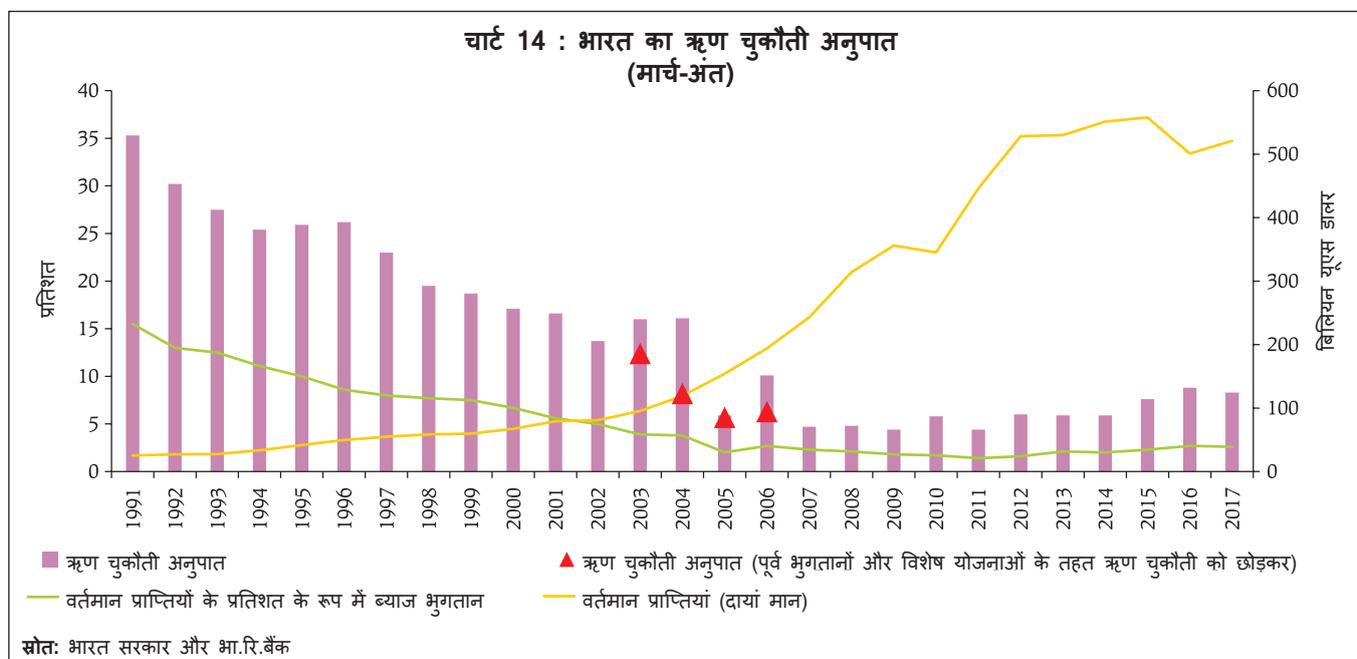
इसके अतिरिक्त, ऋण की परेशानी वाले चरणों के पूर्व खास तौर पर अल्पावधि बाह्य ऋण (अवशिष्ट परिपक्वता) और चालू खाता घाटे में वृद्धि हो जाती है जिससे मौजूदा विदेशी मुद्रा भंडारों पर दबाव बढ़ जाता है। इस पैमाने के द्वारा भी हाल के वर्षों में एक काफी सुधार आया है। मार्च 2017 के अंत की स्थिति के अनुसार, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार इसकी बाह्य वित्तीय आवश्यकताओं के लगभग 175 प्रतिशत के स्तर पर थे जो कि टेपरिंग की बात-चीत के दौर की तुलना में कहीं अधिक थे (चार्ट 13)।



IV.3 ऋण चुकौती अनुपात 1990 के दशक की तुलना में कहीं अधिक बेहतर रहा

एक अन्य संकेतक जो ऋण संबंधी जोखिमों को दर्शाता और सामान्य तौर पर उसका प्रयोग किया जाता है वह है ऋण चुकौती अनुपात जिसे वर्तमान प्राप्तियों⁷ के अनुपात के रूप में सकल ऋण चुकौती भुगतानों के रूप में परिभाषित किया गया है। सामान्य तौर पर, 1990-91 से भारत का ऋण चुकौती अनुपात अधोगामी रहा है केवल उन वर्षों को छोड़कर जहां

⁷ आईएमएफ ऋण चुकौती अनुपात को किसी एक वर्ष के लिए निर्यात की गई सामग्री और सेवाओं की तुलना में दीर्घावधि और अल्पावधि में बाह्य ऋण चुकौती के संबंध में चुकाए गए मूलधन और ब्याज भुगतानों के अनुपात के रूप में परिभाषित करता है (एक्सटर्नल डेट स्टैटिस्टिक्स : गाइड फॉर कंपाइलर्स एंड यूजर्स, 2003)।



बाह्य ऋण के समय-पूर्व भुगतानों या विशेष योजनाओं, जैसे कि रीसर्जेंट इंडिया बॉण्ड और इंडिया मिलेनियम जमा, के मोचन के कारण स्थूल चुकौतियां की गईं। इसके अलावा, वर्तमान प्राप्ति - जो अर्थव्यवस्था की ऋण चुकौती क्षमता को प्रदर्शित करती हैं - में भी 1999-2000 से 2011-12 के दौरान कई गुना वृद्धि दर्ज की गई और इस अवधि के दौरान इसने ऋण चुकौती अनुपात को सीमित रखने में मदद प्रदान की। 2014-15 और 2015-16 में वर्तमान प्राप्ति में कमी आने और /या ईसीबी के मोचन के कारण उच्चतर भुगतान होने से ऋण चुकौती अनुपात में थोड़ी वृद्धि दर्ज की गई। तथापि, 2016-17 में मुख्यतः वर्तमान प्राप्ति में वृद्धि होने से ऋण चुकौती अनुपात में सुधार आया (चार्ट 14)।

ऋण व्यवहार्यता के परिप्रेक्ष्य से, ऋण ग्रस्तता के विविध पैमानों का उपयोग शोधन क्षमता और चलनिधि जोखिम का पता लगाने के लिए किया जाता है। भारत के मामले में, ऐतिहासिक विश्लेषण यह दर्शाते हैं कि वार्षिक ऋण चुकौती भुगतानों के प्रति बाह्य ऋण के स्टॉक में एकांगी संबंध रहा है। तथापि, इस प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है जब अर्थव्यवस्था के आकार (बाह्य ऋण-जीडीपी अनुपात) के कारण बाह्य ऋण सामान्य हो गया हो और जबकि ऋण चुकौती भुगतानों को चुकौती क्षमता के रूप में मापा जाता है (बॉक्स II)। दूसरे शब्दों में विश्लेषण यह बताता है कि किसी प्रकार के 'पॉजी वित्तपोषण' के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं जहां विदेशी उधारियों को पूर्ववर्ती

बॉक्स II: भारत के बाह्य ऋण और ऋण चुकौती भुगतानों के बीच संबंध

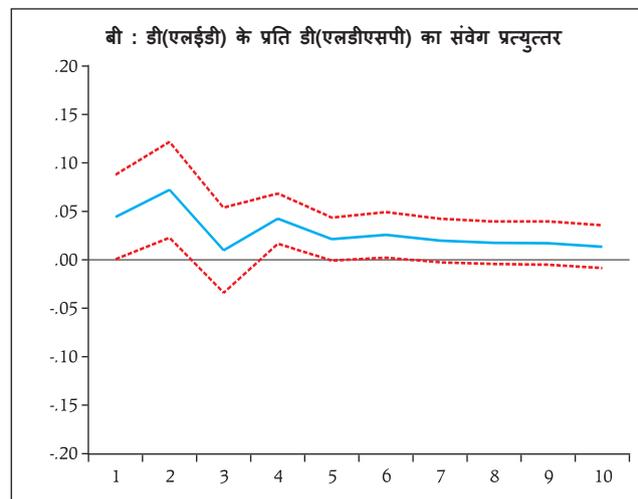
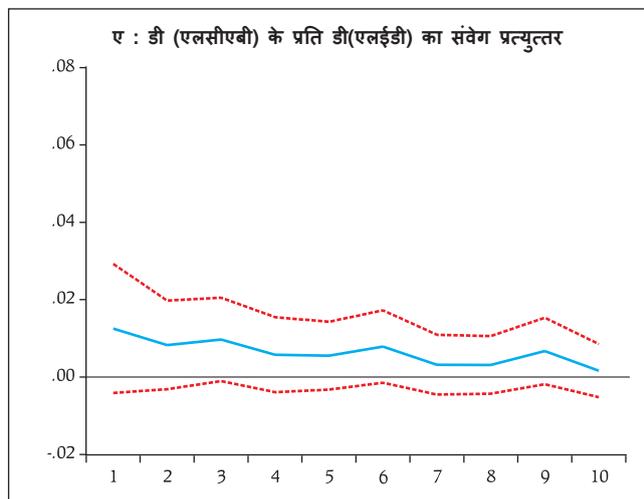
किसी अर्थव्यवस्था के बाह्य ऋण भार से संबंधित जोखिम को सामान्य तौर पर अर्थव्यवस्था की ऋण चुकौती क्षमता के प्रति मूल्यांकित किया जाता है। 'डेट ओवरहेंग' (अत्यधिक ऋण) संबंधी साहित्य इस बात को रेखांकित करते हैं कि वृहत्तर ऋण घरेलू संवृद्धि को प्रभावित करते हैं क्योंकि संभावित ऋण चुकौती लागत घरेलू और विदेशी निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है (करुगमैन, 1988 और सैक्श, 1089)। ऋण चुकौती अनुपात संसाधनों पर भारी दबाव डालने की क्षमता रखते हैं और भुगतान कठिनाइयों और परेशानी का जोखिम उनसे जुड़ा

हुआ होता है। आईएमएफ के अनुसार, एक कम और स्थिर ऋण चुकौती अनुपात का अर्थ यह होता है कि बाह्य ऋणों का मौजूदा स्तर वहनीय है। अन्य अध्ययनों की अनुभवजन्य पद्धति के अनुसरण करने से कारण कार्य-संबंधों की दिशा का सत्यापन होता है जिसके लिए 1970 से 2016 की अवधि तक के वार्षिक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है।

दोनों श्रृंखलाओं में इकाई मूल के उपस्थिति के परिप्रेक्ष्य में (अनुबंध II और III)⁸ सभी चरों को उनके लघुगणकीय मूल्यों

(जारी...)

⁸ तथापि, संदर्भ हेतु इकाई मूल की जांच के लिए केवल संवर्द्धित डिक्ली फुलर परीक्षण के परिणाम लिए गए हैं जिन्हें अनुबंध II और III में दिया गया है।



के पहले अंतर के रूप में लिया गया है। पहले एक वेक्टर स्वचालित समाश्रयण (वीएआर) कर अनुमान लगाया गया और संवेग सुझाव दर्शाते हैं कि यद्यपि बाह्य ऋण (ईडी) चालू खाता संतुलन (सीएबी) में आघातों के प्रति सकारात्मक उत्तर प्रदान करता है, परंतु इसका प्रभाव सांख्यिकीय रूप से उल्लेखनीय नहीं है। तथापि, ऋण चुकौती भुगतान (डीएसपी) बाह्य ऋण में सकारात्मक आघात के साथ बढ़ते हैं और सांख्यिकीय रूप से इसका उल्लेखनीय प्रभाव दो वर्षों तक रहता है (चार्ट ए और बी)। अन्य सभी संवेग उत्तर सांख्यिकीय रूप से उल्लेखनीय नहीं पाए गए और इसलिए उन्हें रिपोर्ट नहीं किया गया।

डी(एलईडी) के मौजूदा मान और डी(एलडीएसपी) के पुराने मानों के बीच सह-संबंध निश्चित करने और इसका विपरीत सिद्ध करने के उद्देश्य से गैंगर कारण-कार्य-संबंध की भी जांच की गई (सारणी II.1)।

परिणाम यह दर्शाते हैं कि भारत के बाह्य ऋण और ऋण चुकौती के बीच कारण-कार्य-संबंध संरेखीय है अर्थात् बाह्य ऋण गैंगर ऋण चुकौती भुगतानों को उत्पन्न करता है और ऋण चुकौती भुगतानों से बाह्य ऋण की दिशा में कोई 'विपरीत कार्य-कारण' नहीं है, जिसका अर्थ यह हुआ कि उच्चतर बाह्य ऋण के साथ ऋण चुकौती बोझ बढ़ता है। तथापि, जब अर्थव्यवस्था के आकार के कारण (अर्थात् बाह्य ऋण-जीडीपी अनुपात) बाह्य ऋण सामान्य हो जाता है और भुगतान क्षमता (वर्तमान क्षमता) के संदर्भ में ऋण चुकौती भुगतानों को मापा जाता है तो किसी भी दिशा में गैंगर कारण-कार्य-सिद्धांत का संचरण नहीं होता है (सारणी II.2)। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि बाह्य ऋण तब तक प्रबंधकीय होता है जब तक कि तदनुसूची चुकौती क्षमता बढ़ती है। इस प्रकार के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं कि ऋण चक्र में बढ़ते हुए ऋण स्तर और ऋण चुकौती भुगतान अवहनीय हो गए हों और परिणामस्वरूप ऋण चूक हो गई हो।

सारणी II.1 : बाह्य ऋण और ऋण चुकौती भुगतानों के बीच गैंगर कारण-कार्य-संबंध

कारण-कार्य संबंध की दिशा एच ₀	लैंग की संख्या	एफ-सांख्यिकी	प्रायिकता	परिणाम
डी(एलईडी) के कारण गैंगर कारण डी (एलडीएसपी) नहीं है	2	3.80	0.03	अस्वीकार्य
डी (एलडीएसपी) के कारण गैंगर कारण डी(एलईडी) नहीं है	2	0.94	0.40	अस्वीकार्य नहीं

नोट: डी(एलईडी) लॉग रूप में बाह्य ऋण का पहला अंतर है और डी(डीएसपी) लॉग रूप में ऋण चुकौती भुगतानों का पहला अंतर है।

सारणी II.2 : बाह्य ऋण-जीडीपी अनुपात और ऋण चुकौती अनुपात के बीच गैंगर कारण-कार्य-संबंध

कारण-कार्य संबंध की दिशा एच ₀	लैंग की संख्या	एफ-सांख्यिकी	प्रायिकता	परिणाम
डी(ईडीआर) के कारण गैंगर कारण डी (डीएसपीआर) नहीं है	2	0.86	0.48	अस्वीकार्य नहीं
डी(डीएसपीआर) के कारण गैंगर कारण डी(ईडीआर) नहीं है	2	0.64	0.60	अस्वीकार्य नहीं

नोट: वर्तमान प्राप्तियों के अनुपात के रूप में डी(ईडीआर) बाह्य ऋण-जीडीपी अनुपात का पहला अंतर और डी(डीएसपीआर) ऋण चुकौती भुगतानों का पहला अंतर है।

उधारियों की चुकौती करने के लिए उठाया गया हो जैसा कि 1990 के दशक में कुछ लातिन अमेरिकी देशों द्वारा किया गया था।

V. देशी-विदेशी परिप्रेक्ष्य

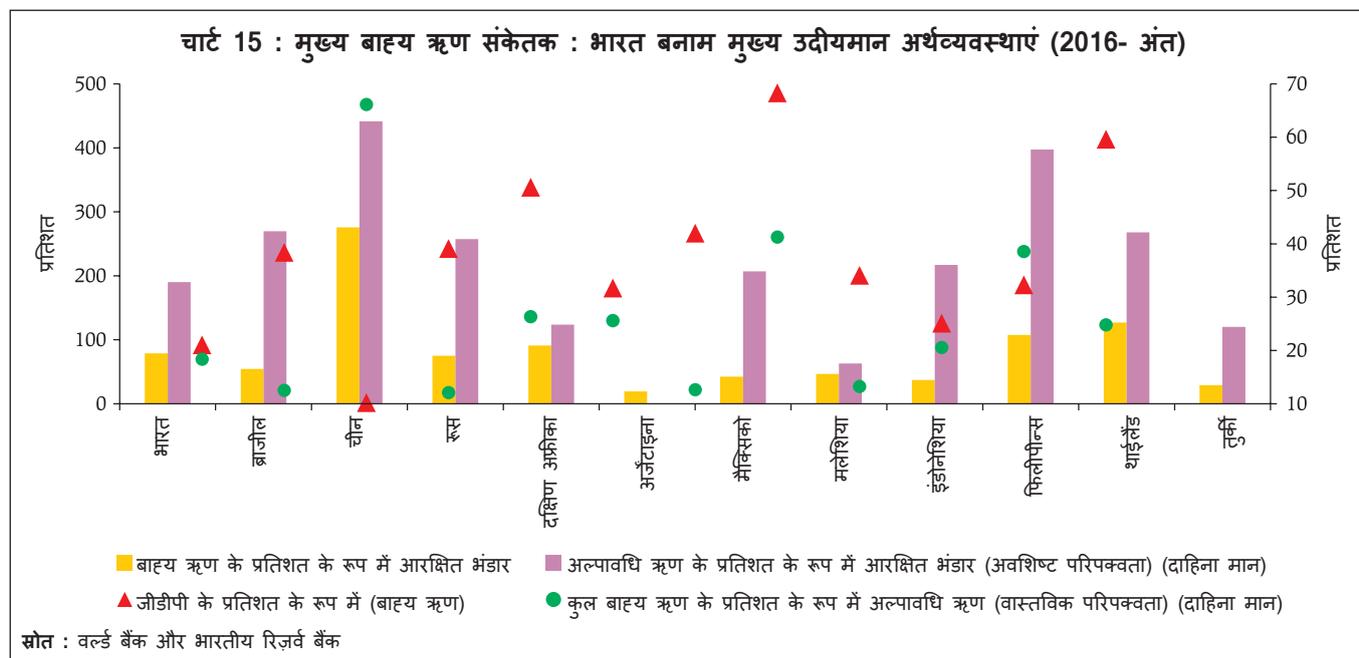
2016 के अंत में मौजूद स्टॉक के संदर्भ में भारत सर्वाधिक बाह्य ऋणग्रस्त उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्था ईएमई था- यह चीन, ब्राजील और रूस के बाद चौथा सर्वाधिक बाह्य ऋण ग्रस्त देश था। तथापि, जीडीपी अनुपात की तुलना में बाह्य ऋण के संदर्भ में भारत की स्थिति संगत रूप से बेहतर है। कुल बाह्य ऋण के लिए आरक्षित निधि के संदर्भ में भारत की रैंक ब्राजील और रूस की तुलना में बेहतर है। इसी प्रकार, भारत के कुल बाह्य ऋण में अल्पावधि ऋण (वास्तविक परिपक्वता) की हिस्सेदारी चीन, मलेशिया, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, तुर्की और फिलीपीन्स की तुलना में बेहतर है। तथापि, अल्पावधि ऋण (अवशिष्ट परिपक्वता) के लिए आरक्षित कोष दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और मलेशिया को छोड़कर अन्य ईएमई की तुलना में कम था (चार्ट 15)।

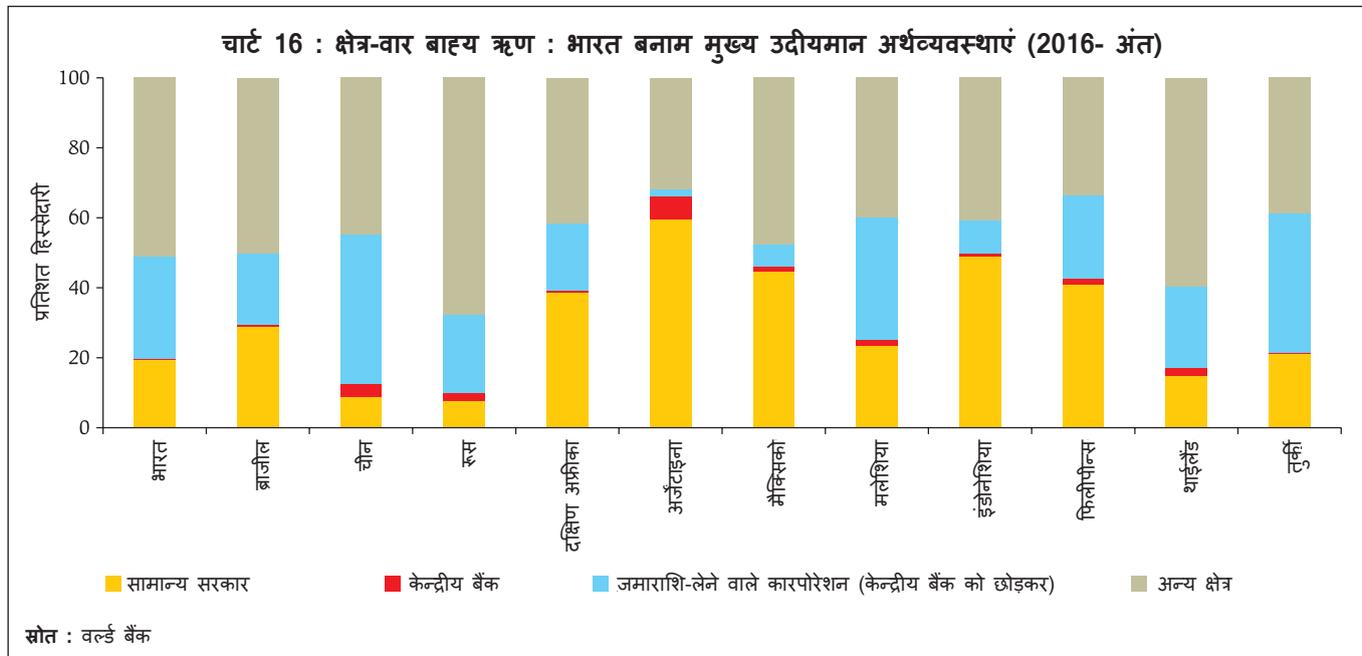
सरकारी (पूर्ण-स्वामित्व) ऋण कुल बाह्य कर्ज का लगभग 20 प्रतिशत है जो अन्य प्रमुख ईएमई जैसे कि अर्जेंटीना (59 प्रतिशत), इंडोनेशिया (49 प्रतिशत), मैक्सिको (45 प्रतिशत), फिलीपीन्स (41 प्रतिशत) और दक्षिण अफ्रीका (39 प्रतिशत) से कम है। भारत में जमाराशि ग्रहण करने वाले कारपोरेशनों (केन्द्रीय बैंक को छोड़कर) की हिस्सेदारी बाह्य

कर्ज में लगभग 29 प्रतिशत है; यह अनुपात चीन (43 प्रतिशत), तुर्की (40 प्रतिशत) और मलेशिया (35 प्रतिशत) के मामले में अधिक है। भारत के संबंध में कुल बाह्य ऋण में गैर-वित्तीय क्षेत्र (अन्य क्षेत्र) की भागीदारी रूस और थाईलैंड की तुलना में कम है (चार्ट 16)।

लिखतों के संदर्भ में, भारत की बाह्य देनदारियां मुख्यतः 'ऋणों' के माध्यम से हैं जो कि 2016 के अंत की स्थिति के अनुसार कुल बकाया देनदारियों के 40 प्रतिशत से अधिक है। मुख्य उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं जहां देनदारियों में 'ऋण' की हिस्सेदारी भारत से अधिक है उनमें फिलीपीन्स, तुर्की, इंडोनेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। प्रमुख उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं में 'मुद्रा और जमा राशियों' में भारत का हिस्सा कुल बाह्य ऋण में सर्वाधिक है जबकि कुल बाह्य ऋण में 'व्यापार क्रेडिट और अग्रिमों' के तहत हिस्सेदारी में चीन के बाद दूसरे नम्बर पर है। ऋण प्रतिभूतियों के जरिए उठाई गई भारत की बाह्य देनदारियां अधिकतर अन्य उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं, जिसमें चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, से कम हैं। फिलीपीन्स, तुर्की, अर्जेंटाइना, रूस, मैक्सिको और ब्राजील की विदेशी मुद्राओं में उठाए गए बाह्य ऋण में हिस्सेदारी भारत से अधिक है (चार्ट 17)।

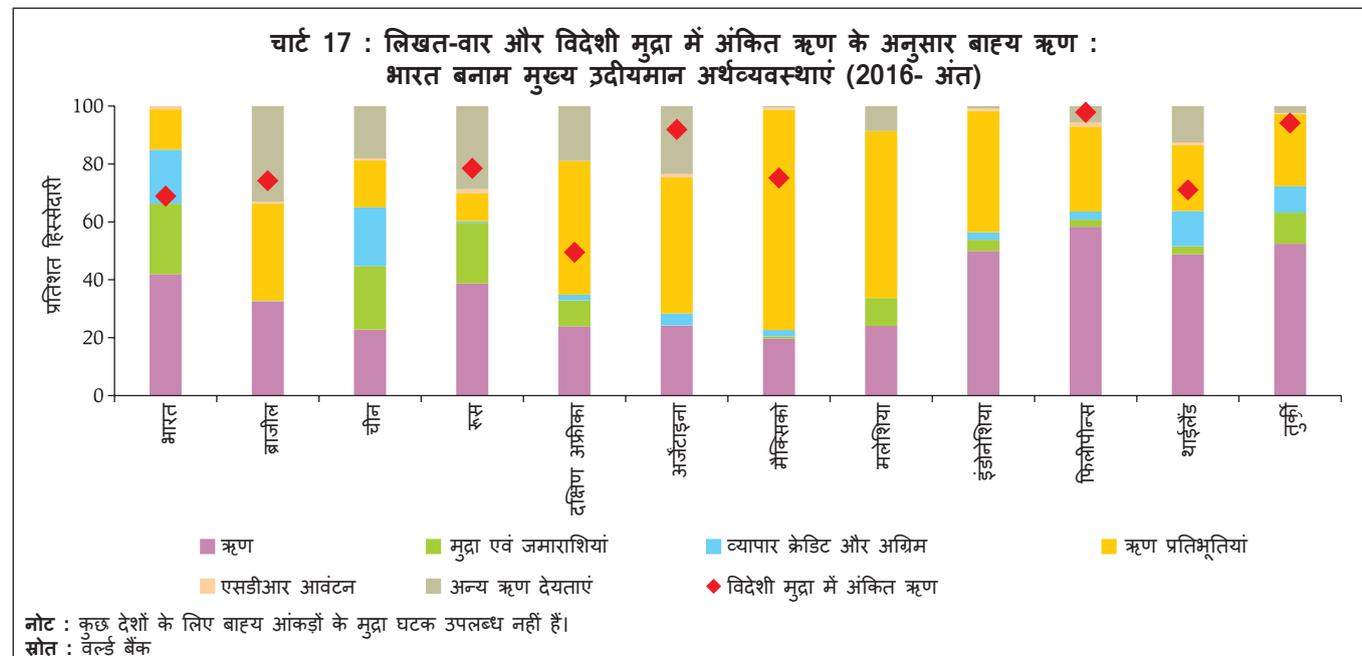
देश-विदेश का तुलनात्मक अध्ययन दर्शाता है कि कई उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं ने हाल के वर्षों में बाह्य



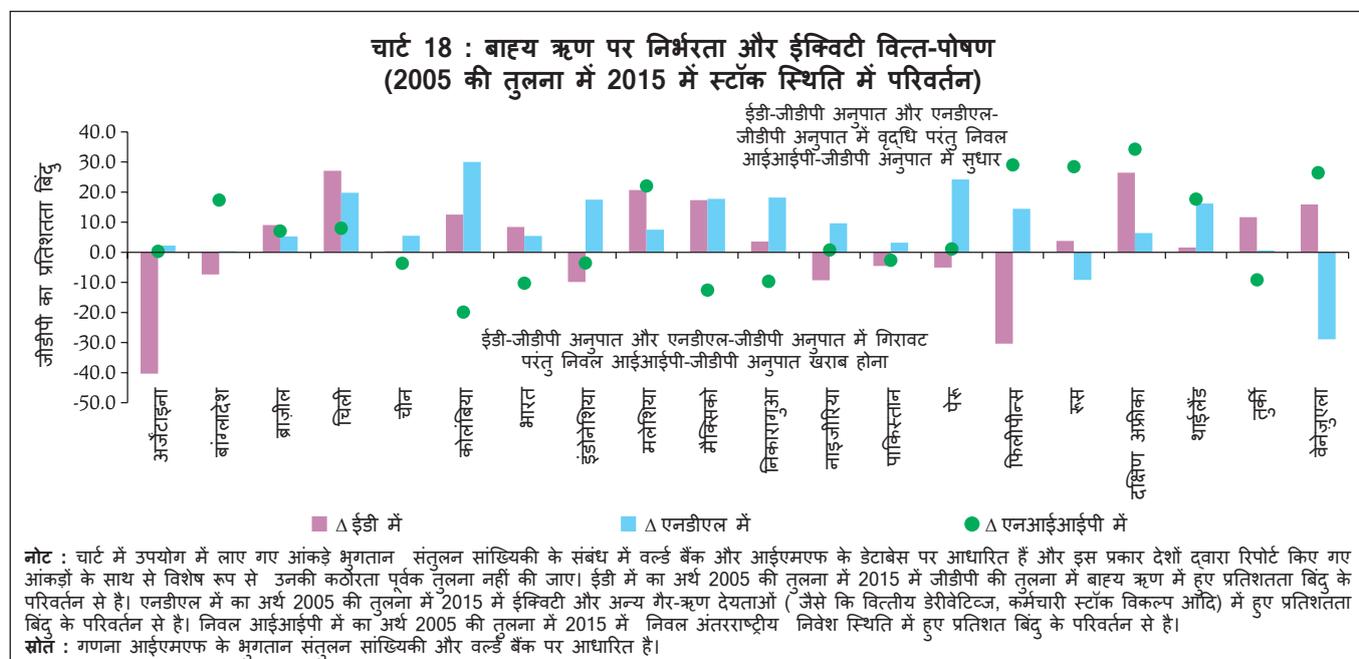


ऋण की तुलना में एक प्रवाह का निर्माण करते हुए गैर-ऋण प्रतिभूतियों पर अपनी निर्भरता बढ़ाई है। तथापि, चीन, अर्जेंटाइना, पेरू, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और फिलीपीन्स के विपरीत 2005-2015 के दौरान गैर-ऋण विदेशी पूंजी की तुलना में बाह्य ऋण(जीडीपी के संदर्भ में मापित) के प्रति भारत के रुझान में वृद्धि हुई है⁹। इसके अतिरिक्त, भारत का

बाह्य आस्तियों का सृजन धीमा रहा है जिसके परिणामस्वरूप संदर्भाधीन अवधि के दौरान अनिवासियों के निवल दावों के रूप में निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति में कमजोरी आई है। कुछ ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं नामतः, ब्राज़ील, चिली, मलेशिया, फिलीपीन्स, दक्षिण अफ्रीका और थाईलैंड जिन्होंने ऋण और /या इक्विटी देयताओं के प्रति रुझान बढ़ने के



⁹ किसी देश की इक्विटी और अन्य ऋण देयताओं के स्टॉक की गणना (एनडीएल) वर्ष के अंत में कुल बाह्य देयताओं से इसके बाह्य ऋण के स्टॉक को घटा कर की गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2005 से भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति को जारी करना प्रारंभ किया।



बावजूद निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थितियों में सुधार किया है।

VI.6 उपसंहार

समाप्ति पर यह कहा जा सकता है कि भारत की बाह्य ऋण स्थिति में 1990 के पूर्वार्ध से उल्लेखनीय परिवर्तन प्रदर्शित हुआ है। जहां भारत पूंजी खाते को छूट प्रदान करने के लिए विवेकपूर्ण रूप से क्रमिक और धीरे-धीरे कार्य करता रहा है फिर भी इसके बाह्य ऋण के आकार और इसकी संघटना में वक्त के साथ विस्तार हुआ है जो कि पनपती हुई आवश्यकताओं और नीतिगत विकल्पों के अनुरूप रहा है। बढ़ता हुआ गैर-सरकारी और छूट-रहित ऋण घरेलू आर्थिक गतिविधि में भारतीय निजी कारपोरेट क्षेत्र की विस्तारित भूमिका का उल्लेख करता है, परंतु क्रेडिट और बाजार जोखिमों के प्रति संवेदनशीलता को भी बढ़ाता है। जैसा कि अनुभवजन्य विश्लेषण बताते हैं यद्यपि भारत के अल्पावधि ऋण में सन् 2000 के मध्य से इजाफा हुआ है तथापि, उसी के अनुरूप विदेशी मुद्रा भंडार में हुई वृद्धि ने बाह्य ऋण के जाल से घरेलू अर्थव्यवस्था को बचाए भी रखा है।

बाह्य ऋण की प्रोफाइल में एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है कि हाल के वर्षों में भारतीय रुपए में अंकित ऋण की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है जिसे सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उठाया गया एक प्रमुख नीतिगत उपाय कहा जा सकता

है और यह भारतीय रुपए में अंकित ऋण के लिए विदेशी निवेशकों के बढ़ते हुए रुझान को भी दर्शाता है। बाह्य ऋण संकेतकों के विविध मानदंडों के अनुसार चीन को छोड़कर भारत अपनी समकक्ष अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर है। फिर भी, गहराते वैश्विक वित्तीय उतार-चढ़ाव के परिप्रेक्ष्य में ऋण आधारित वित्त पोषण पर बढ़ती हुई निर्भरता - विशेष रूप से ऋण प्रवाह- बाह्य संवेदनशीलताओं का निर्माण कर सकती है और इस प्रकार इसकी नियमित निगरानी की जानी अपेक्षित है।

संदर्भ

आइजेनमैन, जोशुआ और माकेल एम. हचिन्सन (2010), 'एक्सचेंज मार्केट प्रेशर एंड एक्सपोज़र बाई इंटरनेशनल रिजर्व्स: इमर्जिंग मार्केट्स एंड फिअर ऑफ लॉस इयूरिंग 2008-09 क्राइसिस', एनबीईआर, वर्किंग पेपर सं. 16260

फटाई, ओ.ओ. (2016), 'कैजुअल नेक्सस बिटवीन एक्सटर्नल डेट एंड इकनॉमिक ग्रोथ: दि नाइजीरियन केस', इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एंड कामर्स इन्नोवेशन, खंड 4, पीपी : 92-98

इंटरनेशनल मॉनीटरी फंड (2000), 'डेट-एंड रिज़र्व रिलेटेड इंडिकेटर्स ऑफ एक्सटर्नल वलनरेबिलिटी', अन्य विभागों के परामर्श के साथ नीति विकास और समीक्षा विभाग बनाया गया, मार्च

इंटरनेशनल मॉनीटरी फंड (2003), "एक्सटर्नल डेट स्टैटिक्स : गाइड फॉर कंपाइलर्स एंड यूजर्स", जून

कुरुगमैन पॉल (1988), "फाइनेंसिंग वर्सेस फॉरगिविंग ए डेट ओवरहेडिंग", जर्नल ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, खंड 29 : 253-268

लिंडनेर, पीटर एंड सुंग इयून जुंग (2014), "कारपोरेट वलनरेबिलिटीज़ इन इंडिया एंड बैंक्स लोन परफार्मेंस", आईएमएफ वर्किंग पेपर सं. 14/232

मैनज़ोची, स्टेफैनो (1997), "एक्सटर्नल फाइनेंस एंड फॉरेन डेट इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़", आईएमएफ वर्किंग पेपर सं. 97/ 134

सैक्श, जेफरी (1989), "दि डेट ओवरहेडिंग आफ डेवलपिंग कंट्रीज़", इन डेट स्टैबलाइजेशन एंड डेवलपमेंट : एसे इन मेमरी ऑफ कार्लोस डिआज़ अलेज़ेन्ड्रो ईडी बाई काल्वो ए. ग्युल्लेरिमो एंड अदर्स (बासिल ब्लैकवेल : ऑक्सफोर्ड), पी. 80-102

भारतीय प्रतिभूति और मुद्रा विनिमय बोर्ड (2017), वार्षिक रिपोर्ट, 2016-17

वर्ल्ड बैंक (2016), अंतरराष्ट्रीय डेट स्टैटिस्टिक्स, वर्ल्ड बैंक ग्रुप

वर्ल्ड बैंक (2017), अंतरराष्ट्रीय डेट स्टैटिस्टिक्स, वर्ल्ड बैंक ग्रुप

अनुबंध 1 : भारतीय ऋण बाजार में भागीदारी के लिए एफपीआई हेतु प्रमुख नीतिगत परिवर्तन

वर्ष	सरकारी बॉन्ड	वर्ष	कारपोरेट बॉन्ड
अप्रैल 2004	खजाना बिलों में एफआईआई की अनुमति प्रदान की गई	मार्च 1998	समग्र अनुमोदित सीमा के भीतर एफआईआई को गैर-सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों में भी निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई *
नव. 2004	एफआईआई की सीमा बढ़ाकर 1.75 बिलियन यूएस \$ की गई	दिसं. 2004	सरकारी बॉन्डों के लिए निर्धारित सीमा के ऊपर 0.5 बिलियन की पृथक एफआईआई सीमा
अप्रैल 2006	एफआईआई की सीमा बढ़ाकर 2.0 बिलियन यूएस \$ की गई	अप्रैल 2006	सीमा बढ़ाकर 1.5 बिलियन यूएस \$ की गई और उसे केवल कारपोरेट बॉन्डों के लिए प्रतिबंधित किया गया
जन. 2007	एफआईआई की सीमा बढ़ाकर 2.6 बिलियन यूएस \$ की गई	सितं. 2006	टिअर II बॉन्डों के लिए 0.5 बिलियन यूएस \$ की पृथक सीमा
जन. 2008	एफआईआई की सीमा बढ़ाकर 3.2 बिलियन यूएस \$ की गई	जून 2008	सीमा बढ़ाकर 3.0 बिलियन यूएस \$ की गई
जून 2008	एफआईआई की सीमा बढ़ाकर 5.0 बिलियन यूएस \$ की गई	अक्तू. 2008	सीमा बढ़ा कर 6.0 बिलियन यूएस \$ की गई
नव. 2010	सीमा बढ़ाकर 10 बिलियन यूएस \$ की गई (बढ़ाई गई 5 बिलियन यूएस \$ की राशि को दीर्घावधि जी-सेक में निवेश किया जा सकेगा जिसकी परिपक्वता 5 वर्ष से अधिक हो)	फर. 2009	सीमा बढ़ा कर 15 बिलियन यूएस \$ की गई
नव. 2011	सीमा बढ़ाकर 15 बिलियन यूएस \$ की गई	नव. 2010	सीमा बढ़ा कर 20 बिलियन यूएस \$ की गई #
जून 2012	जी-सेक(दीर्घावधि) लिए उप-सीमा को बढ़ाकर 10 बिलियन यूएस \$ किया गया।	मार्च 2011	दीर्घावधि बॉन्डों में सीमा बढ़ा कर 25 बिलियन यूएस \$ की गई
जन. 2013	<ul style="list-style-type: none"> • कुल सीमा बढ़ाकर 25 बिलियन यूएस \$ की गई • दीर्घावधि श्रेणी के लिए उप-सीमा बढ़ाकर 15 बिलियन यूएस \$ की गई • खजाना बिलों में कोई निवेश नहीं 	नव. 2011	सीमा 5 बिलियन यूएस \$ बढ़ाई गई
जून 2013	कुल सीमा बढ़ाकर 30 बिलियन यूएस \$ की गई	सितं. 2012	क्यूएफआई (पात्र विदेशी निवेशकों) को 1 बिलियन यूएस \$ तक की अनुमति प्रदान की गई
अप्रै. 2014	एफआईआई को अवशिष्ट परिपक्वता के साथ जी-सेक में एक वर्ष या अधिक के लिए अनुमति प्रदान की गई	अप्रै. 2013	(उप-सीमाओं को मिलाते हुए) सीमा 51 बिलियन यूएस \$ की गई
जुला. 2014	जी-सेक में मौजूदा निवेश सीमा (30 बिलियन यूएस \$) के भीतर उप-सीमा को बढ़ाकर 25 बिलियन यूएस \$ किया गया, जिसमें न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता 3 वर्ष की हो (तदनुसार, एसडब्ल्यूएफ, बीमा और पेंशन निधियों आदि के लिए सीमा में 5 बिलियन यूएस \$ की कमी की गई)	अप्रै. 2016	51 बिलियन यूएस \$ की सीमा को रु.2443.23 बिलियन निर्धारित किया गया (मसाला बॉन्डों सहित)
अक्तू. 2015	अक्तूबर 2015 से केन्द्रीय जी-सेक और एसडीएल के लिए एफपीआई सीमाओं में तिमाही वृद्धि	सितं. 22, 2017	<ul style="list-style-type: none"> • रु.2273.22 बिलियन (मसाला बॉन्डों को छोड़कर) 3 अक्तूबर 2017 से प्रभावी • वित्त वर्ष 18-19 के लिए रु. 170.01 बिलियन की अतिरिक्त सीमा • कारपोरेट बॉन्डों के लिए रु. 2443.23 बिलियन की एफपीआई सीमा 01 जनवरी 2017 से (मसाला बॉन्डों को छोड़कर)
मार्च 2017 के अंत की स्थिति	रु. 2,410 बिलियन (.35 बिलियन यूएस \$)^		
सितं. 2017 के अंत की स्थिति	रु. 2,751 बिलियन (.43 बिलियन यूएस \$)		
अक्तू. 2017 से	रु. 2,983 बिलियन (.44 बिलियन यूएस \$)		

* ऋण की अनुमोदित समग्र सीमा के भीतर 70:30 मार्ग के लिए 0.1 बिलियन यूएस \$ और 100 प्रतिशत ऋण सीमा के मार्ग के लिए 0.9 बिलियन यूएस \$ की पृथक उप-सीमाएँ जिन्हें बाद में जनवरी 2008 में इन मार्गों के सीमांकन के समाप्त करने तक, बाद में संशोधित किया गया।

इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के दीर्घावधि (>5 वर्ष) बॉन्डों के लिए वृद्धिशील राशि

^ अक्तूबर 2015 से केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में और राज्य विकास उधारों में एफपीआई द्वार निवेश के लिए सीमाओं को रूप के रूप में घोषित/निर्धारित किया गया। कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े तिमाही के प्रारंभ में यूएस डॉलर के प्रति भारतीय रुपये के लिए संदर्भ दर का उपयोग कर अनुमानित किए गए हैं।

अनुबंध 2 : व्यापार उधार, आयातों और रुपया-डॉलर विनिमय दर के संबंध में बाह्य ऋण में इकाई मूल के लिए संवर्धित डिक्ली-फुलर परीक्षण

अंत्य परिकल्पना: एलटीसीओएस, एलआईएम और एलईआर के पास एक इकाई मूल है लैंग दूरी: (स्वचालित- एसआईसी आधारित) नमूना अवधि : 2000:ति2 से 2017:ति4							
संवर्धित डिक्ली फुलर सांख्यिकी		एलटीसीओएस		एलआईएम		एलईआर	
		टी-सांख्यिकी	प्रायिकता*	टी-सांख्यिकी	प्रायिकता*	टी-सांख्यिकी	प्रायिकता*
		-1.14	0.69	-1.28	0.63	0.07	0.96
परीक्षण के प्रमुख मान	1% स्तर	-3.53		-3.53		-3.53	
	5% स्तर	-2.91		-2.90		-2.91	
	10% स्तर	-2.59		-2.59		-2.59	

* मैककिनॉन (1996) एक-पक्षीय पी-मान

अनुबंध 3 : बाह्य ऋण और ऋण चुकौती भुगतानों में इकाई मूल के लिए संवर्धित डिक्ली-फुलर परीक्षण

अंत्य परिकल्पना: एलईडी और एलडीएसपी के पास एक इकाई मूल है बहिर्जात : नीयत लैंग दूरी: (स्वचालित- एसआईसी आधारित) नमूना अवधि : 1970 से 2016					
संवर्धित डिक्ली फुलर सांख्यिकी		एलईडी		एलडीएसपी	
		टी-सांख्यिकी	प्रायिकता*	टी-सांख्यिकी	प्रायिकता*
		-0.72	0.83	0.90	0.78
परीक्षण के प्रमुख मान	1% स्तर	-3.58		-3.59	
	5% स्तर	-2.93		-2.93	
	10% स्तर	-2.60		-2.60	

* मैककिनॉन (1996) एक-पक्षीय पी-मान

अंत्य परिकल्पना: ईडीआर और डीएसपीआर के पास एक इकाई मूल है बहिर्जात : नीयत लैंग दूरी: (स्वचालित- एसआईसी आधारित)					
संवर्धित डिक्ली फुलर सांख्यिकी		ईडीआर		डीएसपीआर	
		टी-सांख्यिकी	प्रायिकता*	टी-सांख्यिकी	प्रायिकता*
		-2.52	0.12	-1.53	0.51
परीक्षण के प्रमुख मान	1% स्तर	-3.60		-3.59	
	5% स्तर	-2.94		-2.93	
	10% स्तर	-2.61		-2.60	

* मैककिनॉन (1996) एक-पक्षीय पी-मान

बैंकिंग सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सर्वेक्षण: 2016-17*

बैंकिंग सेवाओं (आईटीबीएस) में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के वार्षिक सर्वेक्षण में भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाएं/सहायक संस्थाएं और भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाएं शामिल हैं। इस सर्वेक्षण में उनकी आय, व्यय और लाभप्रदता के साथ-साथ उनकी निधि/गैर-निधि आधारित व्यवसाय के प्रोफाइल को एकत्र किया गया है। वर्ष 2016-17 के दौरान, सीमापारीय मौजूदगी वाले बैंक की सभी श्रेणियों के बैंक क्रेडिट, ब्याज आय और लाभप्रदता में गिरावट आई और उनकी समेकित बैलेंस शीट भी संकुचित हुई, जो बैंकिंग सेवाओं में व्यापार की वैश्विक कमियों को दर्शाता है।

प्रस्तावना

बैंकिंग सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (आईटीबीएस) किसी अर्थव्यवस्था में निवास करने वाले लोगों को (ए) विदेशी बैंकों और (बी) विदेशी सहयोगियों की स्थानीय मौजूदगी के माध्यम से प्रदान की गई बैंकिंग सेवाओं को कवर करता है। इसमें निधि-आधारित सेवाएं (जैसे, जमा-लेना, फर्मों को उधार देना, उपभोक्ता वित्त) और बहुत सी गैर-आस्तित-आधारित सेवाएं (जैसे, प्रतिभूति हामीदारी अंकन, स्थानीय मुद्रा में बॉन्ड ट्रेडिंग, विदेशी मुद्रा व्यापार, अभिरक्षा सेवाएं, वित्तीय परामर्श सेवाएं, निधि हस्तांतरण और प्रबंधन सेवाएं)² शामिल हैं। दशकों से, सीमापारीय बैंकिंग सेवाओं की मांग को पूरा करने के लिए विदेशों में काम कर रहे भारतीय बैंकिंग केंद्रों की संख्या और भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की संख्या में वृद्धि हुई है और नियमित रूप से उनकी दक्षता और अन्य मापदंडों का मूल्यांकन करना उपयोगी है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सेवाओं से संबंधित सांख्यिकीय वैश्विक नियमावली के अनुसार, विश्व व्यापार संगठन (डबल्यूटीओ) के

* यह आलेख बाह्य देयताएं और आस्तित सांख्यिकी प्रभाग, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक की सीमा जयसवाल, पृथ्वीस जाना और पल्लवी द्वारा तैयार किया गया है। लेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि रिजर्व बैंक द्वारा साझा किया गया हो।

¹ आईटीबीएस 2016-17 से संबंधित विस्तृत आंकड़े 1 नवंबर 2017 को रिजर्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर जारी किए गए हैं जहां सर्वेक्षण के अंतर्गत कवर किए गए बैंकिंग सेवाओं का और विवरण भी दिया गया है।

² संदर्भ अवधि 2015-16 के साथ इस श्रृंखला में पिछला आलेख रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन के नवंबर 2016 के अंक में प्रकाशित हुआ था।

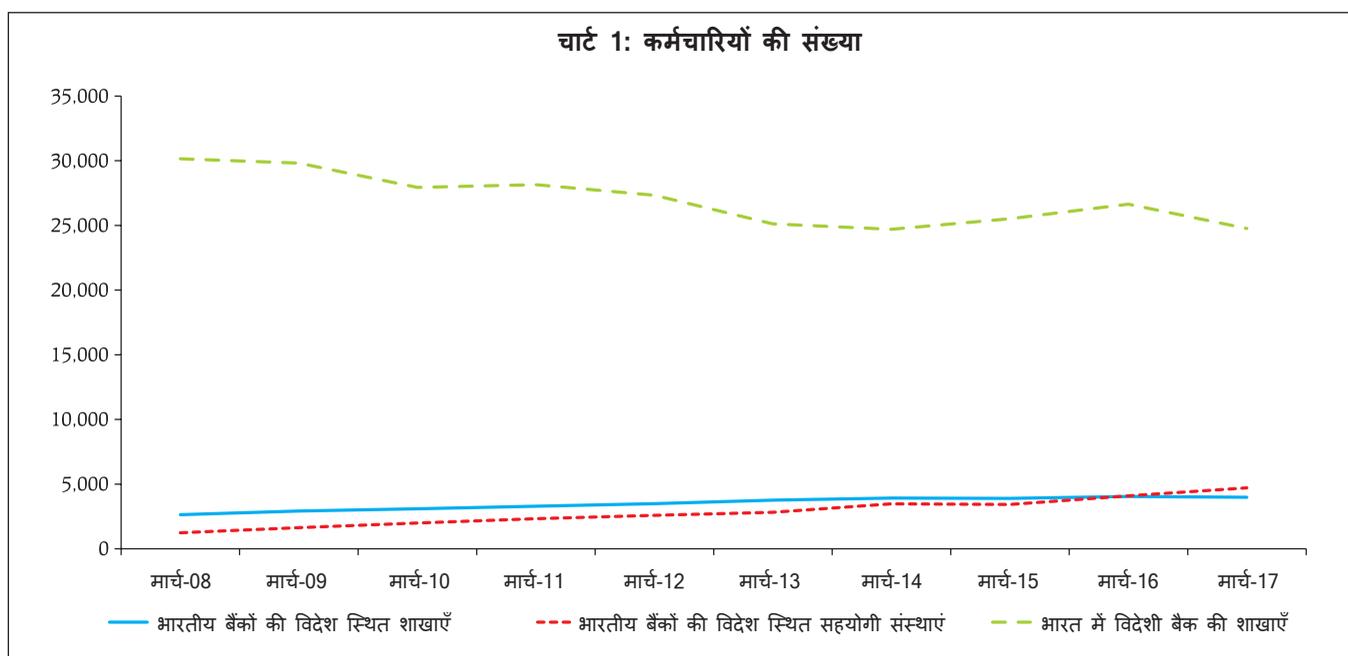
अंतर्गत व्यापार और सेवा संबंधी सामान्य करार के फ्रेमवर्क में परिकल्पना की गई है कि किसी वाणिज्यिक सेवा की सुपुर्दगी चार विधियों में से किसी एक में की जा सकती है अर्थात्, विधि-1 (सीमा-पार विनिमय), विधि-2 (विदेश में उपभोग), विधि-3 (वाणिज्यिक मौजूदगी) एवं विधि-4 (वास्तविक व्यक्ति की गतिविधि)। सीमा-पारीय मौजूदगी वाले बैंकों द्वारा सेवा का लाभ उठाने वाले क्षेत्र में प्रदान की गई सेवा विधि-3 के अंतर्गत आती है। ऐसी मौजूदगी प्रतिनिधि कार्यालयों, शाखाओं, सहायक कंपनियों, एमोसिएट्स एवं प्रतिनिधियों जैसे निवेश माध्यमों के माध्यम से हो सकते हैं। वित्तीय सेवा क्षेत्र के उदारीकरण की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए जीएटीएस अन्य बातों के साथ-साथ आईटीबीएस से संबंधित सुसंगत और तुलनात्मक सांख्यिकी की जरूरत पर जोर देता है।

विधि-3 आपूर्ति के अंतर्गत मुहैया कराई जाने वाली बैंकिंग सेवाओं से संबंधित सूचना को संकलित करने के लिए रिजर्व बैंक वर्ष 2006-07 से आईटीबीएस सर्वेक्षण करवा रहा है। सर्वेक्षण में भारत में संचालित विदेशी बैंकों के साथ-साथ भारतीय बैंकों की सीमा-पारीय शाखाएँ और सहयोगी संस्थाएं भी शामिल हैं। आईएमएफ के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड इंटरनेशनल इनवेस्टमेंट पोजीशन मैनुअल: छठा संस्करण (बीपीएम6) के अनुसार अनुषंगी संस्था सीधे निवेश उद्यम (डीआईई) है जिस पर सीधे निवेशक नियंत्रण करने में सक्षम है, जिन्हें अस्तित्व में मान लिया जाता है अगर निवेश प्राप्त करने वाले उद्यम के कुल इक्विटी में निवेशक की बड़ी हिस्सेदारी होती है तो।

वर्ष 2016-17 के सर्वेक्षण में भारतीय बैंकों की 192 विदेशी शाखाएं और 325 विदेशी सहायक कंपनियों के साथ-साथ भारत में प्रचलित विदेशी बैंकों की 286 शाखाएं शामिल हैं। चूंकि सीमा पार की उपस्थिति वाले सभी बैंकों ने सर्वेक्षण पर प्रतिक्रिया देते हैं, यद्यपि नवीनतम वर्ष के आंकड़े अनंतिम रहते हैं, तथापि परिणाम संगणना की स्थिति प्रस्तुत करते हैं। इस लेख में, पिछले कुछ सालों में बैंकिंग सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण शाखा नेटवर्क (खंड 2), निधि आधारित और गैर-निधि आधारित व्यवसाय (खंड 3 और 4) और लाभप्रदता (खंड 5) के संदर्भ में किया गया है। कुछ अंतिम विचार खंड 6 में दिए गए हैं

2. शाखा विभाजन

सीमा पार से व्यापार और अन्य गतिविधियों की बढ़ती मांग के अनुरूप बैंकों की सीमा पार मौजूदगी बढ़ी है। भारतीय



बैंकों की विदेशी शाखाओं की संख्या धीरे-धीरे मार्च 2008 में 121 (2,629 कर्मचारियों के साथ) से मार्च 2017 में 192 (3,984 कर्मचारियों के साथ) तक बढ़ गई (चार्ट 1)। इस तरह की शाखाओं की सबसे बड़ी संख्या यूनाइटेड किंगडम (33) में थी, उसके बाद हांगकांग (17), सिंगापुर (16), संयुक्त अरब अमीरात (15), श्रीलंका (13) और दक्षिण अफ्रीका (12) था। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का भारतीय बैंकों की समुद्रपारीय उपस्थिति में दबदबा है, जहां भारतीय स्टेट बैंक की सबसे बड़ी समुद्रपारीय उपस्थिति (22 देशों में 61 शाखाएं) है, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा (15 देशों में 47 शाखाएं) है। विदेशी बैंक की शाखाओं की संख्या मार्च 2017 में 286 तक घटाने से पहले मार्च 2008 में 273 से बढ़कर मार्च 2016 में 317 हो गई और उनके कर्मचारियों की संख्या मार्च 2008 में 30,159 से कम होकर मार्च 2017 में 24,766 तक हो गई। भारतीय

बैंकों की विदेशों में स्थित शाखाओं ने 63.3 प्रतिशत स्थानीय कर्मचारियों को बहाल किया जबकि भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों के 99.3% कर्मचारी स्थानीय थे (सारणी 1)।

3. निधि आधारित कारोबार

पिछले रुझानों को आगे बढ़ाते हुए बैंक के सभी समूहों (अर्थात्, भारतीय बैंकों की विदेश स्थित शाखाएँ, विदेशों में संचालित उनकी सहयोगी संस्थाएं और भारत में कार्यशील विदेश के बैंकों की शाखाएँ) की आस्तियों/देनदारियां वर्ष 2016-17 में संकुचित हो गईं (सारणी 2 एवं चार्ट 2)। भारतीय बैंकों की विदेश स्थित शाखाओं के कारोबार और भारतीय बैंकों की विदेश स्थित सहायक संस्थाओं ने भारत में संचालित विदेशी बैंकों (-1.4 प्रतिशत) की तुलना में उच्चतर संकुचन (क्रमशः -5.2 और 5.7) दर्ज किया।

सारणी 1: कर्मचारियों की संरचना- 2015-16 और 2016-17

श्रेणी	विदेश में कार्यरत भारतीय बैंकों की शाखाएं		विदेश में कार्यरत भारतीय बैंकों की सहयोगी संस्थाएं		भारत में कार्यरत विदेशी बैंक की शाखाएं	
	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17
शाखाओं की कुल संख्या	189	192	310	325	317	286
कर्मचारियों की कुल संख्या :	4,040	3,984	4,091	4,704	26,642	24,766
जिसमें से -						
स्थानीय	2,549	2,520	3,616	4,194	26,487	24,602
भारतीय	1,368	1,417	401	458		
अन्य	123	47	74	52	155	164

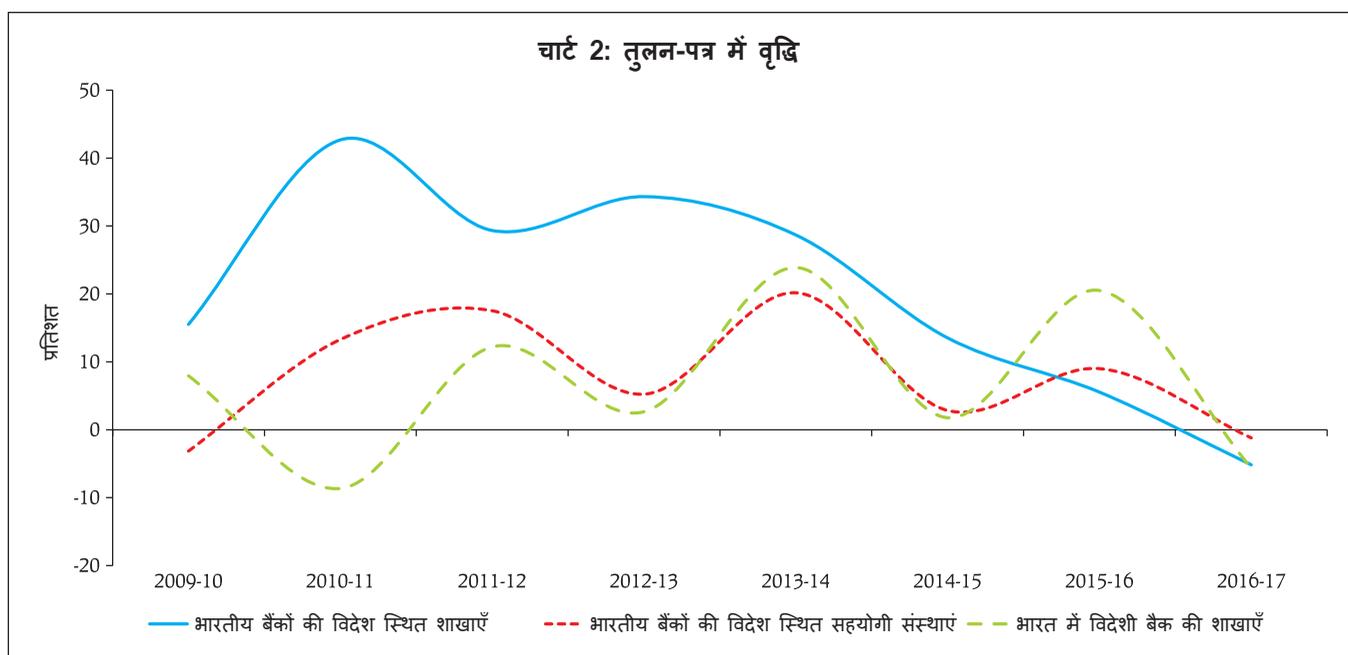
सारणी 2: तुलन-पत्र - 2012-13 से 2016-17(मार्च अंत)

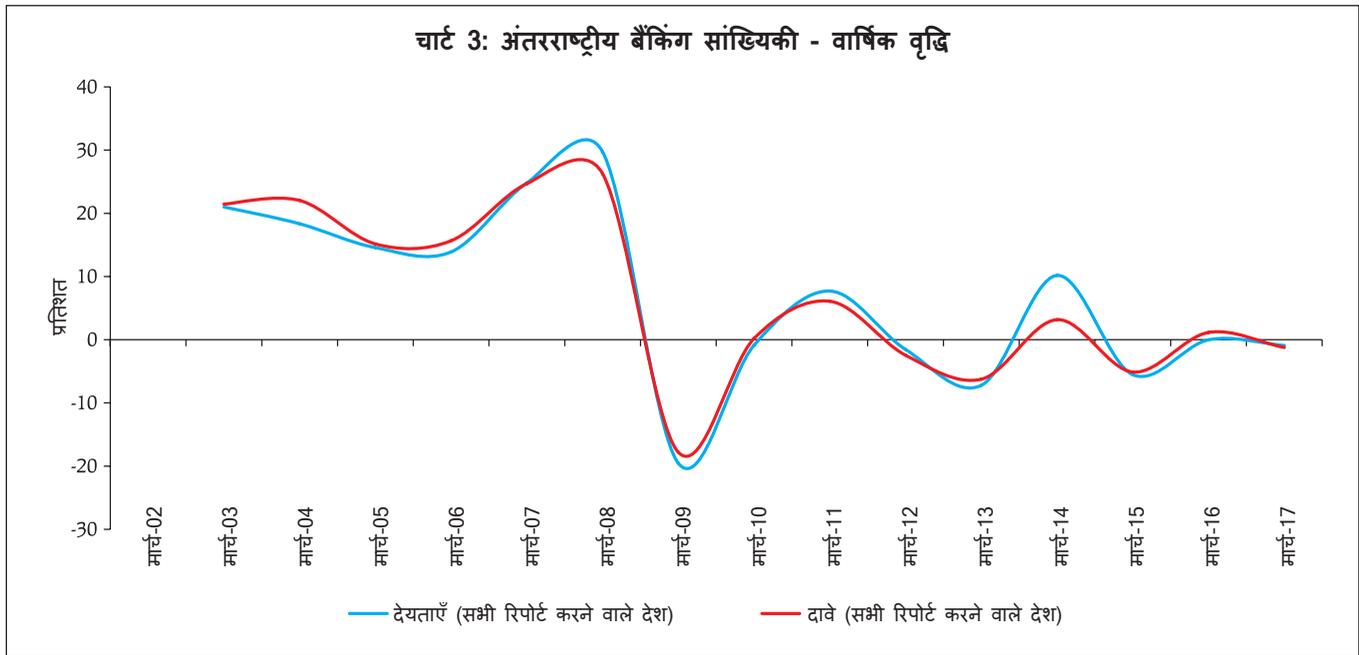
श्रेणी	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
	विदेश में कार्यरत भारतीय बैंकों की शाखाएं				
कुल आस्तियों की तुलना में क्रेडिट (%)	58.9	58.5	57.4	58.3	59.6
कुल देयताओं की तुलना में जमाराशियां (%)	39.5	39.0	39.0	36.7	36.4
कुल आस्तियां/देयताएं(बिलियन रुपए)	9,939.8	12,791.2	14,520.0	15,323.6	14,530.7
कुल आस्तियां/देयताएं(बिलियन अमरीकी डालर)	182.8	212.8	232.0	231.1	224.2
विदेश में कार्यरत भारतीय बैंकों की सहयोगी संस्थाएं					
कुल आस्तियों की तुलना में क्रेडिट (%)	66.5	67.9	70.7	69.1	68.5
कुल देयताओं की तुलना में जमाराशियां (%)	55.2	58.2	58.1	56.7	55.9
कुल आस्तियां/देयताएं (बिलियन रुपए)	848.3	1,050.9	1,069.5	1,347.5	1,271.3
कुल आस्तियां/देयताएं (बिलियन अमरीकी डालर)	15.6	17.5	17.1	20.3	19.6
भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाएं					
कुल आस्तियों की तुलना में क्रेडिट (%)	50.7	40.8	44.8	46.2	42.4
कुल देयताओं की तुलना में जमाराशियां (%)	46.7	47.8	53.7	56.0	57.5
कुल आस्तियां/देयताएं(बिलियन रुपए)	6,066.5	7,290.3	7,497.6	8,172.7	8,075.2
कुल आस्तियां/देयताएं(बिलियन अमरीकी डालर)	111.5	121.3	119.8	123.2	124.6

* मार्च अंत में रुपए/अमरीकी डालर रिज़र्व बैंक संदर्भ दर का प्रयोग

यह उल्लेखनीय है कि औसतन सभी बैंक समूहों के तुलन-पत्र पहले (2009-14) की तुलना में हालिया तीन वर्षों (2014-17) के दौरान धीमी गति से बढ़े हैं। समान पैटर्न अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक के अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी (आईबीएस) में वैश्विक स्तर पर देखी गई (चार्ट 3)। यह नोट किया गया है कि मार्च 2017 में सभी आईबीएस रिपोर्ट करने

वाले देशों के संयुक्त सीमा पार देनदारियाँ और आस्तियां (स्थानिक बैंकिंग सांख्यिकी - एलबीएस) मार्च 2014 में उनके स्तर की तुलना में 5 प्रतिशत से अधिक कम थीं। इसके लिए आर्थिक गतिविधियों के सामान्य स्तर के आलोक में बैंक-वित्तपोषण की कम आवश्यकताओं को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो बड़ी चिंता की बात रही है और इसलिए निरंतर



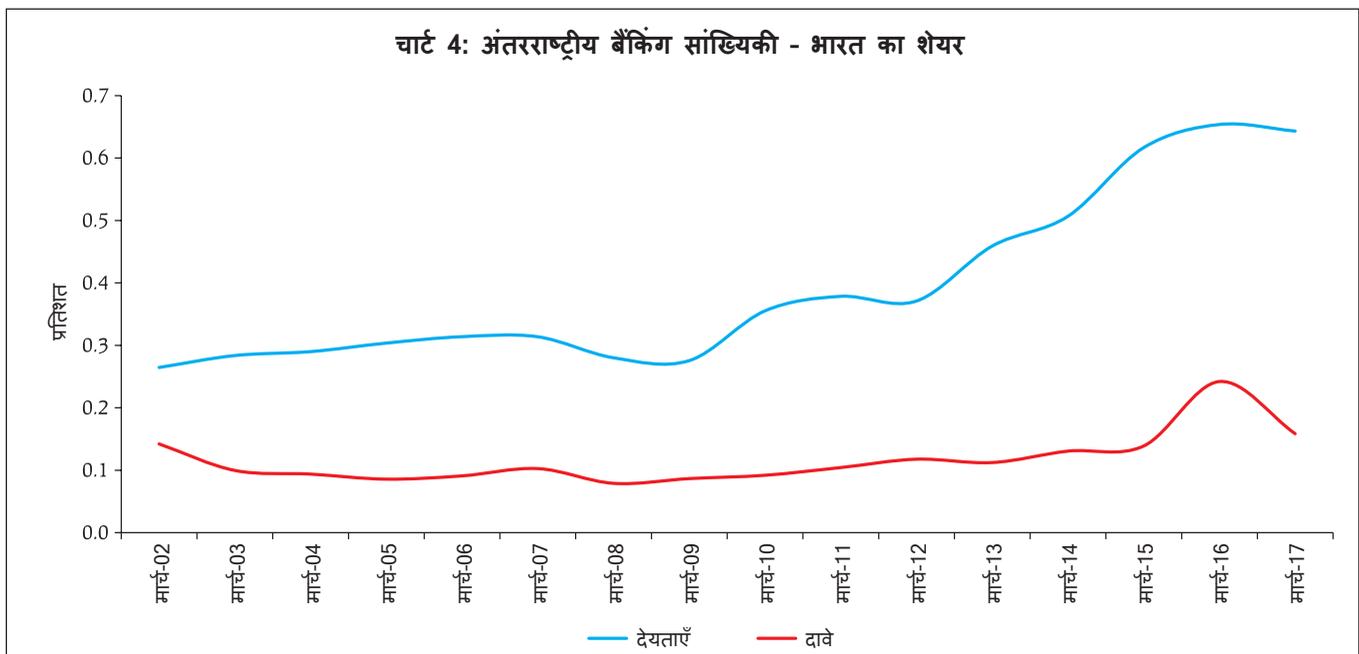


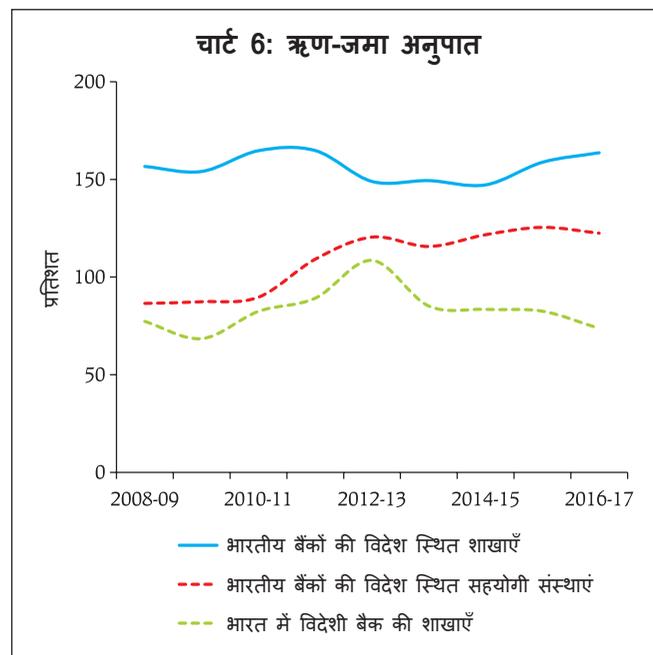
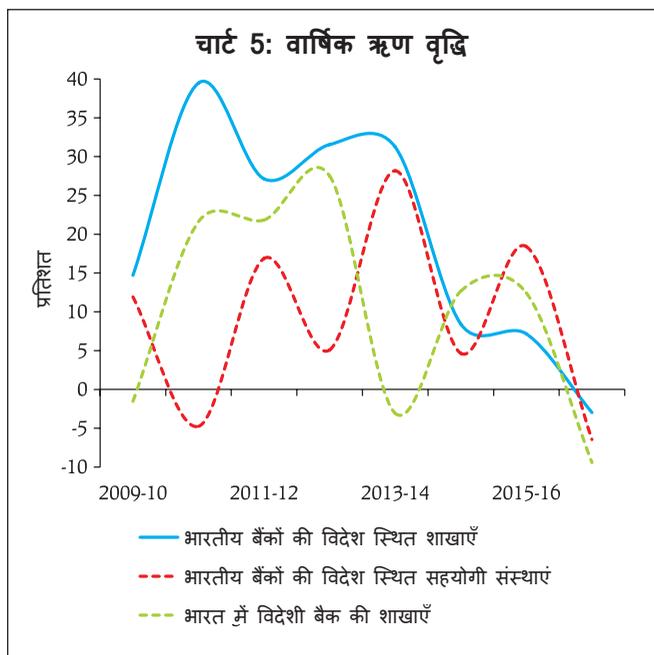
कम ब्याज दर व्यवस्था, आसान चलनिधि की स्थिति और वैश्विक स्तर पर कई अन्य नीतिगत उपायों जैसे कदम की आवश्यकता जताई गई।

आईबीएस देनदारियों/आस्तियों में भारत की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम है किंतु वर्ष 2002-2016 तक यह धीरे-धीरे बढ़ी है। मार्च 2016 के अंत तक आईबीएस-रिपोर्ट करने वाले देशों की संयुक्त देनदारियों और आस्तियों में भारत की

हिस्सेदारी क्रमशः 0.65 प्रतिशत और 0.24 प्रतिशत तक रही। हालांकि, ये 2016-17 के दौरान आंशिक रूप से कम हुई (चार्ट 4)।

निधि आधारित बैंकिंग व्यवसाय (सारणी 2 और चार्ट 2) की स्वभाव की स्थिति तीन बैंक समूहों (चार्ट 5) द्वारा दिए गए ऋणों में गिरावट से बहुत अच्छे से परिलक्षित होती है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि मार्च 2017 में भारतीय बैंकों की





विदेशी शाखाओं के यूएस \$ 224 बिलियन आस्ति-आधार का लगभग 60 प्रतिशत ऋण था, जबकि यह भारत में विदेशी बैंक की आस्ति का 42 प्रतिशत (125 बिलियन अमरीकी डॉलर) था।

देनदारियों के पक्ष में, भारत में विदेशी बैंकों की शाखाओं को छोड़कर सभी बैंक समूहों ने वर्ष 2016-17 के दौरान जमाराशियों में गिरावट देखी। भारत में अन्य बैंकों की तरह, भारत में विदेशी बैंक ने विनिर्दिष्ट बैंक नोट (एसबीएन) के विमुद्रीकरण के बाद अगले वर्ष में अपने जमा आधार में वृद्धि देखी। हालांकि, सीमापारीय उपस्थिति के कारण ऋण देने के लिए इन बैंकों द्वारा जमाराशि जुटाने में बाधा नहीं रही है क्योंकि वे मुख्यालयों से वित्तपोषण सहित अन्य अवसरों के माध्यम से संसाधनों को जुटा लेते हैं। नतीजतन, उनके ऋण-जमा अनुपात आम तौर पर लगभग 100 प्रतिशत या उससे भी ऊपर का रहा है, जो कि लगातार भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं का भी मामला रहा है (चार्ट 6)।

4. गैर-निधि आधारित कारोबार

विभिन्न बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक ग्राहकों से सुनिश्चित और अंतर्निहित शुल्क या कमीशन लेते हैं। ऐसे शुल्क और कमीशन पर सूचना बैंकिंग सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण स्केच प्रदान करती है एमएसआईटीएस के मुताबिक, आईटीबीएस सर्वे ने ऐसी सेवाओं को ग्यारह प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया है। बैंकों के विभिन्न समूहों की कुल आय में शुल्क आय का हिस्सा 11-22 प्रतिशत के बीच है (सारणी 3)।

भारतीय बैंकों की विदेशी सहायक कंपनियों की शुल्क आय में वर्ष 2016-17 में लगातार तीसरे साल गिरावट आई है, लेकिन पिछले वर्ष में गिरावट आने के बाद, विदेशों में संचालित भारतीय बैंकों की शाखाओं और भारत में संचालित विदेशी बैंक की शाखाओं के मामले में यह बढ़ गया था (सारणी 3)। इसे समान रूप से वर्ष 2016-17 के चार तिमाहियों में बाँट दिया गया था (चार्ट 7)। भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाएं

सारणी 3: बैंकिंग सेवाओं के लिए शुल्क आय/कमीशन

(राशि ₹ बिलियन में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
भारतीय बैंकों की विदेश स्थित शाखाएँ	93.5	89.6	94.3	87.3	94.0
भारतीय बैंकों की विदेश स्थित सहयोगी संस्थाएँ	4.8	16.6	13.0	10.4	9.3
भारत में विदेशी बैंक की शाखाएँ	74.5	78.8	72.7	70.6	71.3

सारणी 4: बैंकिंग सेवाओं में व्यापार में गतिविधि का हिस्सा

(प्रतिशत)

गतिविधि	विदेश में कार्यरत भारतीय बैंकों की शाखाएं					भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाएं				
	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
जमाराशि खाता प्रबंधन सेवाएं	8.3	1.3	1.2	1.4	3.4	5.1	4.6	2.8	1.9	1.8
ऋण संबंधी सेवाएं	43.2	27.8	28.2	30.0	30.1	12.2	11.9	12.0	13.8	9.7
वित्तीय पट्टा सेवाएं	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
व्यापार वित्त संबंधी सेवाएं	36.7	16.0	16.0	15.8	21.5	22.1	17.1	16.6	18.7	15.6
भुगतान और धन अंतरण सेवाएं	5.7	3.1	3.6	3.8	3.3	15.0	15.7	18.3	23.5	23.8
निधि प्रबंधन सेवाएं	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	4.4	5.6	7.1	6.0
वित्तीय कन्सल्टेंट्स और परामर्शी सेवाएं	0.1	1.2	1.3	0.8	0.4	15.0	16.6	17.2	10.8	10.5
हामीदारी सेवाएं	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	2.9	0.6	0.8	1.1
समाशोधन और निपटान सेवाएं	0.3	0.4	0.5	0.6	0.5	1.2	0.9	0.7	1.0	0.7
व्युत्पन्नी, स्टॉक, प्रतिभूति, विदेशी मुद्रा व्यापार सेवाएं	3.5	22.1	20.8	23.7	20.4	17.6	20.9	20.4	9.5	16.4
अन्य वित्तीय सेवाएं	2.3	28.0	28.4	23.9	20.1	5.6	4.8	5.9	13.0	14.3
समस्त गतिविधियां	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

‘ऋण से संबंधित सेवाएं’, ‘व्यापार वित्त संबंधी सेवाएं’ और ‘व्युत्पन्न, स्टॉक, प्रतिभूतियां, विदेशी मुद्रा व्यापार सेवाओं’ को प्रदान करने पर अपना ध्यान केंद्रित करती हैं, जो 2016-17 के दौरान उनकी शुल्क आय का 70 से अधिक रहा था। भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों के पास अधिक विविधतापूर्ण उत्पाद थे और ‘भुगतान एवं धन प्रेषण सेवाएं’ शुल्क आय के सबसे बड़े स्रोत थे (सारणी 4)।

बैंकिंग सेवाओं से भारतीय बैंक की शाखाओं की सर्वाधिक कमाई यूके में थी उसके बाद यू.ए.ई., हांगकांग और सिंगापुर

के शाखाओं की थी (सारणी 5) और उनकी शुल्क आय का एक प्रमुख हिस्सा निवासियों को प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त हुआ है (चार्ट 8)। इन प्रचालनों से भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बैंकों की कमाई इन देशों में भारतीय बैंकों द्वारा इसी तरह के कार्यों से प्राप्त राशि से अधिक रही है।

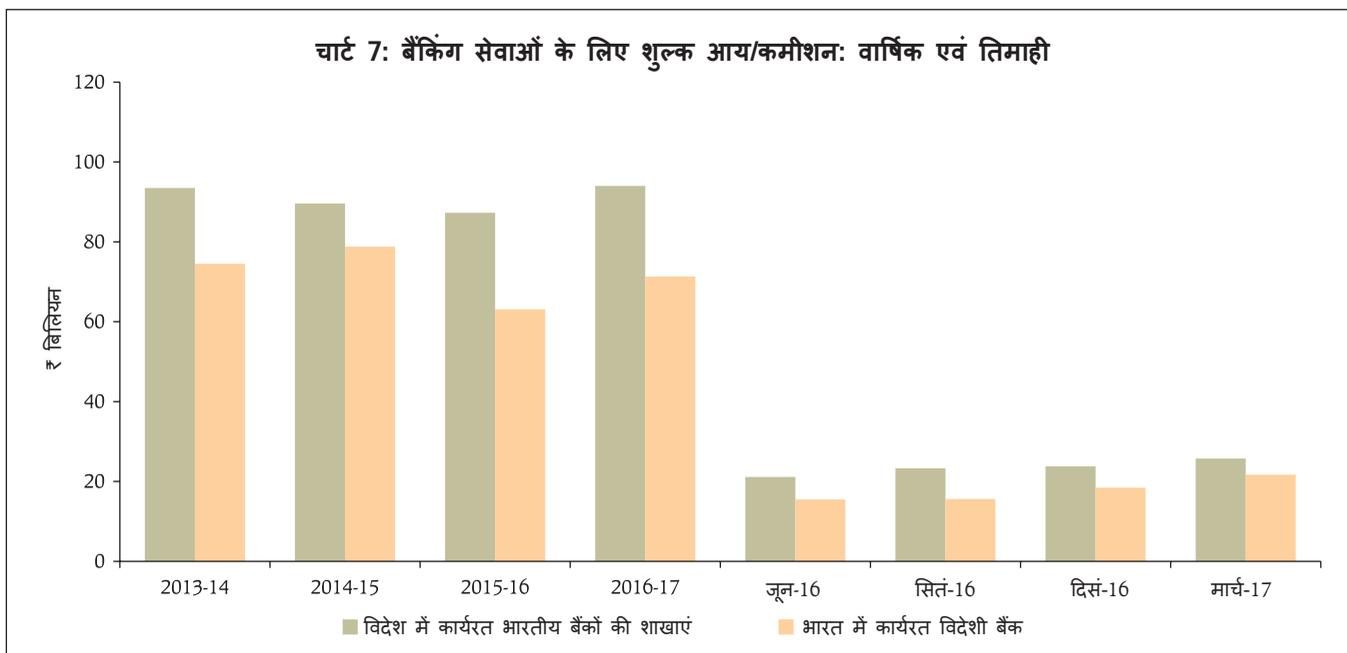
5. लाभप्रदता

वर्ष 2016-17 के दौरान अग्रिम घटने से भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं (आईबी_बीआर_ओ) की ब्याज आय में 2.9 प्रतिशत की गिरावट हो गई और उनकी कुल आय में 4.6

सारणी 5: विदेश में कार्यरत भारतीय बैंकों की शाखाओं और भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शुल्क से होने वाली आय का देशवार वर्गीकरण

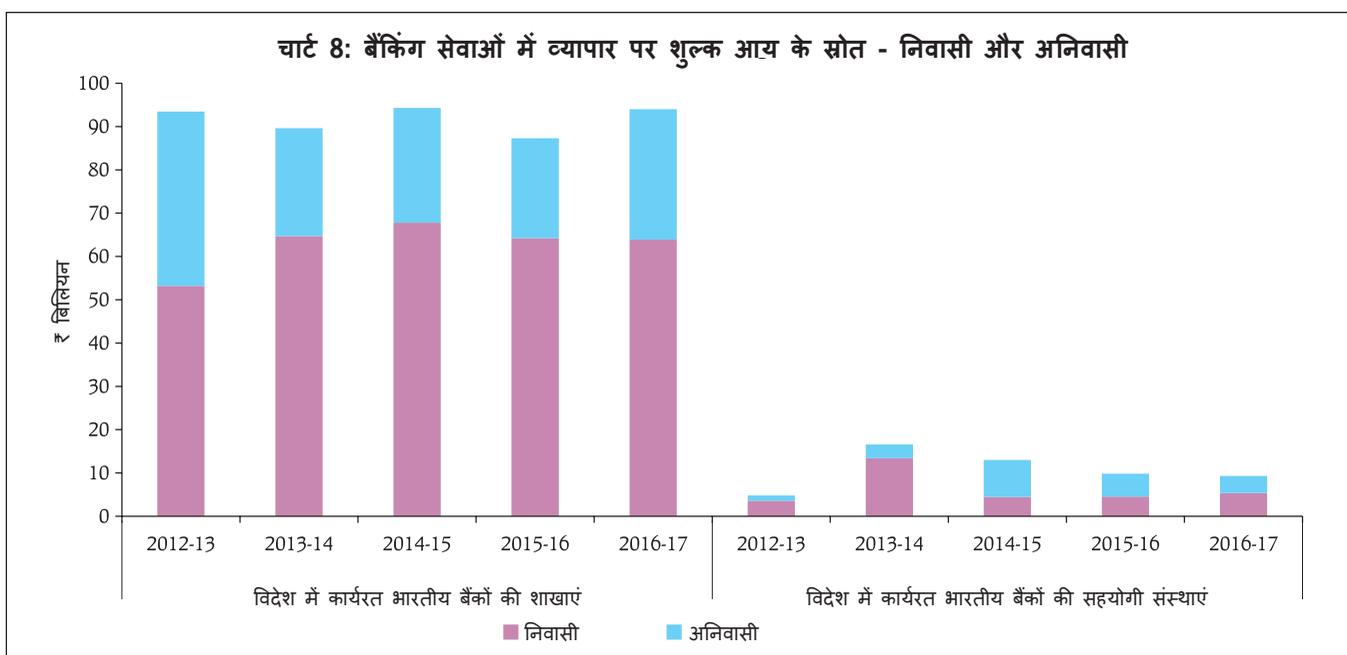
(राशि बिलियन ₹ में)

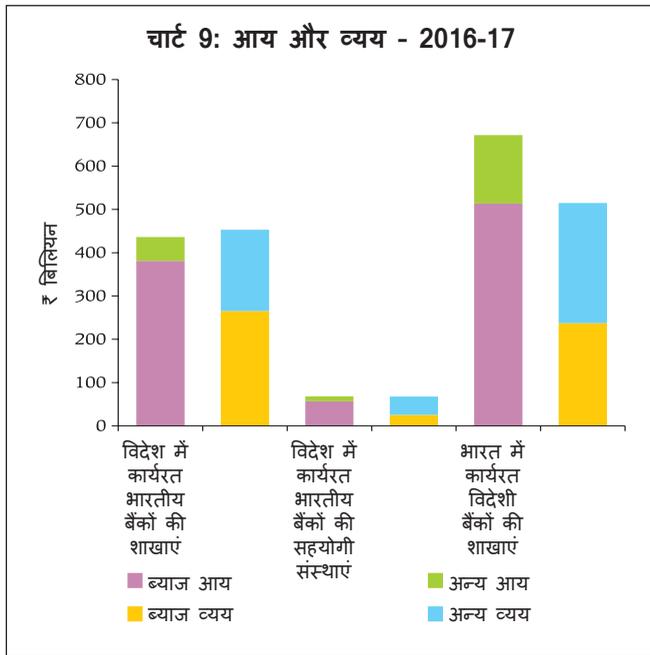
	विदेश में कार्यरत भारतीय बैंकों की शाखाएं					भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाएं				
	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बहरीन	2.9	3.9	5.2	3.9	3.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
हांगकांग	9.4	7.9	8.2	7.2	6.2	15.7	13.4	13.5	4.4	4.2
जापान	1.0	1.2	0.8	1.4	0.9	1.4	1.2	1.4	1.6	1.4
सिंगापुर	8.2	7.5	7.3	6.8	5.7	3.6	2.3	2.2	2.4	2.0
श्रीलंका	15.4	0.3	0.4	0.3	0.7	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
यूई	4.1	8.5	9.9	9.0	8.0	0.2	0.4	0.4	0.5	0.8
यूके	38.8	49.8	52.3	48.0	48.2	18.5	23.0	18.5	16.4	16.4
यूएसए	4.3	3.7	4.1	4.1	3.7	20.4	26.6	25.6	28.6	35.2
अन्य देश	9.4	6.8	6.1	6.6	17.4	14.6	11.8	10.9	9.1	11.2
कुल	93.5	89.6	94.3	87.3	94.0	74.5	78.8	72.7	63.1	71.3



प्रतिशत की कमी आ गई क्योंकि ब्याजेतर आय में भी काफी गिरावट आई थी। इससे उस वर्ष के दौरान उनकी आय से अधिक व्यय की एक विशिष्ट स्थिति उत्पन्न हो गई। भारत के विदेशी बैंकों (एफबी_बीआर_आई) की भी ब्याज आय कम थी, फिर भी उच्च ब्याजेतर उपार्जन के कारण उनकी कुल आय में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बैंकों के कारोबार वित्तपोषण

मॉडलों में भिन्नता को कुल व्यय में ब्याज व्यय के शेयर में उचित ढंग से दर्शाया गया था, जिसमें भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं का 58.6 प्रतिशत, भारतीय बैंकों की विदेशी सहायक संस्थाओं (आईबी_एसयूबी_ओ) का 37.5 प्रतिशत और भारत में प्रचालित विदेशी बैंकों का 46.1 प्रतिशत शेयर था (चार्ट 9 और सारणी 6)।





कम आस्ति आधार के बावजूद, भारत में विदेशी बैंकों ने आमतौर पर विदेशी बैंकों और भारतीय बैंकों की सहायक कंपनियों की तुलना में अधिक लाभप्रदता दर्ज किया है। उच्च शुल्क आय बढ़ाने वाली गैर-निधि आधारित गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के कारण ऐसा हुआ। वर्ष 2016-17 के दौरान बैंकों के सभी समूहों में क्रेडिट आधार और ब्याज आय में गिरावट भारत में विदेशी बैंकों के आस्ति आधार को कम करने और गैर-ब्याज आय में वृद्धि के साथ-साथ हुई और,

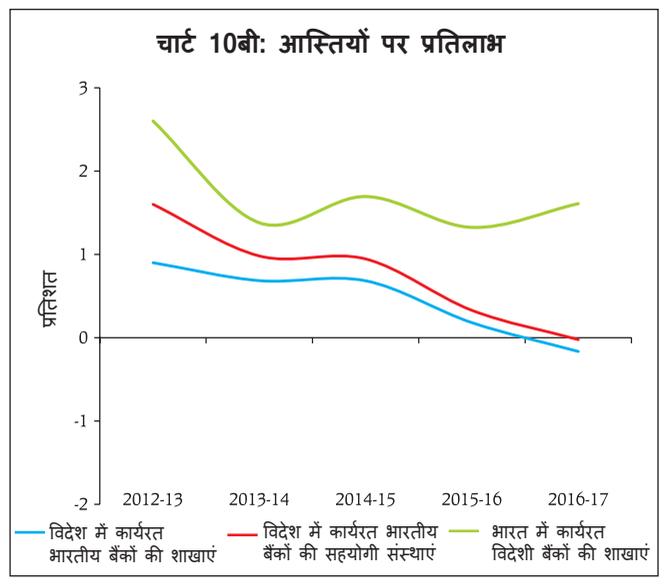
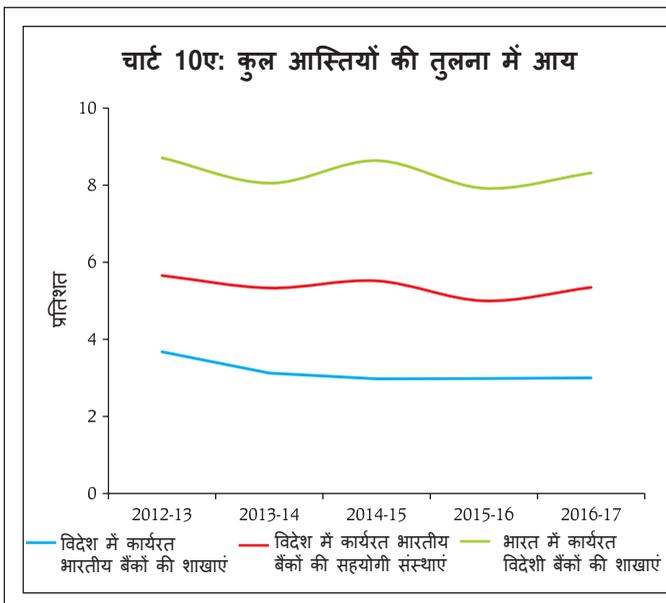
सारणी 6: आय और व्यय - 2012-13 से 2016-17

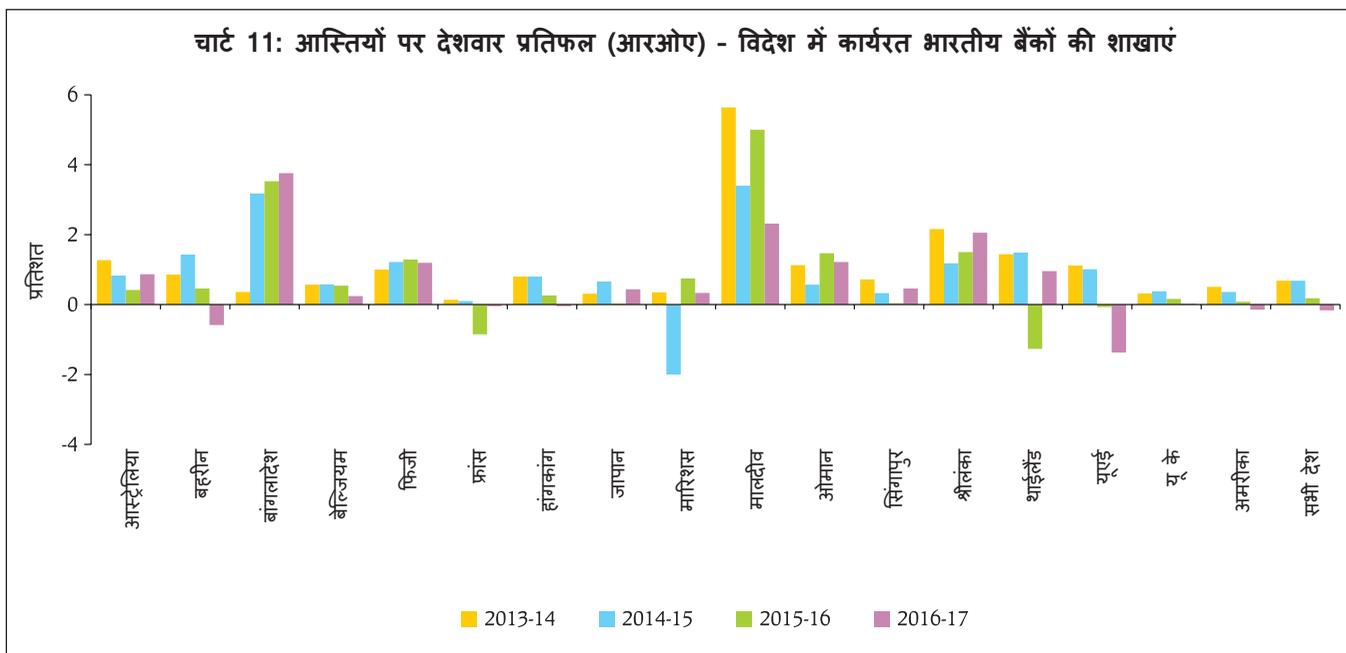
(राशि ₹ बिलियन में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
विदेश में कार्यरत भारतीय बैंकों की शाखाएं					
आय	365.6	399.8	432.3	457.3	436.1
व्यय	273.7	306.4	318.8	419.4	453.0
विदेश में कार्यरत भारतीय बैंकों की सहयोगी संस्थाएं					
आय	48.0	56.1	59.0	67.3	68.0
व्यय	34.3	45.8	48.4	62.8	67.7
भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाएं					
आय	528.4	587.2	647.7	647.4	671.7
व्यय	372.6	446.5	489.5	498.1	514.8

इस प्रकार, कुल आस्तियों के अनुपात में होने वाली आय में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। हालांकि, भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं/सहायक कंपनियों के लिए लाभप्रदता अनुपात (आस्तियों पर प्रतिलाभ - आरओए) अचानक कम हो गई थी, लेकिन भारत में विदेशी बैंकों के लिए यह उनकी गैर-ब्याज आय में वृद्धि के कारण बढ़ गया था (चार्ट 10ए और 10बी)।

देशवार आंकड़ों से पता चलता है कि बांग्लादेश में प्रचलित भारतीय बैंक की शाखाओं को वर्ष 2016-17 के दौरान सर्वाधिक आरओए (3.8 प्रतिशत) प्राप्त होना जारी रहा और उसके बाद मालदीव में स्थित बैंक थे (2.3 प्रतिशत)। बहुत





अधिक शाखाओं वाले देशों में अनुपात सिंगापुर के लिए 0.5 प्रतिशत, यूके के लिए 0.02 प्रतिशत और हांगकांग के लिए -0.05 प्रतिशत कम था (चार्ट 11)।

6. निष्कर्ष

वर्ष 2016-17 के दौरान, वैश्विक आर्थिक गतिविधियों के निचले स्तर के कारण भारत से/के लिए बैंकिंग सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंद था। हाल की अवधि में बैंकिंग सेवाओं में व्यापार में वैश्विक वृद्धि कम हो गई है, विशेषकर पिछले तीन वर्षों में, जैसा कि बीआईएस के अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग आँकड़े (आईबीएस) में दर्शाए गए हैं। बैंकों की सीमा पार की उपस्थिति का विस्तारित चरण अब समाप्त होने के निकट आ गया है और वर्ष 2016-17 में भारत में विदेशी बैंकों की शाखाओं/कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है। भारत में विदेशी बैंकों की तुलना में भारत के विदेशी बैंकों के मामले में तुलन-पत्र

में गिरावट अधिक स्पष्ट थी। बैंक निधियों की अल्प मांग के परिणामस्वरूप सभी बैंक समूहों द्वारा ऋण देने में कमी आ गई थी। भारत में विदेशी बैंकों के विमुद्रीकरण संबंधी जमाराशि में मामूली वृद्धि को छोड़कर, इन बैंक समूहों द्वारा जमाराशि जुटाने में भी कमी आई है।

हालांकि, गैर-निधि आधारित गतिविधियों में सीमा पार के बैंकों की निधि आधारित गतिविधियों के कमजोरी नहीं देखी गई थी। शुल्क और अन्य आय बैंकों की लाभप्रदता का एक महत्वपूर्ण घटक बने रहे। भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं की अधिकांश आमदनी निवासियों को सेवाएं प्रदान करके हुई। भारत में प्रचलित विदेशी बैंकों की कुल आय का एक प्राथमिक घटक ब्याजेत्तर आय है, जिसके कारण कम आस्ति आधार के बावजूद उनकी आय और लाभप्रदता आम तौर पर भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं की तुलना में अधिक हो जाती है।

संदर्भ:

अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी (वेब-लिंक: http://www.bis.org/statistics/about_banking_stats.htm?m=6%7C31)।

कोर्नफोर्ड, एंड्रू (2009), स्टेटिक्स फॉर इन्टरनेशनल ट्रेड इन बैंकिंग सर्विसेस: रिक्वायरमेंट्स, अवेलेबिलिटी एंड प्रोस्पेक्ट्स, यूनाइटेड नेशन्स कोन्फरेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट (यूएनसीटीएडी) डिस्कशन पेपर सं. 194।

गौत्ज़िनिस, अपोस्टोलोस (2005), इन्टरनेशनल ट्रेड इन बैंकिंग सर्विसेस एंड द रोल ऑफ द डब्ल्यूटीओ: डिस्कशिंग द लीगल फ्रेमवर्क एंड पॉलिसी ओब्जेक्टिव्स ऑफ द जेनेरल एग्रीमेंट

ऑन द ट्रेड इन सर्विसेस एंड द करेंट स्टेट ऑफ प्ले इन द दोहा राउंड ऑफ ट्रेड नेगोशिएशन्स, इन्टरनेशनल लॉयर वॉल्यूम 39, सं. 4 (विंटर), अमेरिकन बार एसोशिएसन्स।

भारतीय रिज़र्व बैंक (2006), रिपोर्ट ऑफ द टेक्निकल ग्रुप ऑन स्टेटिक्स फॉर इन्टरनेशनल ट्रेड इन बैंकिंग सर्विसेस।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन (विभिन्न अंक), रिजल्ट्स ऑफ द एन्यूअल सर्वे ऑन इन्टरनेशनल ट्रेड इन बैंकिंग सर्विसेस।

यूनाइटेड नेशन्स स्टेटिक्स डिवीजन (यूएनएसडी) और अन्य (2010), मैनुअल ऑन स्टेटिक्स ऑफ इन्टरनेशनल ट्रेड इन सर्विसेस (एमएसआईटीएस)।

वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुद्रा और बैंकिंग

मूल्य और उत्पादन

सरकारी खाते और खज़ाना बिल

वित्तीय बाजार

बाह्य क्षेत्र

भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

प्रासंगिक श्रृंखला

विषयवस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिंदा आर्थिक संकेतक भारतीय रिज़र्व बैंक	57
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	58
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	59
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरीकी डालर का क्रय/विक्रय	60
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमरीकी डॉलर)	61
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं मुद्रा और बैंकिंग	61
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	62
7	मुद्रा स्टॉक (एम ₃) के स्रोत	63
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	64
9	चलनिधि समुच्चय	64
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	65
11	आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत	65
12	वाणिज्य बैंक सर्वेक्षण	66
13	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेश	66
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	67
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन	68
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार अभिनियोजन	69
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक मूल्य और उत्पादन	70
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)	71
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	71
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	71
21	थोक मूल्य सूचकांक	72
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100) सरकारी खाते और खज़ाना बिल	75
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	75
24	खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	76
25	खज़ाना बिलों की नीलामी वित्तीय बाजार	76
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	77
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	78
28	वाणिज्यिक पत्र	78
29	चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	78
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	79

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
	बाह्य क्षेत्र	
31	विदेशी व्यापार	80
32	विदेशी मुद्रा भंडार	80
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां	80
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	81
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत जावक विप्रेषण	81
36	भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक	82
37	बाह्य वाणिज्यिक उधार	82
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमरीकी डॉलर)	83
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (बिलियन ₹)	84
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमरीकी डॉलर)	85
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (बिलियन ₹)	86
42	अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	87
	भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	88
	प्रासंगिक शृंखला	
44	लघु बचत	89
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	90
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	91
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	92
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	93

टिप्पणियां : .. = उपलब्ध नहीं।
 - = शून्य/नगण्य
 प्रा/अ = प्रारंभिक/अनंतिम आसं = आंशिक रूप से संशोधित

सं. 1 : चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2016-17	2016-17		2017-18	
		ति1	ति2	ति1	ति2
	1	2	3	4	5
1 वस्तु क्षेत्र (% परिवर्तन)					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	6.6	7.6	6.8	5.6	6.1
1.1.1 कृषि	4.9	2.5	4.1	2.3	1.7
1.1.2 उद्योग	7.0	9.0	6.5	1.5	6.9
1.1.3 सेवाएं	6.9	8.2	7.4	7.8	6.6
1.1क अंतिम खपत व्यय	10.5	9.8	9.5	8.5	6.0
1.1ख सकल नियत पूंजी निर्माण	2.4	7.4	3.0	1.6	4.7
	2016-17	2016		2017	
		सितं.	अक्तू.	सितं.	अक्तू.
	1	1	2	3	4
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	4.6	5.0	4.2	3.8	-
2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)					
2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंक					
2.1.1 जमा राशियां	11.3	10.8	9.2	8.2	9.2
2.1.2 ऋण	4.5	10.1	8.7	6.5	7.1
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	5.2	10.2	8.8	7.1	7.8
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	17.4	6.5	8.0	16.4	15.9
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	-12.9	14.7	16.0	-4.0	-5.1
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	10.6	13.7	10.4	5.6	6.5
3 अनुपात (%)					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	20.50	21.00	20.75	20.00	19.50
3.3 नकदी-जमा अनुपात	5.3	4.7	4.9	4.9	4.7
3.4 ऋण-जमा अनुपात	72.9	74.3	74.4	73.1	72.9
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात	41.4	32.0	22.3	88.8	76.8
3.6 निवेश-जमा अनुपात	28.2	28.3	29.0	30.5	30.8
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	28.4	30.2	42.6	184.4	337.6
4 व्याज दरें (%)					
4.1 नीति रिपो दर	6.25	6.50	6.25	6.00	6.00
4.2 रिवर्स रिपो दर	5.75	6.00	5.75	5.75	5.75
4.3 सीमांत स्थायी सुविधा दर	6.75	7.00	6.75	6.25	6.25
4.4 बैंक दर	6.75	7.00	6.75	6.25	6.25
4.5 आधार दर	9.25/9.60	9.30/9.65	9.30/9.65	9.00/9.55	8.95/9.45
4.6 एमसीएलआर (एक दिवसीय)	7.75/8.20	8.85/9.15	8.80/9.10	7.75/8.10	7.70/8.05
4.7 एक वर्ष से अधिक की मीयादी जमा दर	6.50/7.00	7.00/7.30	6.50/7.30	6.25/6.75	6.25/6.75
4.8 बचत जमा दर	4.00	4.00	4.00	3.50/4.00	3.50/4.00
4.9 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)	5.97	6.43	6.18	5.88	5.85
4.10 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	5.82	6.52	6.36	6.11	6.11
4.11 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.05	6.63	6.46	6.22	6.18
4.12 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.14	6.58	6.46	6.24	6.22
4.13 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर आय	7.00	6.81	6.83	6.83	7.00
5 आरबीआई संदर्भ दर और फारवर्ड प्रीमिआ					
5.1 भा.रु.-अमरीकी डालर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	64.84	66.66	66.86	65.36	65.09
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	69.25	74.75	72.91	77.06	75.68
5.3 फारवर्ड प्रीमिआ अमरीकी डालर 1-माह (%)	5.09	6.66	5.38	4.96	4.52
3-माह (%)	4.97	6.21	5.38	4.28	4.36
6-माह (%)	4.90	5.85	5.35	4.19	4.36
6 मुद्रास्फीति (%)					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	4.5	4.4	4.2	3.3	3.6
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	4.1	4.1	3.3	2.9	3.2
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	1.7	1.4	1.3	2.6	3.6
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	3.4	3.7	2.1	0.2	3.3
6.3.2 ईंधन और पावर	-0.3	-2.9	-1.2	9.0	10.5
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	1.3	1.1	1.3	2.7	2.6
7 विदेशी व्यापार (%परिवर्तन)					
7.1 आयात	0.5	-0.6	10.7	18.1	7.6
7.2 निर्यात	5.4	4.1	8.9	25.8	-1.1

भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 2 : भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(बिलियन ₹)

मद	अंतिम शुक्रवार/शुक्रवार की स्थिति						
	2016-17	2016	2017				
		नवंबर	अक्टू. 27	नवंबर 3	नवंबर 10	नवंबर 17	नवंबर 24
	1	2	3	4	5	6	7
1 निर्गम विभाग							
1.1 देयताएं							
1.1.1 संचलन में नोट	13,101.81	11,642.37	16,091.94	16,130.06	16,280.91	16,332.83	16,344.50
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	0.12	0.32	0.16	0.17	0.16	0.18	0.17
1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां	13,101.93	11,642.69	16,092.10	16,130.22	16,281.07	16,333.02	16,344.68
1.2 आस्तियां							
1.2.1 सोने के सिक्के और बुलियन	675.08	716.83	727.46	701.52	701.52	701.52	701.52
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	12,422.35	10,909.76	15,356.67	15,420.79	15,571.70	15,623.72	15,635.48
1.2.3 रुपया सिक्का	4.50	5.64	7.97	7.91	7.85	7.77	7.67
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	—	10.46	—	—	—	—	—
2 बैंकिंग विभाग							
2.1 देयताएं							
2.1.1 जमाराशियां	10,389.43	11,389.28	8,149.29	8,093.75	7,823.16	7,864.93	8,033.15
2.1.1.1 केंद्र सरकार	50.00	153.89	1.01	1.01	1.01	1.00	1.00
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	—	—	946.73	946.73	946.73	946.73	946.73
2.1.1.3 राज्य सरकारों	0.42	0.42	0.42	32.70	0.42	0.42	0.42
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	5,087.73	4,172.89	4,370.59	4,609.06	4,367.41	4,651.39	4,365.90
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	55.13	35.79	34.01	39.31	36.95	35.51	36.55
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	18.92	14.23	17.54	17.85	17.83	17.68	19.33
2.1.1.7 अन्य बैंक	279.49	232.52	255.32	260.32	256.54	254.20	258.77
2.1.1.8 अन्य	4,897.74	6,779.54	2,523.65	2,186.76	2,196.27	1,957.98	2,404.45
2.1.1.9 भारत के बाहर वित्तीय संस्थान	—	—	—	—	—	—	—
2.1.2 अन्य देयताएं	8,411.18	9,672.21	8,876.17	8,588.34	8,832.00	8,807.45	8,852.09
2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां	18,800.61	21,061.49	17,025.46	16,682.08	16,655.16	16,672.38	16,885.24
2.2 आस्तियां							
2.2.1 नोट और सिक्के	0.12	0.32	0.16	0.17	0.16	0.18	0.17
2.2.2 विदेश में रखे शेष	10,263.49	12,682.83	9,207.53	8,985.04	9,034.87	8,934.26	8,958.04
2.2.3 ऋण और अग्रिम							
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	—	—	—	—	—	—	—
2.2.3.2 राज्य सरकारों	12.62	14.21	2.53	41.46	41.91	11.23	29.03
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	218.10	30.70	327.40	223.75	247.05	390.30	562.72
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	—	—	—	0.35	—	—	—
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—	—	—
2.2.3.6 नाबार्ड	—	—	—	—	—	—	—
2.2.3.7 एक्विजिशन बैंक	—	—	—	—	—	—	—
2.2.3.8 अन्य	39.91	28.67	48.34	44.64	44.44	48.04	47.09
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल							
2.2.4.1 आंतरिक	—	—	—	—	—	—	—
2.2.4.2 सरकारी खजाना बिल	—	—	—	—	—	—	—
2.2.5 निवेश	7,528.11	7,577.27	6,734.24	6,702.17	6,599.22	6,599.85	6,600.36
2.2.6 अन्य आस्तियां	738.26	727.49	705.26	684.50	687.51	688.52	687.83
2.2.6.1 सोना	613.19	651.11	660.72	637.16	637.16	637.16	637.16

* डाटा अनंतिम है।

सं. 3 : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(बिलियन ₹)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा				एमएसएफ	स्थायी चलनिधि सुविधाएं	बाज़ार स्थिरीकरण योजना	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+6+9-2-4-7-8)
	रिपो	रिवर्स रिपो	परिवर्तन-शील रिपो दर	परिवर्तन-शील रिवर्स रिपो दर				विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4				5	6	
अक्तू. 3, 2017	21.35	145.09	6.25	590.25	10.35	-0.03	-	-	-	-697.42
अक्तू. 4, 2017	21.17	280.05	-	310.48	13.50	-	-	-	-	-555.86
अक्तू. 5, 2017	28.47	149.89	-	639.43	73.40	-	-	-	-	-687.45
अक्तू. 6, 2017	17.50	80.02	7.40	187.13	-	-	-	-	-	-242.25
अक्तू. 7, 2017	75.52	44.79	-	-	3.72	-	-	-	-	34.45
अक्तू. 9, 2017	187.64	56.65	-	-	32.70	-	-	-	-	163.69
अक्तू. 10, 2017	43.07	169.30	4.75	139.25	-	-	-	-	-	-260.73
अक्तू. 11, 2017	21.30	108.44	-	295.12	-	-	-	-	-	-382.26
अक्तू. 12, 2017	22.70	274.79	-	283.65	-	-	-	-	-	-535.74
अक्तू. 13, 2017	28.40	187.44	13.15	190.98	2.79	-0.90	-	100.00	-	-434.98
अक्तू. 16, 2017	190.41	59.94	-	-	32.15	-	-	-	-	162.62
अक्तू. 17, 2017	129.30	83.62	158.25	38.70	9.93	1.25	-	-	-	176.41
अक्तू. 18, 2017	14.00	40.88	17.40	495.55	22.25	-	-	-	-	-482.78
अक्तू. 19, 2017	-	5.66	-	-	25.20	-	-	-	-	19.54
अक्तू. 20, 2017	-	101.90	-	-	12.00	-	-	-	-	-89.90
अक्तू. 21, 2017	-	63.16	-	-	1.75	-	-	-	-	-61.41
अक्तू. 23, 2017	26.25	67.23	-	153.52	59.00	-	-	-	-	-135.50
अक्तू. 24, 2017	25.30	76.31	104.75	129.99	9.00	-1.20	-	-	-	-68.45
अक्तू. 25, 2017	34.25	167.01	-	68.37	0.75	1.01	-	-	-	-199.37
अक्तू. 26, 2017	30.40	309.85	-	121.75	-	-	-	-	-	-401.20
अक्तू. 27, 2017	62.00	319.75	13.85	170.03	-	-	-	100.00	-	-513.93
अक्तू. 30, 2017	156.95	111.76	-	121.02	0.59	-	-	-	-	-75.24
अक्तू. 31, 2017	106.50	190.98	57.75	108.57	-	-	-	-	-	-135.30

सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरीकी डालर का क्रय-विक्रय

i) ओटीसी सेगमेंट में परिचालन

मद	2016-17	2016	2017	
		अक्तू.	सितं.	अक्तू.
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमरीकी डालर) (1.1-1.2)	12,351.00	-418.00	1,259.00	852.00
1.1 क्रय (+)	71,764.00	9,548.00	3,788.00	1,910.00
1.2 विक्रय (-)	59,413.00	9,966.00	2,529.00	1,058.00
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (बिलियन ₹)	822.16	-30.99	81.08	57.31
3 संचयी (मार्च के अंत से) (मिलियन अमरीकी डालर)	12,351.00	10,292.00	16,301.00	17,153.00
(बिलियन ₹)	822.17	686.40	1,066.40	1,123.70
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमरीकी डालर)	10,835.00	5,632.00	31,131.00	31,374.00

ii) मुद्रा फ्यूचर्स सेगमेंट में परिचालन

मद	2016-17	2016	2017	
		अक्तू.	सितं.	अक्तू.
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमरीकी डालर) (1.1-1.2)	0.00	220.00	0.00	0.00
1.1 क्रय (+)	10,456.00	220.00	780.00	1,400.00
1.2 विक्रय (-)	10,456.00	0.00	780.00	1,400.00
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमरीकी डालर)	0.00	0.00	-1,400.00	0.00

सं. 4ए भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार)
परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	31 अक्टूबर 2017 तक		
	दीर्घ(+)	अल्प (-)	निवल(1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	2,455	1,350	1,105
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	6,006	621	5,385
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	26,090	527	25,563
4. 1 वर्ष से अधिक	927	1,606	-679
कुल (1+2+3+4)	35,478	4,104	31,374

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(बिलियन ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	2016-17	2016	2017					
			नव 25	जून 23	जुला. 21	अग. 18	सितं. 29	अक्तू. 27
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 सीमांत स्थायी सुविधा	19.3	4.8	2.5	6.8	3.5	194.8	-	5.5
2 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुनर्वित्त								
2.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
3 प्राथमिक व्यापारियों के लिए चलनिधि सुविधा								
3.1 सीमा	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
3.2 बकाया	14.8	11.7	16.7	15.4	18.1	19.3	19.4	17.9
4 अन्य								
4.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	34.1	16.4	19.2	22.1	21.5	214.1	19.4	23.3

मुद्रा और बैंकिंग

सं. 6: मुद्रा स्टॉक मात्रा

(बिलियन ₹)

मद	मार्च 31 /माह के नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2016-17	2016	2017		
		अक्तू. 28	सितं. 29	अक्तू. 13	अक्तू. 27
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	12,641.2	17,022.1	14,970.3	15,327.6	15,481.8
1.1 संचलन में नोट	13,101.8	17,540.2	15,632.5	15,928.4	16,091.9
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	243.4	227.7	247.4	247.4	247.4
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
1.4 बैंकों के पास नकदी	711.4	753.2	917.0	855.7	865.0
2 जनता की जमाराशियां	14,178.3	10,565.0	13,760.0	12,806.8	12,860.6
2.1 बैंकों के पास मांग जमाराशियां	13,967.4	10,405.4	13,503.1	12,581.9	12,635.7
2.2 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियां	210.9	159.6	256.9	224.9	224.8
3 एम₁ (1 + 2)	26,819.6	27,587.1	28,730.3	28,134.3	28,342.4
4 डाकघर बचत बैंक जमाराशियां	920.6	720.6	968.8	968.8	968.8
5 एम₂ (3 + 4)	27,740.2	28,307.6	29,699.2	29,103.2	29,311.2
6 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियां	101,099.8	96,062.0	103,113.0	103,651.3	103,328.9
7 एम₃ (3 + 6)	127,919.4	123,649.1	131,843.3	131,785.6	131,671.3
8 कुल डाकघर जमाराशियां	2,562.1	2,277.9	2,717.2	2,717.2	2,717.2
9 एम₄ (7 + 8)	130,481.4	125,926.9	134,560.5	134,502.8	134,388.5

सं. 7: मुद्रा स्टॉक (एम₃) का स्रोत

(बिलियन ₹)

स्रोत	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2016-17	2016		2017	
		अक्तू. 28	सितं. 29	अक्तू. 13	अक्तू. 27
	1	2	3	4	5
1 सरकार को निवल बैंक ऋण	38,566.1	37,263.5	40,773.0	41,136.2	40,415.1
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	6,208.1	6,472.7	5,428.9	5,425.6	4,922.8
1.1.1 सरकार पर दावे	7,512.0	7,563.8	6,967.3	6,860.0	6,711.0
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	7,499.4	7,545.7	6,950.9	6,814.2	6,708.5
1.1.1.2 राज्य सरकारें	12.6	18.0	16.4	45.9	2.5
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमाराशियां	1,303.9	1,091.1	1,538.4	1,434.5	1,788.2
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	1,303.5	1,090.7	1,538.0	1,434.1	1,787.8
1.1.2.2 राज्य सरकारें	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	32,358.0	30,790.9	35,344.1	35,710.6	35,492.3
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	84,114.9	79,457.3	85,519.8	84,596.4	84,832.8
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	72.9	73.7	74.4	72.7	81.8
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	84,042.0	79,383.6	85,445.5	84,523.7	84,751.0
2.2.1 वाणिज्य बैंकों द्वारा बैंक ऋण	78,414.7	73,844.1	79,834.4	78,907.4	79,121.7
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	5,548.9	5,489.6	5,529.7	5,530.8	5,540.8
2.2.3 वाणिज्य और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	78.4	49.9	81.4	85.6	88.5
3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)	25,582.3	26,364.4	27,212.8	27,122.1	27,084.9
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	23,972.1	24,487.1	26,078.3	25,987.6	25,950.4
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	23,974.1	24,489.2	26,080.3	25,989.6	25,952.4
3.1.2 विदेशी देयताएं	2.0	2.0	1.9	1.9	2.0
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	1,610.2	1,877.3	1,134.5	1,134.5	1,134.5
4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	250.9	235.1	254.8	254.8	254.8
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	20,594.8	19,671.3	21,917.2	21,323.9	20,916.3
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	8,333.5	9,086.2	9,055.4	8,938.5	8,883.3
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	12,261.3	10,585.0	12,861.8	12,385.4	12,033.1
एम₃ (1+2+3+4-5)	127,919.4	123,649.1	131,843.3	131,785.6	131,671.3

सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(बिलियन ₹)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2016-17	2016		2017	
		अक्तू. 28	सितं. 29	अक्तू. 13	अक्तू. 27
	1	2	3	4	5
मौद्रिक समुच्चय					
एन एम1 (1.1 + 1.2.1+1.3)	26,819.6	27,587.1	28,730.3	28,134.3	28,342.4
एन एम2 (एन एम1 + 1.2.2.1)	71,695.2	69,656.4	74,524.3	74,160.1	74,223.4
एन एम3 (एन एम2 + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4- 2.5)	129,706.3	124,085.8	133,583.8	133,532.4	133,531.5
1 घटक					
1.1 जनता के पास मुद्रा	12,641.2	17,022.1	14,970.3	15,327.6	15,481.8
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियां	113,690.9	103,892.8	115,267.4	114,861.4	114,593.6
1.2.1 मांग जमाराशियां	13,967.4	10,405.4	13,503.1	12,581.9	12,635.7
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	99,723.5	93,487.4	101,764.3	102,279.5	101,957.9
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	44,875.6	42,069.3	45,793.9	46,025.8	45,881.1
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	1,570.6	1,821.5	1,157.0	1,182.0	1,300.8
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	54,847.9	51,418.1	55,970.4	56,253.8	56,076.8
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	210.9	159.6	256.9	224.9	224.8
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग /सावधि निधीयन	3,163.2	3,011.3	3,089.2	3,118.5	3,231.2
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	129,185.0	123,371.4	132,764.0	132,873.7	132,413.3
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	38,566.1	37,263.5	40,773.0	41,136.2	40,415.1
2.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	6,208.1	6,472.7	5,428.9	5,425.6	4,922.8
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	32,358.0	30,790.9	35,344.1	35,710.6	35,492.3
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	90,618.9	86,107.9	91,991.0	91,737.5	91,998.3
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैंक ऋण	72.9	73.7	74.4	72.7	81.8
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	90,546.0	86,034.2	91,916.6	91,664.8	91,916.4
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)	6,462.5	6,552.9	6,423.6	7,065.7	7,094.4
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	250.9	235.1	254.8	254.8	254.8
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	23,819.8	23,245.7	25,594.4	25,603.7	25,819.1
2.3.1 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	23,972.1	24,487.1	26,078.3	25,987.6	25,950.4
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	-152.3	-1,241.5	-483.9	-383.9	-131.3
2.4 पूंजी खाता	18,195.5	18,732.9	19,907.6	19,796.9	19,784.0
2.5 अन्य मदें (निवल)	5,353.9	4,033.5	5,121.8	5,402.9	5,171.8

सं. 9: चलनिधि समुच्चय

(बिलियन ₹)

समुच्चय	2016-17	2016	2017		
		अक्तू.	अग.	सितं.	अक्तू.
	1	2	3	4	5
1 एन एम ₃	129,706.3	124,085.8	130,471.8	133,583.8	133,531.5
2 डाकघर जमाराशियां	2,562.1	2,277.9	2,717.2	2,717.2	2,717.2
3 एन ₁ (1 + 2)	132,268.3	126,363.6	133,189.1	136,301.0	136,248.7
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3
4.1 सावधि मुद्रा उधार	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
4.3 सावधि जमाराशियां	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
5 एन ₂ (3 + 4)	132,297.7	126,393.0	133,218.4	136,330.4	136,278.0
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियां	317.9	313.6	..
7 एन ₃ (5 + 6)	132,615.6	136,644.0	..

सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(बिलियन ₹)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2016-17	2016		2017	
		अक्तू. 28	सितं. 29	अक्तू. 13	अक्तू. 27
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 संचलन में मुद्रा	13,352.7	17,775.3	15,887.3	16,183.3	16,346.8
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमाराशियां	5,441.3	4,463.2	4,844.8	4,656.8	4,677.5
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	5,087.7	4,184.1	4,534.1	4,348.1	4,370.6
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	210.9	159.6	256.9	224.9	224.8
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	19,004.8	22,398.2	20,988.9	21,064.9	21,249.0
2 स्रोत					
2.1 भा.रि.बैं.के देशी ऋण	3,115.3	6,762.2	3,711.2	3,761.0	3,927.1
2.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण	6,208.1	6,472.7	5,428.9	5,425.6	4,922.8
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण(2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	6,195.9	6,455.0	5,413.0	5,380.1	4,920.7
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-
2.1.1.1.2 खज़ाना बिलों में निवेश	-	-	-	-	-
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	7,494.9	7,544.6	6,942.4	6,806.0	6,700.5
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	7,494.9	7,534.2	6,942.4	6,806.0	6,700.5
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	4.5	1.1	8.5	8.2	8.0
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमाराशियां	1,303.5	1,090.7	1,538.0	1,434.1	1,787.8
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल भा.रि.बैं. ऋण	12.2	17.6	15.9	45.4	2.1
2.1.2 बैंकों पर भा.रि.बैं. के दावे	-3,165.7	215.9	-1,792.1	-1,737.2	-1,077.6
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को ऋण और अग्रिम	-3,165.7	215.9	-1,792.1	-1,737.2	-1,077.6
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैं. के ऋण	72.9	73.7	74.4	72.7	81.8
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	14.8	14.8	19.3	18.4	19.4
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	250.9	235.1	254.8	254.8	254.8
2.3 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	23,972.1	24,487.1	26,078.3	25,987.6	25,950.4
2.3.1 सोना	1,288.3	1,426.9	1,324.6	1,388.2	1,388.2
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	22,684.0	23,060.4	24,753.9	24,599.6	24,562.4
2.4 पूंजी खाता	7,512.8	8,358.5	8,413.6	8,310.9	8,218.6
2.5 अन्य मदें (निवल)	820.6	727.8	641.8	627.6	664.6

सं. 11: आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत

(बिलियन ₹)

मद	मार्च 31 /माह के अंतिम शुक्रवार/शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया						
	2016-17	2016		2017			
		अक्तू. 28	सितं. 29	अक्तू. 6	अक्तू. 13	अक्तू. 20	अक्तू. 27
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	19,004.8	22,398.2	20,988.9	21,084.4	21,064.9	21,685.5	21,249.0
1 घटक							
1.1 संचलन में मुद्रा	13,352.7	17,775.3	15,887.3	16,003.6	16,183.3	16,464.9	16,346.8
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमाराशियां	5,441.3	4,463.2	4,844.8	4,825.4	4,656.8	4,990.7	4,677.5
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	210.9	159.6	256.9	255.4	224.9	229.9	224.8
2 स्रोत							
2.1 सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण	6,208.1	6,472.7	5,428.9	5,846.2	5,425.6	5,150.3	4,922.8
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण	-3,165.7	215.9	-1,792.1	-2,144.3	-1,737.2	-865.8	-1,077.6
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण	72.9	73.7	74.4	70.3	72.7	67.0	81.8
2.4 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	23,972.1	24,487.1	26,078.3	26,002.6	25,987.6	26,014.4	25,950.4
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	250.9	235.1	254.8	254.8	254.8	254.8	254.8
2.6 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	8,333.5	9,086.2	9,055.4	8,945.3	8,938.5	8,935.3	8,883.3

सं. 12: वाणिज्य बैंक सर्वेक्षण

(बिलियन ₹)

मद	माह के नियत अंतिम शुक्रवार/ माह के नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2016-17	2016		2017	
		अक्तू. 28	सितं. 29	अक्तू. 13	अक्तू. 27
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 निवासियों की कुल जमाराशियां	106,200.3	96,743.3	107,826.7	107,398.7	107,126.4
1.1.1 मांग जमाराशियां	12,814.4	9,342.7	12,368.8	11,445.7	11,504.0
1.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	93,385.9	87,400.6	95,457.9	95,953.0	95,622.4
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	42,023.6	39,330.3	42,956.1	43,178.9	43,030.1
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	1,570.6	1,821.5	1,157.0	1,182.0	1,300.8
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	51,362.2	48,070.3	52,501.9	52,774.2	52,592.3
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	3,163.2	3,011.3	3,089.2	3,118.5	3,231.2
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	115,141.3	109,239.5	119,476.5	119,603.5	119,625.6
2.1.1 सरकार को ऋण	30,297.5	28,813.9	33,245.1	33,626.2	33,406.8
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	84,843.8	80,425.6	86,231.5	85,977.3	86,218.9
2.1.2.1 बैंक ऋण	78,414.7	73,844.1	79,834.4	78,907.4	79,121.7
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	77,875.4	72,821.8	79,370.7	78,421.6	78,499.5
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	44.2	100.3	50.2	77.9	73.6
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	12.2	17.9	12.9	15.9	18.7
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	6,372.9	6,463.3	6,334.0	6,976.1	7,004.8
2.2 वाणिज्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	-152.3	-1,241.5	-483.9	-383.9	-131.3
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	1,983.5	2,243.4	1,726.6	1,833.4	2,075.0
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियां	1,376.3	2,574.6	1,348.7	1,371.8	1,371.0
2.2.3 समुद्रपार विदेशी मुद्रा उधार	759.5	910.3	861.9	845.5	835.3
2.3 निवल बैंक रिज़र्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	8,867.0	4,623.3	7,144.4	6,839.4	6,211.8
2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शेष	5,087.7	4,184.1	4,534.1	4,348.1	4,370.6
2.3.2 उपलब्ध नकदी	613.6	655.1	818.3	754.1	763.6
2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम	-3,165.7	215.9	-1,792.1	-1,737.2	-1,077.6
2.4 पूंजी खाता	10,441.0	10,132.7	11,252.3	11,244.3	11,323.7
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	4,051.6	2,734.1	3,968.7	4,297.5	4,024.8
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	3,877.6	3,910.1	4,008.2	3,682.6	3,850.8
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	-62.4	-267.7	-291.2	-432.4	-491.7

सं. 13: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेश

(बिलियन ₹)

मद	मार्च 31, 2017 की स्थिति	2016		2017	
		अक्तू. 28	सितं. 29	अक्तू. 13	अक्तू. 27
		1	2	3	4
1 एसएलआर प्रतिभूतियां	30,309.6	28,831.8	33,258.0	33,642.1	33,425.5
2 वाणिज्यिक पत्र	1,159.6	1,079.0	1,040.4	1,093.4	1,085.0
3 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर					
3.1 सरकारी उद्यम	91.9	77.1	110.8	108.0	112.8
3.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	567.3	478.2	677.9	691.4	696.7
3.3 अन्य	51.8	43.6	42.8	42.6	43.0
4 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर					
4.1 सरकारी उद्यम	1,118.5	1,189.9	1,121.4	1,065.2	1,065.2
4.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	1,680.0	1,529.5	1,822.7	1,804.9	1,823.7
4.3 अन्य	810.9	726.0	635.4	654.6	659.0
5 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
5.1 म्यूचुअल फंड	134.0	801.7	203.9	783.0	790.9
5.2 वित्तीय संस्थाएं	844.3	635.4	787.4	732.9	728.6

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

(बिलियन ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में) /नियत शुक्रवार की स्थिति							
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक			
	2016-17	2016	2017		2016-17	2016	2017	
		अक्त.	सित.	अक्त.		अक्त.	सित.	अक्त.
	1	2	3	4	5	6	7	8
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	221	219	221	221	150	148	147	147
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	2,397.7	2,315.3	2,214.8	2,186.1	2,330.7	2,247.5	2,161.1	2,133.8
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	1,765.5	1,646.7	1,577.1	1,483.3	1,698.6	1,579.6	1,525.4	1,432.6
1.2 बैंकों से उधार राशि	573.6	591.4	545.0	580.6	573.5	590.7	544.5	580.3
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	58.6	77.2	92.6	122.2	58.6	77.2	91.2	121.0
2 अन्य के प्रति देयताएं	118,405.4	109,941.0	120,187.2	119,470.5	115,376.9	107,149.6	117,134.6	116,414.6
2.1 कुल जमाराशियां	110,485.7	102,001.9	112,088.1	111,426.4	107,576.6	99,317.9	109,175.4	108,497.4
2.1.1 मांग	13,104.8	9,561.2	12,645.3	11,778.3	12,814.4	9,342.7	12,368.8	11,504.0
2.1.2 मीयादी	97,381.0	92,440.7	99,442.7	99,648.1	94,762.2	89,975.2	96,806.6	96,993.4
2.2 उधार	3,192.8	3,034.4	3,125.1	3,266.0	3,163.2	3,011.3	3,089.2	3,231.2
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	4,726.9	4,904.7	4,974.0	4,778.1	4,637.1	4,820.4	4,870.0	4,686.0
3 रिज़र्व बैंक से उधार	218.1	525.1	405.3	327.4	218.1	525.1	405.3	327.4
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	—	—	—	—	—	—	—	—
3.2 अन्य	218.1	525.1	405.3	327.4	218.1	525.1	405.3	327.4
4 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	5,869.3	4,973.6	5,489.9	5,273.1	5,701.3	4,839.2	5,352.3	5,134.2
4.1 उपलब्ध नकदी	630.5	673.4	836.4	784.9	613.60	655.1	818.3	763.6
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	5,238.8	4,300.2	4,653.6	4,488.2	5,087.7	4,184.1	4,534.1	4,370.6
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	2,934.5	3,039.1	2,927.9	3,141.7	2,437.3	2,615.5	2,502.6	2,699.1
5.1 अन्य बैंकों के पास शेष	1,898.0	1,889.4	2,018.7	2,118.7	1,700.1	1,711.4	1,823.4	1,926.1
5.1.1 चालू खाते में	197.3	159.3	188.5	179.7	160.6	139.7	157.1	159.5
5.1.2 अन्य खातों में	1,700.7	1,730.2	1,830.2	1,939.0	1,539.5	1,571.6	1,666.2	1,766.5
5.2 मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	296.9	465.7	386.0	463.8	77.0	286.4	230.1	287.9
5.3 बैंकों को अग्रिम	380.4	298.5	259.8	255.2	379.5	295.1	258.7	247.2
5.4 अन्य आस्तियां	359.1	385.4	263.5	303.9	280.7	322.7	190.4	237.9
6 निवेश	31,161.1	29,631.3	34,220.4	34,374.4	30,309.6	28,831.8	33,258.0	33,425.5
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	31,144.8	29,606.7	34,158.4	34,305.3	30,297.5	28,813.9	33,245.1	33,406.8
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	16.4	24.5	62.0	69.1	12.2	17.9	12.9	18.7
7 बैंक ऋण	80,817.8	76,099.2	82,287.6	81,584.2	78,414.7	73,844.1	79,834.4	79,121.7
7क खाद्यान्न ऋण	652.4	1,185.0	655.2	813.7	539.3	1,022.3	463.7	622.3
7.1 ऋण नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	78,490.1	74,023.0	80,047.2	79,465.3	76,148.5	71,822.6	77,651.4	77,059.7
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	263.5	227.6	212.0	240.9	246.0	210.3	200.2	227.7
7.3 देशी बिल- भुनाए गए	1,402.8	1,243.6	1,364.6	1,271.7	1,365.9	1,212.2	1,325.0	1,234.2
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	248.6	220.3	255.4	225.7	246.4	219.3	254.1	224.4
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	412.7	384.6	408.4	380.5	407.9	379.7	403.7	375.8

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन

(बिलियन ₹)

मद	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 31, 2017	2016	2017		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		अक्तू. 28	सितं. 29	अक्तू. 27	2017-18	2017
	1	2	3	4	5	6
1 सकल बैंक ऋण	71,347	67,055	72,068	70,996	-0.5	5.9
1.1 खाद्यान्न ऋण	400	815	398	412	2.9	-49.5
1.2 गैर-खाद्यान्न ऋण	70,947	66,239	71,671	70,584	-0.5	6.6
1.2.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	9,924	9,302	9,971	9,810	-1.1	5.5
1.2.2 उद्योग	26,800	26,047	26,404	25,991	-3.0	-0.2
1.2.2.1 सूक्ष्म और लघु	3,697	3,543	3,690	3,585	-3.0	1.2
1.2.2.2 मझौले	1,048	1,087	1,019	940	-10.3	-13.5
1.2.2.3 बड़े	22,055	21,417	21,696	21,466	-2.7	0.2
1.2.3 सेवाएं	18,022	15,849	17,749	17,336	-3.8	9.4
1.2.3.1 परिवहन परिचालक	1,104	1,020	1,126	1,123	1.7	10.2
1.2.3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	179	181	181	173	-3.2	-4.4
1.2.3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	375	383	370	364	-2.9	-5.0
1.2.3.4 नौवहन	84	105	75	70	-16.9	-33.5
1.2.3.5 पेशेवर सेवाएं	1,377	1,218	1,305	1,366	-0.8	12.1
1.2.3.6 व्यापार	4,279	3,925	4,346	4,265	-0.3	8.6
1.2.3.6.1 थोक व्यापार	1,932	1,741	1,875	1,855	-4.0	6.5
1.2.3.6.2 खुदरा व्यापार	2,347	2,184	2,471	2,410	2.7	10.3
1.2.3.7 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	1,856	1,787	1,863	1,829	-1.4	2.4
1.2.3.8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	3,910	3,345	3,862	3,615	-7.6	8.1
1.2.3.9 अन्य सेवाएं	4,859	3,885	4,619	4,531	-6.8	16.6
1.2.4 व्यक्तिगत ऋण	16,200	15,041	17,547	17,447	7.7	16.0
1.2.4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	208	196	178	178	-14.6	-9.4
1.2.4.2 आवास	8,601	8,113	9,086	9,035	5.0	11.4
1.2.4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	661	613	653	532	-19.6	-13.3
1.2.4.4 शेयरों और बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	48	46	57	54	14.6	17.8
1.2.4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	521	463	599	637	22.2	37.7
1.2.4.6 शिक्षा	701	710	720	718	2.4	1.0
1.2.4.7 वाहन ऋण	1,705	1,680	1,786	1,804	5.8	7.4
1.2.4.8 अन्य व्यक्तिगत ऋण	3,755	3,220	4,468	4,489	19.5	39.4
1.2अ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	24,357	22,985	24,266	23,792	-2.3	3.5
1.2अ.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	9,909	9,286	9,950	9,771	-1.4	5.2
1.2अ.2 सूक्ष्म और लघु उद्यम	9,020	8,468	9,079	8,867	-1.7	4.7
1.2अ.2.1 विनिर्माण	3,697	3,543	3,690	3,585	-3.0	1.2
1.2अ.2.2 सेवाएं	5,322	4,925	5,389	5,282	-0.8	7.3
1.2अ.3 आवास	3,683	3,566	3,688	3,662	-0.6	2.7
1.2अ.4 माइक्रो क्रेडिट	189	183	164	167	-11.6	-8.8
1.2अ.5 शिक्षा ऋण	604	610	600	589	-2.5	-3.3
1.2अ.6 अजा/अजजा के लिए राज्य प्रायोजित संस्थाएं	6	6	3	3	-55.8	-55.8
1.2अ.7 कमजोर वर्ग	5,546	5,121	5,422	5,430	-2.1	6.0
1.2अ.8 निर्यात ऋण	425	456	458	434	2.1	-4.9

सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार अभिनियोजन

(बिलियन ₹)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 31, 2017	2016	2017		वित्तीय वर्ष में अब तक 2017-18	वर्ष-दर-वर्ष 2017
		अक्तू. 28	सितं. 29	अक्तू. 27		
	1	2	3	4	5	6
1 उद्योग	26,800	26,047	26,404	25,991	-3.0	-0.2
1.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	345	344	329	324	-5.9	-5.7
1.2 खाद्य प्रसंस्करण	1,455	1,293	1,385	1,339	-8.0	3.6
1.2.1 चीनी	327	292	280	264	-19.2	-9.5
1.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	184	162	179	178	-3.0	10.2
1.2.3 चाय	35	39	42	43	21.6	10.2
1.2.4 अन्य	909	800	883	854	-6.1	6.6
1.3 पेय पदार्थ और तंबाकू	173	168	163	155	-10.0	-7.7
1.4 वस्त्र	1,963	1,906	1,954	1,935	-1.4	1.5
1.4.1 सूती वस्त्र	964	908	971	958	-0.5	5.5
1.4.2 जूट से बने वस्त्र	23	21	27	25	8.3	17.3
1.4.3 मानव-निर्मित वस्त्र	204	196	225	227	11.3	15.7
1.4.4 अन्य वस्त्र	773	780	730	724	-6.2	-7.2
1.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद	107	104	111	108	0.7	3.6
1.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद	105	104	106	105	-0.5	1.0
1.7 कागज़ और कागज़ से बने उत्पाद	326	345	312	308	-5.7	-10.9
1.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आण्विक इंधन	596	482	472	461	-22.7	-4.5
1.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद	1,724	1,516	1,575	1,529	-11.3	0.8
1.9.1 उर्वरक	335	255	246	243	-27.4	-4.8
1.9.2 औषधि और दवाइयां	464	471	477	459	-1.0	-2.5
1.9.3 पेट्रो केमिकल्स	507	372	432	418	-17.6	12.2
1.9.4 अन्य	419	418	419	409	-2.2	-2.0
1.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	392	366	406	401	2.3	9.4
1.11 कांच और कांच के सामान	79	84	78	78	-1.1	-6.6
1.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद	542	538	578	535	-1.3	-0.5
1.13 मूल धातु और धातु उत्पाद	4,211	4,116	4,169	4,144	-1.6	0.7
1.13.1 लोहा और स्टील	3,192	3,095	3,225	3,223	0.9	4.1
1.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	1,018	1,020	944	922	-9.5	-9.7
1.14 सभी अभियांत्रिकी	1,496	1,499	1,508	1,507	0.7	0.6
1.14.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	336	344	349	363	8.0	5.6
1.14.2 अन्य	1,160	1,155	1,159	1,144	-1.4	-0.9
1.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपस्कर	736	719	712	702	-4.6	-2.4
1.16 रत्न और आभूषण	690	685	724	696	0.8	1.5
1.17 निर्माण	822	787	834	839	2.1	6.7
1.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर	9,064	8,971	8,949	8,839	-2.5	-1.5
1.18.1 पावर	5,254	5,208	5,262	5,161	-1.8	-0.9
1.18.2 दूरसंचार	851	838	871	846	-0.5	0.9
1.18.3 सड़क	1,800	1,810	1,717	1,727	-4.1	-4.6
1.18.4 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	1,160	1,114	1,099	1,105	-4.7	-0.8
1.19 अन्य उद्योग	1,973	2,020	2,040	1,986	0.6	-1.7

सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(बिलियन ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में)/अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति					
	2016-17	2016	2017			
		जुला. 29	जून 30	जुला. 07	जुला. 21	जुला. 28
	1	2	3	4	5	6
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	32	32	29	29	30	29
1 कुल जमाराशियां (2.1.1.2+2.2.1.2)	527.8	438.5	506.3	518.5	538.0	519.2
2 मांग और मीयादी देयताएं						
2.1 मांग देयताएं	183.2	162.1	155.0	158.0	164.9	163.1
2.1.1 जमाराशियां						
2.1.1.1 अंतर-बैंक	45.0	41.7	30.9	36.8	39.0	39.2
2.1.1.2 अन्य	106.3	83.6	94.4	95.4	100.6	98.8
2.1.2 बैंकों से उधार	2.0	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	30.0	28.2	29.7	25.9	25.2	25.1
2.2 मीयादी देयताएं	947.6	839.5	872.1	881.1	889.2	867.8
2.2.1 जमाराशियां						
2.2.1.1 अंतर-बैंक	512.6	478.2	453.6	451.5	445.4	439.4
2.2.1.2 अन्य	421.5	354.8	412.0	423.1	437.4	420.4
2.2.2 बैंकों से उधार	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	9.2	6.4	6.5	6.5	6.4	8.1
3 रिज़र्व बैंक से उधार	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 अधिसूचित बैंक/राज्य सरकार से उधार	517.2	390.2	462.5	467.4	443.5	434.9
4.1 मांग	180.4	105.4	178.8	178.0	170.3	168.8
4.2 मीयादी	336.8	284.8	283.7	289.4	273.2	266.2
5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	66.6	43.4	46.4	46.7	45.4	45.6
5.1 उपलब्ध नकदी	3.7	2.7	3.0	2.7	2.9	3.2
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	62.9	40.8	43.4	44.0	42.5	42.4
6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेष	17.5	6.3	7.1	7.2	7.5	7.2
7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	329.8	281.3	312.6	312.3	312.8	309.8
8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	254.4	204.9	223.8	228.9	213.5	211.7
9 बैंक ऋण (10.1+11)	458.7	449.2	482.5	477.5	483.6	475.6
10 अग्रिम						
10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	458.6	449.1	482.5	477.5	483.6	475.6
10.2 बैंकों से प्राप्य राशि	777.0	691.3	732.2	730.8	713.1	716.0
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

मूल्य और उत्पादन

सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)

समूह/उप समूह	2016-17			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	अक्तू. 16	सितं. 17	अक्तू. 17	अक्तू. 16	सितं. 17	अक्तू. 17	अक्तू. 16	सितं. 17	अक्तू. 17
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 खाद्य और पेय पदार्थ	135.3	134.9	135.2	137.4	139.6	140.4	136.3	138.0	139.7	137.0	139.0	140.1
1.1 अनाज और उत्पाद	130.8	128.9	130.2	131.3	135.2	135.9	128.7	133.6	133.9	130.5	134.7	135.3
1.2 मांस और मछली	137.9	140.1	138.7	137.6	142.0	141.9	138.4	143.0	142.8	137.9	142.4	142.2
1.3 अंडा	128.9	130.7	129.6	130.1	130.5	130.9	130.3	129.7	131.4	130.2	130.2	131.1
1.4 दूध और उत्पाद	135.2	132.4	134.1	136.0	140.2	141.5	132.7	138.7	139.1	134.8	139.6	140.6
1.5 तेल और चर्बी	120.3	112.0	117.3	120.8	120.7	121.4	112.5	114.5	114.9	117.8	118.4	119.0
1.6 फल	138.1	132.8	135.6	138.4	147.8	146.6	130.4	137.5	135.6	134.7	143.0	141.5
1.7 सब्जी	139.2	144.8	141.1	149.2	154.5	157.0	155.1	160.7	173.2	151.2	156.6	162.5
1.8 दाल और उत्पाद	165.6	170.3	167.2	170.2	137.1	136.4	175.7	124.5	124.1	172.1	132.9	132.3
1.9 चीनी और उत्पाद	112.1	114.9	113.0	113.4	121.0	121.4	115.4	122.4	122.6	114.1	121.5	121.8
1.10 मसाले	135.1	143.8	138.0	136.3	134.7	135.5	145.3	137.3	137.8	139.3	135.6	136.3
1.11 गैर नशीले पेय पदार्थ	128.1	122.4	125.7	128.7	131.7	131.3	122.5	124.8	125.1	126.1	128.8	128.7
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	141.7	139.2	140.5	142.4	149.3	150.3	139.6	145.0	145.5	141.1	147.3	148.1
2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ	140.1	144.2	141.2	140.9	149.8	150.5	144.3	153.6	154.6	141.8	150.8	151.6
3 कपड़ा और जूते	137.9	127.8	133.9	138.8	145.2	146.3	128.0	132.0	132.6	134.5	140.0	140.9
3.1 कपड़ा	138.6	128.9	134.8	139.6	146.1	147.2	129.1	133.3	134.0	135.5	141.1	142.0
3.2 जूते	133.7	121.7	128.7	134.3	139.7	140.6	121.9	124.6	124.9	129.1	133.4	134.1
4 आवास	--	128.0	128.0	--	--	--	128.7	135.7	137.3	128.7	135.7	137.3
5 ईंधन और लाइट	130.1	116.4	124.9	129.8	137.4	138.1	115.2	120.6	122.6	124.3	131.0	132.2
6 विविध	125.0	120.6	122.9	125.7	130.3	130.7	120.9	124.5	124.5	123.4	127.5	127.7
6.1 घरेलू सामान और सेवा	131.3	124.3	128.0	131.8	137.9	138.4	124.5	128.1	128.3	128.4	133.3	133.6
6.2 स्वास्थ्य	128.1	121.6	125.6	128.7	133.4	134.1	121.8	126.1	126.6	126.1	130.6	131.3
6.3 परिवहन और संचार	117.4	112.8	114.9	117.8	121.2	120.9	112.8	115.7	115.0	115.2	118.3	117.8
6.4 मनोरंजन	125.9	121.0	123.2	126.5	132.3	132.9	121.2	124.5	124.8	123.5	127.9	128.3
6.5 शिक्षा	132.3	131.1	131.6	133.0	139.6	140.1	131.9	135.9	136.3	132.4	137.4	137.9
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव	121.7	120.3	121.1	123.0	126.7	127.4	120.8	124.4	124.6	122.1	125.7	126.2
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	132.4	127.9	130.3	133.8	137.6	138.3	128.6	132.4	133.5	131.4	135.2	136.1

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	योजक कारक	2016-17	2017		
				अक्तू.	सितं.	अक्तू.
	1	2	3	4	5	6
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2001	4.63	276	278	285	287
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	5.89	870	876	893	901
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	-	875	881	899	907

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 20: मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2016-17	2017		
		अक्तू.	सितं.	
	1	2	3	4
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)	29,665	30,071	29,899	29,505
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)	42,748	43,230	40,120	39,385

स्रोत: मुंबई में सोने और चांदी के मूल्य के लिए भारत बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लि., मुंबई।

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारत	2016-17	2016	2017		
			अक्तू.	अग.	सितं. (अ)	अक्तू. (अ)
	1	2	3	4	5	6
1 सभी पण्य	100.000	111.6	111.5	114.8	114.3	115.5
1.1 प्राथमिक वस्तुएं	22.618	128.9	129.1	135.3	130.8	133.4
1.1.1 खाद्य वस्तुएं	15.256	140.3	141.9	150.9	144.8	148.0
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+ दाल)	3.462	152.0	155.2	143.0	144.0	143.1
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	138.7	145.5	191.4	162.9	177.1
1.1.1.3 दूध	4.440	134.3	134.8	139.7	140.1	140.0
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	133.0	128.5	134.9	134.9	135.9
1.1.1.5 मसाले	0.529	140.5	142.0	122.9	124.0	125.1
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं	0.948	150.5	147.9	140.3	139.5	139.3
1.1.2 खाद्येतर वस्तुएं	4.119	122.2	120.0	120.8	120.3	119.2
1.1.2.1 फाइबर	0.839	117.1	115.0	119.0	117.5	113.2
1.1.2.2 तिलहन	1.115	136.0	131.4	127.1	128.0	128.1
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएं	1.960	114.9	113.8	114.3	115.0	113.4
1.1.2.4 फूल	0.204	137.4	137.6	155.2	140.4	151.8
1.1.3 खनिज	0.833	113.1	105.2	120.8	119.5	120.8
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	98.4	88.0	107.6	105.1	107.6
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	164.4	165.3	166.9	169.9	166.9
1.1.4 कच्चा तेल और नैसर्गिक गैस	2.410	73.1	71.3	66.0	64.3	69.8
1.2 ईंधन और बिजली	13.152	86.3	84.6	89.1	90.7	93.5
1.2.1 कोल	2.138	109.0	107.0	117.5	117.5	117.5
1.2.1.1 कुकिंग कोल	0.647	108.2	101.4	135.5	135.5	135.5
1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोल	1.401	110.5	110.7	110.7	110.7	110.7
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	90.2	88.8	95.0	95.0	95.0
1.2.2 खनिज तेल	7.950	73.3	71.2	77.0	79.1	82.2
1.2.3 बिजली	3.064	104.2	103.9	100.6	102.0	106.1
1.3 विनिर्मित उत्पाद	64.231	110.7	110.8	112.8	113.4	113.7
1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	9.122	125.4	126.7	127.4	128.2	128.3
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	137.1	136.3	132.7	131.8	133.6
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियस,मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	127.7	130.7	128.2	125.9	129.5
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	120.2	121.1	119.4	118.2	118.9
1.3.1.4 सब्जियाँ और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	107.0	107.6	106.3	107.9	108.3
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	132.3	133.1	143.4	144.2	143.8
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	136.2	138.8	137.4	139.2	139.2
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	114.6	114.3	111.7	112.0	112.7
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	127.0	127.8	128.4	128.7	128.5
1.3.1.9 चीनी,गुड़ और शहद	1.163	124.8	126.3	133.4	133.1	132.3
1.3.1.10 कोक, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	125.5	125.9	127.0	123.9	126.8
1.3.1.11 मैक्रोनी,नूडल्स,और कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	137.1	144.3	130.4	130.4	132.3
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	125.9	126.5	131.3	132.2	132.3
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	124.5	125.9	114.8	114.2	115.0
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	126.3	126.7	127.0	126.2	127.1
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	143.2	145.6	142.7	144.5	141.8
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	165.4	168.1	152.9	152.4	151.2
1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण	0.909	116.1	115.9	118.6	120.1	119.0
1.3.2.1 शराब और स्पिरिट	0.408	113.3	113.9	114.1	114.5	113.5
1.3.2.2 माल्ट लिकर और माल्ट	0.225	114.2	114.9	117.8	118.4	118.1
1.3.2.3 शीतल पेय,मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी के अन्य उत्पाद	0.275	121.8	119.6	125.8	129.9	127.8
1.3.3 विनिर्मित तंबाकू उत्पाद	0.514	141.6	140.6	149.7	150.9	148.9
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	141.6	140.6	149.7	150.9	148.9
1.3.4 वस्त्र विनिर्माण	4.881	111.2	110.8	113.7	113.4	113.2
1.3.4.1 धागों की कटाई और वस्त्र तैयार करना	2.582	103.3	103.3	106.3	106.2	105.5
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	120.9	120.2	123.1	122.2	122.5
1.3.4.3 बुने हुए और क्रॉचिडेट फेब्रिक्स	0.193	107.1	106.4	107.2	106.9	108.6
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	121.7	121.6	124.4	124.3	124.0
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	143.0	139.1	141.9	143.1	143.7
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	112.9	110.7	116.4	116.2	116.2
1.3.5 विनिर्मित तैयार वस्त्र	0.814	131.0	131.1	136.1	136.6	137.1
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर वुलन के तैयार वस्त्र	0.593	133.9	132.2	137.5	138.3	138.2
1.3.5.2 बुने हुए क्रॉचिडेट वस्त्र	0.221	123.3	128.1	132.2	131.9	134.1

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारंक्र	2016-17	2017			
			अक्तू.		सितं. (अ)	
			अग.	अक्तू. (अ)	अग.	अक्तू. (अ)
1	2	3	4	5	6	
1.3.6 चमड़ा और उससे बने हुए उत्पाद का विनिर्माण	0.535	122.6	123.1	119.3	119.2	119.1
1.3.6.1 चमड़े की टैनिंग और ड्रेसिंग; ड्रेसिंग और फर की रंगायी	0.142	119.9	120.3	109.0	109.0	109.2
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और दोहन	0.075	132.3	133.7	128.5	130.3	132.6
1.3.6.3 जूते-चप्पल	0.318	121.5	121.9	121.8	121.2	120.3
1.3.7 लकड़ी के विनिर्माण और लकड़ी और कॉर्क के उत्पाद	0.772	129.8	128.5	132.2	132.4	132.3
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	122.9	122.7	120.5	118.9	119.2
1.3.7.2 विनियर शीट, प्लायवुड का विनिर्माण, लॅमिन बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड और अन्य पॅनल और बोर्ड	0.493	127.3	125.7	131.4	132.2	132.1
1.3.7.3 बिल्डरों की बढ़ईगीरी	0.036	153.8	157.5	163.3	163.3	160.4
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	140.3	137.9	138.4	138.6	138.3
1.3.8 कागज़ और कागज़ के उत्पाद का विनिर्माण	1.113	113.6	112.9	118.1	119.3	119.6
1.3.8.1 लुगदी, कागज़ और कागज़ बोर्ड	0.493	117.7	116.8	120.2	122.0	122.4
1.3.8.2 लहरदार कागज़ और पेपर बोर्ड और कागज़ के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	114.7	115.0	117.1	119.5	119.5
1.3.8.3 कागज़ की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	105.9	104.4	115.9	114.9	115.3
1.3.9 मुद्रण और रिकार्ड मीडिया का पुनरुत्पादन	0.676	141.1	141.2	143.8	144.6	143.1
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	141.1	141.2	143.8	144.6	143.1
1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पाद का विनिर्माण	6.465	111.0	110.3	111.1	111.3	111.7
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	104.7	103.9	107.7	107.5	108.6
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	118.7	118.3	116.5	116.7	116.8
1.3.10.3 प्लास्टिक और सिंथेटिक रबड़ प्राथमिक रूप में	1.001	113.7	112.1	111.3	112.6	112.7
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एगोकेमिकल उत्पाद	0.454	116.8	115.3	114.9	115.1	114.8
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	108.5	108.4	108.8	108.7	108.9
1.3.10.6 साबुन और डिटरजेंट, सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	113.7	113.9	115.5	114.7	114.6
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	106.5	106.2	108.4	108.9	109.1
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	94.1	92.4	96.3	95.8	97.1
1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण	1.993	119.7	119.8	120.7	121.5	122.1
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	119.7	119.8	120.7	121.5	122.1
1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद का विनिर्माण	2.299	107.5	106.9	107.6	106.8	107.6
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब, रबड़ टायर की रिट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	101.4	101.5	100.5	100.3	100.0
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	90.4	88.4	91.3	91.2	91.7
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	113.3	112.8	113.8	112.5	114.0
1.3.13 अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	3.202	109.8	110.3	111.4	111.9	111.8
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	116.6	116.4	118.6	117.0	117.1
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	116.2	115.2	111.4	113.3	113.4
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	94.3	87.9	89.0	87.5	90.9
1.3.13.4 चीनी मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी	0.222	111.8	111.7	113.0	112.8	113.0
1.3.13.5 सीमेन्ट, चूना और प्लास्टर	1.645	110.6	112.6	113.0	114.1	113.4
1.3.13.6 कंक्रीट, सीमेन्ट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं	0.292	115.3	115.0	118.4	119.1	120.0
1.3.13.7 पत्थरों को काटना, आकार देना और सवारना	0.234	117.4	116.5	116.3	116.5	116.4
1.3.13.8 अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद	0.169	70.9	68.9	78.4	77.4	77.4
1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण	9.646	91.1	91.0	98.5	100.4	100.7
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	82.9	82.5	93.7	96.9	97.0
1.3.14.2 मेटलिक आयरन	0.653	79.4	84.1	95.1	101.7	99.2
1.3.14.3 नरम इस्पात-अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	89.8	90.6	92.1	93.4	92.7
1.3.14.4 नरम इस्पात- लंबे उत्पाद	1.081	85.3	83.8	92.0	91.9	91.7
1.3.14.5 नरम इस्पात- चपटे उत्पाद	1.144	89.4	89.8	99.9	103.3	104.8
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	85.6	84.2	92.3	93.4	93.3
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील अर्ध निर्मित	0.924	84.1	85.3	95.4	96.9	95.8
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	107.8	106.8	112.6	114.3	116.1
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	100.1	98.2	105.9	107.5	109.0
1.3.14.10 कास्टिंग	0.925	102.2	100.1	104.2	103.7	105.7
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं	0.271	118.2	120.3	117.5	118.1	117.7
1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण	3.155	105.1	105.1	106.3	108.5	108.8
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	102.5	102.1	104.1	105.4	105.5
1.3.15.2 धातु से बने टैंक, जलाशय और डिब्बे	0.660	109.2	107.2	117.5	119.7	121.6
1.3.15.3 बाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलर्स को छोड़कर	0.145	108.5	110.9	109.4	109.4	109.4
1.3.15.4 धातु की फोर्जिंग, दबाना, स्टैपिंग और रोल फॉर्मिंग, पाउडर धातुकर्म	0.383	94.7	93.6	87.5	88.7	89.8
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हाईवेयर	0.208	111.5	111.2	93.5	107.6	93.6
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	108.1	110.5	112.0	113.1	116.3
1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण	2.009	108.3	108.5	109.5	109.2	111.8
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे	0.402	106.7	106.0	104.0	104.0	104.3
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	127.3	127.3	127.4	127.4	127.4

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (समाप्त)
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारत	2016-17	2017			
			अक्तू.	अग.	सितं. (अ)	
					अक्तू. (अ)	
1	2	3	4	5	6	
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	104.1	104.1	104.7	104.7	116.0
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	0.641	100.0	101.1	104.5	103.4	104.9
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण	0.181	103.1	102.3	105.9	105.9	108.7
1.3.16.6 हाथ घड़ी और दीवार घड़ी	0.076	137.9	140.2	136.6	136.7	136.9
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	104.3	102.5	102.6	102.6	102.6
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	96.6	95.2	105.1	107.9	112.8
1.3.17 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का विनिर्माण	2.930	108.2	107.9	109.9	110.2	110.2
1.3.17.1 विद्युत मोटर्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बिजली वितरण और नियंत्रण संबंधी उपकरण	1.298	105.0	104.6	106.5	106.9	106.5
1.3.17.2 बैटरी और एक्यूम्युलेटर	0.236	120.4	121.3	115.2	115.3	115.3
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	118.8	117.2	122.9	123.7	121.6
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के वायर और केबल	0.428	99.7	98.4	104.5	106.1	106.6
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	108.5	107.7	111.6	110.8	110.9
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	119.4	119.9	121.5	120.9	121.6
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	104.4	105.2	105.4	106.0	106.8
1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण	4.789	107.9	107.9	108.5	108.2	109.1
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन, एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	104.1	103.6	102.8	101.4	102.0
1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण	0.162	114.3	114.1	115.0	116.8	115.0
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	106.6	105.9	107.2	108.3	108.3
1.3.18.4 बेयरिंग, गियर्स, गेयरिंग और ड्राइविंग उपकरण	0.340	104.5	102.9	110.2	106.8	108.6
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर	0.008	77.8	74.2	79.6	79.5	79.5
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने -उतारने वाले उपकरण	0.285	103.2	103.0	103.8	105.9	106.0
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	124.9	125.9	126.8	126.3	127.6
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	112.3	112.6	112.3	112.3	112.7
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	100.1	98.7	100.9	100.0	102.7
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	79.6	80.1	75.0	75.5	75.5
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	116.9	118.5	119.5	116.9	120.3
1.3.18.13 कपड़ा, परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	116.2	115.7	115.7	115.5	119.0
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	115.8	117.0	119.2	119.1	120.2
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	73.7	72.0	70.9	70.9	71.0
1.3.19 मोटर वाहन, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का विनिर्माण	4.969	110.4	110.6	110.4	110.5	110.6
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	113.4	113.3	113.3	112.6	112.8
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	107.2	107.5	107.3	108.2	108.2
1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण	1.648	107.7	107.9	109.1	109.6	109.8
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली वस्तुओं का निर्माण	0.117	158.7	158.6	158.8	158.8	158.8
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टॉक	0.110	100.6	103.3	103.6	105.0	104.7
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	102.8	102.7	104.1	104.6	104.9
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाड़ी	0.117	118.0	118.1	119.8	119.8	119.9
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	116.5	115.3	119.1	119.1	119.0
1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण	0.727	114.1	114.9	120.3	120.1	124.6
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	114.1	114.9	120.3	120.1	124.6
1.3.22 अन्य विनिर्माण	1.064	119.7	123.7	105.0	105.3	106.6
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	118.4	122.5	102.1	102.4	103.8
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	158.0	159.1	173.0	162.2	185.2
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	124.7	126.0	125.7	125.7	126.1
1.3.22.4 खेल और खिलौने	0.005	125.2	124.8	128.3	126.8	126.9
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और सामग्री	0.049	143.3	144.5	153.5	153.5	153.5
2 खाद्य सूचकांक	24.378	134.7	136.2	142.1	138.6	140.6

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 22: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)

उद्योग	भारत	2015-16	2016-17	अप्रैल-सितंबर		सितंबर	
				2016-17	2017-18	2016	2017
	1	2	3	4	5	6	7
सामान्य सूचकांक	100.00	114.7	120.0	117.7	120.6	118.2	122.7
1 क्षेत्रवार वर्गीकरण							
1.1 खनन और उत्खनन	14.37	97.3	102.5	92.8	96.4	87.7	94.6
1.2 विनिर्माण	77.63	115.9	121.0	119.6	121.9	121.0	125.1
1.3 बिजली	7.99	133.8	141.6	144.1	152.3	145.6	150.5
2 उपयोग आधारित वर्गीकरण							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	112.0	117.5	113.4	117.6	109.8	117.0
2.2 पूंजीगत माल	8.22	98.4	101.5	98.7	98.5	99.0	106.3
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	118.4	122.3	121.2	121.7	121.2	123.5
2.4 बुनियादी/निर्माण वस्तुएं	12.34	120.3	125.0	124.8	127.3	124.7	125.3
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	119.1	122.6	124.2	122.3	135.4	128.9
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	117.2	126.5	122.3	131.4	123.9	136.3

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सरकारी खाते और खज़ाना बिल

सं. 23: केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में

(राशि बिलियन ₹ में)

मद	वित्तीय वर्ष	अप्रैल-सितंबर			
	2017-18 (बजट अनुमान)	2017-18 (वास्तविक)	2016-17 (वास्तविक)	बजट अनुमानों का प्रतिशत	
				2017-18	2016-17
	1	2	3	4	5
1 राजस्व प्राप्तियां	15,157.7	7,287.7	6,979.9	48.1	50.7
1.1 कर राजस्व (निवल)	12,270.1	6,336.2	5,300.2	51.6	50.3
1.2 करेतर राजस्व	2,887.6	951.5	1,679.7	33.0	52.0
2 पूंजीगत प्राप्तियां	6,309.6	5,638.8	4,528.6	89.4	75.3
2.1 ऋण की वसूली	119.3	83.9	79.4	70.3	74.6
2.2 अन्य प्राप्तियां	725.0	301.7	214.1	41.6	37.9
2.3 उधारियां और अन्य देयताएं	5,465.3	5,253.2	4,235.1	96.1	79.3
3 कुल प्राप्तियां (1+2)	21,467.4	12,926.5	11,508.4	60.2	58.2
4 राजस्व व्यय	18,369.3	11,298.5	10,258.8	61.5	59.3
4.1 ब्याज भुगतान	5,230.8	2,579.1	2,268.1	49.3	46.0
5 पूंजी व्यय	3,098.0	1,628.0	1,249.6	52.5	50.6
6 कुल व्यय (4+5)	21,467.4	12,926.5	11,508.4	60.2	58.2
7 राजस्व घाटा (4-1)	3,211.6	4,010.9	3,279.0	124.9	92.6
8 राजकोषीय घाटा {6-(1+2.1+2.2)}	5,465.3	5,253.2	4,235.1	96.1	79.3
9 सकल प्राथमिक घाटा [8-4.1]	234.5	2,674.1	1,967.0	1,140.2	477.0

स्रोत : महालेखानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(बिलियन ₹)

मद	2016-17	2016	2017					
		अक्तू. 28	सितं. 22	सितं. 29	अक्तू. 6	अक्तू. 13	अक्तू. 20	अक्तू. 27
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	323.7	231.1	462.8	443.5	392.3	373.9	393.6	314.6
1.2 प्राथमिक व्यापारी	243.5	187.5	247.0	260.7	216.6	204.6	234.8	213.5
1.3 राज्य सरकारें	146.2	523.8	857.9	892.9	922.9	943.9	778.9	944.5
1.4 अन्य	343.4	768.2	688.2	706.0	779.0	782.8	702.9	775.6
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	216.2	344.1	414.1	382.4	360.6	364.0	365.1	342.4
2.2 प्राथमिक व्यापारी	316.5	312.8	268.7	295.9	255.9	256.5	250.5	278.6
2.3 राज्य सरकारें	193.6	120.7	145.6	145.6	120.7	120.7	120.7	120.7
2.4 अन्य	120.9	109.9	145.6	150.4	174.7	190.2	155.3	169.9
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	512.3	637.8	496.7	439.6	440.7	411.3	440.2	378.0
3.2 प्राथमिक व्यापारी	551.8	594.0	546.8	590.3	632.9	603.0	622.7	612.8
3.3 राज्य सरकारें	26.3	25.2	29.7	29.7	29.7	29.7	29.7	29.7
3.4 अन्य	326.4	308.3	342.3	364.9	340.3	360.7	331.9	364.6
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक	—	—	—	—	—	—	—	—
4.2 प्राथमिक व्यापारी	—	—	—	—	—	—	—	—
4.3 राज्य सरकारें	1,560.6	796.1	1,386.0	1,251.7	894.5	761.4	1,235.7	1,211.9
4.4 अन्य	5.1	7.5	13.8	11.0	8.0	5.0	5.2	6.2
कुल खज़ाना बिल								
(14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)	3,320.8	4,163.4	4,645.5	4,702.1	4,666.6	4,641.4	4,426.3	4,544.8

14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं हैं। यह बिल स्वरूप के अनुसार मध्यवर्ती हैं क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए परिसमाप्त किए जाते हैं।

सं. 25: खज़ाना बिलों की नीलामी

(राशि बिलियन ₹ में)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां				स्वीकृत बोलियां				कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)
		संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या	कुल अंकित मूल्य						
			प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी		प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
91-दिवसीय खज़ाना बिल												
2017-18												
सितं. 27	100	54	1,440.13	52.63	46	100.00	52.63	152.63	98.50	6.1081		
अक्तू. 4	70	49	1,052.66	60.63	27	70.00	60.63	130.63	98.51	6.0668		
अक्तू. 11	70	47	870.08	28.41	19	70.00	28.41	98.41	98.51	6.0668		
अक्तू. 17	70	37	870.11	10.00	30	70.00	10.00	80.00	98.50	6.1081		
अक्तू. 25	70	43	631.53	198.56	26	70.00	198.56	268.56	98.50	6.1081		
182-दिवसीय खज़ाना बिल												
2017-18												
अक्तू. 11	20	43	109.72	—	18	20.00	—	20.00	97.01	6.1812		
अक्तू. 17	20	31	103.30	—	6	20.00	—	20.00	97.01	6.1812		
अक्तू. 25	20	35	133.16	—	8	20.00	—	20.00	97.01	6.1812		
364-दिवसीय खज़ाना बिल												
2017-18												
अक्तू. 4	20	53	177.96	—	7	20.00	—	20.00	94.18	6.1966		
अक्तू. 11	20	41	105.17	—	19	20.00	—	20.00	94.16	6.2192		
अक्तू. 17	20	47	145.55	—	22	20.00	—	20.00	94.16	6.2192		
अक्तू. 25	20	37	87.11	—	12	20.00	—	20.00	94.16	6.2192		

वित्तीय बाजार

सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

स्थिति के अनुसार		दरों का दायरा	
		भारित औसत दरें	
		उधार लेना/उधार देना	उधार लेना/उधार देना
		1	2
अक्तूबर	3, 2017	5.00-6.00	5.85
अक्तूबर	4, 2017	5.00-6.00	5.85
अक्तूबर	5, 2017	4.95-6.00	5.82
अक्तूबर	6, 2017	4.95-6.06	5.84
अक्तूबर	7, 2017	4.50-6.00	5.75
अक्तूबर	9, 2017	5.00-6.10	5.95
अक्तूबर	10, 2017	4.95-6.07	5.88
अक्तूबर	11, 2017	4.95-6.10	5.85
अक्तूबर	12, 2017	4.95-6.00	5.84
अक्तूबर	13, 2017	4.80-6.20	5.83
अक्तूबर	16, 2017	4.95-6.30	6.01
अक्तूबर	17, 2017	4.95-6.15	5.98
अक्तूबर	18, 2017	4.95-6.10	5.95
अक्तूबर	21, 2017	4.65-5.90	5.51
अक्तूबर	23, 2017	4.95-6.11	5.85
अक्तूबर	24, 2017	4.95-6.20	5.86
अक्तूबर	25, 2017	4.95-6.06	5.88
अक्तूबर	26, 2017	4.95-6.00	5.84
अक्तूबर	27, 2017	4.80-6.05	5.86
अक्तूबर	30, 2017	4.85-6.10	5.89
अक्तूबर	31, 2017	4.85-6.20	5.88
नवंबर	1, 2017	5.00-6.05	5.87
नवंबर	2, 2017	4.95-6.05	5.84
नवंबर	3, 2017	4.90-6.10	5.84
नवंबर	6, 2017	4.95-6.05	5.86
नवंबर	7, 2017	4.95-6.05	5.85
नवंबर	8, 2017	4.95-6.06	5.91
नवंबर	9, 2017	4.95-6.05	5.89
नवंबर	10, 2017	4.90-6.05	5.88
नवंबर	13, 2017	4.90-6.05	5.91
नवंबर	14, 2017	4.90-6.05	5.84
नवंबर	15, 2017	4.90-6.02	5.85

टिप्पणी: नोटिस मुद्रा सहित

सं. 27: जमा प्रमाण-पत्र

मद	2016		2017		
	अक्तू. 28	सितं. 15	सितं. 29	अक्तू. 13	अक्तू. 27
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (बिलियन ₹)	1,816.0	824.1	1,144.5	1,168.0	1,286.2
1.1 पखवाड़े के दौरान जारी (बिलियन ₹)	51.5	117.7	169.2	149.6	137.7
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	6.42-7.02	6.12-6.53	6.09-6.68	6.10-6.61	6.10-6.63

सं. 28: वाणिज्यिक पत्र

मद	2016		2017		
	अक्तू. 31	सितं. 15	सितं. 30	अक्तू. 15	अक्तू. 31
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (बिलियन ₹)	3,961.2	4,423.9	3,932.1	4,796.8	4,892.3
1.1 पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (बिलियन ₹)	535.9	1,250.7	1,162.9	1,069.9	1,355.9
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	6.31-11.97	5.59-11.80	5.89-11.00	5.98-11.79	6.06-11.23

सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(बिलियन ₹)

मद	2016-17	2016		2017				
		अक्तू. 28	सितं. 22	सितं. 29	अक्तू. 6	अक्तू. 13	अक्तू. 20	अक्तू. 27
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	259.0	262.6	245.2	322.7	195.6	239.5	177.4	266.1
2 नोटिस मुद्रा	46.8	105.0	11.7	8.4	75.3	2.1	81.2	4.0
3 मीयादी मुद्रा	8.4	8.2	5.5	7.6	20.6	6.1	8.2	11.1
4 सीबीएलओ	1,700.2	1,847.5	2,026.1	2,433.7	2,519.5	1,936.6	2,413.4	2,014.0
5 बाजार रिपो	1,753.3	1,856.2	1,748.4	2,424.3	1,867.0	1,942.4	1,767.3	1,869.6
6 कार्पोरेट बांड में रिपो	2.5	0.4	12.4	1.8	8.0	3.7	3.2	2.7
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	55,345	57,738	67,231	86,072	67,951	65,728	49,353	59,299
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	1,249.1	1,080.6	865.7	846.4	905.1	632.5	692.6	353.5
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	50.7	35.8	58.3	97.5	25.9	22.6	34.2	21.6
10 खजाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	45.1	61.0	72.9	36.0	11.7	26.5	19.6	12.8
10.2 182-दिवसीय	11.8	15.7	17.2	13.9	8.8	15.8	6.0	8.4
10.3 364-दिवसीय	18.5	18.2	12.5	21.9	12.6	24.5	7.2	1.8
10.4 नकदी प्रबंधन बिल	13.8	-	8.4	-	-	-	-	-
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	1388.8	1,211.3	1,034.9	1,015.7	964.1	721.8	759.6	398.2
11.1 भारतीय रिज़र्व बैंक	-	20.8	2.6	20.8	1.4	20.5	0.1	20.8

सं. 30: गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(राशि बिलियन ₹ में)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2016-17		2016-17 (अप्रै.-अक्टू.)		2017-18 (अप्रै.-अक्टू.)*		अक्टू. 2016		अक्टू. 2017*	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 इक्विटी शेयर	116	303.6	63	221.8	106	247.0	4	52.9	10	74.3
1ए प्रीमियम	113	291.3	60	213.6	105	239.4	4	51.9	10	72.6
1.1 पब्लिक	105	280.7	60	215.7	98	215.9	4	52.9	8	50.3
1.1.1 प्रीमियम	102	270.4	57	207.6	97	209.3	4	51.9	8	49.1
1.2 राइट्स	11	22.9	3	6.2	8	31.1	-	-	2	24.0
1.2.1 प्रीमियम	11	20.9	3	6.0	8	30.0	-	-	2	23.6
2 अधिमान शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 पब्लिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 राइट्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 डिबेंचर	16	295.5	10	238.9	4	39.0	-	-	-	-
3.1 परिवर्तनीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 पब्लिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2 राइट्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 अपरिवर्तनीय	16	295.5	10	238.9	4	39.0	-	-	-	-
3.1.1 पब्लिक	16	295.5	10	238.9	4	39.0	-	-	-	-
3.1.2 राइट्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 बांड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 पब्लिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 राइट्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 कुल (1+2+3+4)	132	599.0	73	460.8	110	285.9	4	52.9	10	74.3
5.1 पब्लिक	121	576.1	70	454.6	102	254.8	4	52.9	8	50.3
5.2 राइट्स	11	22.9	3	6.2	8	31.1	-	-	2	24.0

* आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी)

बाह्य क्षेत्र

सं. 31: विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2016-17	2016		2017			
			अक्तू.	जून	जुला.	अग.	सितं.	अक्तू.
			1	2	3	4	5	6
1 निर्यात	बिलियन ₹	18,541.0	1,559.3	1,490.4	1,443.0	1,507.5	1,845.4	1,503.3
	अमरीकी मिलियन डालर	276,547.0	23,360.6	23,127.9	22,387.3	23,566.2	28,636.4	23,098.2
1.1 तेल	बिलियन ₹	2,120.3	185.3	144.6	175.9	196.1	233.8	207.3
	अमरीकी मिलियन डालर	31,622.3	2,776.0	2,244.3	2,728.5	3,066.3	3,627.9	3,185.3
1.2 तेल से इतर	बिलियन ₹	16,420.7	1,374.0	1,345.8	1,267.1	1,311.3	1,611.6	1,296.0
	अमरीकी मिलियन डालर	244,924.7	20,584.6	20,883.6	19,658.8	20,499.9	25,008.6	19,912.9
2 आयात	बिलियन ₹	25,668.2	2,302.5	2,382.1	2,188.3	2,272.6	2,423.1	2,415.6
	अमरीकी मिलियन डालर	382,740.9	34,495.1	36,964.9	33,950.7	35,526.6	37,601.8	37,117.0
2.1 तेल	बिलियन ₹	5,825.6	484.7	495.9	500.0	495.9	527.7	604.4
	अमरीकी मिलियन डालर	86,865.7	7,261.2	7,694.6	7,757.4	7,752.4	8,189.0	9,286.7
2.2 तेल से इतर	बिलियन ₹	19,842.6	1,817.8	1,886.3	1,688.3	1,776.7	1,895.4	1,811.2
	अमरीकी मिलियन डालर	295,875.2	27,233.9	29,270.3	26,193.3	27,774.2	29,412.8	27,830.3
3 व्यापार शेष	बिलियन ₹	-7,127.2	-743.2	-891.7	-745.3	-765.1	-577.7	-912.4
	अमरीकी मिलियन डालर	-106,193.9	-11,134.5	-13,837.1	-11,563.4	-11,960.5	-8,965.3	-14,018.8
3.1 तेल	बिलियन ₹	-3,705.4	-299.4	-351.2	-324.1	-299.8	-293.9	-397.1
	अमरीकी मिलियन डालर	-55,243.4	-4,485.2	-5,450.4	-5,028.9	-4,686.1	-4,561.1	-6,101.5
3.2 तेल से इतर	बिलियन ₹	-3,421.9	-443.8	-540.5	-421.2	-465.3	-283.8	-515.3
	अमरीकी मिलियन डालर	-50,950.6	-6,649.2	-8,386.7	-6,534.6	-7,274.3	-4,404.2	-7,917.3

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

सं. 32: विदेशी मुद्रा भंडार

मद	इकाई	2016	2017					
		नवं 25	अक्तू. 20	अक्तू. 27	नवं 3	नवं 10	नवं 17	नवं 24
		1	2	3	4	5	6	7
1 कुल भंडार	बिलियन ₹	24,941	26,021	25,956	25,749	25,949	25,902	25,937
	अमरीकी मिलियन डालर	365,306	399,921	398,761	398,739	399,293	399,534	400,742
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	बिलियन ₹	23,316	24,388	24,324	24,168	24,367	24,318	24,354
	अमरीकी मिलियन डालर	341,089	374,908	373,772	374,320	374,876	375,096	376,305
1.2 स्वर्ण	बिलियन ₹	1,368	1,388	1,388	1,339	1,339	1,339	1,339
	अमरीकी मिलियन डालर	20,461	21,241	21,241	20,667	20,667	20,667	20,667
1.3 एसडीआर	बिलियन ₹	1,065	1,063	1,063	1,063	1,061	1,061	1,061
	अमरीकी मिलियन डालर	99	98	97	96	97	97	97
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	बिलियन ₹	1,442	1,500	1,490	1,491	1,490	1,498	1,497
	अमरीकी मिलियन डालर	159	148	147	146	147	147	147
	अमरीकी मिलियन डालर	2,314	2,273	2,259	2,261	2,261	2,273	2,273

सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां

(मिलियन अमरीकी डालर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2016-17	2016	2017		2016-17	2017-18
		अक्तू.	सितं.	अक्तू.	अप्रै.-अक्तू.	अप्रै.-अक्तू.
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियां	116,867	124,402	118,021	119,161	-1,898	2,695
1.1 एफसीएनआर (बी)	21,002	38,172	20,238	20,623	-7,144	-379
1.2 एनआर (ई) आरए	83,213	75,481	85,381	85,949	4,563	3,091
1.3 एनआरओ	12,652	10,750	12,401	12,590	683	-17

सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(मिलियन अमरीकी डालर)

मद	2016-17	2016-17	2017-18	2016	2017	
		अप्रै.-अक्तू.	अप्रै.-अक्तू.	अक्तू.	सितं.	अक्तू.
	1	2	3	4	5	6
1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)	35,612	25,048	22,430	4,167	1,101	1,571
1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1.1.2)	42,215	25,733	27,777	5,854	2,187	2,212
1.1.1.1 सकल अंतर्वाह/सकल निवेश	60,220	37,290	37,691	7,478	3,384	3,945
1.1.1.1.1 ईक्विटी	44,701	28,502	28,682	6,300	2,213	2,786
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	5,900	2,902	6,415	490	99	28
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक	30,417	20,240	17,341	5,272	1,598	1,744
1.1.1.1.1.3 शेयरों की अधिप्राप्ति	7,161	4,679	4,280	434	419	910
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की ईक्विटी पूंजी	1,223	682	646	104	98	104
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	12,343	7,062	6,812	1,020	958	1,020
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	3,176	1,726	2,197	158	213	139
1.1.1.2 प्रत्यावर्तन / विनिवेश	18,005	11,557	9,915	1,624	1,197	1,733
1.1.1.2.1 ईक्विटी	17,318	11,292	9,728	1,604	1,167	1,732
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	687	265	186	20	30	1
1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)	6,603	685	5,347	1,688	1,086	641
1.1.2.1 ईक्विटी पूंजी	9,792	5,430	3,089	1,392	475	335
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	2,925	1,707	1,733	244	244	244
1.1.2.3 अन्य पूंजी	4,450	2,135	3,051	212	1,098	256
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन / विनिवेश	10,564	8,587	2,526	160	730	195
1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)	7,612	8,104	17,340	-49	-1,724	2,821
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	-	-	-	-	-	-
1.2.2 एफआईआई	7,766	7,909	17,412	-40	-1,493	3,053
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	-	-	-	-	-	-
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	154	-196	72	9	231	231
1 विदेशी निवेश अंतर्वाह	43,224	33,153	39,770	4,118	-623	4,393

सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमरीकी डालर)

मद	2016-17	2016	2017		
		अक्तू.	अग.	सितं.	अक्तू.
	1	2	3	4	5
1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण	8,170.7	621.4	1,096.8	1,093.3	811.3
1.1 जमाराशियां	283.8	25.1	28.7	35.2	22.0
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	92.9	5.7	8.8	6.3	6.2
1.3 इक्विटी / डेट में निवेश	443.6	30.2	30.2	43.3	33.2
1.4 उपहार	749.5	60.6	81.3	83.9	85.1
1.5 दान	8.8	0.3	0.8	0.6	0.6
1.6 यात्रा	2,568.0	187.9	450.2	398.3	279.9
1.7 निकट संबंधियों का रखरखाव	2,169.5	158.6	240.7	227.0	201.1
1.8 चिकित्सा उपचार	17.3	1.5	2.1	3.8	2.0
1.9 विदेश में शिक्षा	1,536.4	140.4	240.7	278.0	167.4
1.10 अन्य	300.8	11.1	13.2	16.8	13.8

सं. 36: भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (रीर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (नीर)

मद	2015-16	2016-17	2016		2017	
			नवंबर	अक्तूबर	अक्तूबर	नवंबर
	1	2	3	4	5	
36-मुद्रा निर्यात और व्यापार आधारित भारांक (आधार: 2004-05=100)						
1 व्यापार आधारित भारांक						
1.1 नीर	74.75	74.65	75.01	76.43	76.95	
1.2 रीर	112.08	114.51	115.79	119.15	119.96	
2 निर्यात आधारित भारांक						
2.1 नीर	76.45	76.38	76.71	78.30	78.86	
2.2 रीर	114.44	116.44	117.61	121.33	122.20	
6-मुद्रा व्यापार आधारित भारांक						
1 आधार : 2004-05 (अप्रैल-मार्च) =100						
1.1 नीर	67.52	66.86	67.04	67.45	67.68	
1.2 रीर	122.71	125.17	126.31	129.42	130.01	
2 आधार : 2016-17 (अप्रैल-मार्च) =100						
2.1 नीर	101.00	100.00	100.27	100.89	101.23	
2.2 रीर	98.04	100.00	100.91	103.40	103.87	

सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार पंजीकरण

(राशि अमरीकी मिलियन डालर में)

मद	2016-17	2016		2017	
		अक्तू.	सितं.	अक्तू.	अक्तू.
	1	2	3	4	
1 स्वचालित मार्ग					
1.1 संख्या	729	57	79	64	
1.2 राशि	16,247	1,759	3,156	1,402	
2 अनुमोदन मार्ग					
2.1 संख्या	37	1	2	8	
2.2 राशि	5,738	12	327	3,004	
3 कुल (1+2)					
3.1 संख्या	766	58	81	72	
3.2 राशि	21,985	1,771	3,483	4,406	
4 भारत औसत परिपक्वता (वर्षों में)	5.30	5.90	6.20	5.00	
5 ब्याज दर (प्रतिशत)					
5.1 6 महीने के लिबॉर पर भारत औसत मार्जिन या अस्थिर दर के ऋणों के लिए संदर्भ दर	1.62	1.44	1.26	1.02	
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-14.75	0.58-13.00	0.00-11.00	0.00-11.20	

सं. 38: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमरीकी डालर)

मद	अप्रै.-जून 2016 (आं.सं)			अप्रै.-जून 2017 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	254,325	247,356	6,969	296,104	284,699	11,405
1 चालू खाता (1.1+1.2)	124,970	125,371	-401	140,515	154,856	-14,341
1.1 पण्य	66,618	90,453	-23,835	73,659	114,881	-41,222
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	58,352	34,918	23,434	66,857	39,976	26,881
1.2.1 सेवाएं	39,381	23,636	15,745	45,916	27,701	18,215
1.2.1.1 यात्रा	4,803	4,562	241	6,242	4,845	1,396
1.2.1.2 परिवहन	3,897	3,678	219	4,178	4,072	106
1.2.1.3 बीमा	516	287	229	625	352	272
1.2.1.4 जीएनआईई	130	162	-32	156	152	4
1.2.1.5 विविध	30,035	14,948	15,087	34,716	18,280	16,436
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	18,246	674	17,573	18,439	1,136	17,304
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	8,058	8,005	53	8,467	8,265	202
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	1,403	1,268	135	1,174	1,218	-44
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	539	209	331	548	237	310
1.2.2 अंतरण	15,306	1,304	14,002	16,148	1,690	14,458
1.2.2.1 आधिकारिक	58	217	-159	92	237	-145
1.2.2.2 निजी	15,248	1,087	14,161	16,056	1,453	14,603
1.2.3 आय	3,665	9,977	-6,312	4,792	10,585	-5,793
1.2.3.1 निवेश आय	2,753	9,278	-6,525	3,650	10,040	-6,391
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	912	700	212	1,143	544	598
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	129,166	121,985	7,181	155,226	129,843	25,383
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	72,114	66,129	5,985	92,709	73,021	19,688
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	14,173	10,291	3,881	15,410	8,174	7,236
2.1.1.1 भारत में	11,748	5,852	5,895	14,702	4,449	10,253
2.1.1.1.1 इक्विटी	7,874	5,784	2,090	10,656	4,327	6,329
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	3,169	-	3,169	2,919	-	2,919
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	705	69	636	1,127	122	1,006
2.1.1.2 विदेश में	2,425	4,439	-2,014	708	3,725	-3,017
2.1.1.2.1 इक्विटी	2,425	2,427	-2	708	1,768	-1,060
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	731	-731	0	758	-758
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	1,281	-1,281	0	1,199	-1,199
2.1.2 संविभाग निवेश	57,941	55,838	2,103	77,299	64,847	12,452
2.1.2.1 भारत में	56,260	55,020	1,241	76,134	64,213	11,921
2.1.2.1.1 एफआईआई	56,260	55,020	1,241	76,134	64,213	11,921
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	45,591	43,227	2,365	57,312	56,625	687
2.1.2.1.1.2 ऋण	10,669	11,793	-1,124	18,823	7,588	11,234
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	1,681	818	863	1,165	634	530
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	26,222	27,822	-1,600	34,691	33,722	968
2.2.1 बाह्य सहायता	1,860	1,137	723	1,826	1,179	647
2.2.1.1 भारत द्वारा	15	58	-43	14	70	-56
2.2.1.2 भारत को	1,846	1,079	767	1,812	1,110	702
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	3,362	5,376	-2,013	6,391	6,650	-259
2.2.2.1 भारत द्वारा	974	493	482	2,438	2,283	156
2.2.2.2 भारत को	2,388	4,883	-2,495	3,953	4,367	-414
2.2.3 भारत को अल्पावधि	21,000	21,310	-310	26,474	25,893	580
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	21,000	21,121	-122	25,735	25,893	-159
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	0	189	-189	739	0	739
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	21,139	21,288	-148	21,607	15,441	6,166
2.3.1 वाणिज्य बैंक	21,112	21,287	-175	21,607	14,383	7,225
2.3.1.1 आस्तियां	9,426	8,569	856	7,589	1,217	6,373
2.3.1.2 देयताएं	11,687	12,718	-1,031	14,018	13,166	852
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	11,573	10,195	1,378	12,799	11,561	1,237
2.3.2 अन्य	27	0	27	0	1,059	-1,059
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	35	-35	0	23	-23
2.5 अन्य पूंजी	9,692	6,712	2,980	6,219	7,635	-1,416
3 भूल-चूक	189	-	189	362	-	362
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	6,969	-6,969	0	11,405	-11,405
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	0	6,969	-6,969	0	11,405	-11,405

सं. 39: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(बिलियन ₹)

मद	अप्रै.-जून 2016 (आं.सं)			अप्रै.-जून 2017 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	17,012	16,546	466	19,086	18,351	735
1 चालू खाता (1.1+1.2)	8,359	8,386	-27	9,057	9,982	-924
1.1 पण्य	4,456	6,051	-1,594	4,748	7,405	-2,657
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	3,903	2,336	1,568	4,309	2,577	1,733
1.2.1 सेवाएं	2,634	1,581	1,053	2,960	1,786	1,174
1.2.1.1 यात्रा	321	305	16	402	312	90
1.2.1.2 परिवहन	261	246	15	269	262	7
1.2.1.3 बीमा	35	19	15	40	23	18
1.2.1.4 जीएनआईई	9	11	-2	10	10	0
1.2.1.5 विविध	2,009	1,000	1,009	2,238	1,178	1,059
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	1,221	45	1,175	1,189	73	1,115
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	539	535	4	546	533	13
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	94	85	9	76	78	-3
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	36	14	22	35	15	20
1.2.2 अंतरण	1,024	87	937	1,041	109	932
1.2.2.1 आधिकारिक	4	15	-11	6	15	-9
1.2.2.2 निजी	1,020	73	947	1,035	94	941
1.2.3 आय	245	667	-422	309	682	-373
1.2.3.1 निवेश आय	184	621	-436	235	647	-412
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	61	47	14	74	35	39
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	8,640	8,160	480	10,006	8,369	1,636
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	4,824	4,423	400	5,976	4,707	1,269
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	948	688	260	993	527	466
2.1.1.1 भारत में	786	391	394	948	287	661
2.1.1.1.1 इक्विटी	527	387	140	687	279	408
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	212	0	212	188	0	188
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	47	5	43	73	8	65
2.1.1.2 विदेश में	162	297	-135	46	240	-194
2.1.1.2.1 इक्विटी	162	162	-	46	114	-68
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	49	-49	0	49	-49
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	86	-86	0	77	-77
2.1.2 विदेशी निवेश	3,876	3,735	141	4,983	4,180	803
2.1.2.1 भारत में	3,763	3,680	83	4,907	4,139	768
2.1.2.1.1 एफआईआई	3,763	3,680	83	4,907	4,139	768
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	3,050	2,891	158	3,694	3,650	44
2.1.2.1.1.2 ऋण	714	789	-75	1,213	489	724
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.2 विदेश में	112	55	58	75	41	34
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	1,754	1,861	-107	2,236	2,174	62
2.2.1 बाह्य सहायता	124	76	48	118	76	42
2.2.1.1 भारत द्वारा	1	4	-3	1	5	-4
2.2.1.2 भारत को	123	72	51	117	72	45
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	225	360	-135	412	429	-17
2.2.2.1 भारत द्वारा	65	33	32	157	147	10
2.2.2.2 भारत को	160	327	-167	255	281	-27
2.2.3 भारत को अल्पावधि	1,405	1,425	-21	1,706	1,669	37
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	1,405	1,413	-8	1,659	1,669	-10
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	0	13	-13	48	0	48
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	1,414	1,424	-10	1,393	995	397
2.3.1 वाणिज्य बैंक	1,412	1,424	-12	1,393	927	466
2.3.1.1 आस्तियां	630	573	57	489	78	411
2.3.1.2 देयताएं	782	851	-69	904	849	55
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	774	682	92	825	745	80
2.3.2 अन्य	2	0	2	0	68	-68
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	2	-2	0	1	-1
2.5 अन्य पूंजी	648	449	199	401	492	-91
3 भूल-चूक	13	0	13	23	0	23
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	466	-466	0	735	-735
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	0	466	-466	0	735	-735

सं. 40: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(मिलियन अमरीकी डालर)

मद	अप्रै.-जून 2016 (आ.सं)			अप्रै.-जून 2017 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	124,969	125,351	-382	140,509	154,834	-14,324
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	105,999	114,089	-8,090	119,575	142,582	-23,007
1.अ.क.माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	66,618	90,453	-23,835	73,659	114,881	-41,222
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	66,200	86,533	-20,333	73,627	103,615	-29,988
1.अ.क.2 वाणिज्य के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	418	0	418	32	0	32
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	-	3,920	-3,920	-	11,266	-11,266
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	39,381	23,636	15,745	45,916	27,701	18,215
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	45	13	33	26	9	17
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	33	78	-45	57	153	-96
1.अ.ख.3 परिवहन	3,897	3,678	219	4,178	4,072	106
1.अ.ख.4 यात्रा	4,803	4,562	241	6,242	4,845	1,396
1.अ.ख.5 निर्माण	463	233	230	675	286	388
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	516	287	229	625	352	272
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	1,403	1,268	135	1,174	1,218	-44
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	171	1,628	-1,456	162	1,954	-1,792
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	18,848	989	17,859	19,056	1,476	17,581
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	8,058	8,005	53	8,467	8,265	202
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	381	672	-291	402	467	-65
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	130	162	-32	156	152	4
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	633	2,064	-1,431	4,698	4,452	246
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	3,665	9,977	-6,312	4,792	10,585	-5,793
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	912	700	212	1,143	544	598
1.आ.2 निवेश आय	2,286	9,042	-6,756	2,724	9,874	-7,149
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	1,401	4,017	-2,616	1,549	4,681	-3,132
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	31	2,039	-2,009	70	2,298	-2,228
1.आ.2.3 अन्य निवेश	52	2,985	-2,933	186	2,894	-2,708
1.आ.2.4 रिज़र्व आस्तियां	803	1	802	919	0	919
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	467	236	231	925	167	759
1.इ दिवतीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	15,304	1,284	14,020	16,142	1,667	14,475
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	15,248	1,087	14,161	16,056	1,453	14,603
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	14,683	863	13,820	15,504	1,121	14,382
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	565	225	341	553	332	221
1.इ.2 सामान्य सरकार	56	197	-140	86	214	-128
2 पूँजी खाता (2.1+2.2)	221	62	159	114	105	8
2.1 अनत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	32	8	24	75	39	35
2.2 पूँजी अंतरण	189	54	135	39	66	-27
3 वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	128,947	128,913	35	155,119	141,165	13,954
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	14,173	10,291	3,881	15,410	8,174	7,236
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	11,748	5,852	5,895	14,702	4,449	10,253
3.1अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	11,043	5,784	5,259	13,575	4,327	9,248
3.1अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	7,874	5,784	2,090	10,656	4,327	6,329
3.1अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	3,169	-	3,169	2,919	-	2,919
3.1अ.2 ऋण लिखत	705	69	636	1,127	122	1,006
3.1अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	705	69	636	1,127	122	1,006
3.1आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	2,425	4,439	-2,014	708	3,725	-3,017
3.1आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	2,425	3,158	-733	708	2,526	-1,818
3.1आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	2,425	2,427	-2	708	1,768	-1,060
3.1आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	-	731	-731	-	758	-758
3.1आ.2 ऋण लिखत	0	1,281	-1,281	0	1,199	-1,199
3.1आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	-	1,281	-1,281	-	1,199	-1,199
3.2 संविभाग निवेश	57,941	55,838	2,103	77,299	64,847	12,452
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	56,260	55,020	1,241	76,134	64,213	11,921
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	45,591	43,227	2,365	57,312	56,625	687
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	10,669	11,793	-1,124	18,823	7,588	11,234
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	1,681	818	863	1,165	634	530
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिज़र्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	6,861	3,878	2,983	4,737	5,946	-1,209
3.4 अन्य निवेश	49,973	51,937	-1,964	57,672	50,793	6,880
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	11,600	10,195	1,405	12,799	12,620	179
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	27	0	27	0	1,059	-1,059
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	11,573	10,195	1,378	12,799	11,561	1,237
3.4.2.3 सामान्य सरकार	-	-	-	-	-	-
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	14,762	17,605	-2,843	17,026	10,650	6,375
3.4.3अ भारत को ऋण	13,773	17,055	-3,281	14,573	8,298	6,275
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	989	550	438	2,453	2,352	100
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	145	279	-134	14	589	-575
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	21,000	21,310	-310	26,474	25,893	580
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	2,466	2,548	-81	1,361	1,041	320
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	-	-	-	-	-	-
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	6,969	-6,969	0	11,405	-11,405
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	-	-	-	-	-	-
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	-	-	-	-	-	-
3.5.3 आईएमएफ में रिज़र्व निधियों की स्थिति एन.ए	-	-	-	-	-	-
3.5.4 अन्य रिज़र्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	6,969	-6,969	0	11,405	-11,405
4. कुल आस्तियां / देयताएं	128,947	128,913	35	155,119	141,165	13,954
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	67,745	57,143	10,602	77,510	70,647	6,863
4.2 ऋण लिखत	58,735	62,252	-3,517	76,248	58,073	18,175
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	2,466	9,517	-7,050	1,361	12,445	-11,085
5. निवल भूल-चूक	189	-	189	362	-	362

सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(विलियन ₹)

मद	अप्रै.-जून 2016 (आ.स)			अप्रै.-जून 2017 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	8,359	8,385	-26	9,057	9,980	-923
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	7,090	7,632	-541	7,708	9,191	-1,483
1.अ.क.माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	4,456	6,051	-1,594	4,748	7,405	-2,657
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	4,428	5,788	-1,360	4,746	6,679	-1,933
1.अ.क.2 वाणिज्य के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	28	0	28	2	0	2
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	-	262	-262	0	726	-726
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	2,634	1,581	1,053	2,960	1,786	1,174
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	3	1	2	2	1	1
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	2	5	-3	4	10	-6
1.अ.ख.3 परिवहन	261	246	15	269	262	7
1.अ.ख.4 यात्रा	321	305	16	402	312	90
1.अ.ख.5 निर्माण	31	16	15	43	18	25
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	35	19	15	40	23	18
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	94	85	9	76	78	-3
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	11	109	-97	10	126	-116
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	1,261	66	1,195	1,228	95	1,133
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	539	535	4	546	533	13
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	25	45	-19	26	30	-4
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	11	9	2	10	10	0
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	42	138	-96	303	287	16
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	245	667	-422	309	682	-373
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	61	47	14	74	35	39
1.आ.2 निवेश आय	153	605	-452	176	636	-461
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	94	269	-175	100	302	-202
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	2	136	-134	5	148	-144
1.आ.2.3 अन्य निवेश	3	200	-196	12	187	-175
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	54	0	54	59	0	59
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	31	16	15	60	11	49
1.इ दिवतीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	1,024	86	938	1,040	107	933
1.इ.1 वित्तीय निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	1,020	73	947	1,035	94	941
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	982	58	924	999	72	927
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	38	15	23	36	21	14
1.इ.2 सामान्य सरकार	4	13	-9	6	14	-8
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	15	4	11	7	1	6
2.1 अनत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	2	1	2	5	3	2
2.2 पूँजी अंतरण	13	4	9	3	4	-2
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	8,625	8,623	2	9,999	9,099	899
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	948	688	260	993	527	466
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	786	391	394	948	287	661
3.1अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	739	387	352	875	279	596
3.1अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	527	387	140	687	279	408
3.1अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	212	0	212	188	0	188
3.1अ.2 ऋण लिखत	47	5	43	73	8	65
3.1अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	47	5	43	73	8	65
3.1आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	162	297	-135	46	240	-194
3.1आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	162	211	-49	46	163	-117
3.1आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	162	162	0	46	114	-68
3.1आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	49	-49	0	49	-49
3.1आ.2 ऋण लिखत	0	86	-86	0	77	-77
3.1आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	86	-86	0	77	-77
3.2 संविभाग निवेश	3,876	3,735	141	4,983	4,180	803
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	3,763	3,680	83	4,907	4,139	768
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	3,050	2,891	158	3,694	3,650	44
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	714	789	-75	1,213	489	724
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	112	55	58	75	41	34
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	459	259	200	305	383	-78
3.4 अन्य निवेश	3,343	3,474	-131	3,717	3,274	443
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	776	682	94	825	813	12
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मुवमेंट; एनआरजी)	2	0	2	0	68	-68
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	774	682	92	825	745	80
3.4.2.3 सामान्य सरकार	-	-	-	-	-	-
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	987	1,178	-190	1,097	686	411
3.4.3अ भारत को ऋण	921	1,141	-219	939	535	404
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	66	37	29	158	152	6
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	10	19	-9	1	38	-37
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	1,405	1,425	-21	1,706	1,669	37
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	165	170	-5	88	67	21
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	-	-	-	-	-	-
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	466	-466	0	735	-735
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	-	-	-	-	-	-
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए.	-	-	-	-	-	-
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए.	-	-	-	-	-	-
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	466	-466	0	735	-735
4. कुल आस्तियां / देयताएं	8,625	8,623	2	9,999	9,099	899
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	4,532	3,822	709	4,996	4,554	442
4.2 ऋण लिखत	3,929	4,164	-235	4,915	3,743	1,172
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	165	637	-472	88	802	-714
5. निवल भूल-चूक	13	-	13	23	-	23

सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन अमरीकी डालर)

मद	वित्तीय वर्ष/समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2016-17		2016		2017			
			जून		मार्च		जून	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश	148,229	342,659	143,640	294,110	148,229	342,659	151,246	353,406
1.1 इक्विटी पूंजी और पुनर्निवेशित अर्जन	99,114	327,845	97,694	280,149	99,114	327,845	100,932	337,563
1.2 अन्य पूंजी	49,115	14,814	45,946	13,961	49,115	14,814	50,314	15,843
2 संविभाग निवेश	2,615	238,604	1,598	220,551	2,615	238,604	2,084	251,142
2.1 इक्विटी	1,593	153,978	1,596	141,510	1,593	153,978	2,022	154,901
2.2 ऋण	1,022	84,626	2	79,040	1,022	84,626	63	96,241
3 अन्य निवेश	43,433	377,449	45,840	390,676	43,433	377,449	37,058	378,767
3.1 व्यापार ऋण	1,794	88,895	2,413	82,130	1,794	88,895	1,623	89,576
3.2 ऋण	7,305	159,887	4,748	170,334	7,305	159,887	5,146	158,732
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	20,073	117,110	21,603	126,455	20,073	117,110	16,083	118,476
3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं	14,261	11,557	17,077	11,758	14,261	11,557	14,206	11,984
4 रिज़र्व्स	369,955	–	363,506	–	369,955	–	386,539	–
5 कुल आस्तियां/देयताएं	564,231	958,712	554,584	905,338	564,231	958,712	576,928	983,316
6 आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)		-394,480		-350,753		-394,480		-406,388

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

प्रणाली	मात्रा (मिलियन)				मूल्य (बिलियन ₹)			
	2016-17	2017			2016-17	2017		
		अग.	सितं.	अक्तू.		अग.	सितं.	अक्तू.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 आरटीजीएस	107.86	9.46	9.61	10.00	1,253,652.08	113,827.58	127,730.70	115,808.00
1.1 ग्राहक लेनदेन	103.66	9.16	9.32	9.71	849,950.51	79,157.81	91,521.65	82,084.42
1.2 अंतरबैंक लेनदेन	4.17	0.30	0.29	0.29	131,953.25	10,005.58	10,826.48	9,971.68
1.3 अंतरबैंक समाशोधन	0.018	0.002	0.002	0.002	271,748.31	24,664.19	25,382.57	23,751.90
2 सीसीआईएल परिचालित प्रणाली	3.65	0.27	0.30	0.27	1,056,173.36	87,499.01	92,763.82	86,873.56
2.1 सीबीएलओ	0.22	0.02	0.02	0.02	229,528.33	22,784.18	23,778.02	22,981.83
2.2 सरकारी प्रतिभूतियों का समाशोधन	1.51	0.08	0.10	0.08	404,389.08	31,959.78	34,013.49	27,863.13
2.2.1 एकमुश्त	1.34	0.07	0.08	0.06	168,741.46	9,795.75	11,098.06	7,604.53
2.2.2 रिपो	0.168	0.017	0.018	0.016	235,647.62	22,164.03	22,915.42	20,258.60
2.3 विदेशी समाशोधन	1.93	0.17	0.19	0.18	422,255.95	32,755.05	34,972.31	36,028.59
3 पेपर समाशोधन	1,206.69	94.81	94.37	96.41	80,958.15	6,403.59	6,429.99	6,478.86
3.1 चेक ट्रंकेशन प्रणाली	1,111.86	92.05	92.16	94.44	74,035.22	6,224.34	6,271.53	6,340.16
3.2 एमआईसीआर समाशोधन	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1 आरबीआई के केन्द्र	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2 अन्य केन्द्र	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 गैर-एमआईसीआर समाशोधन	94.83	2.76	2.22	1.97	6,922.93	179.25	158.47	138.70
4 खुदरा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन	4,204.96	442.79	427.72	444.62	132,250.12	13,988.09	15,624.23	15,598.70
4.1 ईसीएस नामे	8.76	0.12	0.14	0.12	39.14	0.83	0.84	0.83
4.2 ईसीएस जमा (एनईसीएस शामिल है)	10.10	0.63	0.48	0.50	144.08	10.96	9.60	10.72
4.3 ईएफटी/एनईएफटी	1,622.10	151.61	157.67	158.78	120,039.68	12,500.38	14,182.14	13,851.28
4.4 तुरंत भुगतान सेवाएं (आईएमपीएस)	506.73	75.66	82.85	88.12	4,111.06	651.49	717.60	750.42
4.5 राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच)	2,057.27	214.77	186.58	197.09	7,916.17	824.43	714.06	985.45
5 कार्ड	12,055.87	1,099.84	1,102.84	1,142.16	30,214.00	3,073.12	3,163.59	3,361.88
5.1 क्रेडिट कार्ड	1,093.51	115.99	113.29	124.04	3,312.21	366.03	377.76	422.60
5.1.1 एटीएम का प्रयोग	6.37	0.66	0.65	0.68	28.39	3.05	3.11	3.21
5.1.2 पीओएस का प्रयोग	1,087.13	115.33	112.63	123.36	3,283.82	362.99	374.65	419.39
5.2 डेबिट कार्ड	10,962.36	983.86	989.55	1,018.12	26,901.79	2,707.08	2,785.83	2,939.28
5.2.1 एटीएम का प्रयोग	8,563.06	718.41	724.26	739.72	23,602.73	2,352.96	2,419.54	2,530.58
5.2.2 पीओएस का प्रयोग	2,399.30	265.45	265.30	278.40	3,299.07	354.13	366.29	408.69
6 प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई)	1,963.66	261.14	240.29	245.18	838.01	102.88	109.77	116.98
6.1 एम-वॉलेट	1,629.98	225.43	199.48	201.23	532.42	72.62	81.54	86.60
6.2 पीपीआई कार्ड	333.11	35.67	40.76	43.91	277.52	28.53	26.19	28.80
6.3 पेपर वाउचर	0.51	0.03	0.04	0.04	25.36	1.72	2.05	1.58
7 मोबाइल बैंकिंग	976.85	97.89	113.94	154.49	13,104.76	795.37	848.47	971.13
8 कार्ड बकाया	884.72	843.51	853.11	860.13	-	-	-	-
8.1 क्रेडिट कार्ड	29.84	32.65	33.34	33.87	-	-	-	-
8.2 डेबिट कार्ड	854.87	810.87	819.76	826.25	-	-	-	-
9 एटीएम की संख्या (वास्तव में)	222475	222568	221722	221314	-	-	-	-
10 पीओएस की संख्या (वास्तव में)	2529141	2882422	2900038	2958301	-	-	-	-
11 कुल जोड़ (1.1+1.2+2+3+4+5+6)	19,542.66	1,908.30	1,875.13	1,938.63	2,282,337.40	200,230.07	220,439.54	204,486.06

टिप्पणिया: पिछले 12 माह अवधि का डाटा अनंतिम है।

मोबाइल बैंकिंग - जुलाई 2017 से केवल वैयक्तिक भुगतान के आंकड़ें समाविष्ट किए गए हैं और कारपोरेट भुगतान के आंकड़ें जो पहले शामिल किए थे उन्हें छोड़ दिया गया है।

प्रासंगिक श्रृंखला

सं. 44: लघु बचत

(बिलियन ₹)

योजना		2016-17	2016	2017		
		1	मई	मार्च	अप्रै.	मई
			2	3	4	5
1. लघु बचत	प्राप्तियां	4,341.75	308.59	480.30	27.29	48.03
	बकाया	7,312.73	6,817.61	7,312.73	7,339.92	7,387.84
1.1 कुल जमाराशियां	प्राप्तियां	3,879.55	282.04	397.56	27.92	37.33
	बकाया	4,689.77	4,319.89	4,689.77	4,717.69	4,755.02
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	2,474.46	180.68	239.64	10.63	4.43
	बकाया	920.64	667.94	920.64	931.27	935.69
1.1.2 एमजीएनआरईजी	प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	बकाया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	0.56	0.01	0.49	-0.36	-0.32
	बकाया	33.01	34.27	33.01	32.65	32.33
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	0.01	0.00	0.02	-0.06	-0.04
	बकाया	-0.48	1.09	-0.48	-0.54	-0.58
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	353.34	26.48	41.41	-4.23	-1.19
	बकाया	1,800.66	1,897.58	1,800.66	1,796.43	1,795.24
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना	प्राप्तियां	100.02	6.90	13.93	8.40	12.01
	बकाया	294.53	234.79	294.53	302.93	314.94
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	476.65	34.94	56.00	9.74	15.26
	बकाया	796.58	717.78	796.58	806.32	821.58
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	518.38	501.48	518.38	521.44	527.91
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	36.58	30.66	36.58	37.33	38.38
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	51.77	48.33	51.77	52.12	52.64
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	189.85	137.31	189.85	195.43	202.65
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	474.51	33.03	46.07	3.80	7.18
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	844.53	766.14	844.53	848.33	855.52
	बकाया	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
1.1.9 डाक घर सावधि मीयादी जमाराशियां	बकाया	0	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10 अन्य जमाराशियां	बकाया	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
1.2 बचत प्रमाणपत्र	प्राप्तियां	289.85	18.35	53.84	0.03	7.32
	बकाया	1,989.35	1,925.33	1,989.35	1,989.28	1,996.49
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	120.63	4.97	29.88	-7.13	-5.04
	बकाया	872.39	869.15	872.39	865.26	860.23
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
	बकाया	8.86	8.87	8.86	8.86	8.87
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	-0.01	0.01	-0.49	-10.55	-11.88
	बकाया	535.72	625.01	535.72	525.17	513.30
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	169.23	13.37	24.45	17.73	24.27
	बकाया	460.23	309.96	460.23	477.96	502.21
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	बकाया	0	0.00	-	-0.02	-0.05
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	बकाया	-1.12	-0.95	-1.12	-1.14	-1.18
1.2.7 अन्य प्रमाणपत्र	बकाया	-0.62	-0.60	-0.62	-0.62	-0.62
1.3 लोक भविष्य निधि	प्राप्तियां	113.89	113.89	113.89	113.79	113.68
	बकाया	172.35	8.20	28.90	-0.66	3.38
	बकाया	633.61	572.39	633.61	632.95	636.33

स्रोत: महालेखाकार, डाक और तार।

सं. 45: केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

श्रेणी	केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां				
	2016		मार्च 3	2017	
	सितं. 1	दिसं. 2		जून 4	सितं. 5
(क) कुल (₹ बिलियन में)	47967.49	49246.98	49109.75	50430.94	51451.83
1. वाणिज्य बैंक	40.00	40.92	40.46	39.68	40.37
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.14	0.28	0.16	0.31	0.33
3. बीमाकृत कंपनियां	22.68	22.55	22.90	23.13	23.49
4. म्यूच्युअल फंड	2.13	1.96	1.49	1.44	1.86
5. सहकारी बैंक	2.47	2.63	2.70	2.65	2.62
6. वित्तीय संस्थाएं	0.84	0.86	0.81	0.73	0.78
7. कारपोरेट	1.09	1.05	1.05	1.29	1.04
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	3.82	3.13	3.53	4.29	4.58
9. भविष्य निधियां	6.25	6.24	6.27	6.13	5.99
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	14.80	14.61	14.65	14.29	12.84
11. अन्य	5.79	5.77	5.98	6.07	6.11
11.1 राज्य सरकार	1.84	1.83	1.92	1.91	1.92

श्रेणी	राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां				
	2016		मार्च 3	2017	
	सितं. 1	दिसं. 2		जून 4	सितं. 5
(ख) कुल (₹ बिलियन में)	18114.95	19343.91	20893.41	21467.07	22488.35
1. वाणिज्य बैंक	40.22	41.25	39.01	37.94	37.64
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.35	0.30	0.39	0.38	0.33
3. बीमाकृत कंपनियां	32.67	31.87	32.50	33.53	34.00
4. म्यूच्युअल फंड	1.62	1.36	2.42	1.89	1.92
5. सहकारी बैंक	4.21	4.47	4.75	4.82	4.82
6. वित्तीय संस्थाएं	0.27	0.29	0.30	0.27	0.22
7. कारपोरेट	0.14	0.13	0.17	0.11	0.11
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.08	0.06	0.07	0.08	0.16
9. भविष्य निधियां	16.84	16.81	17.27	18.10	18.37
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.01	0.03	0.06	0.06	0.06
11. अन्य	3.59	3.43	3.05	2.81	2.37
11.1 राज्य सरकार	-	-	-	-	-

श्रेणी	खज़ाना बिल				
	2016		मार्च 3	2017	
	सितं. 1	दिसं. 2		जून 4	सितं. 5
(ग) कुल (₹ बिलियन में)	4202.40	4366.47	3320.80	6135.01	5704.50
1. वाणिज्य बैंक	52.58	50.47	57.85	53.96	52.15
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	1.38	1.80	1.25	1.09	1.32
3. बीमाकृत कंपनियां	1.91	2.02	4.58	3.20	4.32
4. म्यूच्युअल फंड	16.06	12.91	7.85	15.31	12.44
5. सहकारी बैंक	3.52	3.28	5.62	2.48	2.33
6. वित्तीय संस्थाएं	2.75	2.76	4.57	2.60	3.54
7. कारपोरेट	1.21	1.81	1.83	1.54	1.64
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	-	-	-	-	-
9. भविष्य निधियां	0.45	0.43	0.35	0.06	0.20
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.16	0.09	0.02	0.05	0.06
11. अन्य	19.96	24.44	16.09	19.72	22.01
11.1 राज्य सरकार	15.98	20.51	11.02	16.71	18.73

टिप्पणियाँ: "-" नगण्य में कुछ नहीं दर्शाता है।

1. जून 2016 से संशोधित सारणी फार्मेट में केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के साथ राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ और खज़ाना बिलों सहित स्वामित्व का पैटर्न समाविष्ट किया गया है।
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) स्कीम के अंतर्गत जारी विशेष बान्ड शामिल किए गए हैं।
3. वाणिज्य बैंक के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक व्यापारी (पीडी) को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में वे बहुत ही छोटे अंश में हैं।
4. "अन्य" श्रेणी में राज्य सरकारें, पेंशन निधियाँ, सरकारी क्षेत्र की इकाईयाँ, न्याय, एचयूएफ/ वैयक्तिक आदि समाविष्ट हैं।

सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(बिलियन ₹)

मद	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (सं.अ.)	2017-18 (ब.अ.)
	1	2	3	4	5	6
1. कुल वितरण	26,949.34	30,002.99	32,852.10	33,782.60	40,599.68	43,957.96
1.1 गतिविधियां	15,741.62	17,142.21	18,720.62	19,429.44	24,271.15	26,194.51
1.1.1 राजस्व	12,807.14	13,944.26	14,830.18	14,971.45	18,457.92	19,701.57
1.1.2 पूंजी	2,446.11	2,785.08	3,322.62	3,400.51	4,471.03	5,515.05
1.1.3 ऋण	488.38	412.88	567.82	1,057.49	1,342.20	977.89
1.2 गैर गतिविधियां	10,850.47	12,427.83	13,667.69	13,984.15	15,870.24	17,261.83
1.2.1 राजस्व	9,991.40	11,413.65	12,695.20	12,739.11	15,031.91	16,430.73
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	4,543.06	5,342.30	5,845.42	6,134.74	6,881.68	7,536.87
1.2.2 पूंजी	837.14	990.37	946.87	1,207.71	816.42	807.16
1.2.3 ऋण	21.93	23.81	25.63	37.33	21.92	23.94
1.3 अन्य	357.24	432.95	463.79	369.01	458.29	501.62
2. कुल प्राप्तियां	27,690.29	30,013.72	31,897.37	34,487.63	39,810.09	42,551.06
2.1 राजस्व प्राप्तियां	19,716.19	22,114.75	23,876.93	24,504.58	30,356.58	33,511.38
2.1.1 कर प्राप्तियां	16,879.59	18,465.45	20,207.28	20,754.42	23,917.47	27,066.67
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	10,385.91	11,257.81	12,123.48	12,912.47	15,168.50	16,914.54
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	6,462.73	7,176.34	8,051.76	7,803.16	8,706.20	10,105.34
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	30.94	31.30	32.04	38.78	42.77	46.79
2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां	2,836.60	3,649.30	3,669.65	3,750.16	6,439.11	6,444.71
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	355.43	401.62	396.22	347.38	322.08	275.25
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	389.20	391.13	609.55	588.52	595.33	1,245.96
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	129.29	93.85	220.72	155.86	136.03	519.12
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	259.91	297.28	388.83	432.66	459.30	726.84
3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	6,843.95	7,497.11	8,365.63	8,689.51	9,647.78	9,200.62
3 क वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	6,771.94	7,424.19	8,236.30	8,562.02	9,499.05	9,042.73
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	3,352.80	3,358.58	-374.76	2,310.90	6,306.09	...
3क.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	548.40	1,081.30	-3,341.85	604.72	1,958.16	...
3क.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	3,419.14	4,065.61	8,611.06	6,251.12	3,192.96	...
3क.2 बाह्य वित्तपोषण	72.01	72.92	129.33	127.48	148.73	157.89
3ख. वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	6,771.94	7,424.19	8,236.30	8,562.02	9,499.05	9,042.73
3ख.1.1 बाजार उधार (निवल)	6,536.94	6,391.99	6,640.58	6,354.19	6,472.74	6,970.13
3ख.1.2 लघु बचत (निवल)	-85.70	-142.81	-565.80	-785.15	-1,091.76	-941.16
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	329.94	312.90	343.39	298.82	326.18	332.03
3ख.1.4 आरक्षित निधियां	-4.12	34.63	51.09	-33.22	-82.42	-10.45
3ख.1.5 जमाराशियां और अग्रिम	27.22	255.45	275.45	134.70	386.99	502.14
3ख.1.6 नकद शेष	-740.96	-10.72	954.74	-705.03	789.59	1,406.90
3ख.1.7 अन्य	708.62	582.75	536.84	3,297.71	2,697.73	783.13
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	72.01	72.92	129.33	127.48	148.73	157.89
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल वितरण	27.1	26.7	26.4	24.7	26.7	26.1
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल प्राप्तियां	27.8	26.7	25.6	25.2	26.2	25.3
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर राजस्व प्राप्तियां	19.8	19.7	19.2	17.9	20.0	19.9
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कर प्राप्तियां	17.0	16.4	16.2	15.2	15.8	16.1
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर सकल वित्तीय घाटा	6.9	6.7	6.7	6.4	6.4	5.5

स्रोत : केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज

... उपलब्ध नहीं। सं.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान

सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(बिलियन ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	अक्टूबर 2017 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओवरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	
1	आंध्र प्रदेश	602.99	10	355.95	5	-	-
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	-	-	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-
6	गोवा	23.09	8	-	-	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	-	-	-	-	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
10	जम्मू और कश्मीर	-	-	394.56	11	-	-
11	झारखंड	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
13	केरल	-	-	-	-	-	-
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-
16	मणिपुर	-	-	-	-	-	-
17	मेघालय	-	-	-	-	-	-
18	मिज़ोरम	-	-	-	-	-	-
19	नागालैंड	151.93	29	132.54	3	-	-
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	7.34	29	698.35	29	303.82	10
23	राजस्थान	-	-	-	-	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	395.11	19	441.72	13	-	-
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
27	उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-
28	उत्तरप्रदेश	177.21	14	229	13	-	-
29	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-

सं.48: राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश

(बिलियन ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	अक्टूबर 2017 की समाप्ति तक		
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	निलामी खज़ाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	63.03	6.57	0
2	अरुणाचल प्रदेश	7.59	--	0
3	असम	39.26	0.34	14.00
4	बिहार	43.09	--	50.00
5	छत्तीसगढ़	30.52	--	0
6	गोवा	4.35	2.17	0
7	गुजरात	109.85	3.84	70.00
8	हरियाणा	16.78	9.37	0
9	हिमाचल प्रदेश	--	--	5.00
10	जम्मू और कश्मीर	--	--	0
11	झारखंड	--	--	0
12	कर्नाटक	24.77	--	150.00
13	केरल	17.27	--	0
14	मध्य प्रदेश	--	7.43	0
15	महाराष्ट्र	247.23	--	420.00
16	मणिपुर	2.72	0.63	0
17	मेघालय	4.47	0.16	0
18	मिज़ोरम	3.90	0.20	0
19	नागालैंड	9.78	0.25	0
20	उड़ीसा	107.35	11.63	50.00
21	पुदुचेरी	2.70	--	7.71
22	पंजाब	0	0	0
23	राजस्थान	--	--	44.74
24	तमिलनाडु	50.17	--	233.50
25	तेलंगाना	38.48	5.62	0
26	त्रिपुरा	5.79	0.03	0
27	उत्तराखंड	--	--	0
28	उत्तरप्रदेश	24.08	0.64	0
29	पश्चिम बंगाल	83.27	2.04	50.00
	कुल	936.45	50.93	1094.96

वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सारणी सं. 1

- 1.2 और 6: वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं।
3.5 और 3.7: वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।
4.1 से 4.4, 4.8.4.12 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।
4.5, 4.6 और 4.7 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।
4.9 से 4.11 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम निलामी दिन से संबंधित है।

सारणी सं. 2

- 2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।
2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियों और अल्पावधि प्रतिभूतियों/बांडों सहित जैसे - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी।

सारणी सं. 4

<http://nsdp.rbi.org.in> के 'रिज़र्व टेम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वता वार बकाया फॉर्बर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी सं. 5

अन्य को विशेष पुर्नवित्त सुविधा, अर्थात् एक्जिम बैंक को 31 मार्च 2013 से बंद है।

सारणी सं. 6

- अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकड़े सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।
2.2 : आईएमएफ खाता सं.1 की शेष राशि में आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

सारणी सं.7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4: आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांड शामिल हैं।

सारणी सं.8

- एनएम2 और एनएम3 में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।
2.4: चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।
2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

सारणी सं.9

वित्तीय संस्थाओं में एक्जिम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।
एल1 और एल2 मासिक आधार पर और एल3 तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।
जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनःदिए गए हैं।

सारणी सं.13

कालम सं (1),(2) और (3) के सामने दर्शाए गए आंकड़े अंतिम (आरआरबी सहित) हैं और कालम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकड़े अनंतिम (आरआरबी को छोड़कर) हैं।

सारणी सं.15 और 16

डाटा अनंतिम है और चुनिंदा 41 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित है जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (आईएनजी वैश्य को छोड़कर जिसे अप्रैल 2015 को कोटक महिंद्रा के साथ विलय किया गया है) द्वारा दिये गये कुल खाद्येतर ऋण के 90 प्रतिशत शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात ऋण केवल विदेशी बैंक से संबंधित है।

मद 2.1 के अंतर्गत माइक्रो और लघु में विनिर्माण क्षेत्र में माइक्रो और लघु उद्योग को दिए गए ऋण शामिल हैं।

मद 5.2 के अंतर्गत माइक्रो और लघु उद्यमों में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में माइक्रो तथा लघु उद्यमों को दिए गए ऋण शामिल हैं।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पुरानी परिभाषा के अनुसार है और दि. 23 अप्रैल 2015 के एफआईडीडी परिपत्र एफआईडीडी.केका. प्लान.बीसी.54/ 04.09.01/2014-15 के अनुरूप नहीं है।

सारणी सं.17

2.1.1: राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।

2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं हैं।

4. : आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

सारणी सं.24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सारणी सं.30

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं।

1: बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।

2: संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी-अधिमान शेयर शामिल हैं।

सारणी सं.32

आईआईएफ सी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांडों में निवेश तथा सार्क स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा और भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक को अंतरित एसडीआर शामिल नहीं हैं। अमरीकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिज़र्व में रखी गैर-यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यहास को शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रूपी-अमरीकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों में परिवर्तित किया गया है।

सारणी सं.34

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.4 : अनुमान

1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान

'अन्य पूंजी' एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी संस्थाओं/शाखाओं के बीच के ऋण संबंधी लेनदेन से संबंधित है। हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय-अंतराल के कारण ये आंकड़े भुगतान-संतुलन के आंकड़ों से मेल न खाएं।

सारणी सं.35

1.10 : जर्नलों के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

सारणी सं.36

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि या मूल्यहास का संकेतक । 6-मुद्राओं वाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2012-13 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। इससे संबंधित कार्यपद्धति का विवरण बुलेटिन के दिसंबर 2005 और अप्रैल 2014 के अंक में दिया गया है।

सारणी सं.37

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

सारणी सं.38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

सारणी सं.43

1.3: बहुपक्षीय निवल निपटान समूहों से संबंधित है।

3.1: मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नै - तीन केन्द्रों से संबंधित है।

3.3: 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृहों से संबंधित है।

6: दिसंबर 2010 से उपलब्ध।

7: आईएमपीएस लेनदेन शामिल हैं।

9: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा खोले गए एटीएम और व्हाइट लेबल एटीएम शामिल है। अप्रैल 2014 से व्हाइट लेबल एटीएम शामिल किए गए हैं।

मोबाइल बैंकिंग - जुलाई 2017 से केवल वैयक्तिक भुगतान के आंकड़ें समाविष्ट किए गए हैं और कारपोरेट भुगतान के आंकड़ें जो पहले शामिल किए थे उन्हें छोड़ दिया गया है।

सारणी सं. 45

(-): नगण्य को दर्शाता है।

इस तिमाही में, संशोधित टेबल फार्मेट केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों सहित राज्य सरकारों की स्वामित्ववाली प्रतिभूतियाँ और खज़ाना बिलों सहित शामिल है। इसके अतिरिक्त, पहली बार राज्य सरकारों की धारित प्रतिभूतियों को अलग श्रेणी में दर्शाया गया है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्वल डिस्कॉम एशयोरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बान्ड शामिल हैं। वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इसका हिस्सा बहुत कम है।

"अन्य" श्रेणी में राज्य सरकारों, पेंशन निधियां, न्यास, संस्थाएं, हिंदू अविभक्त परिवार / वैयक्तिक आदि. शामिल है।

सारणी सं. 46

वर्ष 2011-12 और उसके बाद के जीडीपी आंकड़ों के लिए आधार वर्ष 2011-12 लिया गया है। वर्ष 2015-16 के आंकड़े 26 राज्यों से संबंधित है।

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि व्यय को छोड़कर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय।

1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुनःचुकोती सहित) और राज्य सरकार के निवल चुकोती से संबंधित है।

1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजा और कार्य से संबंधित है।

2: यह डाटा केंद्र और राज्य सरकारों को दिये गये उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते है।

3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार है।

3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों और 364 दिन के राजकोषीय बिलों के माध्यम से प्राप्त उधारियों सहित।

3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विशेष प्रतिभूतियों में किये गये निवल निवेश को दर्शाते है।

3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।

3बी.1.7: वित्तीय संस्थानों, बीमा और पेंशन निधि, प्रेषण, नकदी शेष निवेश लेखा से लिये गये ऋण, खज़ाना बिलों (364-दिन के खज़ाना बिलों को छोड़कर) सहित।

सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और निलामी खज़ाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपाश्विक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्पकालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।

राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।

प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।

-: नगण्य

सारणी सं.48

समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।

नीलामी खज़ाना बिलों (ए टी बी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारों में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों की खज़ाना बिल शामिल हैं।

--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी संबंधी अवधारणाएं एवं कार्यप्रणालियां भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन के वर्तमान सांख्यिकी संबंधी व्यापक मार्गदर्शिका (<https://rbi.org.in/scripts/publicationsview.aspx?id=17618>) में उपलब्ध हैं।

विस्तृत टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों (जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की हैंडबुक) में उपलब्ध हैं।

बुलेटिन लेख, 2018 के लिए सांकेतिक कैलेंडर

क्र.सं	विषय	बुलेटिन जारी करने का माह
1	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के निर्यात पर सर्वेक्षण: 2016-17	जनवरी
2	भारतीय कंपनियों की विदेशी देयताओं और आस्तियों की वार्षिक गणना:2016-17	फरवरी
3	जमाराशियों का संघटन और स्वामित्व, 2017	
4	केंद्र सरकार का बजट 2017-18: एक मूल्यांकन	मई
5	हाउसहोल्ड की मुद्रास्फीति प्रत्याशा संबंधी सर्वेक्षण : 2017-18	जून
6	औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण: 2017-18	
7	भारत का विदेशी व्यापार: 2017-18	जुलाई
8	निजी कॉर्पोरेट कारोबार क्षेत्र का व्यापक विश्लेषण	
9	अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी 2017	
10	भारतीय अर्थव्यवस्था में निधि लेखों का प्रवाह.2016-17	अगस्त
11	भारत का भुगतान संतुलन:2017-18	
12	मार्च 2018 की समाप्ति तक भारत का बाहरी ऋण	सितंबर
13	कारपोरेट निवेश: 2017-18 में संवृद्धि और 2018-19 की संभावनाएँ	
14	उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण: 2017-18	अक्टूबर
15	निजी कॉर्पोरेट कारोबार क्षेत्र का कार्यनिष्पादन:2017-18	नवंबर
16	बैंकिंग सेवाओं में अंतरराष्ट्रीय व्यापार:2017-18	दिसंबर

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2017	₹300 एक प्रति (काउंटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित) ₹4200 (डाक प्रभार सहित एक वर्ष का अभिदान) ₹3150 (एक वर्ष का रियायती दर*) ₹3360 (एक वर्ष का अंशदान - डाक प्रभार सहित ^o) ₹2520 (एक वर्ष का रियायती दर ^o)	15 अमरीकी डॉलर एक प्रति (डाक प्रभार सहित) 180 अमरीकी डॉलर (एक वर्ष का अभिदान) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय स्टेट 2016-17 पर सांख्यिकीय हैंड बुक	₹550 एक प्रति (सामान्य) ₹600 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय इकोनॉमी 2015-16 पर सांख्यिकीय हैंड बुक	₹500 एक प्रति (सामान्य) ₹550 एक प्रति (डाक प्रभार सहित) ₹375 एक प्रति (रियायती) ₹425 एक प्रति (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्त : 2016-17 के बजटों का अध्ययन	₹500 एक प्रति (काउंटर पर) ₹550 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	अमरीकी डॉलर 23 एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. मिंट रोड माइलस्टोन्स : आरबीआई ऐट 75	₹1650 एक प्रति (काउंटर पर)	अमरीकी डॉलर 50 एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. रिपोर्ट ऑफ दि कमिटी ऑन फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी (तारापौर समिति की रिपोर्ट II)	₹140 एक प्रति (सामान्य) ₹170 (डाक द्वारा एक प्रति)	अमरीकी डॉलर 25 एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
7. भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मूलभूत सांख्यिकी विवरणियां, खंड 41 मार्च 2012	₹270 एक प्रति (काउंटर पर) ₹310 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	अमरीकी डॉलर 10 एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
8. बैंकिंग शब्दावली (2012)	₹80 एक प्रति (काउंटर पर) ₹120 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
9. अनुवाद के विविध आयाम (हिंदी)	₹165 एक प्रति (काउंटर पर) ₹205 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
10. बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन: दशा और दिशा (हिंदी)	₹150 एक प्रति (काउंटर पर) ₹200 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	

टिप्पणिया:

1. उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।
 2. टाइम सीरीज़ डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (<http://dbic.rbi.org.in>)।
 3. भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-1997 (4 खंड), वित्तीय संकट के संदर्भ में केन्द्रीय बैंकिंग की चुनौतियां और भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था: वृद्धि और वित्त भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।
- * भारत में छात्रों, अध्यापकों/ व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- @ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को बढ़ावा देने हेतु, घरेलू ग्राहक जो एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, उन्हें 20 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

हाल के प्रकाशन

सामान्य अनुदेश:

1. बिक्री हुई प्रतियां वापस नहीं ली जाएंगी।
2. प्रकाशन कन्साइनमेंट वीपीपी आधार पर नहीं भेजा जाएगा।
3. जहां कहीं रियायती मूल्य का उल्लेख नहीं है, वहां भारत में छात्रों, अध्यापकों/व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी, बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रकाशन के पिछले अंक उपलब्ध नहीं हैं।
4. प्रकाशनों की (सोमवार से शुक्रवार) तक बिक्री तथा वितरण प्रभाग, कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारिबैं, अमर बिल्डिंग, तल मंजिल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई- 400 001 पर उपलब्ध हैं। बिक्री अनुभाग का संपर्क नं. 022-2260 3000, विस्तार 4002, ई-मेल: spsdcs@rbi.org.in है।
5. अभिदान मुख्यतः एनईएफटी द्वारा किया जाना चाहिए और अग्रेषण पत्र, जिसके साथ एनईएफटी विवरण संलग्न हो, मुख्य महाप्रबंधक, कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, दूसरी मंजिल, मुख्य भवन, मुंबई- 400 001 को संबोधित होना चाहिए।
एनईएफटी फार्म में निम्नलिखित जानकारी भरना अपेक्षित है:

लाभार्थी का नाम	कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारिबैं
बैंक का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक
शाखा तथा पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBIS0MBPA04
खाते का प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8691632-86
प्रेषक से प्राप्तकर्ता की जानकारी	अभिदाता का नाम अभिदाता सं.....

6. प्रकाशनों को शीघ्रतापूर्वक भेजने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तथापि मांग अधिक होने पर पहले आओ पहले पाओ आधार पर प्रकाशनों की आपूर्ति की जाएगी। औपचारिकताएं पूरा करने और उसके बाद उपलब्ध प्रकाशनों को भेजने में न्यूनतम एक महीने का समय लगेगा। 'प्रकाशन प्राप्त न होने की शिकायत' 2 महीने के अंदर भेजी जाए।
7. कृपया अपना अंशदान संख्या, नाम, पता तथा ई मेल आईडी to spsdcs@rbi.org.in को प्रेषित करें ताकि हम सुचारु रूप से आपके साथ संपर्क कर सकें।